

Sixth Series, Vol. IX No. 26

Thursday, December 22, 1977
Pausa 1, 1899 (Saka)

Lok Sabha Debates

Third Session)



(Vol. IX, contains Nos. 21-30)

LOK SABHA SECRETARIAT

**New Delhi
Price- Rs 4.00**

C O N T E N T S

(Sixth Series, Volume IX, Third Session, 1977)

No. 26, Thursday, December 22, 1977/Pausa 1, 1899 (Saka)

COLUMNS

Members Sworn	I
<i>Re. Adjournment Motion</i>	1—3
Oral Answers to Questions :	
*Starred Questions Nos. 509 to 511	3—23
Short Notice Question No. 7	24—27
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 512 to 514 and 516 to 529	27—41
Unstarred Questions Nos. 4767 to 4788 and 4790 to 4894	41—141
Question of Privilege against Chairman, Calcutta Port Trust	141—50
<i>Re. Discussion on prices of sugarcane and gur</i>	150—54
Papers laid on the Table	154—62
Committee on Papers laid on the Table—	
Minutes	162
Messages from Rajya Sabha	162—63
Children (Amendment) Bill
—As passed by Rajya Sabha	163
Committee on Papers laid on the Table—	
Second Report	163
Public Accounts Committee—	
2nd, 18th, 21st, 24th, 31st, 33rd, 36th, 41st, 42nd, 47th and 50th Reports	163—65
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Tenth Report	165

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

Committee on Subordinate Legislation—	
Fourth Report	165
Committee on Government Assurances—	
First Report	165
Bills Introduced—	
(i) Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Bill	166—71
(ii) Election Laws (Amendment) Bill	171
Matters under Rule 377—	
(i) Failure to increase the price of sugarcane	173—77
(ii) Mismanagement in the C.M.I. Ltd. and Eastern Manganese and Minerals Ltd., Domchanch, Bihar	177—79
(iii) Reported News about wrongful confinement of Mr. Justice S. K. Verma by the management of Swadeshi Polytex Ltd., Ghazisabad	179—82
(iv) Fire accident in Samachar Office, Bombay	182—83
(v) Failure to give citizenship rights to refugees who came to India after 1971 Indo-Pak War	183—85
(vi) Sale of several thousand East Pakistan refugee women from Mana camp	185—86
Statement <i>re.</i> Appointment by Indian Red Cross Society of Officials on a Committee to distribute relief materials	186—91
Resolution <i>re.</i> First Report of the Railway Convention Committee	192—234
Prof. Madhu Dandavate	192—94, 222—34
Shri Mohd. Shafi Qureshi	194—214
Shri M. Kalyanasundaram	215—19
Shri V. M. Sudheeran	219—21
Shri K. A. Rajan	221—22
Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill—	
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	235—47
Shri Sikandar Bakht	235, 245—46
Shri Jagannath Rao	236—37

Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya	237
Shri G. M. Banatwalla	238—41
Shri Vayalar Ravi	241—42
Shri Saugata Roy	243—45
Clauses 2, 3 and 1	247
Motion to pass.	247—50
Shri Sikandar Bakht .	247, 249
Dr. Ramji Singh . . .	247—49
Betwa River Board (Amendment) Bill—	
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	250—63
Shri Bhanu Pratap Singh . . .	250—51, 259—63
Shri Tej Pratap Singh	251—56
Shri Laxmi Narain Nayak . .	256—59
Clauses 2 to 7 and 1	263—65
Motion to pass.	265—68
Shri Bhanu Pratap Singh	265, 268
Shri Laxmi Narain Nayak . .	266
Shri Ambika Prasad Pandey	266—67
Motion <i>re.</i> Two serious train accidents on the Northern Railway— <i>contd.</i>	
Shri Saugata Roy	269—88
Dr. Ramji Singh	273—79
Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya . .	279—82
Shri Yuvraj	282—87

LOK SABHA DEBATES

I

LOK SABHA

Thursday, December 22, 1977/Pause 1, 1899
(Saka)

2

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : I rise on a point of order.
(Interruptions).

SHRI VAYALAR RAVI : There is a large scale rigging and the people were prevented from voting. We are demanding and requesting you to take up the adjournment motion and suspend the question Hour.

MR. SPEAKER : I have got your motion. I have requested you to produce *prima facie* material and I have told other Members also who met me that during the interval you may come and meet me and the question can be taken up either this afternoon or tomorrow. There is no difficulty. (Interruptions).

SHRI JYOTIRMOY BOSU : How many Kerala Ministers have been unseated?

SHRI K. LAKKAPPA : At the point of gun even the harijans, the minority communities and weaker sections were threatened.

MR. SPEAKER : Even then, no adjournment motion is necessary. If it is serious, I have already told you to give me the facts. (Interruptions).

SHRI K. LAKKAPPA : We have read that at the point of gun they had been threatened.

MR. SPEAKER : We now take up questions.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : We have succeeded.

SHRI VAYALAR RAVI : In accordance with your instructions we sat down. He is a drain cleaner here.... (Interruptions).

MR. SPEAKER : Order, Order..... (Interruptions). Do not record anything.

SHRI VAYALAR RAVI :*

SHRI JYOTIRMOY BOSU :*

MR. SPEAKER : Question No. 509. We take up questions.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : I request you that the House should be calm and quiet; the House should be in order.

* Not recorded.

MR. SPEAKER : Yet.

SHRI C. M. STEPHEN : For the time he has spoken in English.

MR. SPEAKER : Let us take up questions.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Medical assistance by Red Cross Society to Cyclone hit people

*509. SHRI SURENDRA BIKRAM : SHRI K. MALLANNA :

Will the Minister of HELATH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the details regarding the medical assistance provided by the Red Cross Society for the relief of the cyclone hit victims of Andhra Pradesh ;

(d) whether some foreign countries have also come forward to extend their cooperation to help the cyclone hit people ; and

(c) if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) आनंद प्रदेश के गुप्तर और मठलीपट्टनम इलाकों में रेडक्रॉस के आठ डाक्टर चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भारतीय रेडक्रॉस मुक्त्यालय ने आनंदप्रदेश को एक लाख रुपए के मूल्य की दबाइयों तथा अन्य चिकित्सीय सामग्री भिजवाई है। राज्य में तृकान पीड़ित लोगों के लिए एम्बूलेंस सेवायें भी चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त रेडक्रॉस ने प्रारम्भ के तौर पर लंबाय १२ हजार व्यक्तियों को, जो तृकान के कारण अपने अंग बंदा बैठे हैं, प्रति व्यक्ति अधिकतम पांच सौ रुपए कीमत के कुलिम अंग देने की पेशकश भी की है।

(ख) और (ग). जी, हां। रेडक्रॉस सोसाइटी ने यह बताया है कि फिनलैंड, कांस, जर्मन संघीय गणराज्य, जर्मन जनवादी

गणराज्य ; इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे और पाकिस्तान की नी रेडक्रॉस सोसाइटियों तथा नार्वे, जापान और इंग्लैंड की मरकारों ने २ करोड़ ३७ लाख रुपए के मूल्य की सामग्री अंशदान के रूप में देने की घोषणा की है। इसमें से लगभग १९ लाख रुपए की सामग्री और गाड़ियां प्राप्त हो चुकी हैं। इन चीजों के अलावा अफगानिस्तान, आस्ट्रलिया, बल्जीयम, कनाडा, देनमार्क, फिनलैंड प्रेट्रिटेन, ईरान, जापान, लक्ष्मनवर्ग, मोनेको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका इत्यादि की १८ राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटियों तथा कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों ने अंशदान के रूप में एक बरांड ८१ लाख रुपए की नकद रकम देने की भी पेशकश की है। इस रकम में से २७ लाख २१ हजार रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र विकास : अध्यक्ष जी जिस समय रेडक्रॉस की तरफ हे त्रिग्ला देश को सहायता दी गई थी उस में बड़ा भारी पृष्ठाला तुम्हा था। मैं, भाननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह जो सहायता विदेशों से रेडक्रॉस के माध्यम से आ रही है, इसका वितरण ठीक प्रकार से हो, सही आदिमियों तक बस्तुये पहुँच जायें, इस के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राज नारायण : बस्तुओं के दाटने की व्यवस्था इस समय जो दिल्ली को अस्थिर भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी है, केवल वही नहीं कर रही है, अपिनु जो उस की बांध आनंद में या दूसरे राज्यों में है, वे भी इस व्यवस्था को कर रहे हैं। हम समझते हैं कि समुचित व्यवस्था हो रही है। इस के पूर्व हमारे विभाग के ३० बिस्ट ने वहां जा कर बहुत सी बातों को देखा है और ता० २६ को हमारे यहां के स्टेट मिनिस्टर

झोर एहीजनल सकेटरी थी के० पी० सिंह आदि लोग वहां जा रहे हैं । वे वहां जा कर देखेंगे कि जो दवाइयां झोर कम्बल आदि बस्तुयें भेजी गई हैं उन का वितरण समुचित हो रहा है या नहीं । हमारी जितनी शक्ति झोर लगता है—हम यह जहर देखेंगे कि ठोक लोगों को ठीक डंग से सहायता उपलब्ध हो रही है या नहीं ।

श्री मुरेन्द्र विक्रम : मंत्री जी ने बतलाया कि पूर्व तथा पश्चिम के द्वन्द्वों से दवाइयां, नकदी आदि बस्तुयें सहायता के रूप में प्राप्त हुई हैं । उन्होंने जिव देणों के नाम लिये, उन में चाइना का नाम नहीं बतलाया, क्या चाइना से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है ?

दूसरा प्रश्न—उन्होंने बतलाया है कि 500 रुपए में कृतिम अंग लगाये जायेंगे । मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो 500 रुपए नहीं दे सकेंगे—क्या सरकार ऐसे लोगों के लिए 500 रुपया स्वयं दे कर कम्पनेट करेगी ?

श्री राज नारायण : एक विषय की जानकारी सम्मानित सदस्य को होनी चाहिए कि जो प्राकृतिक विपदा आती है, इस से जो नुकसान होता है, इस की मुख्य जिम्मेदारी कृषि मन्त्रालय की है । अब चाइना ने कृषि मन्त्रालय को कोई चीज भेजी है या नहीं, मगेर मालूम नहीं है । स्वास्थ्य मन्त्रालय को जिन-जिन विदेशी सरकारों ने सहायता दी है या क्या-क्या सहायता देने की उन्होंने घोषणा की है, वह मैंने आप के समल निवेदन कर दिया है । चाइना ने दिया है या नहीं दिया है—इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ।

श्री मुरेन्द्र विक्रम : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का आप ने उत्तर नहीं दिया । 500 रुपए में कृतिम अंग लगाने की जो बात है, बहुत से गरीब आदमी उस को नहीं दे

पायेंगे—क्या सरकार उस को कम्पने करवायेगी ?

श्री राज नारायण : 500 रुपए में कृतिम अंग नहीं बनेगा तो हमारी कोशिश जरूर होगी कि हम उस को कम्पनेट करें । हमारा विभाग नहीं कर सकेगा तो दूसरे विभाग से कराने की कोशिश करेंगे कि उस का जो अंगभंग हुआ है, समुचित रूप से उस की उत्तरीभाग को हटा दें ।

श्रीमती मृजाल गोरे : प्रभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि भान्दा की जो शाक्ता है उस के द्वारा वितरण हो रहा है—यह बात ठीक है । लेकिन जब अधिल भारतीय रेडक्रास सोसायटी के बारे में सब लोगों के मन में मंशय है और पिछले 6-9 महीनों से हम लोग लगातार पूछ रहे हैं और हमें यहां सदन में कहा भी गया था कि आप इस के ऊपर एन्कवायरी नियुक्त करेंगे—क्या यह बात सही है कि न तो हैल्प विनियूटी ने कोई एन्कवायरी नियुक्त की है और नाहीं प्राइम नियूट्रिटर की ओर से कोई एन्कवायरी हुई है, बल्कि जो उस की मैट्रेजिक-बाटी है, उस पर हमारा जाक है, जिस के बिहु आरोप लगाये गये थे, उसी मैट्रेजिक बाटी ने एन्कवायरी नियुक्त की है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ—क्या यह सही कार्य-वाही है कि जिस के बिहु करण्णन प्रोट घूस्खोरी के आरोप लगाये गये हों, वही इन्कवायरी इंस्टीचूट करे ?

श्री राज नारायण : श्रीनन्, सम्मानित सदस्यों का क्यन सत्य है ।

श्रीमती मृजाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया : जिन के ऊपर आरोप है, वे ही एन्कवायरी इंस्टीचूट करें—तो क्या एन्कवायरी इंस्टीचूट कराने का सरकार जा यहीं तरीका है ? मकार इविहैन्दैन एन्कवायरी क्यों नहीं कराती ? मंत्री महोदय ने कहा कि खुद एन्कवायरी करेंगे—उस का क्या हृषा ?

श्री राज नारायण : मैंने सदन में जो अन्वयासन दिया है, उस के प्रति मैं सजग और सुचेत हूँ। रेड कास सोसायटी की मनेजिंग बाड़ी ने श्री सुविमल दत्त को, जो फार्मर कारन लेक्टरी और फार्मर सेटल विजिलेंस कमिश्नर हैं कहा है कि वह इस बारे में प्रिलिमिनरी एनक्वायरी कर लें। (व्यवधान) एक रसपांसिबल आदमी को यह काम दिया गया है कि वह ईशानदारी के साथ ईटेंड में जा कर पूरी एनक्वायरी करें। और उस के बाद भी इस बात की नुंजाइश रहती है कि और कोई एनक्वायरी करना जरूरी है, तो माननीय सदस्य यहां हैं, सदन यहां है और हम लोग भी यहां हैं, फिर एनक्वायरी हो जायेगी। इस में परेक्षानी की क्षमा बात है?

चैम्पली मुकुल योदेरे : मेरा सवाल यह है कि जिन पर आरोप है, क्या वही एनक्वायरी करायेंगे। श्री सुविमल दत्त कैसे आदमी हैं, उस से मुझ कोई नतलब नहीं है। सवाल यह है कि जिन पर आरोप है, क्या वही एनक्वायरी नियुक्त करेंगे। यह क्या तरीका है?

MR. SPEAKER : She says that there are certain allegations against certain of the members.

श्री राज नारायण : माननीय सदस्यों की एंगजायटी, उन का कोनूहल, बिन्कुल उचित है और बजा है। एंगजायटी के लिए हिन्दी में साहित्यिक शब्द कोनूहल होता है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Her question is very simple. She wants to know whether you are holding an enquiry.

SHRI RAJ NARAIN : The question is not very simple; and the answer is also not very simple. The question is complicated; the answer is also complicated.

रेड कास सोसायटी की सारी फाइलों को देखने और सब बातों को सुनने समझने के बाद मनेजिंग बाड़ी ने यह रिकवर्ट की कि दत्त कम्पेटी से एनक्वायरी करा ली जाये।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY : I come from that area. There are a number of countries coming directly to provide aid. The aid is not going to the deserving ones. It must be coordinated. Will the Minister ensure that the whole aid is given to people through the State Government which is handling it in a coordinated way?

श्री राज नारायण : श्रीमान्,

“सीता कर अति विप्रति विशाला ।
बिनाही कहे भलि दीन दयाला ॥”

आनन्द प्रदेश में स्टेट बैंकेंट ने इस नेवरल कैलेंग्टी के साथ किस ढंग से व्यवहार किया है, उस के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जारी देख इस बत को जानता हूँ कि स्टेट बैंकेंट ने इस स्थिति से निष्टाने के लिए ठीक ढंग से काम नहीं किया है।

.... (व्यवधान)

श्री चान्द्रलेखर तिह : सत्य से ये इनकास क्यों करते हैं। आनन्द प्रदेश की सरकार ने इस विपक्ष से निष्टाने के लिए वैसी जांचदारी नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी। (व्यवधान) -

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, the Minister must be called to order. He must be relevant. He cannot make aspersions against the State Government. (interruptions).

MR. SPEAKER : Order, order. I am on my legs. You cannot shout. The question of controlling the House is not in the hands of any one of you. It is in my hands....(interruptions). Do not record.

SOME HON. MEMBERS : ***

Mr. SPEAKER : Mr. Minister, the question that is put to you is this : are you going to channel this through the State Government? Do not get into other controversies, whether the State Government is misusing it or not. Kindly answer the question.

श्री राज नारायण : श्रीमन् यह जानकारी में आप के द्वारा सम्मानित सदन को देना चाहता हूँ कि जो मैट्रियोलॉजीकल डिपार्टमेंट, है, उसमें तुकान आ रहा है, इस की सूचना बहुत पहले दे दी जी। .. (व्यवधान) ..

MR. SPEAKER : A direct question. Why don't you answer ? (Interruptions).

Kindly help the House.

SHRI RAJ NARAIN : Even now do you say that I am not helping the House ?

MR. SPEAKER : Their question is are you willing to channelise the aid through the State Government ?

SHRI RAJ NARAIN : Why not ?

MR. SPEAKER : Please answer that.

श्री राज नारायण : मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जितनी उत्पत्तिका हमारे सम्मानित सदस्य इस सदन में दिख रहे हैं, और वे अंग्रेजप्रदेश के विवरितप्रस्त लोगों के लिए (अवधारणा) स्टेट गवर्नरेंट के द्वारा जो मदद मांगी गई और अब तक जो मदद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को दी (अवधारणा) रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज हमार कंट्रोल में नहीं है (अवधारणा), उसने क्या मदद दी, वहां को गवर्नरेंट ने क्या मांगा यह हम कैसे बता सकते हैं (अवधारणा)

MR. SPEAKER : Do not record anything.

SOME HON. MEMBERS : **

जिसाई और बोकरो इस्पात संबंधों के विस्तार के लिए भासीनरी का अन्युक्त वडे सूचा

* 510. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या इस्पात और जान मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिसाई और बोकरो इस्पात संबंधों के विस्तार कार्य के प्रयोगनार्थ करोड़ों रुपये के मूल्य की भजीनरी तथा अन्य सामग्री बांड में अवश्युक्त पड़ी हुई है ; और

(ल) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस गलत आयोजना के लिए जिम्मदार अवित्तियों के विहङ्ग क्या कार्यवाही की जा रही है ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) A total of about 30,000 tonnes of equipment has been received at site at Bokaro and is awaiting erection. In the case of Bhilai the total tonnage of such material is about 16,000 tonnes.

(b) While undertaking execution of large projects, procurement of equipment and material has to be arranged keeping in view several factors, like the load time required for procurement time needed for further processing, the construction and commissioning schedule etc. In such procurement, especially in the case of big projects like Bokaro and Bhilai, it sometimes becomes necessary to obtain and keep in storage some of the materials so as to ensure that it is readily available and there is no hold up in the construction work.

श्री भानु कुमार शास्त्री : माननीय प्रधायक महोदय, प्रश्न पूछने से पहले, माननीय मंत्री महोदय से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा और यह जानना चाहूँगा कि आपका मंत्रालय मंसद से और इस हाऊस से तथ्यों को छिपाने की बात क्यों कर रहा है ? जो बात पूछी नहीं जा रही है, उसका उत्तर आप दे रहे हैं, जो बात पूछा जा रहा है उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं ।

SHRI BIJU PATNAIK : He has accused that I have not answered the question. I have specifically answered the question. Part (a) of the question is :

"whether machinery and other material worth crores of rupees intended for the expansion work of Bhilai and Bokaro Steel Plants are lying unused in the yard."

I have said 30,000 tonnes are lying at Bokaro and 16,000 tonnes at Bhilai.

Part (b) of the question is :

"if so, the reasons therefor and action being taken against the persons responsible for wrong planning."

I have given the reason.

I am sorry that the hon. Member should say that I have not answered the question.

श्री भानु कुमार शास्त्री : मैंने पूछा है कि कितनी मशीनरी अवश्युक्त पड़ी हुई है और

कितने मूँथ की पड़ी हुई है और आपने उत्तर दिया है कि इनकी स्थापना करना चाकी है। मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी अन्यूटिलाइज़ड है और आप उत्तर दे रहे हैं कि स्थापना होना चाकी है। मैं पूछ रहा हूँ कि कोमत कितनी है और आप जवाब दे रहे हैं कि तोस हजार टन है। अब टन क्या रूपये होते हैं? मुझे ब्रेद के साथ कहना पड़ता है कि मंवियों का स्वभाव हो गया है—आयद मंवी महोदय न जानते हों—मंवालयों के सम्बन्धित सेक्टिरियट से बराबर मूल्य जाती है प्रश्नों के उत्तर में तो भी आपके मंवालय गलत उत्तर बना करके संसद के अन्दर पेश कर देते हैं। मैं फोटो स्टेटकापीज रुदन के अन्दर पेश कर सकता हूँ जो मंवालयों को प्रश्नों पर आफिस ने दी है और आफिस उसको बदल कर हमारे सामने रख देता है। यह बड़े खद की बात है। मेहरबानी करके इस प्रसंग में आप बैसा न करें।

एक पत्र मंवी महोदय को माननीय सदस्य श्री मोहन भैया ने दस अगस्त, 1977 को लिखा था और उसका एकलसिल्वरमेंट भी कर दिया गया था। उस में सारा विवरण दिया गया था। मैं उदाहरण के रूप में एक दो बातें बताना चाहता हूँ। एक ट्रिगर 120 नाम्पर ट्रैक्टर जिस की लागत तीन लाख रुपया है वह डाई वर्ड से बेकार पढ़ा हुआ है। वह केवल 160 घंटे चला है। चालीस टन लाभता वाले इंटरलेशनल ट्रैक्टर वहाँ बेकार पढ़े हुए हैं और भजदूरों से छोटे मोट काम आधा दिन उन पर करवा बरके फिर उनको बेकार रख दिया जा है। कंस्ट्रक्शन इंजिनियरिंग जोन के केन सैक्षण में नहीं कैन

MR. SPEAKER : You can lay a statement on the Table of the House. You put a question.

ओ भानु कुमार शास्त्री : तीन घार ही हैं ज्यादा नहीं हैं। लम्बी मूँची होती तो मैं टेबल पर रख देता। केन सैक्षण में लाखों रुपये के नए केन बेकार पढ़े हुए हैं और हमारे

कर्मचारी बेकार बैठे हुए हैं, लौटिंग घनलोडिंग करने के लिए वी बी सी कम्पनियों को ठेका दिया जाता है, कॉर्टेक्ट दिया जाता है, किराए पर दिया जाता है और हमारे बर्कर बेकार बैठे हुए हैं। प्राइवेट कम्पनियों को किराए पर देना और हमारी मशीनें और हमारे कर्मचारी बहाँ बेकार बैठे रहे यह बहाँ तक ठीक है?

टनिंग और शेपिंग मशीनरी को जंग लग गया है, बिना काम में लाए जंग लग गया है और काम ठेकेदारों को दिया जाता है।

ट्रकों और जीपों की बात भी आप सुन सें। इतना बड़ा स्कैंडल और कहीं नहीं होगा। उनको नीताम में बेच दिया जाता है और उसके बाद वही जीपें और ट्रकें रियेवर करके और वही ठेकेदार उसी कम्पनी में आ कर उनको भिलाई से ठेके ले करके काम में लाते हैं। करोड़ों रुपए का इस तरह से नुकसान हो रहा है। क्या मंवी महोदय सदन के सामने ये सब चीजें नहीं रख सकते ये?

जो जिम्मेदार प्रधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है क्या उनको आप दंडित नहीं करेंगे? मैं पूछता चाहता हूँ कि यह जो आपने टन बताया है इसके बजाय अभी आप कोमत बतायें और बतायें कि कितने करोड़ रुपये की मशीनरी बेकार पड़ी हुई है और कब से बेकार पड़ी हुई है और कब तक आप इस प्रकार की जो अव्यवस्था भिलाई में है इसको समाप्त कर देंगे।

SHRI BIJU PATNAIK : I gave the tonnage because that will be a more probable answer. The money value will not give the tonnages. I think, the hon. Member will note this fact. The total order for the Bhilai Steel Plant was 1,66,000 tonnes out of which orders totalling 1,32,000 tonnes have been placed so far by the end of October, 1977. Out of which 25,500 tonnes have been supplied leaving a balance of one lakh tonnes more yet to come. He says 'unused'.

there is no such thing as unused; it is a continuous process of construction. Parts have to come, machines have to come; sometimes some supplies come, advance supplies of the original parts, even when the first construction has not been there, and they remain unused. If the hon. Member, while making a Rs. 1000-crore plant, gets frightened with a Rs. 40-crore machinery lying temporarily idle, I can only say to the hon. Member that small minds do not take big projects.

श्री भानु कुमार शास्त्री : मुझे बड़ा खेद होता है कि भाज भी....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, on a point of order. The Minister was not right in saying that 'small minds do not take big projects.' That is a reflection on the Members.....

SHRI BIJU PATNAIK : I did not cast any reflection... (Interruptions).

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Minister has not replied to his question properly. His question was that such and such machines were lying idle...

SHRI BIJU PATNAIK : If that is a reflection, I withdraw it readily. But it is not at all a reflection. It was not meant to be a reflection.

श्री भानु कुमार शास्त्री : मंत्री महोदय ने जिस तरीके से उत्तर दिया है मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय संसद् सदस्य वहां घूम कर आये हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं वहां जा कर देखें टाइगर 120 नामक ट्रैक्टर 160 बटे चल कर बेकार पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं रहा है....

SHRI BIJU PATNAIK : For the information of the hon. Member, I wish to say that not only I am going there, but the entire Consultative Committee of the Ministry is going there. The hon. Member can also come, if he wishes so.

श्री भानु कुमार शास्त्री : मैं तो आपको तथ्य दे रहा हूँ कि आप चल कर देखिए। मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। कई मंशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, नंबल भिलाई में ही नहीं, उदयपुर में भी बन्द पड़ी हुई हैं हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड के अन्दर। मंत्री

जी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें, सबाल हमारे देश और पैसे का है। संजय गांधी जब बस्तर यात्रा पर आने वाले थे, तब हम लोग जेल में थे, तो सड़क का निर्माण ठेकेदारों से करवाया गया। इस भिलाई के अन्दर एक मंशीन है जिसका नाम एसफाल्ट प्लान्ट है और एक रोड फिनिशर है, उनका उपयोग नहीं किया गया। यह दोनों मंशीनें जीव और भारत के यद के भवसर पर....

श्री बनी राम बाणी : मंत्री महोदय अपना दिमाग दुरुस्त कर लें, रीब बदायत नहीं किया जायगा।

श्री भानु कुमार शास्त्री : तीन रोड फिनिशर और एसफाल्ट प्लान्ट्स सारे देश में हैं जिनमें से एक भिलाई में है जो जीव और भारत के यद के भवसर पर लदाक्ष के अन्दर सड़क बनाने के लिए काम में लाया गया था। वह बैसे ही पड़ा हुआ है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन सड़क बनाने के लिए ठेकेदारों को दी जाती है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने के लिए मंत्रीजी कुछ विचार करेंगे?

SHRI BIJU PATNAIK : The hon. Member has virtually answered his own question. If the machinery which was bought during the Chinese war—normally a machinery functions for about eight to nine years; that is the life—is lying idle, if that has become junk—I do not know, I have not checked it—if that has become junk and some contractors want to use it, I find no objection. But I shall certainly look into it.

श्री भानु कुमार शास्त्री : जंग नहीं लगेगा तो क्या होगा? यह तो मैंने अपने कर्वैचन में ही कहा है कि जंग लगा हुआ है, अगर इस्तेशाल नहीं करेंगे तो जंग तो लगेगा ही।

MR. SPEAKER : He says he has no information and will look into the matter.

श्री मुबाराज : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति है, कि जो मजदूर काम में लगे हुए हैं, कोई ऐसा

काम बहीं किया जायेगा जिससे वह मजदूर बेरोज़गार बना दिए जायें, क्या उसके बिल्ड करोड़ों रुपए की कम्प्यूटर मशीन बहां से जाकर रखी रही हैं, जिनके लग जाने से हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे ? क्या मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है ?

SHRI BIJU PATNAIK: There are some sections where certain machines are essential for selecting and combining the schedule of raw materials; these electronic equipments are essential for productivity. Manpower cannot help there.

SHRI JYOTIR MOY BOSU: But that is never used.

SHRI BIJU PATNAIK: It is being used; it is not correct.

SHRI K. LAKKAPPA: These are the two premier steel producing centres. The hon. Member has said that materials worth crores of rupees were lying unused and idle and things were not organised properly so that these equipment etc. could be utilised as they should be. It is a very important question, but the answer by the hon. Minister is not only irrelevant.....

MR. SPEAKER: What is the question ?

SHRI K. LAKKAPPA: The other part of the question was: What was the action being taken against the persons responsible for wrong planning. The hon. Minister answered that it was a continuous process. The hon. Minister has also not given the money value of that material lying idle. The material is lying idle and that means, there was faulty planning. Is it because of the faulty planning that raw material and equipment worth crores of rupees has been lying idle ? As the hon. Members here are very much agitated, will he have an impartial enquiry into these matters ? The hon. Minister is a very dynamic person and I am sure, he will set right all these things and see that this premier steel producing centre works properly.

SHRI BIJU PATNAIK: I was trying to hide the omissions of the previous Government though the Members seem to be very much agitated about this. Now, I would like to tell the House that the Bhilai Expansion was supposed to be completed in 1976. You had imported the machinery on that planning. You did not provide the funds for development. Now it will be finished in 1981. Therefore, to tell me that I planned it badly is really begging the question.....

SHRI K. LAKKAPPA: I am asking this Minister.....(Interruptions).

SHRI BIJU PATNAIK: This Minister is going to correct the situation and try to resurrect as much of the debris as possible.

श्री लक्ष्मण मंत्री : मध्यस्थ महोदय, मैंने इस्पात और खान मंत्री को जुलाई, 1977 में एक पत्र लिखा था। उसका उत्तर उनके सेकेटरी द्वारा 10 अगस्त, 1977 को दिया गया, जिसमें कहा गया था कि मंत्री महोदय दौरे पर है और उनके दिल्ली घाने पर आफेरे पत्र से उन्हें घबरात कराया जायेगा। मैंने समझता हूँ कि मंत्री महोदय का इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने जो पत्र उन्हें लिखा था, वह उन के सामने नहीं लाया गया होता। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री भानु कुमार शास्त्री, ने कहा है, वहां बहुत सी मशीनें बिल्कुल नई अवस्था में पड़ी हैं। मैंने स्वयं सारे लेट का दौरा करके देखा है। मैंने अपने पत्र में 1 से ले कर 14 तक सब बिवरण दिया है। मैं इस पत्र** को सदन के टेबल पर रख दूँगा। मैंने कई बार वह जानने की कोशिश की है कि वह सामान क्यों बेकार पड़ा है। मैंने एक पत्र और श्री भेजा है, जिसमें मैंने बताया है कि बिलाई के कंस्ट्रक्शन विभाग में 7,000 मजदूर काम करते थे। वे स्टूचररल लेकेशन का काम 700 रुपए प्रति-टन के हिसाब से करते थे। अब वह काम एच० एस० सी० एल० के माध्यम से लेकेदारों को दे दिया गया है, जो 1700 रुपए से 2200 रुपए प्रति-टन लेते हैं। कांग्रेस लासन के कार्यकाल में यह सीढ़ा हुआ था। चुनाव के दौरान लेकेदारों से हजारों रुपए का चंदा लिया गया था। लेकेदार 1500 रुपए प्रति-टन ले कर 700 रुपए में दूसरे सीढ़ों से यह काम करवाते हैं। इसमें करोड़ों रुपयों की अति हुई है। मैं यह जानवा चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय विविदत्

**The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

इस भाग्य की जांच करवायेंगे, और जो सोग इसमें दोषी हैं, उन्हें ही वे पूर्ववर्ती सरकार के लोग हों, उनके खिलाफ कड़ी कायंवाही करेंगे ?

SHRI BIJU PATNAIK: The hon. Member who is raising these questions had lengthy discussions with me several times. The sins of the previous government are now visiting on us and I shall assure the hon. Member that I shall take as much corrective action as possible and all the allegations that have been made against the construction company, the Hindustan Steel Construction Company or the other officials and contractors.....

AN HON. MEMBER: By when ?

SHRI BIJU PATNAIK: That has to be assessed first and then the contracts once given cannot be rescinded. Otherwise, the work will be delayed further and there will be further escalation of costs. Therefore, we will take the necessary steps. The hon. Member himself is a member of the Consultative Committee. The Committee is meeting in Bhilai by the end of January and we shall look into all these problems there.

श्री राजबद्दी : माननीय मंत्री श्री पटनायक वरिष्ठ एवं अनुभवी मंत्री हैं। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे माननीय प्रश्नकर्ता को स्पाल माइन्ड कह कर उनका अपमान करेंगे।

करोड़ों रुपये की महीनों के आइडल पहुँचे रुपये के सम्बन्ध में एक संसद् सदस्य ने माननीय मंत्री को जुलाई, 1977 में पत्र लिखा था फिर भी माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि मेरी जानकारी में अगर यह मामला लाया जायेगा तो जांच करवायेंगे। अब जुलाई 1977 में मंत्री जी को ऐडेस करते हुए पत्र लिखा गया तो क्या वह उनके पास तक पहुँचा नहीं या अगर पहुँचा है तो क्या वह थीज उनकी जानकारी में नहीं है ? अगर उनकी जानकारी में थी तो उन्होंने उसकी जांच कर्यों नहीं करवायी ?

SHRI BIJU PATNAIK: I do not collect the complaint. If he reminds me, I will certainly look into it.

5000 से अधिक/कम जनसंख्या वाले गांवों में टेलीफोनों को व्यवस्था किया जाना

* 511. श्री राजबद्दी लाल मुमन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने घोषणा की है कि उन गांवों में, जिनकी जनसंख्या 5000 तक है और जहां पर डाकघर हैं, टेलीफोन सुविधाएं देने की व्यवस्था की जायेगी;

(ख) क्या जिन गांवों की जनसंख्या 5000 नहीं है, उनको भी टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसूर प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख). सरकार ने नीति-संबंधी यह निर्णय लिया है कि सामान्य लोगों के उन सभी स्थानों में, जहां की आबादी 5000 या इससे अधिक हो, टेलीफोन की सुविधा (सार्वजनिक टेलीफोन घर), दे दी जाय। यह भी फैसला किया गया है कि पहाड़ी और पिछड़े ज़ोड़ों के उन सभी गांवों में, जहां की आबादी 2500 या इससे अधिक हो, टेलीफोन की सुविधाएं दे दी जायेंगी।

छोटे गांवों में, ये सुविधाएं नीचे लिखे श्रेणीमत स्थानों में दी जायेंगी वहाँते कि सामान्य लोगों के प्रस्तावित स्थानों में अनुमति राबस्त उनके वार्षिक आवर्ती व्यय के 25 प्रतिशत से अधिक, पिछड़े ज़ोड़ों में 15 प्रतिशत से अधिक और पहाड़ी ज़ोड़ों में 10 प्रतिशत से अधिक हो :—

(i) वे स्थान, जहां दारोगा या उससे ऊंचे ग्राहों के अधिकारी के घरीन वाना हो।

(ii) दूरबर्ती स्थान (जिनसे 40 किलोमीटर के बीचे में कोई टेलीफोन एक्सचेंज न हो)

(iii) पर्यावरण केन्द्र/तीर्थ स्थान और
 (iv) कृषि/सिंचाई/विजली परियोजना स्थल/
 टाउन शिवि ।

(ग) ऊपर बताये गये स्थानों पर विभिन्न चरणों के एक कार्यक्रम के अनुसार आगामी पांच वर्षों में टेलीफोन की सुविधाएँ दी जायेंगी ।

श्री रामबीज लाल सुभन : मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने नीति-संबंधी यह नियंत्रण लिया है कि सामान्य लोकों के उन सभी स्थानों में जहां की आबादी 5000 या इससे अधिक हो, टेलीफोन की सुविधा दी जाएगी । मैं मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जिन घारों की आबादी पांच हजार नहीं है, पांच हजार से कम है लेकिन वहां डाकघर या उप-डाकघर है, क्या आपनी नीति के अनुसार आप उनको टेलीफोन से बंचित रखेंगे ? इसरी जानकारी यह देना चाहता हूँ कि देहाती ग्राम्यता में हम पुलिस को रोज आलोचना करते हैं, लेकिन मूँझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पुलिस के पास उतने साधन नहीं हैं जिनसे वह काइम को कंट्रोल कर सके, देहाती ग्राम्यता में जो घार है वहां टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या आप उन घारों में टेलीफोन की व्यवस्था करेंगे ? तोसरी बात यह है कि आप ने करमाया कि जहां बहार 40 किलोमीटर है, वहां आप टेलीफोन लगाने जा रहे हैं, मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि कई स्थानों में 100 किलोमीटर तक के घेरे में कोई भी टेलीफोन नहीं है तो क्या ऐसे स्थानों पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं ? ये तीन मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूँ ।

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साध : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी जो नीति है उसके अनुसार स्टेट कैपिटल से हम लोग जिसे को टेलीफोन

देने वाले हैं, जिसे से सब-डिवीजन को, सब-डिवीजन से तहसील को और तहसील से ब्लाक को देने वाले हैं । इसमें पापुलेशन का कोई सवाल नहीं है । पापुलेशन का सवाल वही आयेगा जहां पानों में स्टेशन आफिसर नहीं है वहां और जहां 40 किलोमीटर के रेडियस में कोई टेलीफोन एक्सचेंज न हो, इसके अलावा जहां इर्टेंगेशन, टूरिज्म, एपी-कल्चर या पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वहां हम पापुलेशन को बेसिस पर ही टेलीफोन का कनेक्शन दे रहे हैं ।

श्री रामबीज लाल सुभन : प्रध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बतलाया है कि अमुक-अमुक स्थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था कर दी जायेगी । मैं जानना चाहता हूँ कि देहाती ग्राम्यता में जो टेलीफोन से बिलकुल ग्रस्त हैं, उनके लिये आप क्या कानूनिकारी कदम उठाने जा रहे हैं ? आप ने यह फैसला किया है कि पांच वर्षों में हम इन-इन स्थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था कर देंगे; पांच वर्ष में न जाने क्या हो, यह पवित्र काम तो जितनी जल्दी हो सके, आप को करना चाहिये ।

आप ने बतलाया है कि दूरदर्ती स्थानों, पर्यावरण केन्द्र, तीर्थ-स्थल, कृषि-सिंचाई-विजली परियोजनाओं, आदि स्थानों पर पांच वर्षों में टेलीफोन की सुविधा दी जायेगी । हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत सरकार में माननीय विदेश मंत्री है, उनके गांव बटेश्वर में, जो हिन्दुस्तान का प्रमुख तीर्थ-स्थल है, वहां भी टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है । यह जो आप ने कहा है कि पांच साल में करेंगे, मैं चाहूंगा कि 6 महीने के अन्दर ऐसे स्थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था की जाये । माननीय मंत्री जो पांच वर्ष की अवधि को बटा कर उससे कम समय में समस्त स्थानों पर अविलम्ब टेलीफोन की व्यवस्था करायें ?

यह सब नों मैंने देहाती आंचल के बारे में कहा—गरन्तु सारे हिन्दुस्तान में टेलीफोन की व्यवस्था बहुत खराब है । संसद सदस्यों के

टेलीफोन पूरा दिन खाल रहते हैं। क्या हिन्दुस्तान की टेलीफोन व्यवस्था को मुशारने के लिये आप कोई क्रान्तिकारी पर उठायेंगे?

संचार मंत्री (श्री बृज साल वर्मा) : प्रधान मंत्रीय महोदय, उत्तराखण्ड के तीस वर्षों के बाद भी अभी तक जिला हैडवाटर्स में टेलीफोन नहीं है...

एक माननीय सदस्य : ऐसे कितने जिले हैं?

श्री बृजसाल वर्मा : पांच जिले ऐसे हैं जहां टेलीफोन नहीं हैं। सब-डिवीजनल हैडवाटर्स 91 हैं, जहां पर टेलीफोन नहीं है। अनेकों तहसील हैडवाटर्स हैं, सब-तहसील हैं, जहां पर टेलीफोन नहीं हैं। इस लिये हम ने कुछ नाम्बर बनाये हैं और उनके मुताबिक हम ने कहा है कि दो वर्षों के अन्दर जितने इम्पोर्टेन्स स्थान हैं, याने से लेकर जितने तक, उन स्थानों पर हम टेलीफोन संग देंगे और इसी विधि के प्रनुसार हम चल रहे हैं ताकि लोगों वा जल्दी से जल्दी वह सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री रामकी लाल सुभन : प्रधान मंत्रीय माननीय वर्मा जी और उनके राज्य मंत्री—दोनों वे: उत्तरों में तारतम्य नहीं है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि 5 वर्षों में लगायेंगे और माननीय वर्मा जी कह रहे हैं कि दो वर्षों में लगायेंगे—इनके जवाब में कोई तारतम्य होना चाहिये।

MR. SPEAKER: He has already answered the question.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the hon. Minister let us know, let the House know—we have written to the Minister quite often—whether in 1978, there would be a White Paper as to which areas are going to have the telephones?

SHRI BRIJ LAL VERMA: Within two years, we are going to have 4,000 long distance telephones and all the headquarters, administrative headquarters will have the telephones.

श्री मुहम्मद शाफ़ी कुरेशी : बैंकवर्ड एरियाल और पहाड़ी इलाकों के लिये जो

नियम बनाये गये हैं, उनकी बुनियाद पर लद्दाख में कभी टेलीफोन नहीं आ सकेगा, क्योंकि आप ने आवादी का तसव्वुर भी अपने दिमाग में रखा है। जहां पर एरिया बहुत बड़ा है और आवादी कम है—क्या उसके लिये आप कुछ अलग से नियम बनायेंगे ताकि उनको भी टेलीफोन फैसिलिटी मिल सके?

श्री مسूद शफ़ी قریشی : بُسْكُوूर

अहरियां और बहावी उच्चों के लिए जो नूम बिलाई कहे हैं उन की बहुत अलग मूल्य में कहीं तक्लिफ़ों नहीं अँके ५—कहुन्के अप ने अबादी का चिरू भी अपे दमाग मूल्य दिया दिया है—जिस पर अहरिया बहुत बुरा है और अबादी कम है—कहा अस के लिए अप कहे अक्स से नूम बिलाई की—ताकि उन को भी तक्लिफ़ों फूस्हेलिटी मूल सके—

श्री बृजसाल वर्मा : जी हां, उसका जवाब मैंने दिया है, नियम बनाये गये हैं कि जहां पर आवादी कम है, वहां भी टेलीफोन लग सकें। लेकिन इस बत्त हम इस आर्डर से निकल रहे हैं—जिला, तहसील, ज़िला—उसके बाद जैसा आप कह रहे हैं, उसके लिये भी किया जायेगा।

श्री मुहम्मद शाफ़ी कुरेशी: यह स्ट्रेटेजिक एरिया है, आवादी कम है—इनके लिये उसके बहुत कुछ-न-कुछ होना चाहिए।

श्री مسूद शफ़ी قریشی : ४

स्ट्रिटेजिक एरिया की अबादी कम है—उन के लिए बुरो कहे जाना चाहिए होना चाहिए—

श्री बृजसाल वर्मा : वहां पर भी हम कर रहे हैं।

श्री किरणी प्रसाद : माननीय मंत्री जी ने जो पोषणायें की हैं, मुझे उनके ही विभाग से स्पष्ट पता चला है कि आप जहां-जहां

टेलीफोन के स्थाने लगाना चाहते हैं, भ्रातों को छिपोड़नों में मैटीरियल नहीं है। मूँस यह भी बताया गया है कि आपका विभाग जंगल-विभाग से कुछ काटेकर करके बत्तियां आदि देने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बोयणा बोयणा-माल ही रह जायेगी या उपयुक्त मैटीरियल की व्यवस्था भी आप कर रहे हैं?

श्री बृद्धताल बर्मा : मैटीरियल हमारे पास है और काटेकर से नहीं बत्ति डिपार्टमेंट लेविल पर सारी चीज़ हो रही है।

MR. SPEAKER: The Question Hour is over. We take up Short Notice Question.....*(Interruptions)*.

श्री रामधारी शास्त्री (पटरीना) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात आप सुन न जूँ। मेरा कहना यह है कि गत्रों के दामों के बारे में जो आप ने 377 के अन्तर्गत इजाजत दी है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। 193 में इसकी वहस करवाइए।... (व्यवस्थान)...

द्वां० सरकी नारायण पांडेय (मंदसौर) : चार दिन से हम इसके लिए कह रहे हैं लेफिल कोई आगान नहीं दिया गया है, इसलिए ग़ढ़ा होना पड़ा है। इस पर दो बंटे की वहस करवाइए।

श्री उपरेता (देवरिया) : दो बंटे की वहस करवाइए।

... (व्यवस्थान)...

MR. SPEAKER: We must follow the procedure; otherwise Parliament will not work effectively. Your voices are not heard; they are not recorded. What is the good if everybody gets up and speaks. This question had been discussed in the House and I have allowed 377 statements.....*(Interruptions)*. Do not record.

द्वां० सरकी नारायण पांडे :**

श्री सुरेश विक्रम :**

MR. SPEAKER: We take up Short Notice Question No. 7.

SHORT NOTICE QUESTION

Supply of MIG spares and automatic weapons by India to Uganda

S.N.Q. 7 SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have seen a recent report in a foreign journal 'Sunday News' that India is supplying MIG spares and a wide range of automatic weapons and ammunitions to Uganda;

(b) if so, what are the terms and conditions and value of such supplies to Uganda;

(c) whether Government are aware that such supplies have caused concern among some foreign friendly Governments; and

(d) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) Attention of Government has been drawn to news items appearing in certain foreign newspapers regarding certain reported deals of arms supply by India to Uganda. The Government of India have neither sold nor have any proposal on hand to sell military hardware to Uganda either directly or indirectly.

(b) Does not arise.

(c) and (d). In the above mentioned cases Government have denied the reports at the Centres where the news items appeared.

SHRI VAYALAR RAVI: I am glad the Minister has categorically denied such reports which appeared in the foreign press. There are deliberate attempts made to malign our country abroad. Also, attempts are made by certain interested foreign powers to create a misunderstanding between friendly countries especially countries friendly to India. This Ugandan problem is one of the very touchy problems, especially also so far as the people of U.K. are concerned. If I may quote the news report which appeared in the *Sunday Times* ...

SHRI JAGJIVAN RAM: Why give publicity to it?

SHRI VAYALAR RAVI: I agree. This report is very mischievous and meant to malign our country. I want a categorical assurance from the minister that all the

**Not recorded.

items that we are taking from the different countries for our own defence purposes, including MIG spares etc. will not be given to any other country and also that even the arms produced in our own country will not be given to countries like Uganda.

SHRI JAGJIVAN RAM: If the hon. member had cared to listen to my reply, there would have been no need for putting this supplementary. I have already said that there is no proposal to sell anything to Uganda directly or indirectly. What else do you require? I have further said that the Government have denied the reports at the Centres where the news items appeared. There has been an unequivocal denial that anything has been supplied to Uganda either directly or indirectly. Even in future, there is no intention at all to supply anything to Uganda.

MR. SPEAKER: This should satisfy him.

SHRI VAYALAR RAVI: India has entered into agreements with certain other countries regarding selling our own small arms and ammunition. In this connection, do the Government have any policy regarding selling our own small arms and firearms produced in this country and if so, what are the criteria fixed for the sale to different countries?

MR. SPEAKER: It does not arise out of this.

SHRI K. GOPAL: This is a deliberate attempt made by some countries to malign India abroad and I am happy the hon. Minister has given a categorical assurance that we are not supplying arms to Uganda. When we obtain technical know-how from the Soviet Union for the manufacture of MIG spares, etc., I want to know whether we have the right to sell them to other countries.

MR. SPEAKER: It depends on the agreement.

SHRI K. GOPAL: Leave alone MIG; when we obtain technical anyhow from any country for manufacturing something, I want to know whether we have the right to sell it.

MR. SPEAKER: It does not arise out of this.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am very happy that the Minister has very categorically said that there is no intention of supplying arms to Uganda. This must have been based on some policy consideration. In view of the fact that according to the International Institute of Strategic Studies, India is emerging as a major exporter of small arms, could the Minister

inform the House as to what is Government's policy according to which Uganda has been denied arms?

MR. SPEAKER: Is there any policy on which Government's refusal is based?

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, that was my question; and you ruled it out. (*Interruptions*).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Uganda has been denied; and the Minister has said it. So, there must have been a policy decision. I have a right to ask about that policy.

MR. SPEAKER: The policy is not to supply to Uganda.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: But why? Why are we afraid? I know that in Uganda, Idi Amin is ruling. (*Interruptions*). Why can't I know? The Minister has said that he has no intention to supply to Uganda. Let the Minister answer the question.

SHRI VAYALAR RAVI: It was a question of policy regarding the sale of arms produced by India. That policy can include Uganda also. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Is there any policy in it? Is it based on any policy, or on any *ad hoc* decision?

SHRI JAGJIVAN RAM: The overriding policy in these matters is the national interest and national prestige.

श्री उपसेन : मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के भाने से पहले वाली सरकार ने भाकीका, युगांडा आदि देशों में जब आजादी का आनंदोत्तम दबाया जा रहा था तो वहाँ की सरकारों को हृषियार या मिश विभानों के पुर्जे भादि देने के बारे में कोई बातचीत की थी, कोई चिट्ठी पत्र लिखा था, क्या इसकी सूचना मंत्री जी को है?

श्री जगजीवन राम : सदस्य महोदय की जानकारी में कोई तथ्य नहीं है।

श्री कंबर साल मुरत : क्या युगांडा ने डायरेक्टी या इंडायरेक्टी कभी भारत सरकार से पुर्जे भादि बरीदने की प्रायना की थी? आपने उत्तर तो दे दिया है कि कोई थी या नहीं की थी। मैंने पूछा है कि कभी भी की थी?

श्री जगमीदर राम : अगर मानवीय सदस्य को बड़ा उत्तराधि है इसने जाने की तो उन्हीं उत्तराधि को मैं समाज कर दूँ यह कह कर कि इनमें कोई तब्दील नहीं है।

1. SHRI SAUGATA ROY: The Minister has already stated that he has no intention to supply arms to Uganda. As you know, Uganda is ruled by a very fascist dictatorship which has been very cruel to Indians and other Asian people. Will the Government be ready to give arms in case a liberation struggle is launched against that regime?

M.L. SPEAKER: It will be considered when the question arises.

SHRI JAGJIVAN RAM: It is hypothetical, Sir. It is never done.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Declaration of P.F. Organisation as Industry

*512. **SHRI K. RAMAMURTHY:** Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Karnataka High Court, in 1973, had given judgement that the P.F. Organisation is an industry and the appeal preferred against this judgement by Government before the Supreme Court was not allowed; and

(b) if so, whether Government propose to declare the P.F. Organisation as an Industry with retrospective effect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): (a) While deciding the Civil Revision petition No. 596/1973 (Shri M. Mariswamy Vs. The Registrar of Trade Unions in Mysore), the High Court of Karnataka at Bangalore held that "As the activity of the Provident Fund Organisation is 'industry' the members of the Unions, who are its employees have to be regarded as 'workmen'." The Supreme Court of India dismissed a Special leave petition filed in the matter.

(b) As there is no provision in the Industrial Disputes Act, empowering the Government to declare any establishment or Organisation as an industry, the question does not arise.

Issue of Stamp in Honour of Dr. Mohd. Iqbal

*513. **SHRI SAUGATA ROY:** Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to issue commemorative stamp in honour of the great Urdu Poet, Allama Dr. Mohd. Iqbal;

(b) if so, the present position in that regard; and

(c) whether the stamp can be released within the Birth Centenary Celebration year, which is currently being celebrated in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal will again be placed before the next meeting of the Philatelic Advisory Committee for its consideration.

(c) This could be known only after the meeting of the Committee.

Reservation of seats for Tribals as Labourers in Factories

*514. **SHRI RAJE VISHVESHVAR RAO :** Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering to reserve seats for the Tribals in the factories as labourers; and

(b) if so, the percentage of seats to be reserved?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). According to the information furnished by the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), the question of giving representation to the members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities in employment with private sector industrial undertakings was examined in that Ministry some time ago arising out of the observations made by the Parliamentary Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As a result of the decision taken in the matter, appeal to the private sector enterprises was issued through the auspices of Directors of Industries, technical authorities and Chambers of Commerce and Industry to ensure that the employment of the members of such communities in the private sector undertakings is stepped up.

The Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance has also issued directives to public sector undertakings under the control of Government through the administrative Ministers concerned for making reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities in their services on the lines of the reservations in Central Government services.

Appointment of I.A.S. Officer as head of E.P.F. as in E.S.I.C.

***516. SHRI UGRASEN : SHRI DINEN BHATTACHARYA :**

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Employees' Provident Fund Organisation and the Employees' State Insurance Corporation are two sister organisations working as social security departments for the welfare of industrial workers;

(b) whether the Head of the Department of the Employees State Insurance Corporation is of the status of the Secretary to the Government of India, whereas the Head of the Department of Employees' Provident Fund is a very junior officer hardly having the status of the Deputy Secretary to the Government of India; and

(c) if so, why an I.A.S. Officer as demanded by the All India Employees' Provident Fund Staff Federation has not so far been appointed as the head of the Organisation to set its affairs in a right direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): (a) The Employees' State insurance Corporation is established for the administration of the Scheme of Employees' State Insurance, and the Employees' Provident Fund Organisation administers the Employees' Provident Fund Scheme, Employees Family Pension and the Deposit Linked Insurance Schemes.

(b) The Director General, Employees' State Insurance Corporation is not an officer of the status of the Secretary to the Government of India, he has been allowed the pay of Rs. 3500/- as personal to him. The grade of pay of the Central Provident Fund Commissioner is Rs. 2000 to 2250.

(c) According to the Employees Provident Fund (Commissioners) Recruitment Rules, the post of the Central Provident Fund Commissioner is to be filled by promotion failing which by transfer on deputation from I.A.S. or Central Secretariat

Service or Central Services Class I. The post was filled by promotion.

Exemption to sick Industrial Units from Payment of Bonus

***517 SHRI CHITTA BASU : SHRI AHMED M PATEL :**

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the number of the industrial actions resorted to by the industrial workers all over the country on the issue of payment of bonus in the recent months;

(b) whether the guidelines concerning the exemption to the marginal and sick industrial units from the effect of the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1977, were duly issued to the State Governments; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Representations were made against the amendments affected in the Payment of Bonus Act, 1965, through an Ordinance promulgated in September, 1975, which was later replaced by an Act of Parliament. There was unrest on the question of bonus but complete information regarding the number of industrial actions resorted to by the workers on this issue is not yet available.

(b) and (c). No, Sir. It was decided not to issue any guidelines in the subject and to leave the question of granting exemption to the discretion of the 'appropriate Governments' under the frame-work of law.

Survey conducted by Geological and Mining Departments in Orissa and Bihar

***518. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:**

(a) whether any survey has been conducted by the experts belonging to Geological and Mining Departments in the State of Orissa and Bihar; and

(b) if so, the precious minerals found as a result of this survey?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Yes, Sir.

(b) Some minor occurrences of gold have been located in Keonjhar, Cuttack and Koraput districts of Orissa and Singhbhum district of Bihar.

Enforcement of the equal Remuneration Act 1976 in Engineering and Instrumentation Industries

*519. SHRI D.B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the names of the industries which have enforced the principle of 'equal pay for equal work';

(b) Whether engineering and instrumentation industries have been covered under the scheme; and

(c) if not, when this principle would be enforced in these industries?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). The Equal Remuneration Act, 1976 which provides for the Payment of equal remuneration to men and women workers for the same work or work of a similar nature has so far been brought into force in respect of 21 employments in :-

1. Plantations (covered under the Plantations Labour Act, 1951).
2. Local authorities.
3. Central and State Governments.
4. Hospitals, nursing homes and dispensaries.
5. Banks, Insurance Companies and other financial institutions.
6. Educational, teaching, training and research institutions.
7. Mines.
8. Employees Provident Fund Organisation, Coal Mines Provident Fund Organisation and Employees State Insurance Corporation.
9. The Food Corporation of India, the Central Warehousing Corporation and State Warehousing Corporations.
10. Manufacturing of Textiles and Textile Products.
11. Factories located in Plantations.
12. Manufacturing of Electrical and electronic machinery, apparatus and appliance.
13. Manufacture of chemical and chemical Products (except Products of Petroleum and coal).

14. Land and water transport.
15. Manufacture of Food products.
16. Other Manufacturing Industries.
17. Electricity, Gas and Water.
18. Wholesale and Retail Trade.
19. Construction including activities allied to construction.
20. Transport, storages and communications.
21. Agriculture and activities allied to agriculture.

It will be seen that engineering and instrumentation services are already covered.

It is proposed to cover all other areas of economic activities, where women are employed, in a phased manner.

Health Insurance Of Rural Workers

*520. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for the Health Insurance of rural workers on the lines of Employees State Insurance Scheme of Industrial workers; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA): (a) and (b). Government is anxious to see that the benefits of social security and health insurance reach the rural workers as well and is examining the possibility of extending the Employees' State Insurance Scheme to rural workers, although no specific proposal has taken shape.

विदेशी हिन्दी लेखक

*521. श्री दया राम जात्याः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृत्या करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विदेशी हिन्दी लेखकों को सम्मानित करने के लिए समिति गठित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने विदेशी लेखकों को सम्मानित किया जा चुका है और वे किन देशों के हैं?

विदेश वंशी (यो अट्टल विहारी वालवेदी) : (क) और (ब). जी हाँ। विदेशी हिन्दी लेखकों को सम्मानित करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप-समिति ने 22 दिसंबर, 1975 को एक पुरस्कार समिति का नठन किया था। पुरस्कार देने के लिए अभी किसी व्यक्ति को नहीं चुना गया है, बल्कि हाल ही में केन्द्रीय हिन्दी समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा पुरस्कार समिति का पुनर्गठन करने के संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इसकी सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा सके।

Loss to Communication System due to Cyclone in Tamilnadu, Kerala and Andhra Pradesh

*522. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether due to the recent cyclone in the Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh, the loss to communication system was very high;

(b) if so, the total damage caused to the communication system in these States; and

(c) the steps being taken to repair the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes Sir, the loss to communication system in Tamil Nadu and Andhra Pradesh was very high. Preliminary estimates of the loss are of the order of Rs. 15 lakhs in Tamil Nadu and Rs. 60 lakhs in Andhra Pradesh. The loss in Kerala was not substantial.

(b) Total damage caused to these communication system in these States is reported to be as follows:—

Tamil Nadu: Trunk communication to Nagapattinam town was completely disrupted. Srirangam 300 lines auto exchange was completely flooded. Approximately 7500 telephone lines in Thanjavur, Trichy and Cuddalore and Salem divisions were affected by flood and cyclone.

Andhra Pradesh: Approximately 8,000 Kms of open wire lines and 48,000 Kms. of wire were damaged, disrupting the open wire communication system. 22238 local

telephones and 167 exchanges including 34 trunk centre (and larger exchanges) and 133 small automatic exchanges (SAXs) in the rural areas went out of order. Rural communication circuits which are mainly on open wire lines were the worst affected, causing telecommunication to many rural areas to be cut off.

Kerala: In Kerala the only damage was to the wireless station antenna on Kalpeni Island, Lakshadweep.

(c) **Tamil Nadu:** Out of about 7509 lines which went out of order on 12-11-77, about 6400 lines were restored by 23-11-77 and balance by 30-11-77. Srirangam exchange was restored on 17-11-77. Trunk communication to Nagapattinam was restored on 19-11-77. This restoration was on temporary basis. Permanent restoration is in progress.

Andhra Pradesh: Out of 22238 telephones which went out of order 21780 have been restored. 164 exchanges including 34 trunk centres have been restored leaving only three rural exchanges to be recommissioned yet. The trunk lines of these three SAXs have been temporarily terminated as Long Distance Public Call Offices (PCOs). The restoration so far is on a temporary basis. Permanent restoration of trunk lines is in progress.

Kerala: Damage to wireless station at Kalpeni has already been repaired temporarily.

Amount of P. F. Family Pension and Damages outstanding Against M/s. Swadeshi Cotton Mill, Kanpur

*523. SHRI KALYAN JAIN: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the amount of provident fund, family pension and damages which are pending against M/s. Swadeshi Cotton Mill, Kanpur;

(b) whether in spite of such a huge arrears and chronic defaults, all legal action proposed to be taken and pending in the court were withdrawn without obtaining any bank guarantee on certain political recommendations; and

(c) if so, what action Government propose to take against the Central Provident Fund Commissioner who is actively involved in many similar cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (Dr. RAM KIRPAL SINHA): (a) and (b). The Employees' Provident Fund Authorities have intimated as follows:—

(a) The amounts of Provident Fund, Family Pension Fund, Insurance Fund contributions and Administrative Charges due from M/s. Swadeshi Cotton Mill Ltd., Kanpur are as under:—

Month	Provident Fund	Family Pension	Employees' Administrative Charges			
			Deposits Linked	Insurance Employees contribu- tions.	Provident Fund	Employees' Deposits Linked Insurance
August, 77	431887.50	7168.50	Nil.	10153.35	Nil	
September 77	419411.00	6766.00	13800.00	9853.65	2800.00	
October 77	419411.00	6766.00	13800.00	9853.65	2800.00	
November 77	419411.00	6766.00	13800.00	9853.65	2800.00	
TOTAL	1690120.00	27466.50	41400.30	39714.30	7400.00	

(The dues for the months of October and November, 1977 have been calculated on provisional basis as the Mill has not submitted the relevant Returns.)

A sum of about Rs. 11.53 lakhs on account of damages is outstanding for late payments made for certain months between May, 1970 and July, 1976.

(b) The Provident Fund contributions have been duly paid by the Mills upto July, 1977. For the non-payment of the Provident Fund and Family Pension dues for the months of August and September, 1977, the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh has written to the Collector to recover Rs. 10,10,284.00 as arrears of land revenue and notice under section 7A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act has been issued to the establishment for determining the Provident Fund dues for the months of October and November, 1977. Whereafter of the amount is not paid by them, the Collector will be asked to recover those dues as arrears of land revenue. Action to launch prosecutions has been initiated. It is not proposed to withdraw any of the pending or proposed legal actions. In the past where prosecutions were filed and withdrawn, the Provident Fund arrears of those cases stand paid in full.

(c) Does not arise.

Elimination of Political Elements from Trade Union Leadership

*524. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether he is aware that the current wave of labour unrest is mainly due to inter-union rivalries;

(b) if so, whether he intends to eliminate political elements from trade union leaderships;

(c) if not, in what other way, does he expect to protect workers from being made victims of politicalised trade union leaders; and

(d) whether he has any plan to legislate in this context to confine trade union leadership only to the worker members?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Inter-union rivalry may be one of the contributory factors towards the labour unrest.

(b) to (d). The questions relating to the outsiders being office bearers of trade

unions and other connected matters are under the examination in the light of the views contained in the Report of the Tripartite Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and the Composition of the Indian Labour Conference.

Camel Post Office;

*525. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to run Camel Post Office in the State of Rajasthan, particularly in the desert areas; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b). No, Sir. One Camel Post Office (Mobile E.D.B.O.) has already been opened on 27-10-77 in village Mithadia of Bikaner District. The Post Office serves two villages i.e. Mithadia and Medayan.

Implementation of Equal Remuneration Act, 1975 in Plantations

*526. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that the Equal Remuneration Act, passed during 1975, the International Women's Year, failed to give justice to women workers in Plantations who constitute 46 per cent in the industry; and

(b) if so, the steps being taken to implement that?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA) : (a) The Equal Remuneration Ordinance, 1975, later replaced by the Equal Remuneration Act, 1976 was extended to plantations on 15-10-1975. The Act is fully applicable to plantations from that date.

(b) All State Governments/Administrations have been requested from time to time to ensure effective implementation of the Act.

Cyclone warning issued by Communication Department

*527. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether his Ministry have enquired into the allegations that the cyclone affected States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh ignored the warning issued by the Communication Department;

(b) if so, the main details of the warning issued;

(c) the extent to which the State Governments were responsible;

(d) whether his Ministry had informed the Central authorities concerned also about the cyclone and the warning issued and about the State Governments ignoring it; and

(e) if not, the reasons therefore ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Warnings against the cyclones were issued by the India Meteorological Department. It is not usual for the Central Government to enquire into the action taken on the warnings by State Governments.

(b) Warnings against the cyclones affecting Andhra Pradesh were issued from 17th November, 1977 until the cyclone came over land on 19th November, 1977. Tamil Nadu was warned against cyclone from 10th November, 1977 until it came over land on 12th November, 1977.

(c) The State Governments are responsible for taking all possible precautions.

(d) Officials of the Departments of the Central Government in the affected areas, such as the Railways, Ports, etc. who are on the warning list of India Meteorological Department were warned against the cyclones.

(e) Does not arise.

Ayurvedic Drugs Factory at Ranikhet, U. P.

*528. DR. MURLI MANOHAR JOHARI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the progress made on the project to establish an Ayurvedic Drugs Factory at Ranikhet in U. P. as had been announced in the Lok Sabha during the Budget Session

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : The Memorandum of Association and Articles of Association have been prepared and are being finalised in consultation with the Department of Company Affairs. It is expected that the aforesaid formality would be completed soon.

Commemorative Stamps issued during the year 1977

*529. PROF. P. G. MAVALANKAR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have finalised the list of special commemorative stamps to be issued in the year 1977;

(b) if so, full details thereof;

(c) whether it is a fact that Government have not included in such a list so far, several outstanding all-India and some

even all-world, famed individuals hailing from Gujarat, in spite of repeated suggestions and proposals in this regard being sent by Members of Parliament and other individuals and institutions from Gujarat and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the programme in respect of stamps issued and proposed to be issued in 1977 is enclosed.

(c) and (d). In accordance with the guide lines prescribed out of the total number of issues in a year (not more than 24/25) not more than 6 should be commemorative of personalities. Hence it has not been possible to issue stamps in honour of all the personalities from Gujarat.

Statement

Programme for the issue of Commemorative Special postage stamps during 1977

Sl. No.	Particulars of stamps	Date of Issue	No. of Stamps	Denomination (in paisa)
1	2	3	4	5
1.	VI International Film Festival	3-1-77	1	200
2.	Sixth World Conference of Earthquake Engineering	10-1-77	1	200
3.	Tarun Ram Phookan (Birth Centenary)	22-1-77	1	25
4.	Paramahansa Yogananda	7-3-77	1	25
5.	1st Asian Red Cross Regional Conference	9-3-77	1	200
6.	Fakhruddin Ali Ahmed	22-3-77	1	25
7.	Asian Oceanic Postal Union	1-4-77	1	200
8.	Narottam Morarjee (Birth Centenary)	8-4-77	1	25
9.	Makhanlal Chaturvedi (Poet)	4-4-77	1	25
10.	Mahaprabhu Vallabhacharya	14-4-77	1	100
11.	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (Golden Jubilee)	23-4-77	1	25
12.	World Environment Day	5-6-77	1	200

1	2	3	4	5
13.	Rajya Sabha (Silver Jubilee)	21-6-77	1	25
14.	Invention of Phonograph (Centenary Year)	20-7-77	1	200
15.	Ananda K. Coomaraswamy (Birth Centenary)	22-8-77	1	25
16.	Ganga Ram	4-9-77	1	25
17.	XXXII International Homoeopathic Congress	6-10-77	1	200
18.	Dr. Ram Manohar Lohia	12-10-77	1	25
19.	XV International Congress on Pediatrics	23-10-77	1	200
20.	Kittur Rani Channamma	23-10-77	1	25
21.	Union Public Service Commission	8-11-77	1	25
22.	Agriexpo—77	19-11-77	1	25
23.	Children's Day	14-11-77	2	25, 100
24.	Senapati Bapat	28-11-77	1	25
25.	Mahatma Jyotiba Phule	28-11-77	1	25
26.	41st Session International Statistical Institute.	13-12-77	1	200
27.	Kamta Prasad Guru	25-12-77	1	25
28.	Great October Socialist Revolution 1917 U.S.S.R.	30-12-77	1	100

SERIES.

1.	Indian Flowers	1-7-77	4	25, 50
2.	INPEX—77	12-10-77	2	100, 200
3.	ASIANA—77	19-10-77	2	100, 30

Former Prime Minister of Burma living in India

4767. SHRI P. V. PERIASAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state whether the former Prime Minister of Burma, Mr. U. Nu is residing in India for the past several years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): Yes, Sir.

Patients in Willingdon Hospital, New Delhi

4768. SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Willingdon Hospital, New Delhi is

running with inadequate staff in proportion to the number of patients treated there;

(b) if so, the daily average of the indoor and outdoor patients treated there in the last three years and till date;

(c) the number of doctors and staff working there; and

(d) when and how many extra doctors and staff are being posted there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE: (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) (a) Keeping in view the given resources the staff posted in the Willingdon Hospital, New Delhi is not considered inadequate.

(b) The daily average attendance of patients in the OPD and admissions in the Indoor is as under:—

	Daily average attendance in OPD	Average admissions per day
1974	2150	64
1975	2430	103
1976	2737	102
1977 (upto Nov.)	2990	119

(c) The Willingdon Hospital has on its strength 204 doctors and 1247 other categories of staff.

(d) To strengthen the Accident and Emergency Department, posts of 11 doctors, 2 Nurses and 2 Stretcher Bearers have recently been sanctioned.

Opening of Post Offices in backward areas of Orissa.

4769. SHRI SRIBATCHA DIGAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) how many Post Offices Government propose to open in the backward districts of Orissa State, District-wise, during the current year;

(b) how many have already been opened so far in such districts;

(c) why the number of Post Offices opened in Phulbani District is so low, though it is the most backward district in the State; and

(d) what special steps Government propose to take to open Post Offices in Phulbani District and how many Post Offices will be opened in this district in the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Total number of Post Offices proposed to be opened 69.

District-wise break

1. Dhenkanal	2
2. Kalahandi	14
3. Keonjhar	

4. Koraput	28
5. Mayurbhanj	13
6. Phulbani	20
7. Sambalpur	2
8. Sundargarh	6

69

(b) 49.

(c) and (d) In most of the proposals for opening of post offices in Phulbani District, anticipated loss was found to be beyond the permissible limit of loss. The target for opening new Post Offices in this district is the second highest among backward districts of Orissa. Efforts are being made to fulfil the target of opening 20 post offices as proposed for the year 1977-78.

राज्यों द्वारा बनियों के नियत पर रायस्टी में बृद्धि की मांग

4770. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या इसलिए और जान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा उन राज्यों से नियत किये जाने वाले बनियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली रायस्टी में बृद्धि किये जाने की मांग की गई है;

(ख) बनियों पर रायस्टी का निर्धारण कब किया गया था; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है प्रथम इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(घ) इसलिए और जान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मूढा): (क) कुछ राज्यों ने अनुरोध किया है कि लोह ध्रयस्क, तांबा ध्रयस्क, मैग्नीज ध्रयस्क और मैग्नेजाइट जैसे कुछ बनियों पर रायस्टी बढ़ा दी जाये।

(ख) कोयला समेत ग्रनेक बनियों पर केवल कुछ बनियों को छोड़कर रायस्टी दरों में पिछसी बार बृद्धि मार्ग, 1975 में की गई थी।

(ग) लौह अयस्क, तांवा अयस्क, मैग्नीज, मैग्नेजाइट और भराइ-रेत पर रायल्टी दरों में वृद्धि के सवाल पर विचार हो रहा है।

Demand for minimum wage to plantation workers

4771. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the wage structure from State to State and estate to estate in plantations is different; and

(b) if so, whether Government are considering the demand of the workers for a common minimum wage all over India?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). The State Governments are the "appropriate Government" under the Minimum Wages Act in respect of plantations; in view of this and in view of the fact that plantations cover Tea, Coffee, Rubber, etc., and as minimum rates of wages are fixed or revised at different times in different states, the minimum rates of wages are bound to be different. There is a well developed system for fixing wages in the Plantation Industry in each area through collective bargaining; it is, therefore, felt that the advisability of standardising wages in the plantation industry is yet to be established.

Utilization of manufacturing capacity of Government Medical Stores Depot—Madras.

4772. SHRI A. MURUGESAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government Medical Stores Depot, Madras has got the requisite facilities to manufacture glucose, saline, etc.;

(b) if so, whether these facilities are being fully utilised; and

(c) the concrete steps proposed to be taken to make full utilisation of capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No.

(b) and (c). Does not arise.

Extension given to the Director of All India Institute of Medical Sciences.

4773. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Director of All India Institute of Medical Sciences was given extension; and

(b) if so, when he was given extension for what period and for what reasons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The appointment of the present Director was renewed for a further period of five years with effect from 27-8-1974. The All India Institute of Medical Sciences had, while considering the case of the present Director for appointment to this post for the first time in 1969 clearly laid-down that this tenure would be renewable for the second term. On completion of the first term, the matter was placed before the Institute, who decided to give second term to the present Director, because the Institute Body deeply appreciated his services and the period of renewal was well within his age of superannuation of sixty years.

Setting up of a Telecommunication equipment factory in Madhya Pradesh

4774. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government have forwarded any proposal to the Central Government for setting up a telecommunication equipment factory in Madhya Pradesh during the Five Year Plan period;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision the Central Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDÉO SÁT): (a) Yes, Sir.

(b) The Madhya Pradesh Government have offered land free of cost and other infrastructural facilities for the factory.

(c) The matter is under consideration and a decision is likely to be taken in the near future.

Allocation of funds for Vijayanagar and Visakhapatnam Steel Plants.

4775. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the allocation of funds made for Vijayanagar and Visakhapatnam Steel Plants during the year 1976-77;

(b) when the work is likely to be commissioned on these steel plants; and

(c) the estimated investment on each of these plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) An allocation of Rs. 1 crore each was made for the two projects during the year 1976-77.

(b) The Detailed Project Report (DPR) on Vijayanagar Steel Plant was received by the Steel Authority of India Limited (SAIL) in April, 1977, while that on Visakhapatnam Steel Plant in October, 1977. Both the DPRs are currently being scrutinised by SAIL. Meanwhile, preliminary work like land acquisition, soil investigation, raw materials testing, etc. have been going on for quite some time. The dates by which the plants are likely to be commissioned will be known only after the DPRs have been scrutinised and approved by the Government and will depend on the availability of financial resources.

(c) As per the DPR, the total fixed investment on Visakhapatnam Steel Plant will be Rs. 1926 crores. The DPR of Vijayanagar Steel Plant has estimated the capital costs for the plant at Rs. 1580 crores.

Ignoring the Family Planning Programme launched by the previous Government.

4776. SHRI MADAVRAO SCINDIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the programme about Family Planning launched by the previous Government is completely being ignored by the present Government; and

(b) if not, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The present Government's policy in regard to

Family Welfare Programme is that the Programme will be pursued vigorously as a wholly voluntary Programme and as an integral part of a comprehensive policy covering education, health, maternity and child care, family welfare, women's rights and nutrition. The Government is strongly committed to achieving a reduction in the birth rate and will spare no efforts to motivate the people to accept the Programme voluntarily in their own interest and in the interest of their children as well as in the larger interest of the nation. Particular attention is being given to the improvement of maternal and child health services and to the availability of high quality services to the people. Educational and motivational efforts have been strengthened in order to make the small family norm popular among the people.

Number of foreign Technicians & working in Rourkela and Durgapur Steel Plants

4777. SHRI SHYAMAPRAS ANNA BHATTACHARYYA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total number of foreign technical experts, engineers, technicians working in Rourkela and Durgapur Steel Plants; and

(b) details country-wise and the salaries, allowances and other perquisites given to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) As on date no foreign experts are working in Rourkela and Durgapur Steel Plants.

(b) Does not arise.

Setting up Hospitals for flying Doctors for emergency illness in remote parts of villages

4778. SHRI ROOP NATH SINGH YADAVA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have a plan to set up hospitals for flying doctors to take care of acute cases of emergency illness in the remote parts of the villages in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The Government have no such plan under consideration.

Opening of post offices in Orissa

4779. SHRI GANANATH PRA-DHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) how many Branch Post Offices, Sub-Post Offices, Post Offices and Public Call Offices and telephone connections will be provided in Orissa in the coming five years ;

(b) whether a Master Plan for this has been drawn up ; and

(c) What are the criteria adopted for construction of such Branch Post Offices, Sub Post Offices, Post Offices and Public Call Offices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRA-SAD SUKHDEO SAI) :

(a) Post Offices :

Roll-On-Plan (1978-83) has not yet been finalised. The tentative proposal of the PMG, Orissa is to open 1532 Extra Departmental Branch Post Offices and 376 Sub Post Offices in the State during the Plan period 1978-1983.

Public Call Offices :

200 long distance Public Call Offices are proposed to be provided in Orissa in the coming five years.

(b) Yes, Sir. The Plan is subject to approval of Planning Commission.

(c) The criteria adopted at present for opening of Post Offices and Public Call Offices in rural areas are detailed in statements 'I' and 'II' laid on the Table of the House [Placed in Library See No. LT-1446/77].

Opening of a Regional Passport Office in Assam

4780. SHRI AHMED HUSSAIN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) Government's policy towards providing more passport offices in the near future ;

(b) the number of regional passport offices likely to start functioning by the end of the current financial year in view of Government's decision to simplify passport systems in the country ; and

(c) whether Government will consider to open at least one regional passport office in Assam by the end of the current financial year; and the likely date when the regional passport office will start functioning there ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): (a) The criterion for the opening of a passport office in a State is that at least 30,000 applications for passports must be received from it, in a year. While Government is conscious of the necessity of opening more passport offices in order to improve the service to the public, the need to have economically viable offices as also the necessity of curtailing non-plan expenditure are the limitations.

(b) Government is keeping a continuous watch on the level of applications received from each State. The number of applications received from Rajasthan has crossed 30,000 and, therefore, opening of an Office in that State during the current financial year is being considered subject to the limitation mentioned at (a) above. ;

(c) The number of applications received from the State of Assam during the current financial year is estimated to be 500 and, therefore, there is no proposal presently to open a passport office in that State during the current financial year.

Telephone connections to people, of Jokihat Block Headquarters, District Purnea, Bihar

4781. SHRI HALIMUDDIN AHMED: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether people of Jokihat Block Headquarters in the District of Purnea in Bihar have demanded installation of telephone connection and if so, when ;

(b) the reason for delay in providing telephone connection to them ; and

(c) the time by which they are likely to be provided telephone connection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) to (c). The demand for installation of telephone facility at Jokihat in Purnea District was originally received in 1972. The proposal was examined, but could not be sanctioned, because it was showing a loss, which could not be condoned according to the policy then prevailing.

A fresh demand for provision of P.C.O. was received in May 1977. With the recent liberalisation of the policy in regard to opening of P.C.Os it has been possible to approve the scheme this time.

The P. C.O. is likely to be commissioned during the current financial year.

**होम्योपथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों को प्रैक्टिस-
बंदी भत्ते का भुगतान करना**

4782. श्री महोत्तम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोर्पी के डाक्टरों के बीच विषयता के बारे में 28 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रस्तुत संख्या 5210 के उत्तर के संबंध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एलो-पैथिक डाक्टरों को मिलने वाले प्रैक्टिसबन्दी भत्ता होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों को भी देने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) से (ग). मारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथिक के चिकित्सकों को प्रैक्टिस-बंदी भत्ता देने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्ताव को मण्डी-शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

22 दिसम्बर, 1977 को पूछे जाने वाले प्रस्तुत का उत्तर भव्य प्रदेश में नसबन्दी के कारण व्यक्तियों की मृत्यु

4783. श्री क्याम लाल खड़े : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में गत वर्षों में बड़े पैमाने पर नसबन्दी की गई और बाद में उनसे अतेकों लोगों की मृत्यु होने के समाचार प्राप्त हुए ; और

(ख) यदि हाँ, तो जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1976-77 के दौरान मंडला जिले में 35,996 पुरुषों और 742 महिलाओं के नसबन्दी प्राप्तेशन किए गए जिसमें प्राप्तेशन के बाद 6 पुरुषों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उन सब के परिवारों को अनुप्रृष्ठवंक वित्तीय सहायता के रूप में पांच-पांच हजार रुपये दे दिए गए हैं।

Sale of Government securities by Indian Red Cross Society

4784. DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Indian Red Cross Society has transacted sale of Government securities without prior press notification ; and ;

(b) if so, the action taken thereon ?

**THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE (SHRI JAG-
DAMBI PRASAD YADAV) :** (a) Yes, Sir.

(b) The question of taking any action does not arise as there is no provision in the rules of the Red Cross which indicate a notification is to be issued prior to the sale of any Government Security by the Indian Red Cross Society.

Fake Organisations

4785. SHRI VASANT SATHE : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the activities of increasing number of fake organisations offering instant relief to various ailments and sale of fake

medical goods by the bogus firms which are reported to be earning crores of rupees every year through mail fraud schemes ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken to curb the activities of these racketeers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Contribution towards Fifth Five year plan of Nepal

4786. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have contributed to the Fifth Five Year Plan of Nepal ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU) : (a) and (b). Since the commencement of the Fifth Five Year Plan of Nepal in July 1975 upto 1977 the Government of India contributed Rs. 20.27 crores towards projects in Nepal and provision of technical assistance to that country.

The principal schemes on which this amount was spent were as follows :—

- (1) East West Highway (Central Sector).
- (2) Kamla Bridge.
- (3) Trisuli Hydel Project.
- (4) Chatra Canal.
- (5) East West Highway (Eastern Sector).
- (6) Kathmandu-Trisuli Road.
- (7) Kosi Area Roads.
- (8) Telephone Exchanges at Biratnagar, Janakpur & Jhapa.
- (9) Technical Assistance.

भ्रष्टाक उद्योग का विकास

4787. श्री दीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या इस्पात और खान मंडी यह बताने की हृषा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाक पर खनन से लेकर निर्यात तक औद्योगिक और व्यापारिक कितने प्रकार

के कर लगाए गए हैं और उस पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अंजित वाधिक राजस्व क्या है ;

(ख) ऐसे वाधिक करों से प्राप्त 'राशि' का कितना प्रतिशत इस उद्योग के विकास के लिए व्यय किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन करों के बोग के परिणामस्वरूप इस उद्योग का दिन प्रतिदिन हास हो रहा है ?

इस्पात और खान मंडालय में राज्य मंडी (ओर करिया मुद्दा) : (क) और (ख). खान स्वामियों द्वारा रायलटी अधिकार स्थिर लगान का भुगतान जो राशि अधिक हो, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 और 95 के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची 2 और 3 में निर्धारित दरों के अनुसार करना होता है । निर्यातिकों को भ्रष्टाक की निर्यात मात्रा पर निर्यात शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार तथा सीमा शुल्क ट्रेफिल अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित दरों पर देना होता है । भ्रष्टाक की किसी भी किसी के नियम के नियर्ति पर भ्रष्टाक खान अम कल्याण कोष अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत 3, 5 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार उपकर भी लगता है । निर्यातों से प्राप्त निर्यात शुल्क तथा उपकर का और निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्यात शुल्क	निर्यात पर उपकर
------	---------------	-----------------

(हजार रुपयों में)		
1975-76	306,53	56,51
1976-77	365,83	73,63
1977-78	216,80	42,54
(प्रकटवार, 77 तक)		

राज्य सरकार द्वारा लगाए जाए अन्य करों तथा उनके द्वारा वसुली गई रायस्टी अधिका स्थिर लगान की राशि के बारे में जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

अध्रक खान अम कल्याण निधि अधिनियम¹ के अंतर्गत प्राप्त उपकर की राशि राज्यों के बीच उनके अध्रक उत्पादन के अनुपात में बांट दी जाती है। यह राशि अध्रक कामगारों और उनके आधिकारों के लिए चिकित्सा, आवास, शिक्षा और अन्य सुविधायें जुटाने पर खर्च की जाती है। अध्रक उद्योग के विकास हेतु अध्रक के नए उपयोगों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है।² अध्रक व्यापार गिरिजिटकों ने अपने कारखानों के लिए 50 लाख हॉ की लागत से ~~एक~~³ एक उपकरणशाला की स्थापना की योजना बनाई है जिसमें औजारों और डाइवो के निर्माण और मरम्मत का काम होगा तथा छोटी प्राइवेट फ्लाई घरों के लिए भी इसमें काम होगा। तकनीकी सुविधाओं और वित्त स्रोतों के बारे में अतिम निर्णय होने तक, जिटकों 2.5 लाख रुपये मूल्य की महीनी के साथ एक छोटी उपकरण बाजा स्थापित कर रही है।

(म) इस उद्योग का लास अध्रक (जो अधिकतर निर्यात होता है) की मांग में निम्नलिखित कारणों से कमी का परिणाम है:—

- (1) अध्रक खण्डों के स्थान पर अध्रक और कृत्रिम पदार्थों से बनी वस्तुओं वैसे प्लास्टिक और पोलिस्ट्रीन का प्रयोग।
- (2) ट्रांजिस्टर वाले उपकरणों का उपयोग जिसमें अध्रक की जहरत नहीं होती।

(3) अमेरिका द्वारा अपने जब्त मंडार के अध्रक की विक्षी।

(4) विश्व औजारों में प्रामतीर पर मंदी का दौर।

बिहार की अनेक खाने उस राज्य में अध्रक खण्डों के व्यापक हितों की देखभाल करने वाले कुछ व्यापारिक घरानों द्वारा आन्तरिक समस्याओं का सामना करने के कारण भी बंद हो गई हैं। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि इस उद्योग का लास कर भार के कारण ही रहा है।

Import of Stainless Steel

4788. SHRI S. R. REDDY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

- (a) whether stainless steel is proposed to be imported this year;
- (b) if so, what is the quantity;
- (c) the price to be paid; and
- (d) the country from which it is sought to be imported?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Stainless steel is being imported during this year.

(b) The canalising agencies have imported 7780 tonnes of stainless steel during April-December 15, 1977. In addition, the policy also provides for direct import.

(c) The prices vary from tender to tender and item to item.

(d) The country of import also depends upon the competitiveness and availability against global tenders. Imports have been made from various countries like West Germany, France, Sweden, Japan, South Korea etc.

Pay scale and selection grade of Pharmacists

4790. SHRI MOHAN LAL PIPIL : SHRI NATHU SINGH :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

- (a) whether Government are aware of the fact that the pharmacists had demanded

that (i) the pharmacists registered under Sections 31(a), 31(b), 31(c) and 32 of the Pharmacy Act, 1948 be recognised as technical hands and the applicable scale of pay of Rs. 425-700 be granted, (ii) the selection grade posts be raised to 30 per cent and (iii) separate higher scale be given for Pharmacists/Store-keepers ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAG-DAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). The recommendations of the Pharmacy Council of India and various other organisations of the pharmacists for the upgradation of their scale of pay of Rs. 330-560, as recommended by the Third Pay Commission, and to bring it at par with Diploma holders of Civil/Electrical Engineering in the scale of Rs. 425-700, the raising of the selection grade posts of pharmacists to 30% and the provision of a separate higher scale for Pharmacists/Store-keepers, were carefully considered, but it was not found possible to agree to the same for the reason that such steep increase in the emoluments of Pharmacists is likely to have repercussion on the other para-medical categories as well as other scientific/technical categories in Class III (now Group 'C') like Laboratory Technicians, Junior Research Assistants, Draffsmen etc. under various Ministries. As regards the increase in the percentage of selection grade posts of Pharmacists, it was decided that it would be more appropriate to take a decision in this regard on the basis of the result of the discussion with the staff side of the National Council (JCM) on the Pay Commission's general recommendations relating to the percentage of posts in Class III (now Group 'C') services to be placed in the selection grade and criteria thereof.

Labourers killed/injured in private and public sector industrial units

4791. **SHRI G. Y. KRISHNAN :** Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of labourers injured/killed in various industrial units in the private and public sectors so far during the current year ; and

(b) what remedial steps are being taken by Government to prevent the recurrence of such incidents ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) As per provisional figures available with the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, there were 1,49,214 cases of injuries including 329 fatalities (excluding Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Manipur, Madhya Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Rajasthan, Meghalaya and Andaman & Nicobar Islands) for the first three quarters.

(b) The Factories Act, 1948 (which is implemented by the State Governments and Union Territory Administrations) has been amended recently to strengthen safety provisions therein.

Representations received from R.M.S. Union

4792. **SHRI A.K. ROY :** Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there has been a repeated representation on behalf of the R.M.S. Union, Class III, Dhanbad, to Government to attach the proposed R.M.S. Sorting Section in Mauvra Express train (27 Up/18 Down) at Dhanbad; and

(b) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yours, Sir. Some representations have been received for attaching the proposed Section to Dhanbad Sub Record Office instead of Muzaffarpur.

(b) It has been decided that it would be attached to Muzaffarpur in view of administrative reasons.

Reduction in Telephone Rates in rural areas

4793. **SHRI VIJAY KUMAR PATHIL :** Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether in view of the growing number of industries in rural areas, Government are proposing to reduce the telephone rates for connections in rural area Urban Exchanges (i.e. long distance connection); and

(b) whether Government are thinking of giving priority to such connections ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS, (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) There is no proposal to reduce the

telephone rates for long distance connections in rural areas from urban exchanges.

(b) No, sir. Connections are being provided in turn subject to technical feasibility and availability of stores.

Ayurvedic dispensary in West Delhi

4794. SHRI BALAK RAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn towards the news item entitled 'Ayurvedic System gets a back seat' appearing in the *Hindustan Times* dated the 13th August, 1977;]

(b) whether there are only six Ayurvedic Dispensaries and none of them is situated in West Delhi, whereas there are 100 allopathic dispensaries in West Delhi, if so, the reasons for the same;

(c) whether Government propose to take necessary steps for the promotion of Ayurvedic system of Medicines in view of its various pronouncements for doing so; and

(d) the details of such plans or steps taken and the time by which those will be achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes.

(b) At present 5 C.G.H.S. Ayurvedic Dispensaries and 1 Ayurvedic Unit are functioning under the C.G.H.S. at the following places:—

1. North Avenue
2. Kidwai Nagar
3. R.K.Puram
4. Gole Market
5. Dev Nagar
6. Delhi Cantt. (Unit).

There is a proposal under consideration to set up more Ayurvedic unit under CGHS Allopathic Dispensaries functioning in Delhi.

(c) Yes.

(d) The following new schemes are under consideration with a view to promote research and training in development and expansion of Ayurvedic System of Medicine:—

1. Setting up of a 300 bedded Ayurvedic Hospital at Hari Nagar, New Delhi (already approved).

2. Setting up of an Ayurveda, Unani and Homoeopathic Hospital (100 bedded each) at Chandiwal Estate, Kalkaji, New Delhi.

3. Publication of books.

4. Training of village vaidyas.

5. Establishment of Regional Institutes for Indian Systems of Medicine (3 in Ayurveda and one in Unani). These Institutes would comprise of an under-graduate college and 4 post-graduate departments.

6. Development of medical and health care programme through Indian Systems of Medicine—provision of treatment through ISM in PHCs. This scheme envisages the provision of a practitioner of ISM in each PHC. 1

7. Establishment of Dispensaries in ISM in the States at sub-centre level. This envisages the setting up of ISMwings at sub-centres.

8. Development of under-graduate education in ISM. This scheme envisages the provision of more funds to the under-graduate colleges of ISM to facilitate these colleges to implement the syllabi as recommended by the Central Council of Indian Medicine.

9. Training of under-graduate teachers.

10. Post-graduate training in Yoga and Nature Cure.

With a view to ensure better and more methodical attention to research in selected important areas, it has been decided to review results of the researches made so far and to split up the existing Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy into four Central Research Councils, one each for (i) Ayurveda and Siddha (ii) Unani (iii) Homoeopathy and (iv) Yoga and Naturopathy.

The above mentioned schemes will be implemented depending upon the availability of funds. Efforts would also be made to lay down targets for the schemes and the period for the achievements of the targets, wherever possible.

Waiving the Statutory Provision for Consultant Doctors

4795. SHRI RAJSHEKHAR KOLUR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether statutory provision for being considered as a consultant after serving as a senior physician/surgeon for six years can be waived by any authority ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE : (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). The posts of Consultants in various Specialities are in Supertime Grade I of C.H.S. In accordance with the provisions of C.H.S. Rules as amended from time to time, the vacancies of Supertime Grade I posts are to be filled on the recommendation of the Departmental Promotion Committee by promotion on the basis of merit with due regard to :-

- (i) Seniority of officers holding posts in Supertime Grade II (now bifurcated into Specialists Grade I and Supertime Grade II) who have rendered not less than six years of service in that category ; and
- (ii) the qualifications and experience requisite for vacancy to be filled.

In accordance with the provision of Rule 17 of C.H.S. Rules, 1963, as amended from time to time, the Central Government may, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provision of the Central Health Service Rules to such extent as might be necessary to ensure satisfactory working of those rules or to remove any inequitable results.

Provided that the power shall not be exercised so as to relax essential qualifications prescribed for appointment by any of the methods specified in the rules (including promotion) or the provisions regarding pension and age of retirement.

No relaxation other than those referred to above are available in the existing C.H.S. Rules.

Telephone Exchanges proposed to be opened in Orissa during 1977-78

4796. SHRI RAMA CHANDRA MALLICK : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of telephone exchanges proposed to be opened during the current

financial year, 1977-78 under General Manager, Telecommunications, Orissa, Circle BB & R ; and

(b) the places of location of the new telephone exchanges ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDÉO SAI) : (a) and (b) : Three new telephone exchanges are proposed to be opened in Orissa Telecommunications Circle during 1977-78, at the following places :-

- (i) BANAMALIPUR (Distt. Puri)
- (ii) PURANA CUTTACK (Distt. Phulbani)
- (iii) PURUSOTTAMPUR (Distt. Ganjam)

हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दुर्ग मार्ग में ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस का उल्लंघन किया जाना

4797. श्री मोहन बन्धा : क्या संसदीय कार्य तथा अमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : / /

(क) क्या जो ठेकेदार 20 और इससे प्रधिक मजदूरों को काम पर लगाते हैं उन्हें ठेका अम (विनियमन तथा उत्पादन) प्रधिनियम के अन्तर्गत बिना लाइसेंस लिये कार्य करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान स्टील बस्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के दुर्ग मार्ग के ठेकेदारों का अंदूरा क्या है जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त किये हैं और वे जान-बूझकर लाइसेंस के उपर्योग का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ग) इन ठेकेदारों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तकि इन मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके ?

अम और संसदीय कार्य भंडालय में राज्य अंगी (श्री लारंग साह) : (क) ठेका अम (विनियमन तथा उत्पादन) प्रधिनियम की धारा 1(4) के साथ पठित धारा 12(1)

के अनुसार कोई भी ठेकेदार, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, उपयुक्त अधिकारी द्वारा उस संबंध में जारी किये गये ताइसेंस के अनुसार और उसके अधीन व्यवस्था को छोड़ कर ठेका थम द्वारा किसी भी कार्य को न अपने जिम्मे लेगा और न करेगा।

(क) और (ग). यह मामला वस्तुतः राज्य सेवा में थाता है और ठेका थम अधिनियम के अधीन इस मामले में 'समुचित सरकार' संबंधित राज्य सरकार है। इस संबंध में राज्य सरकार को निकाला जा रहा है।

Outstanding Telephone Bills against former Ministers and M.Ps.

4798. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the amount of telephone bills outstanding against each former Central Minister and former Members of Parliament and the period to which the amount relates ;

(b) what steps Government have taken to realise the amount in full ; and

(c) in how many cases telephones have been disconnected and if how many cases legal action has been taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(SHRINARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha as soon it is available.

गुजरात में नए डाकघर खोलना

4799. श्री चर्चन सिंह भाई घोड़े : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात संकिल में वर्ष 1977-78 के दौरान कितने नये उप-डाकघर तथा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का विचार है तथा कितने स्थानों पर काउंटरों तथा चलते-फिरते डाकघरों की सुविधायें प्रदान की जावेंगी और कितने लैटर बाक्स स्थापित किये जायेंगी;

(ख) 31 अगस्त, 1977 तक ये कितनी संख्या में उपलब्ध कराये गये ; और

(ग) 1 नवम्बर, 1977 से 31 मार्च, 1978 के दौरान ये कितनी संख्या में उपलब्ध कराये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद तुडवेक साह) : (क) से (ग). बांधित सूचना नीचे तालिका में दी जा रही है :—

तालिका

मंद ज्ञानाम	वर्ष 1977-78 के लिए प्रस्ताव	31-10-77 तक जिनकी व्यवस्था कर दी गई थी	1-11-77 से 31-3-78 के दौरान जिनकी व्यवस्था कर दिये जाने की संभावना है
1	2	3	4
1. उप-डाकघर खोलना	10 (जहरी लोकों में)	जहरी-9	1

1. (प्रामीण लोक भागीण-1 में)
1

1	2	3	4
2. विभागेतर शाश्वा डाकघरों का दर्जा बढ़ावः २ उन्हें विभा- गीय उप-डाकघर बनाना	20 (यामीण क्षेत्रों में)	2	18
3. विभागेतर शाश्वा डाकघर खोलना	91	25	66
4. चलते-फिरते डाक- 3000 वर्टों के बरिए यांवों में डाक-काउंटर सुविधाएं देना।		737	2263
5. यामीण क्षेत्रों में 1500 सेटर-बस्स लगाना		675	825

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में, सम्याचों
की कमी

4800. श्री लालची जाई : क्या
स्वास्थ्य और परिवार कस्याच मंडी यह
बढ़ाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन
अस्पताल, नई दिल्ली के एमरजेंसी विभाग
में अधिकतर आवश्यक औषधियों की कमी
रहती है;

(ख) क्या अस्पताल में प्रतिदिन आने
वाले रोगियों को देखते हुए यहां पर सम्याचों
की जारी कमी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की
क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कस्याच मंडालय
में राज्य मंडी (श्री जगदल्ली प्रसाद यादव) :
(क) विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के
एमरजेंसी विभाग में आवश्यक औषधियों की
कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग). विलिंगडन अस्पताल
में इस समय 730 पलंग हैं तथा 70 और
पलंग बढ़ाये जा रहे हैं। अविष्य में श्री
लालचीकलानुसार पलंग बढ़ाये जाने के
प्रश्न पर संभव-समय पर विचार किया
जायेगा।

आपात-स्थिति के दौरान डाक तथा तार
अविकारियों द्वारा की नई अनियन्त्रितता

4801. श्री लालची सिंह बोहूल :
क्या संचार मंडी यह बताने की कृपा करेंगे
कि डाक तथा तार विभाग के कितने अधि-
कारियों के विशेष आपात-स्थिति के दौरान
अनियन्त्रितताएं करने के आरोप में कार्रवाही
की जा रही है? ■

संचार मंडालय में राज्य मंडी (श्री
नरहरि प्रसाद तुकडेल साह) : बांधित
दूचना एकल की जा रही है। प्राप्त होते ही
इसे सभा-पट्ट पर राज्य-कामेला फारा-

Policy Planning Committee of Ministry of External Affairs

4802. SHRI RAM PARKASH TRIPATHI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Policy Planning Committee of the Ministry of External Affairs is still functioning and if so, the composition thereof ; and

(b) whether there is proposal to associate suitable experts in the fields of cultural affairs, external economic relations, Information Services with the functioning of this Committee on whole time or part time basis ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU) : (a) Yes, Sir. The Policy Planning Committee is composed of the Secretaries of the Ministry of External Affairs with the Foreign Secretary as the Chairman. Whenever specific issues concerning their departments and areas of competence are concerned, other Secretaries of the Government of India are invited as special invitees. The Joint Secretary in the Policy Planning Division is the Member-Secretary of the Policy Planning and Review Committee.

(b) Yes, Sir. The Government desires that the Committee should have greater contacts with experts in the academic and cultural fields to take maximum advantage of available expertise on foreign policy in the country. There is already in existence liaison between Committee and concerned scholars, academicians at Jawaharlal Nehru University, Institute of Defence Studies and Analysis, and the Indian Council of World Affairs. The question of institutionalising these contacts on a continuing basis is being looked into.

बहादुर जह बफर के व्यक्तियों को विवेश नाम दाता

4803. श्री सोम ब्रह्मा त्यागी : क्या विवेश मर्दी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह विलीनी बर्मा यात्रा के द्वितीय स्वर्णी बादशाह बहादुरशाह बफर की विवाहित बर भी थी औ वे;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वर्णी बादशाह बहादुरशाह बफर के व्यक्तियों को भारत लाकर उनकी समाधि बनाने के बारे में बर्मा सरकार के साथ भी चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विवेश बंद्वाल्य में राज्य मंडी (श्री एस० कुमूर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रबन्ध बही उठता।

Hijacking of Indian Airlines Plane during Emergency

4804. SHRI SAMAR GUHA : SHRI KANWAR LAL GUPTA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether an aircraft of the Indian Airlines while flying from Delhi to Jaipur was hijacked and taken to Pakistan during Emergency ;

(b) if so, whether facts about the identities of the hijackers and concessions made to them by the Government of India were kept undisclosed by the former Government ; and

(c) if so, what happened to those hijackers and what role was played by the Government of Pakistan in regard to the hijacking ; and

(d) whether Government have come across the facts about—

(i) the identities of the hijackers ;

(ii) their purpose for hijacking Indian aircraft ;

(iii) conditions of their release ; and

(iv) the role played by Pakistan Government in regard to the hijackers ;

and

(e) if so, facts there about ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU) : (a) to (c). An Indian Airlines Boeing-737 aircraft was hijacked to Lahore on September 10, 1976, while on a scheduled flight (No. 491) between Delhi and Jaipur on the Delhi-Jaipur-Aurangabad-Bombay sector.

Government of Pakistan extended co-operation in securing the safe return of the passengers, the crew and the aircraft. No concessions were made by Government of India to the hijackers.

On October 9, 1976, an official spokesman of the Government of Pakistan stated that preliminary investigations against hijackers had been completed and they would be tried for violating the laws of Pakistan. But, in January 1977, the Government of Pakistan decided to release the hijackers, as it did not have enough evidence to prosecute them and also did not agree to return them to India to face trial. On January 6, 1977, the Government of India expressed its regret and deplored these moves of the Government of Pakistan.

It appears that while no legal action was taken against the hijackers, they have remained under "protective custody" in Pakistan since then. It is learnt from press reports in Pakistan that an application made on behalf of the hijackers for their release has been accepted by the Lahore High Court. Federal Interior Ministry of the Government of Pakistan in its reply is reported to have stated that the detenus hijackers possessed Indian passports and had committed an international crime by hijacking the plane. The case is likely to continue.

प्राविधिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए डाक्टरों की नियुक्ति

4805. श्री बृज राज सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक प्राविधिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की नियुक्ति की जाए है;

(ख) क्या सरकार का विचार नये प्राविधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है और यदि हाँ, तो कब तक तथा कितने और कहाँ होंगे; और

(ग) नये डाक्टरों की नियुक्ति किस ढंग से की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य मंत्री (श्री जगद्विंशी प्रसाद यादव) :

(क) 31-12-76 तक देश में 5,373 प्राविधिक स्वास्थ्य केन्द्र से, जिनमें 4,394 प्राविधिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो या दो से

अधिक, 928 केन्द्रों में एक और 51 में कोई डाक्टर नहीं है।

(ख) छठी पचवर्षीय योजना के लिए अभी तक लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। केन्द्रों की घटास्थिति राज्य सरकार अपनी आवश्यकतानुसार तय करेंगी।

(ग) प्राविधिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए डाक्टरों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा ऐसी नियुक्तियों के लिए निष्पारित उनके नियमों के अनुसार की जाती है।

सिंधी में हैड पोस्ट आफिस खोलना

4806. श्री तूर्चनारायण सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंधी जिला, मध्य प्रदेश में एक हैड पोस्ट आफिस तथा एक तारघर खोलने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वरहर प्रसाद मुख्यमंत्री राज्य) : जिला सिंधी के मौजूदा रीवां डाकघर को दो भागों में विभक्त कर एक मूल्य डाकघर खोलने का प्रस्ताव हासन ही में प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

जहाँ तक तारघर खोलने का प्रस्ताव है, वह उल्लेखनीय है कि मौजूदा सिंधी डाकघर में तार सुविधाएं पहले ही दे दी गई हैं।

Quantity of Plates Supplied to Stock-yards

4807. SHRI SARAT KAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total quantity of plates of different gauge supplied to the different stock yards in the country during the last two years and the basis of such allocation ; and

(b) whether there is any proposal for opening a stockyard at Berhampur in near future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA):
 (a) A statement giving the details of despatches of plates to different stockyards of Hindustan Steel Limited during the last two years is at the annexure. Indian Iron and Steel Co. does not produce any plates. Producers send materials to their stockyards subject to

production/availability on the basis of requisitions submitted by the Branch Managers and Consumer Contact Officers posted in various Branches who collect orders from parties in their respective regions.

(b) There is, at present, no proposal to open a stockyard at Berhampur either by Hindustan Steel Ltd., or by Indian Iron and Steel Company.

Statement

Despatches of plates to stockyards of Hindustan Steel Limited during 1975-76 and 1976-77.

Stockyards	1975-76		1976-77	
	Plates upto 10mm thickness M/T	Plates above 10 mm thickness M/T	Plates upto 10mm thickness M/T	Plates above 10 mm thickness M/T
1. Calcutta	20600	19600	46600	25000
2. Gauhati/Tinsukia	1400	1600	4400	900
3. Visag	600	1900	6800	11700
4. Dhanbad	7400	4500	7200	4300
5. Bokaro	1800	1300	7200	1900
6. Rourkela	1400	700	3300	5500
7. Bhubaneswar	900	900	4000	3300
8. Kanpur	1800	3000	3800	5300
9. Allahabad	3500	3400	9600	8600
10. Bhilai/Nagpur	4400	2900	7200	8900
11. Bobmav/Pune	26500	20200	64800	25100
12. Ahmedabad/Baroda	2100	300	11400	1800
13. Indore	1400	900	3900	1500
14. Delhi/Gaziaabad/Agra	7500	7000	23000	17300
15. Faridabad	500	1300	5700	2900
16. Kota/Jaipur	1900	800	2300	600
17. Jullundar/Batala/Mandigobindgarh/Ludhiana	1500	1300	3400	500
18. Srinagar/Jammu	600	..
19. Madras	10000	9200	20100	11900
20. Secunderabad/Vijaywada	2800	5300	9700	7400
21. Bangalore/Belgaum	3300	3200	18400	3400
22. Coimbatore/Trichy	600	700	11200	1700
23. Cochin	1700	1300	2800	1400
TOTAL	103800	94100	270100	150900

डाक जीवन बीमा से ज्ञान पर व्याज

4808. श्री हरलोकिन्द्र बर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक जीवन बीमा पालिसियों से ज्ञान पर व्याज की दर में इस बीच बढ़ि कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी दर में कितनी और कब से बढ़ि की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद मुख्यमंत्री साम) : (क) और (ख) व्याज की दर 1-3-1975 से 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दी गई है।

ज्ञान-योजना बताने में जो भारतिक्त वर्च आता है, उसे पूरा करने के लिए ज्ञानों पर लगाए गए व्याज की दर निधि की धन राजियों पर अंतिम व्याज की दर से अधिक रखी रखती है। 1-8-1974 में डाक जीवन बीमा निधि को देय व्याज की दर 7 प्रतिशत हो गई थी और इस प्रकार यह दर ज्ञानों पर ली जा रही व्याज दर के बराबर हो गई थी। तीसरे वेतन आयोग की सिफारियों क्रियान्वित करने के फलस्वरूप कर्मचारियों की परिलम्बियां बहु गई, जिनकी बजह से ज्ञान योजना का खर्च भी बढ़ गया था। इस प्रकार ज्ञान-योजना बताने वाले निधि को धाटा हो रहा था। इसलिए, निधि बीमाकांक की सलाह पर व्याज की दर बढ़ा कर 8.5 प्रतिशत कर दी गई थी।

प्रत्येक टेलीफोन को विशेष सुविधायें

4809. श्री सुलाल शाहज़ा : क्या संचार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि टेलीफोन विभाग के जनरल मैनेजर द्वारा कुछ प्रदं बालों को विशेष टेलीफोन मुविधाएं अद्यतन की गई थी और यदि हां, तो क्या

प्रत्येकों को इन सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद मुख्यमंत्री साम) : जहां तक दिल्ली टेलीफोन जिले के रिकांड का प्रस्तुत है, "प्रैसों" को टेलीफोन कनेक्शन टेलीफोन अलाइट करने के निवारों के अनुसार दिये गये हैं। नियम विशेष टेलीफोन देने के यदि किसी खास मामले की जानकारी दी जाए तो उसकी जांच की जाएगी।

Allotment of Posts by Eastern Region
Calcutta to Orissa Circle Geological
Survey of India

4810. SHRI JENA BAIRAGI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) how many class II and class IV posts have been allotted by Eastern Region Calcutta to Orissa Circle, Geological Survey of India since 1974 to 1977 ;

(b) how many of them have been locally recruited ;

(c) whether there is any new circle created since 1974 ; if so, whether administration has been separated ; if not, the reasons therefor ; and

(d) whether there is less staff of class III and class IV in Orissa Circle as compared to other circles ; if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA). (a) Eight Class II posts and eight Class IV posts.

(b) Three Class IV posts were filled up locally. Since direct recruitment to Class II posts is made on all India basis through the Union Public Service Commission, the question of local recruitment does not arise.

(c) In June, 1974, Orissa Circle office was bifurcated into Orissa Circle (North) and Orissa Circle (South). The work relating to administration and accounts has however not been separated so far.

(d) No, Sir.

Setting up of Committee to look into the Grievances of Physiotherapists

4811. SHRI K.B. CHETTRI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether a Committee has been set up to look into the grievances of the Physiotherapists ;

(b) if so, when the report is likely to be submitted ;

(c) whether there is any proposal to bring a legislation to safeguard the interests of the Physiotherapists ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is a proposal to bring a legislation entitled "THE INDIAN COUNCIL ACT OF PARAMEDICAL REHABILITATION PROFESSIONS" in consultation with the State Government/ Union Territories.

(d) The salient features of the proposed legislation are as follows :—

(i) To regulate uniform standards of training of para-medical rehabilitation professions supplementary to rehabilitation medicine.

(ii) To lay down standards of Professional practice, ethics and conduct of qualified paramedical rehabilitation professionals for protection of the public & improved patient care.

The comments of the State/Union Territories are awaited.

(e) Does not arise.

Performance of Public relations and Publicity Officers abroad

4812. SHRI HARI VISHNU KAMATH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in most of our embassies and missions abroad, the performance of Public Relations and Publicity Officers is not commensurate with the expenditure incurred ;

(b) if so, the reasons for such poor performance;

(c) whether Government propose to initiate measures for improvement; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU) : (a) and (b). While there may be some weaknesses in external publicity machinery, considering the limited resources placed at its disposal its performance has by and large been satisfactory. Continuous efforts are made to improve our performance.

(c) and (d). The question of strengthening our publicity units abroad and improvement in their performance is under constant review of the Ministry of External Affairs. The Ministry has appointed a Committee headed by Shri Chanchal Sarkar to look into this matter. The report of the Committee is expected soon.

Unidentified Virus in Delhi

4813. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether some unidentified virus has hit the city of Delhi;

(b) whether proper medicines and treatment has been developed for it; and

(c) if so, the steps taken so far to meet this epidemic ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

भारत में शास्त्र डाकघर

4814. श्री रामानन्द तिवारी : क्या संचार मंत्री यह दाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कून कितने शास्त्र डाकघर हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक डाकघर में कितने विभागीय व्यक्ति श्रद्धांग पोस्ट मास्टर काम करते हैं ;

(ग) इन विभागेतर पोस्ट मास्टरों को कितना मासिक बेतन अवधार मत्ते किये जाते हैं;

(घ) क्या बहते हुए मूल्यों और कार्यालय को व्यान में रखते हुए उन्हें दिया जाने वाला बेतन अवधार पारिश्रमिक अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके बेतनमान में बढ़ि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंडी (व्यापक प्रसाद मुकुदेव साध) : (क) देश में तारीख 30-9-77 को 99,677 विभागेतर लाला डाकघर और 10 विभागीय लाला पोस्ट-मास्टर थे।

(ब) 99,677 विभागेतर लाला पोस्ट-मास्टर और 10 विभागीय लाला पोस्ट-मास्टर।

(ग) इस समय विभागेतर लाला पोस्ट-मास्टरों को एक मिला जुला भत्ता f.yा जाता है। यह भत्ता कम से कम 800 रु. प्रतिमास और अधिक से अधिक 110 रु. प्रतिमास है, जो उनके कार्यभार पर और इस बात पर निर्भर करता है कि डाकघर कितने समय तक खुला रखा जाता है।

(घ) और (ङ). विभागेतर एजेंटों के मजदूरी के ढांचे पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

Enquiry conducted about Indian Red Cross Society

4815. SHRI SHARAD YADAV : DR. RAMJI SINGH : SHRIMATI MRINAL GORE :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Short Notice question No. 5 on 24-6-77 in which he had given an assurance that an enquiry would be conducted about the Indian Red Cross Society and state:

(a) the action taken by Government thereon;

(b) whether it is a fact that three staff cars of Indian Red Cross, the numbers of which are given below and the petrol bills of which are for Rs. 7000 to Rs. 20,000 and more, are being used by the high officers there for their personal use by erasing 'Indian Red Cross' and + mark of these cars. Imported Fiat Vehicle No. DHE 8658, Volks Wagon No. DHC 8295, DHB 6141.

(c) if so, the reasons for delay in conducting an enquiry by Government in this regard;

(d) whether it is also a fact that Rajasthan Government are conducting an enquiry into the charges against a Member of Indian Red Cross Society; and

(e) the action being taken by Government against such guilty persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The inquiry has not yet been completed.

(b) and (c). There are two vehicles (Volks Wagons) Nos. DHC 8295 and DHB 6141 which never had any Red Cross emblem painted on them. The question whether this should be done is under consideration, but the fact that they belong to the Indian Red Cross Society is written on their number plates. The third car (Fiat) No. DHE 8658 which had the Red Cross emblem, is being repainted and in that process the emblem has been defaced; but when the painting work is over the Red Cross emblem will be painted on it again.

The actual petrol bills for the above cars for August, September and October 1977 are as follows:—

August '77 Sept. '77 October '77

		Rs.	Rs.	Rs.
DHE 8658	.	689	1087	699
DHC 8295	.	475	205	..
DHB 6141	.	350	382	382

No unauthorised use of any vehicle by any officer/employee of the Indian Red Cross Society has occurred.

(d) No, Sir. However, the Rajasthan State Branch of the Indian Red Cross Society is conducting an enquiry into some allegations against its Secretary.

(e) Necessary action would be taken on the conclusion of the enquiry mentioned in part (d) above.

Removal of Emblem from Imported Cars by Indian Red Cross Society

4816. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Indian Red Cross Society has removed the emblem (+) from the 3 imported car for the use of Bangladesh refugees (one imported Fiat and two Volks Wagon);

(b) if so, since when these cars have been used without the emblem (+); and

(c) the reasons for the removal of the emblem (+) ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir. However, the Italian Red Cross Society has donated one Fiat car in 1969 and the sister organisations have donated two Volks-Wagons about 7 years back to the Indian Red Cross Society for its use. These were not imported by the Indian Red Cross Society for the use of Bangladesh refugees.

(b) and (c) . In the case of Fiat the emblem on it was defaced when its repairing was taken up recently. As far as the other two cars, Volks-Wagons, are concerned, they never had Red Cross marking, but the fact that they belong to the Indian Red Cross Society is written on the number plates. The question whether the emblem should be painted on them is under consideration of the Indian Red Cross Society.

कर्मचारी राज्य बीमा योग्यना का इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर तथा रत्नाम में सामूहिक दिया जाना

4817. श्री छविराम अरंग : क्या संसदीय कार्य तथा अमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योग्यना मध्य प्रदेश के पूर्व मध्य भारत लोड के 4

प्रमुख ग्राम्योनिक केन्द्रों इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर तथा रत्नाम में 23 जनवरी, 1955 को सामूहिक दिया गई थी और उस समय उसके अन्तर्वर्त 55,000 ग्राम्य लोगों ने अपनी जाति बदल दी थी;

(ख) क्या इस योजना को विस्तार 20 केन्द्रों तक हो जाने से इसके अन्तर्वर्त भाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 1,49,000 हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें देने के लिए इन सभी केन्द्रों पर कितने ग्राम्यधाराय हैं और इन केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का स्थौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के परिवारों के लिये जन्मायों के भारतान्तर जैसी भांतिक सुविधायें देने का का है ?

मध्य तथा संसदीय कार्य अंतर्वर्त में राज्य अंतर्वर्ती (डा० रामकृष्णानन्द सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा नियम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) जी, हां ।

(ख) जी हां । 31-3-1976 की स्थिति के अनुसार ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार, जो चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, द्वारा व्यवस्थित पूर्णकालिक ग्राम्यधारायों की संख्या इस प्रकार है :—

1. इंदौर	.	11
2. उज्जैन	.	5
3. ग्वालियर	.	7
4. रत्नाम	.	2

इनके अतिरिक्त, इंदौर में एक नियोजितों का ग्राम्यधाराय है, जिसका उपयोग कर्मचारी भी करते हैं। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर

में लाभानुभोगियों को पूर्ण चिकित्सा मुविधा (प्रस्ताव में भर्ती होकर इलाज कराने की मुविधा सहित सभी मुविधाएं) दी जाती हैं। रत्नाम में केवल कर्मचारियों को पूर्ण चिकित्सा मुविधा दी जाती है। परिवारों को विस्तृत चिकित्सा मुविधाएं (प्रस्ताव में भर्ती होकर इलाज कराने की मुविधा को छोड़ कर बाकी सभी मुविधाएं) दी जा रही हैं।

(म) रत्नाम में कर्मचारियों के परिवारों को अन्तर्गत मुविधाएं (प्रपस्ताल में शालिल होकर इलाज कराने की मुविधाएं) उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुआ करार

4818. श्री छविराम घर्मल : क्या संसदीय कार्य तथा अमंत्री यह बताने की हुआ करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच चिकित्सा मुविधाओं तथा खर्च के बारे में हुए करार का घोरा क्या है;

(ख) क्या इस करार की कुछ घारामों को निकाल देने के लिये कोई अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अमंत्री राज्य संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (दा० राम हुसान सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा नियम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) मध्य प्रदेश सरकार और कर्मचारी राज्य बीमा नियम के बीच हुए करार की एक प्रतिलिपि सभा पट्टन पर रखी है।

[प्रन्नालय में रखी गयी। इसमें संख्या एल० टी०-1447/77]।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Development of Medical Facilities in Delhi

4819. SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the dispensary facility for the health welfare of the people is in-adequate in view of the total population of Union Territory of Delhi;

(b) if so, the total population of Delhi and the daily average of indoor and outdoor patients in each hospital; and

(c) the extra provision being made for the development of health welfare in the Union Territory of Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b) As on 1-10-77, there are 346 dispensaries in different systems of medicine being run by different agencies for a total population of 5340364 in the Union Territory of Delhi. Keeping in view the resources available, the number of dispensaries is not considered inadequate.

(c) It is proposed to establish two 500 bedded hospitals and seven 100 bedded hospitals besides a chain of new dispensaries in Delhi. Proposals for adding more beds in some of the existing hospitals are also in various stages of consideration.

Vasectomisation of Adivasis and Harijan Bachelors

4820. SHRI SRIBATGHA DIGAL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether during the previous regime large number of Adivasis and Harijans who were bachelors were forcibly vasectomised;

(b) if so, the number of such persons in Orissa State District-wise; and

(c) whether Government would recognise these persons at its own cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PARSAD YADAV): (a) to (c). The information is being collected from the States Union Territories and would be laid on the table of the Sabha when received.

Sub-post Offices in Block H. Q. in Orissa

4821. SHRI SRIBATCHA DIGAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there are many Block Head Quarters in Orissa State without having Sub-Post Offices;

(b) if so, what is the number thereof, District-wise; and

(c) when Government would provide Sub-Post Offices to these places?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). No, Sir. There are only 27 Block Headquarters out of a total of 314 in Orissa State without Sub Post Offices. These 27 Block Headquarters have Extra-Departmental Branch Post Offices. District-wise break up of the Block Headquarters which do not have Sub Post Offices is placed on the Table of the House.

(c) It is proposed to upgrade 10 out of 27 Extra Departmental Branch Post Offices at these Block Headquarters into Departmental Sub Post Offices in the current financial year. The upgradation of Post Offices at the remaining 17 places is being planned for 1978-79.

Statement

District-wise break up of Block Headquarters which are without Sub Post Offices in Orissa State.

SL No.	Name of the District	No. of Block H. qrs. without Sub-Post Offices.
1	2	3
1.	Dhenkanal	1
2.	Kalahandi	6

1	2	3
3.	Ganjam	1
4.	Keonjhar	2
5.	Koraput	8
6.	Mayurbhanj	2
7.	Sambalpur	6
8.	Sundergarh	1

27

Postal Division in Kalahandi, Orissa

4822. SHRI SRIBATCHA DIGAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the backward district Kalahandi in Orissa State does not have a postal division;

(b) whether a proposal to open a postal division there is pending with Government for a long time; and

(c) if so, when the new division will be opened and at which place?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes; Sir. Kalahandi district in Orissa does not have a separate Postal Division.

(b) No; Sir.

(c) Does not arise.

Opening of Yoga Ashrams in the Country

4823. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether on account of the growing popularity of Yoga in the country, Government propose to open more yoga ashrams; and

(b) if so, the number of such ashrams to be opened during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PARSAD YADAV): (a) No. Clinical

research is, however, being conducted for cure of certain diseases through Yoga at a number of Centres. In addition, steps are also being taken to develop the Central Research Institute for Yoga and Vishwavidyalaya Yogashram, New Delhi.

(b) Does not arise.

Production of Steel

4824. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state the total loss in steel production during the last six months due to non-supply of coal and the remedial measures taken ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Only in the months of October and November, 1977 there was a short-fall in steel production, partly on account of shortages of coal. It is, however, not possible to quantify the loss in production on account of shortage of coal alone since production was also adversely affected by some other factors *e.g.* power restrictions/interruptions etc.

Constant liaison is being maintained with the coal producing organisations and the Ministry of Energy who have assured that the requirements of coal and power in the coming months would be fully met. Implications of importing low ash coking coal for blending with Indian coal for use in steel plants to increase productivity is also under examination.

Gold, Nickel, Copper deposits in off-shore areas.

4825. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether according to the geologists, there are possibilities of gold, nickel, copper and cobalt deposits in the off-shore areas in exploitable quantity;

(b) if so, whether any assessment regarding these deposits in the sea-bed in different areas in the country has been made; and

(c) if so, with what results and the steps taken by Government to exploit these deposits

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) "Placer deposits" of gold and concentration of nickel, copper and cobalt in the manganese nodules are known to occur in off-shore areas in different parts of the world.

(b) and (c). Preliminary investigation to a very limited extent carried out in off-shore area of the Orissa Coast to locate "placer deposits" of gold has not indicated any gold.

During the current field season (1977-78) the Geological Survey of India proposes to carry out exploration for off-shore mineral deposits in the eastern and western coast of this country. The question of exploitation of such deposits is at this stage premature.

Utilization of imported oil Fired cornish boiler by Government Medical Stores Depot, Madras

4826. SHRI A. MURUGESAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether an imported oil fired Cornish Boiler was purchased a decade back worth about Rs. 3 lakh at Government Medical Stores Depot, Madras;

(b) whether this Boiler has been put to use; and

(c) if not, the reasons therefor and the action taken against those responsible for its being out of commission ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) An imported oil fired Cornish Boiler was purchased in 1965/1966 at an expenditure of Rs. 78,750/- excluding sales tax freight etc.

(b) No.

(c) The Boiler was originally obtained as a part of the Scheme to set up the manufacture of parenteral preparations in Madras. However, the very existence of Depots was questioned in 1966 and once again in 1969 and the scheme remained on the shelf. In the meantime two huge factories have come up in Madras for the manufacture of Transfusion Fluids which make supplies all over the country. It is not considered advisable or economical to set up any unit for production of Transfusions in Madras. It is proposed to transfer the Boiler to the Safdarjung Hospital, New Delhi.

प्रसूति काल में महिलाओं को मृत्यु

(ब) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

4827. श्री एस० एस० सोयानो :
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंडी (श्री अगवानी प्रसाद यादव) :
(क) और (ब). जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह बात निम्नलिखित सारणी से, जो भारत के महारंगीयक द्वारा तैयार की गई माडल रजिस्ट्रेशन स्कीम पर प्राधारित है, स्पष्ट हो जाती है :—

(क) क्या महिलाओं की विविकांश मृत्यु प्रसूति काल में होती है; और

वर्ष	योग	पुरुष	महिलाएं	हुई मौतें	मौतों की प्रतिशतता
1972	16104	8529	7575	208	2.75
1973	15669	9457	7212	180	2.50

चूंकि अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में जच्चा-मृत्यु दर अभी बहुत ऊँची है, इसलिए भारत सरकार ने जच्चा-मृत्यु दर को घटाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(3) तालुक और जिला स्तर के अस्पतालों में डाक्टरों को प्रशिक्षण देकर और वहां सुरक्षित प्रसव करने के लिए बढ़िया उपस्कर और उपकरण उपलब्ध करवा कर रेफरल सेवाएं सुधार दी गई हैं ताकि जोखियम वाली माताश्रीं का पता लगाया जाए और उन्हें बढ़िया इलाज की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जा सके।

(4) गर्भवती महिलाओं को टेटनेस से बचाने के लिए टीके लगाने और उनका अपोयज अरक्तता से बचाव करने सम्बन्धी योजना को बहुत तेज कर दिया गया है ताकि उनकी टेटनेस के कारण मृत्यु न हो और गर्भावस्था में अरक्तता से उत्पन्न होने वाले रोगों को घटाया जा सके।

(1) प्रांगमरी हैल्प सेन्टरों, तालुक और जिला स्तर के अस्पतालों में महिलाओं को प्रसव सम्बन्धी सेवाएं देने के मूल ढांचे को मजबूत बना कर सुधार किया गया है।

(2) बच्चों के जन्मों के बीच अन्तर रखने और बच्चों की संख्या को सीमित करने के लिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा पाव दम्पत्तियों से सम्पर्क किया जा रहा है क्योंकि तीसरे प्रसव के बाद जच्चा-मृत्यु दर बढ़ जाती है।

(5) दाइयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम [का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया है ताकि परम्परागत प्रामाणी दाइयों को प्रसव कराने के अपूर्तित (प्रसेटिक) और पूर्तिरोधी (एस्ट्रीसेटिक) तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा सके । इन दाइयों को किटें भी दी जा रही हैं ताकि मुश्किल प्रसव कराने के लिए उनके पास उपयुक्त औजार और सामग्री उपलब्ध हो ।

Telephone and Telegraph facilities to Post Office, Sunhi, Kangra;

4828. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an E.D. sub-post Office is functioning at Sunhi in Kangra District, Himachal Pradesh without telephone and telegraph facilities causing inconvenience to the people of the area;

(b) if so, whether there is any proposal for providing telegraph and telephone facilities at Sunhi; and

(c) if so when, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) There are no telephone and telegraph facilities in the Post Office at Sunhi in Kangra District, Himachal Pradesh.

(b) and (c). Terms of rent and guarantee have been quoted to the Himachal Pradesh Government and their acceptance is awaited. As per present policy of the Department, the work can be undertaken only after the rent and guarantee terms are accepted.

फार्मसिस्टरों के नवीकरण में भेदभाव

4829. जी नारू विद्: क्या हवाहश्व और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि ।

(क) क्या एलोपैथी, मायूर्वेदिक तथा होमोपैथिक के डाक्टरों तथा नसौं को प्रति वर्ष अपने रजिस्ट्रेशन का नवीकरण [नहीं

कराना पड़ता जब कि फार्मसिस्टों को इसे अधिनियम रूप से नवीकरण कराना पड़ता है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके बाया वार्षण है और इस बारे में सरकार कब तक एक-रूपता लायेगी;

हवाहश्व और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य भवी (श्री उत्तराधी प्रसाद यादव) :

(क) एलोपैथिक डाक्टरों और नसौं का पंजीकरण राज्य अधिनियमों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपलब्धों के अधीन किया जाता है । कर्नाटक की राज्य चिकित्सा परिषद को छोड़ कर जो उस राज्य में पंजीकृत एलोपैथी डाक्टरों के वार्षिक पंजीकरण पर जोर देती है, आय किसी भी एलोपैथिक और मायूर्वेदिक डाक्टर और नसौं को अपने पंजीकरण का प्रति वर्ष नवीकरण नहीं करवाना पड़ता । फिर भी, कुछ राज्य बोर्ड/होम्योपैथी की परिषदें वार्षिक आधार पर पंजीकरण का नवीकरण करवा रही हैं । इसके अतिरिक्त भारतीय नसिग परिषद के सकल्प के अनुसरण में कई राज्य द नसिग परिषदें हर पांच साल बाद पुनः पंजीकरण की पढ़ति को अपना रही हैं । कुछ राज्य बोर्ड/होम्योपैथी की दरिष्टें भी पांच बर्षों में एक बार पंजीकरण का नवीकरण करवा रही हैं ।

‘नों केम्ब्रिय अधिनियमों नामतः फार्मसी अधिनियम, 1948 और इति चिकित्सक अधिनियम, 1948 में वार्षिक फीस देकर वार्षिक पंजीकरण करवाते की व्यवस्था की गई है । यह उत्तेजनीय है कि फार्मसी अधिनियम, 1948 की द्वारा 46 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संघशासित क्षेत्र दिल्ली ने हाल ही में कार्मासिस्टों के नये पंजीकरण के लिये आजीवन फीस निष्पारित की है और पहले से पंजीकृत फार्मसीस्टों को इस बात की छूट है कि पहले से जल्दी आ रही

प्रचलित प्रणाली के अनुसार अति वर्ष पंजी-करण करवाते रहे या निर्भारित फीस देकर अपने जीवनपर्यन्त के लिये पंजीकरण करवा सके ।

(ब) पंजीकरण को प्रति वर्ष नवा करवाने की पढ़ति को समाप्त करने के लिये सरकार का उक्त दो अधिनियमों में संकोषन करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि यह रेडिस्टर और आंकड़ों को अद्यतन रखने का बहुत अच्छा तरीका है जिसमें भौत, प्रवास, सेवानिवृत्ति आदि जैसी आकस्मिकताओं का चरा चलता है ।

Introduction of Job-oriented Scheme

4830. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

- (a) whether he is considering to introduce any job-oriented scheme under his Ministry during the coming two years;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) the expected jobs that are likely to be created ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Prices of Indian Steel in the World Market

4831. SHRI D. E. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

- (a) whether prices of Indian steel are the lowest in the world market;
- (b) the comparative prices of steel in the world market; and
- (c) whether there is any proposal under Government's consideration to raise the steel prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). Steel prices in the International market fluctuate from time to time depending on many factors. We have sold our steel products at favourable prices in a competitive market.

(c) The Government do not propose to increase the prices of indigenous steel at present.

Postal Stores Department of Orissa

4832. SHRI SRIBATCHA DIGAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) is it a fact that there is only one Postal Stores Department in Orissa whereas in all other States there are more than one; if so, whether there is any proposal to open more postal stores in Orissa and what steps have been taken to implement the same and the place selected for the purpose; and

(b) is there any proposal that the posts of Gazzeted Post-Masters are to be filled up by officiating arrangements throughout the State; if so, the reasons therefor; whether Government have finalised its policy in this regard; if so, when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) At present, there is one Postal Stores Depot in Orissa Circle at Bhubaneswar. Two other Postal Circles viz. Delhi and Jammu and Kashmir have, similarly, only one Postal Stores Depot each. A proposal to set up second Postal Stores Depot in Orissa Circle at Jharsuguda is under examination.

(b) It is not the policy of the Government to make local officiating arrangements in the Gazzeted Posts nor is there a proposal to fill up the Gazzeted post of Postmaster in Orissa Circle on local officiating basis. In the absence of a regular officer, the post has been filled up on officiating basis temporarily.

Modification of the Pilot Nickel Plant

4833. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether modification of the Pilot Nickel Plant and requisite tests etc. have been completed by September, 1977;

(b) whether it has been finally decided to commission the Nickel Plant in Orissa and if so, whether any tender has been called for this construction and if so, when; and

(c) if not, when will it be commissioned ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) to (c) Modifications in the Pilot Plant proposed by M/s Chemical and Metallurgical Design Company Ltd. (C.M.D.C.) were incorporated by them during December, 1976—

May, 1977. Thereafter the tests were taken in hand. Tests were conducted from 31-8-77 to 15-10-77. The report of the tests is awaited. However a preliminary review of the test data indicate that the results of the tests were not satisfactory. The Government has initiated action for the import of foreign technology for the Project.

Amendment of Haj Committee Act

4834. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Haj Committee Act is going to be amended; and

(b) if so, the basic feature of its amendments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): (a) The Haj Committee Act is under active review for possible modifications, to make it more broad-based and representative.

(b) Does not arise, as the Government have not formulated their final views on the subject.

Extra-departmental employees of Post and Telegraph Department in Tamilnadu.

4835. SHRI A. MURUGESAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of extra-departmental employees in Posts and Telegraphs Department District-wise in Tamilnadu;

(d) the number of years for which they are working in that capacity; and

(c) particulars as to when and how their services are proposed to be regularised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of Lok Sabha as soon as it is received.

(c) It is not proposed to regularise their services.

Leakage in reservoir for Sulphuric Acid in Cold Rolling Mill of the BSL

4836. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the reservoir for sulphuric acid in cold rolling mill of the Bokaro Steel Limited made and erected at the cost of Rs. 12 crores by the Simon Carves & Co. has started leaking soon after commissioning;

(b) whether the ovens of the 4 battery of the Cokeoven section of the Bokaro Steel Ltd. have also got damaged within a short period of starting; if so, the reasons therefor;

(c) whether in all those erection, lot of corruption was there which resulted the defects in the plant; and

(d) if so, what steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) No, Sir. Also, the value of the entire block of chemical plant in the Cold Rolling Mill at Bokaro was Rs. 1.65 crores only and not Rs. 12 crores.

(b) No Sir.

(c) No case of corruption in these erections has come to the notice of the Government.

(d) Does not arise.

Membership of Central Trade Union Organisations

4837. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state: What is the total membership of each of the following Central Trade Union Organisations as claimed by themselves and after verification by Government (a) INTUC (b) AITUC (c) HMS (d) CTTU (e) HMP (f) BMS (g) UTUC and (h) UTUC (Lenin Sarani) ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): The claimed membership figures as on the 31st December, 1972 of the organisations concerned (barring AITUC and HMS, which did

not furnish their claim, and HMP which was not addressed) are as follows :—

Name of Organisation	Member-ship
INTUC	22,21,810
CITU	9,12,328
BMS	6,27,968
UTUC	3,62,087
UTUC (Lenin Sarani)	2,48,594
NLO	1,80,416

These claimed figures have not been verified.

The last general verification of membership undertaken was as on the 31st December, 1968, and it was confined to four Central Organisations. The claimed and verified membership figures of these organisations as on that date are as follows :—

Name of the Organisa- tion.	Membership	
	Claimed	Verified
INTUC	20,69,793	13,26,152
AITUC	15,43,320	6,34,802
HMS	7,70,748	4,63,772
UTUC	2,24,667	1,25,754

Post Office Building at Araria, Bihar

4898. SHRI HALIMUDDIN AHMED: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Post Office building at Araria in the District of Purnea in Bihar—a sub-divisional Headquarters is very small and congested and hampering the efficiency of the employees;

(b) if any allotment for construction of a Post Office building was sanctioned by the Bihar Circle, and the amount so sanctioned; and

(c) if so, the action to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) The Post Office building at Araria is congested.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

हिन्दुस्तान चिक लिमिटेड द्वारा आयातित जेनरेटर

4839. श्री जानु कुमार शास्त्री : क्या इस्यात और जान मंदी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो बर्बं पूर्व हिन्दुस्तान चिक लिमिटेड, उदयपुर के लिए सोवियत रूस से एक जेनरेटर का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भारत में आकर यह कितने मूल्य का पड़ा है;

(ग) क्या इस जेनरेटर का अब तक उपयोग नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह जेनरेटर जैसा आया था वैसा डका पड़ा है और आज तक उसको खोला भी नहीं गया है तथा क्या रूस के विशेषज्ञ तकनीशियनों की प्रतीक्षा की जा रही है?

इस्यात और जान मंदी बाबू (श्री करिया लुप्ता) : (क) मैं हिन्दुस्तान चिक लिंग उदयपुर ने अपनी जावर जानों देवारी जस्ता प्राकाशक और विजाव जस्ता प्राकाशक के लिए सोवियत रूस से 5 जेनरेटर मंडाए थे। ये जेनरेटर मई, 1976 से प्राकृतूर, 1977 तक सम्पूर्ण रार्च से किसी भी विस्तृत दृष्टे

(ख) प्रत्येक जेनरेटर की कीमत 25 लाख रुपए है तथा उस पर 45 प्रतिशत आवार शुल्क अलग है।

(ग) और (घ), ये सभी जेनरेटर स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। सभी स्थलों पर सभी विशेषज्ञों की देख-रेख में काम चल रहा है।

Average Earnings of Industrial Workers

4840. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the details of average earnings of the industrial workers; and

(b) the measures being taken by Government to increase their earnings?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Statements I to VI giving available information are laid on the Table of the House. [Placed in library. See No. LT-1448/77]

(b) Apart from fixation and periodic revision of wages in respect of scheduled employments under the Minimum Wages Act, system of Wage Boards, Wage revision committee, etc., is also resorted to for revision of wages. In the organised sector, bilateral agreements on all matters including wages, help in improving the wage levels and earnings of industrial workers.

Arrest of Oil Mill Owners in Delhi

4841. SHRI P. K. KODIYAN : Will the minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether three oil mill owners were arrested in Delhi following the discovery of a racket in imported rapeseed oil; and

(b) if so, the details thereof and the action taken against the culprits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Delay in Publishing Third Digest of Indian Labour Research

4842. SHRI K. RAMAMURTHY : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) when the Third Digest of Indian Labour Research, 1968-72, is likely to be published; and

(b) the reasons for the inordinate delay in publishing it?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b). The

Third Digest of Indian Labour Research, 1968-72, is in the press and the printed copies are likely to be made available to the Labour Bureau, by the end of March, 1978. The publication of the Digest has been delayed on account of constraints such as time taken by the responding agencies in sending the material and its scrutiny, processing and printing.

Implementation of Project Report

4843. SHRI K. RAMAMURTHY : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state the details of Project Reports involving schemes having far reaching effects, prepared with the assistance of International Agencies for the purpose of bringing in distinct improvement in the institutional arrangements of vocational training as stated on page 2 of the Ministry's Annual Report 1976-77 and when they will be implemented?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Yes, Sir. A statement giving the details is enclosed.

Statement

Advanced Vocational Training System. (Vide Para 3.1 of page 2 of the report).

1.1 A project on Advanced Vocational Training System (AVTS) has been launched by the Government of India and State Governments jointly in collaboration with the United Nations Development Programme (UNDP) and International Labour Organisation (ILO). The System envisages training of highly skilled workers and technicians in a variety of advance and sophisticated skills, not available in other Vocational Training Programmes. The project which was commenced in October, 1977, is expected to be completed in four years and six months.

1.2 An agreement on this project was signed by the Government of India, UNDP and ILO on 23rd September, 1977.

The estimated financial costs are as follows :

1. Government of India Rs. 181,830 lakhs.
2. State Governments; Rs. 243,050 lakhs.
3. UNDP/ILO . Rs. 572,467 lakhs.

1.3 The assistance of UNDP/ILO would be in the form of sophisticated equipment and machinery, expertise and fellowship. The Government of India and State Governments would provide necessary facilities; such as buildings, staff and indigenous equipment for implementation of the project. The ILO would be the executing agency.

1.4 The scheme would be introduced in the Advanced Training Institute, Madras and 5 Central Training Institutes for Instructors located at Bombay, Kanpur, Ludhiana, Calcutta and Hyderabad and in 16 selected Industrial Training Institutes. The short-term courses would be geared directly to the needs of the industry. The majority of the trainees have to be from those groups who are already employed, requiring upgrading of skills, retraining or specialization. The total seating capacity of all the Institutes would be 1162. Tentative target for the number of personnel to be trained in the Advanced Training Institutes/Central Training Institutes for Instructors/Industrial Training Institutes by the end of the project period is approximately 12,000.

1.5 The Training is proposed to be imparted in certain selected trades like Process Control Instrumentation, Metrology and Inspection, Tool Design, Heat Treatment, Tool and Die-Making, Indian Standards and Bule Print Reading, Mechanical and Electrical Maintenance, Modern Welding Techniques, etc.

2. Instructional Media & Correspondence Courses Institute. (vide para 3.2 page 2 of the report).

2.1 The results of a study conducted to analyse the causes of failure of apprentices in the All India Trade Test revealed that failure in the subject "Trade Theory" was comparatively high. Non-availability of proper Instructional Material and lack of uniformity in standards of the Instructional Material are amongst the contributing factors for this failure.

2.2 After a study conducted by a SIDA (Swedish International Development Authority) Mission during 1975 on a request from the Government of India, a project document was prepared for setting up an Instructional Media and Correspondence Courses Institute. The Project envisages preparation and dissemination of Instructional Material by experts in the field in a centralised manner to ensure uniformity of standards with the consideration to quality.

2.3 The main production centre is proposed to be located at Kanpur. The facilities in the Regional Directorates of Apprenticeship Training and the Central Training Institutes are proposed to be utilised for preparation and dissemination of the material.

2.4 The project is proposed to be implemented with assistance from the Swedish International Development Authority (SIDA). International Labour Organisation (ILO) is to be the executing agency. The duration of the project as proposed is 3 years 2 months. The project proposal has not yet been approved by the Planning Commission and hence the question of implementation does not arise at present.

3. Skill Testing Certification and Gradation of Industrial Skills. (vide para 3.2 page 2 of the report).

3.1 At present there is no system of Occupational Classification or Gradation of Skill ed Workers, at the national level, even though a review indicates that many similar or identical jobs exist in different industries, workshops etc. A project document was therefore prepared for implementation with assistance of Swedish International Development Authority (SIDA). The International Labour Organisation (ILO) is to be the executing agency.

3.2 The project envisages introduction of skill testing, certification and gradation of Industrial Skills. The pilot project is proposed to be limited to a few selected trades in the machine shop and electrical groups in the industries in and around Bangalore and Poona. The duration of the project as proposed is two years. The project proposal has not yet been approved by the Planning Commission and hence the question of implementation does not arise at present.

4. Vocational Training for Women. (vide Para 4.1 page 2 of the report).

4.1 Based on the Feasibility Study Report of the Swedish Experts, details of the first phase of the Project on Vocational Training Programme for Women were worked out in consultation with ILO/SIDA. Agreement for this Project was formally signed between Government of India and ILO/SIDA on 31st March, 1977. The total cost of this phase of the Project would be Rs. 3.5 crore.

4.2 The Project envisages provision of training facilities in basic skill, advance skill and instructional training in a few selected trades with high employment potential. Short-term specialised courses

are also proposed for upgrading and retraining in selected fields, based on the local demand from industry or voluntary organisations.

4.3 This phase of the Project would help in developing necessary infra-structure in the form of trained instructors, training methodology, curricula and training material for new occupations suitable for women. It would also conduct research studies to identify training needs of women in urban and rural areas with different economic and training levels. The Programme is expected to have a significant impact when the trained Instructors would impart training in various fields to a large number of women in different States all over the Country.

4.4 The existing Central Training Institute for Women Instructors, New Delhi has been upgraded into a National Vocational Training Institute for Women. This Institute was formally inaugurated in May 1977 and started its training activities in advance skill training with the introduction of ad-hoc courses in Secretarial Practice and Dress Making. It offers regular courses in Advance skill training in Dress Making and Embroidery & Needle Crafts. In addition, it continues to impart training in instructional skill in the trade of Cutting & Tailoring.

4.5 Two Regional Vocational Training Institutes one each at Bombay and Bangalore have been set-up in August and October, 1977 respectively. Basic skill training courses have been introduced in three trades viz. Dress Making, Secretarial Practice and Electronics in these Institutes. Advance skill courses and instructional training are proposed to be introduced during next academic session.

Publication of Research Study by National Labour Institute

4844. SHRI K. RAMAMURTHY : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) Whether the National Labour Institute has published for sale the research study in a successful public sector undertaking in Tamil Nadu on Work Innovation in an Organisation; and

(b) whether this research study will be translated in Tamil and other regional languages for circulation among the labour?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) The research study undertaken in the Bharat Heavy Electricals Limited, Tiruchirappalli, has not been published so far.

(b) There are no plans for such translations at present.

पटना में आयोजित योग सम्मेलन में किया गया निर्णय

4845. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कार्यक्रम बना रही है;

(ख) पटना में आयोजित योग सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए हैं; और

(ग) देश में कितने योग केन्द्र हैं तथा सरकार ने उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राजकीय मंत्री (श्री जगदम्भी प्रसाद यादव) :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अनुसन्धान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् निम्नलिखित केन्द्रों को योग में कलीनिकल अनुसन्धान के लिए अनुदान देती रही है :—

(1) भारतीय योग तथा सम्बद्ध विज्ञान अनुसन्धान संस्थान, विपुली ।

(2) शिवानन्द मठ, गोहटी ।

(3) योगिक उपचार एवं अनुसन्धान केन्द्र, जयपुर ।

(4) आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

प्रामीण स्वास्थ्य योजना में जब स्वास्थ्य रक्षकों को योग में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान और विश्वविद्यालय योगाश्रम, नई दिल्ली, जिसे केन्द्रीय सरकार ने योग उपक्रम (प्रबन्ध शहर) अधिनियम, 1977

के अन्तर्गत अपने भविकार में से लिया है, का विकास करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् ने स्कूल और कालेज स्तर पर योग का प्रशिक्षण देने के लिए एक पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है।

(ब) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय समा पट्टन पर रख दी जाएगी।

विदेशी के धर्मार्थ अस्पतालों को वित्तीय सहायता

4846. श्री दयाराम शास्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में धर्मार्थ अस्पतालों की संख्या कितनी है तथा गत दो वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ब) क्या आपात स्थिति के समय से अनेक अस्पतालों को वित्तीय सहायता रोक दी गई है तथा इसको पुनः जानू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य मंत्री (श्री जगद्वी प्रसाद यादव) :

(क) सूचना एकत्र की जा रही है और समा पट्टन पर रख दी जाएगी।

(ख) (i) जी, नहीं।

(ii) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय मिशनों के भवनों के लिए दिया जाने वाला किराया

4847. श्री दयाराम शास्य : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के लिए भारत सरकार ने कितनी इमारतें

किराये पर ली हैं और इनके लिए प्रति वर्ष कितना किराया देना पड़ता है; और

(ब) भारतीय मिशनों के लिए, सरकार ने कितने देशों में इमारतें खरीदी हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुम्हू) : (क) 1-3-1977 को विदेशों में भारतीय मिशनों/केन्द्रों के लिए कुल मिलाकर 1839 परिसर या इमारतें किराये पर थीं। उक्त तारीख तक इनका वार्षिक किराया 5,77,07,612.00 रुपए बनता था।

(ख) भारत सरकार ने 39 देशों में अपने मिशनों/केन्द्रों के लिए इमारतें खरीद ली हैं/बनवा ली हैं जिन पर कुल मिलाकर 5,22,84,627.00 रुपए की लागत आई है।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी

4848. श्री दयाराम शास्य : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और इस कार्य पर सरकार प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च करती है; और

(ब) ऐसे मिशनों की संख्या कितनी है, जिनमें हिन्दी के प्रचार की सामर्थी उसी देश में प्रकाशित की जाती है और उन मिशनों की मंस्त्रा कितनी है, जहां भारत में प्रचार सामर्थी भी जाती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुम्हू) : (क) विदेश-स्थित मिशनों में सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए हमने उन्हें हिन्दी जानने वाले भविकारी तथा निझी सहायताकों के साथ-साथ हिन्दी टाइपराइटर, पुस्तकें, समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं, लिंगाकोन रिकांड तथा चार्ट

भी भेजे हैं। अभी तक इन मर्नों पर कूल खर्च की बजट में अलग से व्यवस्था नहीं हुई। किन्तु उन्हें विविध खर्च में शामिल कर लिया गया है।

(क) चूंकि विदेशों में हिन्दी मुद्रण की मुश्विधा उत्तम नहीं है, इसलिए हिन्दी के प्रसार की सारी सामग्री भारत से भेजनी पड़ती है।

Purchase of Sponge Iron Plant from West Germany

4849. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Government have decided to buy a sponge iron plant from West Germany;

(b) if so, whether MECON does not have the full sponge iron technical know-how;

(c) Whether MECON has been retained by several foreign countries to prepare feasibility studies in regard to sponge iron plants; and

(d) if so, the reasons for getting West German plant for sponge iron making ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARJA MUNDA) : (a) A demonstration sponge iron plant is being set up in Hothagudem (Andhra Pradesh) with the assistance of U.N.D.P. Government of India and Government of Andhra Pradesh will both participate in this project. The plant will be based on the SL/RN technology of Lurgi (West Germany) using 100% Solid Reductant with whom a contract for supply of equipment has also been entered into.

(b) and (d). Though MECON have the capacity of providing consultancy and detailed engineering services, for process know-how, foreign collaboration is required.

(c) MECON have prepared feasibility studies for steel complex based on sponge iron plants for Bangladesh, Dubai and Abu Dhabi. They have also been appointed as Consultants by the Government of Nigeria for a one million tonne integrated steel plant based on sponge iron plant.

Telegrams in Devanagari

4850. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telegrams of all the Indian languages can be sent in Devanagari script; and

(b) if so, what steps are proposed to be taken by the Directorate of Posts and Telegraphs to popularise sending of telegrams in Devanagari script ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The Department has already taken steps to popularise the use of Devanagari script in telegrams through various mass communication media such as advertisements in newspapers, posters, metallic tablets, etc.

Extending Co-operation by Danish Government for Child Care Services for Rural Areas

4851. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) Whether the Danish Government has extended its co-operation regarding the Child Care Services in Rural Areas of India; and

(d) if so, the details regarding the aid and programme in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The Danish Government have expressed their willingness to provide assistance for strengthening of Family Welfare and Maternity and Child Health Services in rural and semi-urban areas in the country.

(b) The object of the proposed project drawn up by this Ministry for this purpose is to promote family welfare through the creation of facilities for the integrated delivery of health, nutrition, Maternity and Child Health and Family Welfare Services closer to the houses of the people in rural areas. The project is designed to cover 10 selected districts in 5 States. It is proposed, among other things, to add an operation theatre and a 6 bedded ward to Taluka/Sub-divisional hospitals, renovate and provide additional equipment at Primary Health Centres and to provide additional sub-centres so that each sub-centre may be able to cover a population of 5000. The proposal is still under consideration.

It is expected that the Government may provide assistance for this project to the tune of about Rs. 10 to 12 crores.

Fragmentation of Estates to avoid Application of Plantations Labour Act

4852. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that the fragmentation of the holdings of Estates into smaller units is taking place all over India in order to avoid application of the Plantation Labour Act;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken to stop such deeds ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) to (c). The All India Plantation Workers Federation has in a representation to Government on 12-11-1977 stated *inter alia* that the Plantations are being fragmented in order to avoid application of the Plantations Labour Act. This aspect will be kept in view while finalising the proposals on the Plantations Labour Amendment Bill which is now before the Rajya Sabha.

Installation for Telex Equipment in Bombay

4853. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of COMMUNICATION be pleased to state:

(a) whether Standard Programme Controlled Exchange (Telex) equipment was procured and installed at Bombay; and

(b) its cost and capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

S.P.C. Telex Exchange in New Delhi

4854. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether provision of SPC Telex Exchange was made for New Delhi Centre; and

(b) if so, its estimated cost thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) A proposal for installing S.P.C. Type Transit Telex exchange at Delhi is under consideration.

(b) The estimated cost of the project is about Rs. 3.7 Crores.

Sino-Indian Relations

4855. PROF. P.G. MAVALANKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he has been recently giving public statements outside the Parliament but inside the country urging for a steady and improved Sino-Indian relationship;

(b) if so, broad details thereof;

(c) whether Government have contemplated as well as taken any concrete steps in this direction during the period March 25, 1977 to December 10, 1977; and

(d) if so, full facts thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): (a) and (b). Foreign Minister has stated that Government of India welcomed steps towards normalisation of relations with China on the basis of the Five Principles, including the principles of reciprocity and mutual benefit.

(c) and (d). In the period March 25 to December 10, 1977, Government have taken a series of initiatives towards normalisation of relations to mutual benefit, including the renewal of trade and shipping links between India and China and promoting exchanges of delegations between the two countries in fields of medicine, agriculture, sports etc. More exchanges on functional grounds to mutual benefit in future in the fields of trade, culture, science and technology are envisaged.

Inviting Representation from Political Parties

4856. PROF. P.G. MAVALANKAR: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government invite representatives of some or all political parties wherever a dialogue on one or more issues of constitutional, political, Legislative matters facing the Parliament and the country is arranged;

(b) if so, full facts thereof;

(c) whether one or more independents, unattached to any Political party, are also invited;

(d) if so, full facts thereof;

(e) if not, why not; and

(f) full details of participants and subjects at such dialogues and meetings which took place between Government and opposition leaders in the years 1974, 1975, 1976 and 1977?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) (a) to (f). Meetings with the representatives of political parties/groups represented in Parliament including some independent members are held, as and when required, to discuss issues of political, constitutional and legislative matters. There are no hard and fast rules in regard to invitations. The purpose is to exchange views with parties concerned. A statement indicating the dates of the meetings, subjects discussed, Leaders/Members invited and Leaders/Members who attended the meetings during the years 1974 to 1977 (upto 20th December, 1977), is laid on the Table of the House [Placed in Library See No. LT-1449/77]

Press and Information Units in Indian Embassies

4857. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether all our Embassies, High Commissions and Diplomatic Missions abroad do possess separate Press and Information units;

(b) if so, full facts thereof;

(c) whether Government propose to strengthen and improve the said units, particularly in the more important of our diplomatic missions abroad; and

(d) if so, when and how?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU) : (a) and (b). All our Diplomatic Missions abroad do not have separate Press and Information Units. A list of the countries where our Missions have full-time officers looking after information work is placed on the Table of the House. In the remaining Missions also, one of the officers devotes usually a good part of his time to press and information work.

(c) and (d). The question of strengthening our publicity units abroad and improvement in their performance is under constant review of the Ministry of External Affairs. The Ministry has appointed a Committee headed by Shri Chanchal Sarkar to look into this matter. The report of the Committee is expected soon.

Statement

List of the countries where Indian Missions have full-time units looking after Information work

1. Accra (Ghana)
2. Addis Ababa (Ethiopia)
3. Ankara (Turkey)
4. Baghdad (Iraq)
5. Bangkok (Thailand)
6. Bonn (Federal Republic of Germany)
7. Brussels (Belgium)
8. Buenos Aires (Argentina)
9. Cairo (Egypt)
10. Canberra (Australia)
11. Colombo (Sri Lanka)
12. Dacca (Bangladesh)
13. Dar-es-Salam (Tanzania)
14. Djakarta (Indonesia)
15. The Hague (Netherlands)
16. Hong Kong (Hong Kong)
17. Islamabad (Pakistan)
18. Kabul (Afghanistan)
19. Kathmandu (Nepal)
20. Kuala Lumpur (Malaysia)
21. Kuwait (Kuwait)
22. Khartoum (Sudan)
23. London (U.K.)
24. Lusaka (Zambia)
25. Moscow (USSR)
26. New York—PMI (USA)
27. New York—CGI (USA)
28. Nairobi (Kenya)
29. Ottawa (Canada)
30. Paris (France)
31. Prague (Czechoslovakia)
32. Peking (China)
33. Port of Spain (Trinidad & Tobago)
34. Rome (Italy)
35. Rangoon (Burma)
36. Rabat (Morocco)
37. Seoul (Republic of Korea)
38. San Francisco (USA)
39. Singapore (Singapore)
40. Tehran (Iran)
41. Tokyo (Japan)

42. Thimpu (Bhutan)
43. Vienna (Austria)
44. Washington (USA)
45. Warsaw (Poland)
46. Jeddah (Saudi Arabia)
47. Lagos (Nigeria)

भिलाई इस्पात संयंत्र के अन्तर्गत दिल्ली, राजहरा, नन्दनी लौह अधिक खानों में ठेकेदारी प्रधा के अन्तर्गत काम कर रहे मजदूर

4858. श्री भोहन भैव्या : क्या संसदीय कार्य तथा अम मंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित दिल्ली, राजहरा, नन्दनी आदि लौह अधिक खानों में ठेकेदारी प्रधा के अन्तर्गत कितने मजदूर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन ठेकेदारों ने ठेका अम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के उपर्यांतों के अन्तर्गत लाइसेंस ले रखे हैं तथा क्या वे लाइसेंसों की शर्तों का पालन कर रहे थे और

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक किन सुविधाओं के अधिकारी हैं तथा ठेकेदार इनको क्या सुविधाएं दे रहे हैं ?

अम और संसदीय कार्य भंडालय में राज्य मंडी (श्री लारंग साय) : (क) से (ग). सूचना एकदम की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान स्टील कन्ट्रोलर लिमिटेड द्वारा दिया गया ठेका

4859. श्री भोहन भैव्या : क्या इस्पात और खान मंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हिन्दुस्तान स्टील बर्कर कन्ट्रोलर लिमिटेड में कार्यालय ठेकेदारों का और प्रधा है और प्रत्येक ठेकेदार को किस-किस काम के लिए कितने-कितने भूत्य के तेके दिए गए हैं ?

इस्पात और खान भंडालय में राज्य मंडी (श्री करिया भूत्य) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Complaints for overcharging of Telephone Bills in Metropolitan Cities

4860. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of complaints for overcharging of bills for the telephones in all the Metropolitan cities of the country, separately in the last 3 years;

(b) in how many cases these complaints were found genuine;

(c) whether Government are aware that in many cases either the telephone bills were not sent at all or the amount of telephone bill was much less;

(d) if so, the details thereof in the last 3 years; and

(e) what specific steps Government have taken in the last 6 months to avoid overcharging, under-charging and for not sending the bills properly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) The number of complaints for overcharging of bills for telephones in the metropolitan cities of the country for the last 3 years are as follows:—

	1974-75	1975-76	1976-77
Bombay	18,821	19,426	30,035
Calcutta	2,747	6,677	21,085
Madras	3,720	5,421	6,755
New Delhi	7,170	8,970	11,550

(b) The number of complaints found genuine is as follows:—

		1974-75	1975-76	1976-77
Bombay	.	786	1,349	1,118
Calcutta	.	505	1,132	3,161
Madras	.	259	965	580
New Delhi	.	1,220	1,980	1,920

(c) to (e). Billing is computerised in all the Metropolitan telephone districts. A list of the telephone numbers for which bills are not prepared by the computer for want of master data, is produced by the computer. This list is examined and bills are issued manually thereafter wherever due. A watch is kept on the disposal of these non-issue lists. A few instances do arise where delay occurs in feeding master data due to late receipt of completed Advice notes and the subscribers remain unbilled. However in Delhi Telephone District there is a general delay of about two months in the issue of bills due to non-availability of computer time. Contract has now been awarded to an other computer agency on 30-11-1977 to ensure timely issue of bills. As on 1-12-1977 items pending for issue of bills were 820; in respect of bills due to be issued upto 31-3-1977.]

Billing is computerised and hence human errors are avoided.

Fortnightly meter readings are taken.

फाइलरिया रोग का निवान/नियंत्रण

4861. श्री घर्मसिंह चाई पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाइलरिया रोग पर नियंत्रण करने के लिए कोई धोषणीय अवधा इंजेक्शन का पता लगाया गया है;

(ख) इस धोषणीय अवधा इंजेक्शन का नाम क्या है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें फाइलरिया रोग का प्रभाव विशेष रूप से धूम्रिक है; और

(घ) फाइलरिया रोग के उन्मूलन के कार्यक्रम का व्यूहार क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगद्वारी प्रसाद यादव) :

(क) और (ख). यद्यपि फाइलरिया पर काढ़ा पाने के लिए भारत में और अन्य स्थानों पर अनेक नई धोषणीयों से परीक्षण किए जा रहे हैं तथापि अमरीका में 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खोज की गई डाइफिल्कार्बनियाइन ही एक दवा है जिसे इस संक्षण को कम करने और इस रोग के प्रसार का नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) भान्ध प्रदेश, विहार, केरल, उडीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अनेक धूम्रिकों को यह रोग है या उनमें इस रोग के कीटाणु हैं।

(घ) इस देश में उपलब्ध जानकारी एवं तकनीक से तथा व्याप्त परिस्थितियों में इस रोग का उन्मूलन करना तो सम्भव नहीं है, परन्तु इसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय फाइलरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस रोग को फैलाने वाले मछुर पैदा न हों, इसके लिए लावनियाशी उपाय बरते जाते हैं तथा जिन धूम्रिकों के लारीर में इस रोग के कीटाणु होते हैं, उनका पता लगाकर उनका उपचार किया जाता है। प्रयोग के रूप में इस कार्यक्रम को भान्ध प्रदेश, गुजरात और उत्तर

प्रदेश के चुनिदा ग्रामीण लोकों में भी चलाया गया है। फाइलेरिया नियंत्रण का स्थायी उपाय तो पर्याप्त और कारगर जल निकास में निहित है, किन्तु इसके लिए दिपुल धनराशि की आवश्यकता है। जिन शहरी लोकों में फोइलेरिया फैला हुआ है, उनमें जल निकास कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।

मांगरोल नगर (जूनागढ़) को पोरबन्दर, बेरावल, बम्बई, भावनगर और राजकोट से सीधी टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाना

4862. श्री घर्मसिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य जूनागढ़ जिसे में मांगरोल नगर को पोरबन्दर, बेरावल, बम्बई, भावनगर और राजकोट से सीधी टेलीफोन लाइन से कब तक जोड़ा जाएगा;

(ख) क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक मांगरोल शहर को सीधी टेलीफोन लाइन द्वारा किन-किन नगरों से जोड़ दिया गया है?

संचार भंडालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) मांगरोल और राजकोट के बीच सीधा ट्रूक सर्किट पहले से ही मांजूद है। वर्तमान यातायात के प्राधार पर मांगरोल से पोरबन्दर, बेरावल, बम्बई और भावनगर के लिए सीधा ट्रूक सर्किट देने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

(ख) मांगरोल और केशोड के बीच एक 8 बीनल प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि प्रतिरक्षित और भागामी मार्गे पूरी की जा सकें।

(ग) मांगरोल शहर से जूनागढ़, केशोड, राजकोट, माषपापुर और बील के लिए सीधा सर्किट पहले ही उपलब्ध है।

पोस्टल सील्स कोशापरेटिव यूनियन और डाक तथा तार विभाग के बीच करार

4863. श्री मवाद तिह औहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्तीगढ़ पोस्टल सील्स को-प्रापरेटिव यूनियन और विभाग ने गत वर्ष के प्रत्यन्त में करार पर हस्ताक्षर किए थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ख) यह कोशापरेटिव यूनियन कब से भोहरें बनाने का काम कर रही है और क्या सरकार ने जांच करने के बाद इसके दबाकर्मियों की मजूरी निर्धारित की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार भंडालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी, नहीं।

(ख) भर्तीगढ़ की डाक सील शोदोगिक सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। यह समिति तभी से डाक सीलों का निर्वाचन कर रही है। कुणल श्रमिकों की मजूरी तय करने का मसला समिति और उसके मदस्यों के बीच का एक मसला है।

गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में डाक टिकट

4864. श्री मवाद तिह औहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में दो बार डाक टिकट जारी किए गए थे;

(क) यदि हों, तो क्या दोनों बार फिलार्टिलिक कमेटी ने उसकी स्वीकृति दी थी और यदि हों, तो किस भाषार पर;

(ग) फिलार्टिलिक कमेटी के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या ऐसी डाक-टिकट जारी करने के बारे में कोई मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) यदि हों, तो तस्वीरन्धी व्यौरा क्या है और क्या उन मानदंडों के अनुसार महापुरुषों की शताव्दियां भनाने के अवसर पर उनकी स्मृति में दो बार डाक-टिकट जारी करने को अनुमति नहीं है; और

(ङ) यदि हों, तो गत दो महीनों में इस मंबंध में किन-किन के तथा कितने प्रावेदन पर इस भाषार पर खारिज किए गए हैं?

संचार यंत्रालय में राज्य मंडो (बी नरहरि प्रसाद मुख्यमंत्री साय) : (क) जी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास पर केवल एक बार 1-10-52 को 1 आने मूल्य का डाक-टिकट जारी किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). रिष्टली फिलेटली सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नई समिति का गठन किया जा रहा है।

नीति-निर्देशक सिद्धांतों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। इनके अनुसार कुल 24/25 डाक-टिकटों में से प्रसिद्ध व्यक्तियों पर निकाले जाने वाले स्मारक डाक-टिकट 6 से अधिक नहीं होने चाहिए।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विवेद/स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए निर्वाचित नीति-निर्देशक सिद्धांत

1. भ्रासामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, स्मारक डाक-टिकट जारी करने के किसी प्रस्ताव पर ध्यातीर

पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा; जब तक उसके संबंध में विभाग को 18 महीने पहले सूचना न दे दी जाय।

2. किसी व्यक्ति के सम्मान में सामान्यतः स्मारक डाक-टिकट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी 100वीं जयंती या बरसी का अवसर न हो। किसी व्यक्ति की पहली या 100वीं बरसी पर भी स्मारक डाक-टिकट जारी किया जा सकता है।
3. किसी भी घटना के उपलब्ध में स्मारक डाक-टिकट सामान्य रूप से तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी अर्धशताब्दी या शताब्दी का अवसर न हो। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर ही विशेष डाक-टिकट जारी करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाय। अन्य घटनाओं की स्मृति में केवल विशेष कैसिलेजन जारी किए जाये।
4. किसी वर्ष में जारी किए जाने वाले हाक-टिकटों में से (24/25 डाक-टिकटों से अधिक नहीं) प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जारी किए जाने वाले स्मारक डाक-टिकटों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. साहित्य अकादमी की राय ले लिने के बाद ही साहित्यकारों पर डाक-टिकट जारी किए जाने के प्रस्तावों पर विचार किया जाए।
6. अत्येक डाक-टिकट जारी करने की योजना पर, सामान्यतया, जारी करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले कारंवाई बुह कर दी जाए और डाक-टिकट की डिजाइन बनाने तथा उसके भुदण के लिए भारतीय मुख्य ब्रेस को पूरे छह महीने का भवय दिया जाय।

Charges against Director, Central Research Institute for Ayurveda, Patiala

4864. DR. BALDEV PRAKASH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether his Ministry have received any complaints against Director, Central Research Institute for Ayurveda, Patiala, regarding corruption, mis-appropriation of funds, illegalities and multifarious irregularities and abuse of power and if so, what action has been taken by Government so far against the said officer and if not, the reasons for delay;

(b) whether any enquiry has been ordered or conducted against the said officer by Government and if so, what is the result of the enquiry report and the action proposed in it by the enquiry officer;

(c) whether the said officer was taken from Punjab Cadre, and if so, whether the post was advertised and the qualifications prescribed; and

(d) the qualifications of the said officer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Yes. An on-the-spot preliminary enquiry has been conducted by an officer of the Ministry of Health and Family Welfare. A note on a secret enquiry on the complaint has also been furnished by the C.B.I. separately. These reports are under consideration. Orders of revision of Shri Keerti Sharma were issued on 9th December, 1977 and he has since been relieved of his charge.

(c) Yes. Initially a post of Project Officer was allowed for the Central Research Institute (Ayurveda) Patiala by the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy. Meanwhile the Executive Committee of the Council also sanctioned a post of Director in the pre-revised scale of Rs. 1100—1400 at its meeting held on 24th November, 1970 and recruitment rules for this post were also approved. However, the appointment of Director for Central Research Institute (Ayurveda), Patiala was not taken up as the appointment of Shri Keerti Sharma as Project Officer for this Institute had meanwhile been approved by the Vice-President of the Council.

The post of Project Officer was not advertised as the Central Council for Re-

search in Indian Medicine and Homoeopathy had at that time not framed recruitment rules for the post of Project Officer, Central Research Institute (Ayurveda), Patiala, against which Shri Keerti Sharma was appointed, on deputation basis, with the concurrence of the Government of Punjab, with effect from the 26th February, 1971. His appointment was also approved by the Executive Committee of the Council at its meeting held on 3-7-1971. A proposal for setting up of three more Central Research Institutes for Ayurveda in the various regions alongwith the staffing pattern which *inter-alia* included post of a Director in each Institute, was approved in the scale of Rs. 1100—1400 by the Executive Committee at its meeting held on 24-11-1970. However, the scale of pay of post of Director was upgraded from Rs. 1100—1400 to Rs. 1300—1600 by the Executive Committee at its special meeting held on 11th February, 1971. Accordingly, the post of Project Officer, Central Research Institute for Ayurveda, Patiala, was converted into that of Director. However, Shri Keerti Sharma continued as Project Officer on deputation, on the same terms as before. The recruitment rules for the post of Director, Central Research Institute (Ayurveda) were subsequently modified by the Executive Committee at its meeting held on 5-3-1973. The posts of Director, Central Research Institute (Ayurveda), Patiala and the Central Research Institute (Ayurveda) Choruthuruthy were advertised on an all India basis in March, 1973. Even though the recommendations of the Selection Committee were approved by the Executive Committee at its meeting held on the 30th March, 1974, yet these could not be implemented due to certain objections raised by a Member of the Governing Body of the Central Council of Research in Indian Medicine and Homoeopathy. This matter was reconsidered at the 12th meeting of the Executive Committee of the Council, held on 19th October, 1974 and the President of the Council decided to meet the selected candidates but no such meeting took place. As no appointment was done for the post of Director, Central Research Institute (Ayurveda), Patiala, the deputation period of Shri Keerti Sharma was extended further upto the 6th February, 1976, with the approval of the Executive Committee. Later, it was decided to depute Shri Keerti Sharma to the post of Director, National Institute of Ayurveda, Jaipur, with effect from the 7th February, 1976 where he served for about 6 months. On reversion from the post of Director, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Shri Keerti Sharma was appointed as Director, Central Research Institute (Ayurveda), Patiala in the scale of Rs. 1500—1800 on fresh deputation basis for a period of 2 years with effect from 25th August, 1976. This appointment

was made with the concurrence of the Government of Punjab. Steps are being taken to advertise the post of Director, again.

(d) On the basis of the information furnished by Shri Keerti Sharma, he possesses the following qualifications:—

1. Ayurvedacharya (Degree in Ayurveda) from Board of Examination, Ayurvedic Department, PEPSU Government, Patiala.
2. Honours in Sanskrit (Shastri) from Punjabi University.
3. M.A. (Hindi) from Punjab University.

Telex Facilities for Export of Mica from Giridih (Bihar)

4866. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Giridih (Bihar) is famous for mica trade in the world and foreign exchange to the tune of about Rs. 40 crores is earned from mica exports to the various countries of the world:

(b) whether in the absence of telex facilities, the headquarter of Export Trade of the Mica Trade Corporation of India has to incur unnecessary expenditure on the telex facility which is available in Patna, 200 miles away from the mica area:

(c) whether 14 mica exporters of Giridih and the Mica Trade Corporation of India have applied for the provision of telex facility in Giridih and many traders have expressed their desire to take telex lines connections:

(d) if so, whether Government propose to provide telex facility in Giridih for the development of mica trade and coal mine industries there; and

(e) if so, by what time?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDÉO SAI) (a) to (e). Giridih is a well-known mica trading centre and substantial foreign exchange is earned through mica export.

12 parties including Mica Trade Corporation of India have recently applied for telex connections at Giridih. A project for installation of a 20-line telex exchange at Giridih is under examination. It is hoped that a new telex exchange can be commissioned in 1979, and connections provided to all these parties.

A telex exchange is working at Dhanbad, situated about 50 Kms. from Giridih. Any intending subscriber at Giridih desirous of obtaining connection urgently, can be provided such connection from this telex as a long distance connection.

Friendly relations with S.E. Asian Countries

4867. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Ministry of External Affairs have drawn up any socio-cultural plan for strengthening friendship with Governments and peoples of the S.E. Asian countries;

(b) if so, the facts thereabout;

(c) whether any cultural exchanges have been made with these countries during 1977;

(d) whether programme for exchange of teachers, students, scholars, artists and men of culture between India and the S.E. Asian countries have been drawn up;

(e) if so, the facts thereabout;

(f) whether India will set up new centres of culture and strengthen the existing cultural institution in these countries; and

(g) if so, the facts thereabout?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU). (a) and (b). The Government propose to sign cultural agreements with all countries in S.E. Asia with which we do not have such agreements at present and to follow up all such cultural agreements with bilaterally agreed time-bound cultural exchange programmes. Moreover, the recent Conference of Heads of Indian Missions in South-East and East Asia in August 1977 made a number of useful recommendations to the Government for promoting cultural relations. These recommendations have generally been accepted and some of them are already under implementation. The Government have also appointed an Evaluation Committee under Shri Ashoke Mehta to Evaluate the performance of the Indian Council for Cultural Relations and to suggest guidelines for its future activities. The Government hope that the Council shall become a more active instrument for promoting cultural relations with South East Asia.

(c) Yes, Sir. These exchanges have covered visits by writers, scholars, journalists and artists, holding of art exhibitions and presentation of books and objects of art, as well as deputation of Indian academicians to foreign universities.

(d) and (e). Detailed programme is under preparation by the ICCR and in the Department of Culture, wherever feasible.

(f) and (g). Yes, Sir. As for establishment of Indian cultural centres in South-East Asia, the Government would like to set up such centres, wherever practicable. The Government would also give due consideration to any request from cultural institutions in the region for projects which would strengthen cultural contacts with India.

Quantity of Calcium Ammonium Nitrate supplied to Orissa and Andhra Pradesh

4868. SHRI SARAT KAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the total quantity of Calcium Ammonium Nitrate supplied to Orissa and Andhra Pradesh during last three years from the Rourkela Fertiliser Plant;

(b) what are the basis of allocation of such quantities to the different States; and

(c) whether the profitability in marketing in the nearest zone to the Plant has been taken into consideration or not?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) The quantity of Calcium Ammonium Nitrate (CAN) supplied to the States of Orissa and Andhra Pradesh from the Rourkela Fertilizer Plant during the years 1974-75 to 1976-77 is indicated below:—

Quantities supplied
(In tonnes)

	Orissa	Andhra Pradesh
1974-75 . . .	61,090	65,569
1975-76 . . .	60,379	160,562
1976-77 . . .	69,469	121,095

(b) and (c). The allocation of CAN to the different States is made by Government after taking into account agro-economic requirements, supply plan given

by the manufacturers and the past pattern of distribution. In the supply plan, the consideration of profitability in marketing in the nearest zone is also aimed at, subject to development of a diversified market in different States to meet changing marketing conditions.

आक तथा तार विभाग द्वारा डाक्टरी जांच कराये विना पालिसी देना

4869. श्री हरयोदिन वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की रुपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सब है कि डाक तथा तार विभाग डाक्टरी जांच कराये विना डाक जीवन बीमा पालिसी दे रहा है ; और

(ब) यदि हां, तो कब से तथा कितनी राशि तक की पालिसी दी जाती है ?

संचार विभाग में राज्य बंदी (श्री नरहरि प्रसाद तुलादेव साय) : (क) जी हां ।

(क) विना डाक्टरी जांच के डाक जीवन बीमा योजना 1-6-1972 से चालू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत बीमा की प्रतिक्रिया सीमा 4000 रुपये है।

दलित पूर्व एवियाई राष्ट्र एसोसिएशन (एसीए) को संनिक गठबोड़ में बदला

4870. श्री हरयोदिन वर्मा : क्या विवेत मंत्री यह बताने की रुपा करेंगे कि :

(क) क्या दलित पूर्व एवियाई राष्ट्र एसोसिएशन को संनिक गठबोड़ में बदला जा रहा है ; और

(ब) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विवेत मंत्रालय में राज्य बंदी (श्री एस० तुम्हूँ) : (क) सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी नहीं है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

ठाक जीवन बीमा पालिसी पर ज्ञान देना

4871. श्री हरगोदिल्ल बर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाक जीवन बीमा पालिसी पर पूर्व ज्ञान बकाया रहने पर भी पुनः ज्ञान दे दिया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1976-77 में इस प्रकार कितना ज्ञान दिया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (जी नरहरि प्रसाद मुख्यमंत्री साय) : (क) जी हाँ ।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान कुल 80,09,633 रुपये का ज्ञान दिया गया था । दूसरा ज्ञान मंजूर करते समय पिछले ज्ञान की रकम और उस पर देय रकम का समायोजन कर दिया जाता है और केवल शुद्ध रकम का भुगतान किया जाता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दूसरी बार दिए गए ज्ञान के पांकड़े भलग से नहीं रखे जाते ।

Geological Survey of Sidhi Distt. of M.P.

4872. SHRI SURYA NARAIN SINGH: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Geological Survey of India is carrying out survey in Sidhi District of M.P. for exploring the possibility of mineral in the area for the last 10 years;

(b) if so, whether any success has been achieved so far; and

(c) if not, what is the use for wasting money for the work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Yes, Sir.

(b) The assessment of coal deposits in the part of the Singrauli coal field in M.P. has indicated a large reserve of about

1350 million tonnes of coal in Sidhi district of M.P. Investigation for copper in Byraib-Bahartola area was initiated in 1973-74 and is still in progress as preliminary results warrant further exploration

(c) Question does not arise.

Financial assistance to Bhutan

4873. SHRI P. RAJAGOPAL NAI-
DU: Will the Minister of EXTERNAL
AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government gave financial assistance for Five Year Plan of Bhutan;

(b) if so, the assistance given; and

(c) the purposes for which the assistance was given?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): (a) Yes, Sir.

(b) The total assistance envisaged by the Government of India for Bhutan's Fourth Five year Plan (1976-1981) which is now in its second year of implementation, is in the region of approximately Rs. 70 crores.

(c) In keeping with the traditional and specially close links of friendship between India and Sovereign Independent Bhutan, the financial assistance from the Government of India has contributed to the building up of infrastructure in Bhutan including the fields of agriculture, animal husbandry, education, forestry development and small industries. Apart from Govt. of India's assistance towards Bhutan's Five Year Development Plans, Govt. of India have undertaken to build a cement plant on turn-key basis and a hydro-electric power plant for the mutual benefit of India and Bhutan.

झमेठी में विशेष टेलीफोन सेवा पर किया गया ज्ञान

4874. श्री सुभाष भारूजा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र श्री संजय गांधी के बुनाव क्षेत्र झमेठी मुलतानपुर में विशेष टेलीफोन सेवाओं का जाल बिला दिया गया था ;

(ब) यदि हां, तो संचार मंत्रालय में उस अधिकारी का नाम क्या है जिसके आदेश पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाही की गई और यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अमेठी निर्बाचिन लेब से बातचीत करने के लिए श्री संजय गांधी को हाट लाइनें प्रदान की गई थीं और यदि हां, तो किस आधार पर की गई थीं और अन्य निर्बाचिन लेबों में ऐसी सुविधा प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ी ; और

(घ) क्या इम मंत्रालय के अधिकारी 8 और 13 मार्च के बीच दिल्ली से रायबरेली और अमेठी जाते रहे थे और यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं और उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य बंडी (जो नर-हरि प्रसाद मुख्यमंत्री लाय) : (क) चुनाव के कारण अनियन्त्रित ट्रंक यातायात का निपटारा करने के लिए अमेठी में केवल एक ट्रंक बोर्ड और दिल्ली व मुम्बानपुर के बीच एक ट्रंक मॉकिट की व्यवस्था की गई थी ।

(ब) संचार की यह व्यवस्था मॉकिट प्रध्यक्ष ने उहूं सौंपे गए अधिकारों और दाव-नार महानियों के तारीख 3-2-77 वे परिवर्त सं० 5 में दिए गए दिना-नियों का प्रयोग करते हुए की थी ।

(ग) ऐसी कोई हाट लाइन नहीं दी गई थी ।

(घ) 8 और 13 मार्च, 1977 के बीच मंत्रालय के किसी भी अधिकारी ने इन दोनों स्थानों का भौपत्तारिक रूप से दौरा नहीं किया था ।

T.B. symptoms in school going children of Madras

4875. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether T. B. symptoms have been noticed in a large number of the school going children and even amongst children from affluent families in the Madras schools; and

(b) if so, the measures taken to protect the children from this disease?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The information is being collected from the Government of Tamil Nadu and will be laid on the Table of the Sabha.

Publication of list of Medicines for Reimbursement

4876. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the list of approved Ayurvedic, Unani and Siddha Pharmacies published by Government for the purpose of reimbursement of the cost of medicines for Central Government employee, the name of Shri Aurobindo Asharam Ayurvedic Pharmacy does not find a place ;

(d) if so, whether Government propose to rectify the omission; and

(c) if not, the reason therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Under the existing procedure, the Pharmacies in Indian Systems of Medicine and Homoeopathy (including Ayurveda, Unani and Siddha) are approved on the recommendation of the State/Union Territory Governments. The Union Territory of Pondicherry has not sent any proposal for the inclusion of the name of Shri Aurobindo Asharam Ayurvedic Pharmacy in the approved list. If that Govt. sends the proposal, the same will be considered.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना और अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों की पदोन्नति

4877. श्री दयाराम शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 17 नवम्बर 1977 के ग्रन्तारांकित प्रश्न संख्या 762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना और अस्पतालों में काम कर रहे फार्मासिस्टों की संख्या कितनी है, जिनकी योग्यता हाई स्कूल से कम है और जिन्होंने अनुभव के प्राधार पर अपना पंजीकरण कराया है ;

(ख) उन डॉक्टरों को फार्मासिस्टों के पदों पर पदोन्नति करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, जो बैंडिक्युलेट हैं और जिनकी सेवा 10 वर्ष से अधिक हो गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के होम्योपैथिक औषधालयों में काम करने वाले फार्मासिस्टों की नियुक्ति केवल अनुभव के प्राधार पर होती है, न कि डिप्लोमा के प्राधार पर और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्भी प्रसाद यादव) :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में काम करने वाले एम्स फार्मासिस्टों की संख्या क्रमशः 29 और तीन है जिनकी योग्यता हाई स्कूल से कम है और जिन्होंने अनुभव के प्राधार पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वित्तगढ़न अस्पताल, नई दिल्ली में ऐसा कोई फार्मासिस्ट नहीं है।

(ख) डॉक्टरों को फार्मासिस्टों के पदों पर पदोन्नति करने का कोई प्रस्ताव

नहीं है क्योंकि फार्मासिस्टों के लिए निर्धारित भर्ती नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) होम्योपैथिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति उनके अनुभव के प्राधार पर की जाती है, क्योंकि उनके लिए कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं है।

Shortage of beds in the Hospitals of Delhi[1]

4878. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) is Government aware of the fact that there is an acute shortage of beds in hospitals in Delhi;

(b) is it also a fact that there is no co-ordination between the hospitals run by the Central Government, Delhi Administration and Municipal Corporations; and]

(c) if yes, the steps taken by the Government to have proper co-ordination and to provide more beds for the patients?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The availability of beds in the hospitals in Delhi is three per thousand population, as against one bed for four thousand population for the country as a whole.

(b) and (c). No, Sir. A Hospital Board has been constituted under the Chairmanship of Lieutenant Governor, Delhi to coordinate health and medical care services in the capital.

पहाड़ी तथा बर्फीले जलों में डाक का बांटा जाना

4879. श्री रामानन्द तिकारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और बर्फीले जलों में साथा दाकघरों में गैर-विभागीय पोस्टमास्टरों को नांद-नांव और चर-चर पैदल जाकर स्वयं डाक बांटनी पड़ती है ;

(ख) क्या ऐसे स्थानों पर जाक्षां डाकघरों के पोस्टमास्टरों की सहायता के लिए सरकार का विचार पूर्णकालिक कर्मचारी भववा डाकिया नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए निर्णय की मुद्रण बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संवार मंदिरालय ये राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद मुकुदेव जाय्य): (क) विधानसभा जाक्षा पोस्टमास्टरों को, गांवों में, जिनमें पहाड़ी और बर्फीले इलाके भी जामिल हैं, डाक वितरण का काम केवल ऐसे मामलों में सौंपा जाता है जिनमें कार्यभार के आधार पर अलग से वितरण एंडेंटों/शामीण पोस्टमैनों का धोखित्य नहीं सिद्ध होता। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में, समान्यतः डाक-वितरण संबंधी काम बहुत कम रहता है।

(ख) सामान्यतौर पर वितरण एंडेंटों के अलग से पद ऐसे सभी डाक घरों के लिए मंदूर कर दिए जाते हैं जहाँ कार्यभार के आधार पर इन पदों का धोखित्य सिद्ध होता है।

(ग) और (घ), उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखने हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

Indian Red Cross Society

4880. SHRI UGRASEN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 5 on 24-6-1977 regarding disappearance of eight blank cheques in 1975 and subsequently a sum of about Rs. 52,000 found, withdrawn from the Red Cross Society, New Delhi's account with the State Bank of India and state:

(a) was any action taken against persons responsible for safety of cheque books;

(d) whether in a raid by Delhi Excise Department, large quantity of liquor was found in June, 1977, at the Red Cross Society, New Delhi's premises without licences; if so, full report about the same;

(c) whether there is age limit for retirement in Red Cross Society and what is the age of the present Secretary General;

(d) why Lok Sabha polling day i.e. 16th March, 1977, in Delhi was not declared a holiday in Red Cross Society, New Delhi; and

(e) who opened the newly constructed marble Red Cross building and what the tablet reads?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The case is under investigation by the Police. However, the bankers have provisionally paid to the Society a sum of Rs. 50,100 withdrawn from the Society's account under forged signatures in February/March, 1975. !

(b) There has been no raid whatsoever by the Delhi Excise Department at the Red Cross Society's premises.

(c) Yes. Ordinarily, the age of retirement of the regular employees of the Society is 60 years but the Society may, in special circumstances, continue or employ a person beyond that age. The age of the present Secretary-General of the Society is 68 years.

(d) The office of the National Headquarters was closed on the Lok Sabha polling day i.e. March 16, 1977 and some workers who were engaged on urgent work were also asked to take time off to cast their votes.

(e) The then acting President of India who is also the President of the Indian Red Cross Society opened the newly constructed headquarters building of the Society on 25-6-1977.

The tablet bears the words "Opened by Shri B. D. Jatti, President of India, on 25th June, 1977".

Low pay to extra Departmental Post Masters

4881. SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA: Will the Minister OF COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Extra-Departmental Post Masters working in remote rural areas draw the lowest pay, when Government have decided the minimum salary policy;

(b) what is the total number of employees working in the extra Departmental Post Offices;

(c) whether Government are sympathetic to raise their pay; and

(d) if so, what will be their pay and when they are to get it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Considering the fact that the Branch Postmasters work for only limited hours a day the allowance payable to them is not considered inadequate.

(b) As on 31-3-77 the total number of Extra Departmental agents was 222495.

(c) and (d). The wage structure of the Branch Postmasters is under review.

Cost of Production of a pair of Rail Wheel

4882. SHRI ISUKHENDRA SINGH: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the cost of production of one pair of rail wheels with axle and at what price they are sold to the Railways; and

(b) the cost of production of one ton of steel in the various steel plants and at what price it is being exported?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). The cost of production of different categories of steel varies from plant to plant depending on several factors like product mix, capital cost etc. Similarly, the export prices for different categories of steel are subject to fluctuations depending on International market conditions. Railways are being supplied a pair of rail wheels with axle at a price of Rs. 4308 (exclusive of excise duty and JPC cess).

अलीगढ़ पोस्टल सील्स संगठन का कार्यालय

4883. श्री नवाब सिंह जौहान: क्या संचार मंत्री यह बताने की हुया करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ पोस्टल सील्स कोआपरेटिव सोसायटी/संगठन के श्रमिकों के कार्य करने का स्थान न हवादार

है और न ही वहां रोजनी और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का विचार इन समस्याओं को तुरन्त हल करने का है तथा अम कल्याण सम्बन्धी अन्य मुदियाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

संचार अंकालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद मुख्यमंत्री साय) : (क) सोसाइटी के श्रमिकों के लिए जो शेड बनाए गए हैं, उनमें य प्रति पंखों और बत्तियों के ब्वाइंट नहीं लगे हैं, फिर भी यह कहना सही नहीं है कि वे हवादार नहीं हैं या उनमें रोजनी अपर्याप्त है।

(ख) यह सोसाइटी एक स्वतंत्र सहकारी संस्था है और यह डाक-तार विभाग के नियंत्रण में आने वाली एक इकाई नहीं है। इसलिए, अपने कर्मचारियों के कल्याण के बारे में ध्यान देना सोसाइटी का काम है।

Setting up of an Export oriented Aluminium Plant in M.P.

4884. SHRI SURYA NARAIN SINGH: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Russian experts have submitted a report to government for setting up an export oriented aluminium plant in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details therein; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) to (c). A feasibility report was got prepared by a Soviet agency for setting up an export-oriented alumina plant based on Mainpat bauxite deposits. The feasibility report concluded that the exploitation of these deposits would not be economical for export of alumina. It was, therefore, not possible to proceed further in the matter.

Threatening Letter to Indian High Commission.

4885. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that country's High Commission in London have been threatened for assassination in case a person who is being tried in Srinagar on charges of Bank robbery and murder, is not released immediately;

(b) if so, his reaction in the matter; and

(c) the steps proposed to be taken for the security of the High Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU) :

(a) An anonymous message recorded in a cassette tape was received by our High Commissioner in London on 8th November, 1977 threatening his life if a person who was convicted in 1968 in Jammu and Kashmir for armed dacoity and murder was not released immediately. This person had managed to escape from jail on 8/9 December, 1968 and was rearrested in June, 1976 when he, alongwith two other persons, attacked a Bank in Jammu and Kashmir and murdered the Bank Manager.

(b) The case is being dealt with under the process of Law.

(c) Basically, the provision of security for personnel and property of Embassies, High Commissions, Consulates, etc., is the responsibility of the host Governments. For our part, we have advised all our Missions to observe and intensify all departmental security measures and to keep in close liaison with the local foreign offices and security agencies. In selected Missions, home-based security staff have been posted.

In the present case, the matter has been brought to the notice of the U.K. Government for ensuring adequate protective arrangements.

Construction and completion of Projects in S. E. Asia, West Asia and Africa.

4886. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the projects which have been completed and are being constructed by Indian firms in the private, public and joint sectors in S.E. Asia, West Asia and Africa and money involved in these projects; and

(b) how many persons are employed in these projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU):

(a) and (b). Indian firms are participating in a large number of projects in South-East Asia, West Asia and Africa. The requisite information is being collected and will be placed on the table of the House as soon as possible.

Supersession in P & T Department

4887. SHRI SHYAM SUNDER GUPTA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of officers, former Secretary, Ministry of Communications superseded first as Joint Secretary then Additional Secretary and then Secretary;

(b) the post in the pay and date on which he joined in Posts and Telegraphs Department;

(c) the date on which he was promoted to the Telegraph Engineering Service and his academic professional qualifications;

(d) the number of times he was sent to foreign countries with their names for training or for some other assignment while working in the Director General, Posts and Telegraphs, Ministry of Communications; and

(e) the utility/benefit which the Department got from such foreign tours/visits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRINARHARI PRASAD SUKHDEO SAI):

(a) Appointments to senior posts of the level of Joint Secretary and above in the Government of India are filled on the basis of selection on merit from amongst officers belonging to different organised Group 'A' Services keeping in view the requirements of each job and the qualifications and experience of persons within the field of choice. These appointments are made on tenure deputation from various Services. Officers of diverse Services have no common seniority, and as such the question of supersession would not arise in such appointments.

(b) Shri S. M. Agarwal joined as Engineering Supervisor in Posts and Telegraphs Department on 3-11-1941 in the pay scale of Rs. 80-5-120-10-240.

(c) He was appointed as Assistant Divisional Engineer (Telegraphs) (Probationer) on 14-10-1944 on the results of the competitive examination conducted by the then Federal Public Service Commission in November, 1945. His academic/professional qualifications are B. Sc./Graduate, Institute of Electrical Engineers(London).

(d) and (e). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha.

[Placed in Library(See No. 17-1450)/77]

Alleged complaints of corruption and misuse of powers against CPFC.

4888. SHRI DENEN BHATTACHARYA : Will the Minister of Parliamentary Affairs and Labour be pleased to state.

(a) whether many complaints, including complaints by Members of Parliament were made against the present Central Provident Fund Commissioner alleging corruption, misuse of powers etc;

(b) if so, whether instead of independently investigating those complaints as required by Government's instructions, the same were referred to the C.P.F.C.; and

(c) whether in the interest of clean administration, Government would refer those complaints to the C.B.I. for proper and independent investigation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA): (a) Some complaints have been received.

(b) Factual position was ascertained from the Office of the Central Provident Fund Commissioner. The matter was subsequently examined in the Ministry after scrutinising the relevant files called for from the Office of the Commissioner and a report was submitted to the Shah Commission. Simultaneously, the matter has been referred to an independent authority for advice.

(c) The question of referring these complaints to the C.B.I. will be considered at the appropriate time, if such reference is considered necessary.

Anand Margis meeting abroad

889. SHRI PRASANNBHAI MEHTA : DR. HENRY AUSTIN : SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA : SHRI ANANT DAVE :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the press report 'Marg meet abroad to review strategy';

(b) if so, whether they have decided to hold the meeting in London;

(c) whether the Government of India have requested the U.K. Government not to allow the conference; and

(d) if so, the reaction of that Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU) (a) Yes, Sir.

(b) The Government have no information on the venue of the meeting.

(c) and (d). Do not arise.

Arrest of Bangladesh Citizens.

4890. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether many Bangladesh citizens have been arrested during 1977;

(b) if so, their number:

(c) how many of them have been tried and imprisoned, pushed back to Bangladesh and are still in Indian prison;

(d) whether many Bangladesh minorities have helplessly crossed into India and are staying here for several years;

(e) whether they are living as Stateless persons in India;

(f) whether it has created extremely difficult situation for earning their livelihood and particularly regarding education of their sons and daughters; and

(g) if so, will the Government grant them citizenship right without delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): (a) to (c). Information on it is being collected which will be laid on the Table of the House. However, no Bangladeshi nationals have been pushed back; those who are found crossing over to or staying in India illegally are asked to go back.

(d) to (g). These points were covered to the extent possible in the Statement made in Lok Sabha by the Minister of State in the Ministry of External Affairs on 1st December, 1977.

श्री धीरेन्द्र बहुचारी को विशेष टलोकोन
सेवा प्रदान करना

4891. श्री सुमात्र ग्राहका : क्या संचार
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री धीरेन्द्र बहुचारी को
दिल्ली टेलीफोन्स के भूतपूर्व महाप्रबन्धक
द्वारा विशेष टेलीफोन सेवा और अनियमित
टेलीफोन कनेक्शन दिये गये थे ; और

(ख) क्या श्री धीरेन्द्र बहुचारी को
टेलीफोन बिलों में विशेष छूट दी गई
थी : और यदि हाँ, तो उससे मंत्रालय को कितन-
हानि हुई तथा यह विशेष छूट दिये जाने के
कारण क्या ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री
नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) दिल्ली
टेलीफोन्स के पूर्वबत्ती महाप्रबन्धक ने श्री धीरेन्द्र
बहुचारी को अनियमित टेलीफोन कनेक्शन
नहीं दिये थे ।

(ख) अधिक काले बीटर होने के संबंध
में श्री धीरेन्द्र बहुचारी को कोई छूट नहीं
दी गई थी ।

युवक कांग्रेस को अनियमित कनेक्शन दिया
जाना

4892. श्री सुमात्र ग्राहका : क्या
संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन्स के भूतपूर्व
जनरल बैनेजर द्वारा युवक कांग्रेस को कितने
अनियमित कनेक्शन दिये गये थे ;

(ख) क्या ये कनेक्शन नियमों के
अनुसार दिये जा सकते थे और यदि नहीं, तो
ये कनेक्शन दिये जाने के कारण क्या थे ;

(ग) क्या उनके बिलों के भूगतान
किया गया था और यदि नहीं, तो क्या इस
संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ;
और

(घ) इस प्रकार के अनियमित कनेक्शन
देने के जिम्मेदार व्यक्ति के विशुद्ध क्या कार्यवाही
की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री
नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) दिल्ली
टेलीफोन्स नई दिल्ली के रिकार्ड के अनुसार
पूर्वबत्ती महाप्रबन्धक, टेलीफोन, नई दिल्ली
ने यूथ कांग्रेस के नाम अनियमित टेलीफोन
कनेक्शन नहीं दिये थे तथापि, यदि किसी
स्थान मामले की जानकारी दी जाये तो उसकी
जांच कराई जा सकती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न हो नहीं उठता ।

Study of Impact of Minimum Wages on Farm Products

4893. SHRI D.D. DESAI : Will the
Minister of Parliamentary Affairs and
Labour be pleased to state:

(a) whether any study has been made
to find out the impact of fixing minimum
wages on the economics of farm products;

(b) if so, whether farmers are suffering
losses in periods of falling prices due to
minimum wages fixed at a time of higher
consumer prices, remaining the same; and

(c) if the answer to (a) is in the negative,
the reasons for not undertaking such
studies ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS AND LABOUR (SHRI
RAVINDRA VARMA) : (a) No Sir,

(b) Does not arise.

(c) The well-accepted principle of mini-
mum wages is that statutorily fixed mini-
mum wages are considered socially desira-
ble and necessary irrespective of the pro-
fitability and the paying capacity of the
employer.

Medical Facilities to M.P.s.

4894. SHRI AJIT SINH DABHI : Will the Minister of Health and
Family Welfare be pleased to state:

(a) whether medical facilities under the
Central Government Health Scheme are
being given to Ex-Members of Parliament

residing in Delhi, New Delhi, Bombay, Allahabad, Meerut, Nagpur, Kanpur, Calcutta, Madras, Bangalore and Hyderabad only whereas the Ex-Members of Parliament not residing in these cities are not given these Medical facilities;

(b) whether parents of Members of Parliament are given the medical attendance/treatment available to Members of Parliament and Members to their families only if they reside in the above-mentioned cities;

(c) whether the type of facilities available in a hospital to Members of Parliament and their family Members has to conform to the scale prescribed by the hospital concerned for Class I Officers; and

(d) if so, the status of the Members of Parliament equal to Class I Officer in regard to availability of these medical facilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) :

(a) The medical facilities under the Central Government Health Scheme are being given to the Ex-Members of Parliament residing in the cities covered under the Central Government Health Scheme. The Central Government Health Scheme is at present functioning in the cities of Delhi, Bombay, Allahabad, Meerut, Nagpur, Kanpur, Calcutta, Madras, Bangalore, Hyderabad and Patna,

(b) The medical facilities under the Central Government Health Scheme are available to parents of Members of Parliament if they are mainly dependent upon and are residing with them at Delhi/New Delhi. Parents of the Members of Parliament who are beneficiaries of the Central Government Health Scheme and who may be visiting other cities where the Scheme is operating and stay in the areas covered by the Scheme are entitled for free medical treatment under the said Scheme on the basis of the authorisation to be given by the appropriate authority.

(c) and (d). The Members of Parliament are treated on par with Group A (Class I) Officers of the Central Government in the matter of availability of medical facilities.

—

15 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST CHAIRMAN, CALCUTTA PORT TRUST

MR. SPEAKER : Now papers to be laid on the Table. Shri Barnala.

SHRI SAUGATA ROY : Sir, what about my adjournment motion?

MR. SPEAKER : I will allow you to raise it under....

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore) Sir, I have talked to the Minister and he has agreed to meet my point.

MR. SPEAKER : He can, I do not know.

SHRI SAUGATA ROY : It is a very serious matter.....(interruptions)

MR. SPEAKER : The Minister wants to make a statement. Would you allow him?

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) : Is he laying a paper on the Table?

MR. SPEAKER : No, he wants to make a statement about sugarcane. Many Members are interested in it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Sir, according to your Direction No. 2, a member wanting to raise a question involving breach of privilege has precedence over the Minister's statement. Sir, I have given notice of a motion of privilege against the Chairman of the Calcutta Port Trust. He gave evidence before the Public Accounts Committee....

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : Sir, I rise on a point of order... (interruptions) Have you allowed him to raise the privilege motion under rule 222? Are you allowing him?

MR. SPEAKER : Mr. Bosu, you are raising this question again and again.

SHRI VAYALAR RAVI : He wants to move these motions against the officers...

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I know he is shielding the bureaucrats, including the Chairman of the Calcutta Port Trust... (interruptions) Sir, if you do not allow it to be raised now, you will have to face it in the next session.

MR. SPEAKER : All right, Mr. Bosu. I have never been afraid in my life. It is too late.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Sir, I want to point out....

MR. SPEAKER : I have heard you. I have told you that I am not allowing the privilege motion. If you have any other matter, you can raise it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Do you mean to say that a small employee, class 3 employee...

MR. SPEAKER : I have heard you.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Listen to me.

MR. SPEAKER : I have listened to you half a dozen times.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : A Class III employee comes and reveals things before one of your Committees, and for doing that he is...**

MR. SPEAKER : Please don't record.

SOME HON. MEMBERS:**

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): On a point of order. The Public Accounts Committee has certain privileges to take evidence.

MR. SPEAKER : Do you know the facts?

SHRI C. K. CHANDRAPPAN : I am raising a point of order. If an ordinary employee has been asked to give evidence before a Committee, it is the duty of the House, because the Committee is acting on behalf of the House, to give him protection, if a bureaucrat is going to victimise that employee. From what he has said, as I understood him, the Chairman of the Calcutta Port Trust is going to victimise this employee for giving evidence before the Public Accounts Committee. If the case is like that, it is the responsibility of the House to look into the matter and protect the employee. You cannot just shut him out. You give an assurance that you will look into the matter. I am not going into the merits of the case. I am raising an issue. Because the Public Accounts Committee is acting on behalf of this House, is a Committee appointed by this House, if anybody is victimised for giving evidence before that Committee...

MR. SPEAKER : Your point of order has many "if's".

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): The question is whether he is being victimised for giving evidence or not. It is very easy for the bureaucrat to say that he is not taking action against him for this. Under the garb of some fictitious charge, he can be dismissed, when the real object is to penalise him for giving evidence. Therefore, kindly do not go by the language of the charge given to

him. It is very easy to suppress it. Therefore, it is essential that the Privileges Committee should go into the matter. Otherwise, do you expect that anybody in this country will co-operate with any Committee of the House? This is a question of the very functioning of this House. Let the Privileges Committee decide whether there was a real intention which has been camouflaged by the notice. This matter cannot be decided like this.

SHRIVAYALAR RAVI : On a point of order. An attempt at victimisation by the Chairman of the Calcutta Port Trust against an employee is being alleged. Before taking a decision, you have to find out whether the concerned employee had made an appeal to the same Committee to look into this matter, requesting the protection of the Committee. Before it comes to this House, the PAC must look into it.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir, the House would like to be enlightened by you in this matter. Here is a serious allegation made by an hon. Member. He makes out a case of breach of privilege. *Prima facie*, it seems that it would amount to a breach of privilege if certain investigations confirm his allegation. So, the duty of the House clearly to my mind is to go into this matter and to ask the Chair to investigate this matter because the Committee of the House is the House itself. There is no difference between the Committee of the House and the House itself. Therefore, if any witness has tendered, an evidence which has ultimately led to his persecution, then the House will have to protect that witness. We would like to be assured by you that you will look into the matter, investigate into it and then come before the House with your finding.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : What was the observation of the Committee? I quote:

"Thank you very much. Your assistance has been very useful to the Committee.

Now, you apprehend some attack on you. You say, you require some protection. I am quite sure that the Committee is unanimous in this regard that such persons should be protected by the arms of law. Secondly, for tendering evidence before the Committee, nobody can be penalised or victimised under any circumstances by any authority because this is a Committee of the highest forum in democracy."

**Not recorded.

What is the letter that he has received? I quote that also:

"You have submitted a number of memoranda containing allegations relating to various department/sections and personnel of Calcutta Port Trust. The allegations made "are purported to be based on official documents and records" I have been directed by the Chairman to obtain explanation from you as to how you procured such records and documents and in case such records and documents or information pertaining thereto were obtained through other Calcutta Port Trust employees, you are required to furnish the names and designation of such employees."

What more do you want? I feel that the matter be referred to the judicial committee of this House, namely, the Privileges Committee. It is an all-party Committee. So, there is no cause for complaint. I move that the matter be referred to the Privileges Committee. Sir, you get the sense of the House (*Interruptions*).

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North West): Sir, in the Public Gallery, we have got a lot of school children. In the interest of their education, they should be sent away from the Public Gallery before we carry on our deliberations.

MR. SPEAKER : No, no. They are entitled to know what we are doing. (*Interruptions*).

बी गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : प्रध्यायक महोदय, लक्ष्मण चित्र यहाँ नये आरे हैं। उन्हें दूसरो जगह की देनीराहे हैं, इस लिए वह कभी कभी चंक उठते हैं।

PROF. P. G. MAVALANKAR : On a point of order. Mr. Jethmalani, my esteemed friend, made some observations. I want to go on record to say that the practice here has been that a Member of the House shall not take any notice of anybody in the Gallery. That is the practice. Therefore, he need not refer to persons in the Gallery. That is not done. We are not supposed to take any notice of whosoever may be sitting in the Gallery. (*Interruptions*).

SHRI SUSHIL KUMAR DHARA (Tamluk) : Sir, I want to say something. Please give me a chance.

बी गौरीशंकर राय : ऐसा है कि वह एक नये आकर्षी है, आपको नोटिस नहीं भेजा चाहिए। (व्यवहार)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कमेटी में बयान देने के लिए कोई आदमी आनंदट्रूट किया जाता है या विविटमार्ज किया जाता है तो वह भी चाफ प्रिविलेज का केस है। जो बयान दिया है माननीय सदस्य ज्योतिर्मय दासु ने उससे यह पता लगता है कि उन से कहा थाया है कि आप ने कमेटी को इन्कार्मेशन पास आन किया है तो यह मामला एक जांच का अवसर बनता है। हाउस की एक कमेटी को या प्रिविलेज कमेटी को इसकी एन्कार्यायरी करनी चाहिए ताकि यह मालूम हो जाए कि कोई आदमी इस बात के लिए देनलाइज हुआ है या नहीं। जितने भी चाफ प्रिविलेज होते हैं उन में सब से सीरियस भी चाफ प्रिविलेज होता है विविटमार्जेशन कार दि सर्विस आफ दि कमेटी एंड आनंदट्रूट इन दि सर्विस आफ दि कमेटी। तो यह सब से सीरियस किस्म का भी चाफ प्रिविलेज है। तो कमेटी इसी की एन्कार्यायरी करे और एन्कार्यायरी के बाद अगर जिम्मेदारी साबित हो जाए तो उसको सजा दी जाए। लेकिन प्राइमाफेस्टी यह केस एन्कार्यायरी के लिए बनता है, इसलिए इस को प्रिविलेज कमेटी के सामने भज दिया जाय।

SHRI SUSHIL KUMAR DHARA : I have been trying my best to impress upon you something. Please listen to me, Sir. This is also a question of privilege for a Member. What Mr. Jyotirmoy Basu alleged, I am also alleging in the same manner. I sent notices of privilege motions twice, but you rejected them. In support of what Mr. Jyotirmoy Basu has said today, I want to say that it is clear, from the letter which he read out just now, that this notice which was given to Mr. Haripada Ghosh was given to him on the 17th December, 1976. He came before the Public Accounts Committee on the 15th March, 1975. Some unscrupulous officers took advantage of the Emergency and he was suspended. That poor man is now in the streets. You will be astonished to know that he has nothing to feed his family of seven members. He has a very brilliant son, but he had to give up his studies. He is now a wage-earner; he is earning wages by manual labour and thereby he is maintaining the whole family. You should take some notice of it. In this

[Shri Sushil Kumar Dhar]

way the bureaucracy, the unscrupulous officers must not be allowed to do anything; they should be restrained. I can tell you sir, that Shri Haripada Ghosh is going to be repented soon; this retrenchment order has been signed by FA & CAO and it has been kept by the Chairman of the Calcutta Port Trust in this desk. As soon as this House rises on 23rd on the 24th that notice will be served to Mr. Haripada Ghosh. That employee who came before the Public Accounts Committee to help the Committee is thus being punished. I can say with all assurances that the Calcutta Port Trust authorities are very corrupt. I have written to the Minister and to the Secretary several letters in this respect during the last four months. But nothing has been done.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Mr. Speaker, Sir, Shri Haripada Ghosh appeared before the Public Accounts Committee on the 15th March, 1975. He was issued a charge-sheet on 12th July, 1975 and again on 21st July, 1975. Ultimately, a letter was written to him on 17th December, 1976, that he should disclose the names of those persons from whom he got the information and placed it before the Public Accounts Committee.

The Public Accounts Committee is a body which is there to have surveillance over the Government and it is accountable to this House. This Mr. Ghosh was asked to give relevant evidence before the Public Accounts Committee and he did so and mentioned about the functioning of the Port Trust. For this, he has been victimised. This does amount to breach of privilege and needs to be referred to the Committee of Privileges.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag) : Sir, Shri Jyotirmoy Basu has raised a very important point, but the only trouble is that he does not take the entire House into confidence, because he presents the matter in such a way, it seems, that he is quarrelling with the whole House.

The point is that there are various Committees which have been appointed by you and as Shri Shyamandan Mishra pointed out those are the Committees of the House and people giving evidence before such Committees should not be victimised. This is, therefore, a fit case to be sent to the privileges Committee.

MR. SPEAKER : In view of the strong views of the House, I shall revise my opinion, but I am duty-bound to tell you why I withheld my consent. When Shri Jyotirmoy Basu sent me a notice about this—I always think that the privilege is a quasi-criminal matter and one must

take a serious view of it—immediately I called or a report from the Chairman of the Public Accounts Committee whether it is a case of victimisation or it is something outside the victimisation.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Not necessary.

MR. SPEAKER : Please hear me now. I have heard you; you have a duty to hear me now.

The Chairman of the Public Accounts Committee sent me a report saying that this has nothing to do with the evidence given before the Committee; it is totally something different. It is on that basis that I have withheld my consent. I have a duty to respect the opinion of the Chairman of any Committee, for that matter, that is appointed. It is because of that that I withheld my consent. Now, that the House is so much agitated about it, I shall revise my opinion.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki) : Mr Speaker, Sir, I want to make one submission. When you referred this to the Chairman of the Public Accounts Committee, I have no opinion eitherway. The fact of the matter was that this employee sent in a petition to the former Chairman of the Public Accounts Committee, Shri H. N. Mukherjee. He made a record on that after going through it that this Committee has nothing to do with it; this does not amount to any violation of any privilege or any undertaking given. He did that after going through all the facts. Subsequently, you sent it to me and I quoted that Chairman's observations. Before the Speaker sent these papers to me, this employee sent the papers to this Committee also. I saw that he was given a transfer order from one section to another. He disobeyed the transfer orders. On the basis of violation of that transfer order, some action was taken. This is a very distant thing from what is happening. Therefore, before the privilege matter came up, objectively, I made a casual record before I received any intimation from you saying that this has nothing to do with the assurance given by the Committee and, therefore, there is nothing that the Committee has got to pursue. When you sent it to me, I gave this background material and passed it back to you. I have got very definite views about it, but as this is a matter which I dealt with, I do not want to make any representation before this House.

There is another point and that is, you will have to consider what it does amount to.

If all the facts stated are correct, it amounts to contempt of a Committee.

And there is a procedure, if it amounts to contempt of a Committee, and that is that the Committee will consider and the Chairman of the Committee, as per the opinion of the Committee, will make a submission to you.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : No, no.

SHRI C. M. STEPHEN : This I am saying not as the Chairman of the Committee, but as a Member of this House. You may kindly take this aspect into consideration.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : The House is supreme.

SHRI C. M. STEPHEN : That is all right. What the procedure must be.....

SHRI JYOTIRMOY BOSU : On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER : You have a duty to hear others also.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I cannot be misled like this.

Under Rule 222....(Interruption) I am on a point of order, Sir.

SHRI C. M. STEPHEN : I am already on a point of order.

I am not pleading for anybody. I am only putting this question before you, not as Chairman of the Public Accounts Committee but as a Member of this House which is keen that precedents laid down must be healthy precedents. Supposing somebody comes before my committee or the committee on Lokpal and supposing he has committed a contempt there and that committee is seized of that and if the Chairman writes to you, then you can take it as a matter of privilege. This is the procedure. Before you finally say as to what should be done, what the procedure must be is a matter you may kindly consider so that healthy precedents are laid down.

I have nothing against sending this matter to anybody. I am not at all taking any position either way. Now that you have mentioned that the matter was sent to the Chairman of the Public Accounts Committee, I am giving to the House the background of the matter without expressing an opinion as to whether a privilege is involved or not. As a member of the House again and not as a Chairman of the Public Accounts Committee, I am submitting that healthy precedents should be laid down. If the allegation is that a privilege of a committee has been violated, then the matter must initially go before that committee and you may consider this.....

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : No, no.. (Interruption) It is a question of privilege. You please give your ruling.

MR. SPEAKER : I am allowing it..(Interruption)

Taking into consideration the strong views expressed in the House, I am revising my opinion and I am sending it to the Privileges Committee.

SHRI RAJ NARAIN : What about my privilege motion ?

MR. SPEAKER : It is under consideration. I have called for an explanation.

Mr. Barnala.

SHRI RAJ NARAIN : Privilege matters should come first. Then, Sir, this House is going to adjourn tomorrow.

MR. SPEAKER : Privilege questions will not lapse.

SHRI RAJ NARAIN : Then, what is the meaning of 'earliest opportunity' ?

MR. SPEAKER : 'Earliest' means as early as possible.

Mr. Barnala.

12.43 hrs.

RE. DISCUSSION ON PRICES OF SUGAR CANE AND GUR

श्री सुरेन्द्र विकाम (गाहजहांपुर) : प्रध्याया जी, मेरी बात सुन लीजिये । मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी, जो भारी लोलने के लिए छड़े हो रहे हैं, चीनी और गुड़ की जो दुर्दशा हो रही है, उसके बारे में हम सब लोगों को पूरी जानकारी दें और यह बताएं कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं ।

श्री बबी राम बग्गी (मथुरा) : प्रध्याया जी, यह लोक सभा है और भारत के किसानों का जब दिल हिलता हो, तो लोक सभा को भी हिलना चाहिए । यह लोक सभा है और यहां पर मुख्य दरबार जैसे कायदे कानून नहीं चलेंगे । गुड़ और गन्डे के सदास को ले कर, मैं आंबों में होकर आया हूँ, किसान

[**श्री मनो राम बागड़ी**]

वाहि वाहि कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें बचाओ। उन किसानों की ही बदीनत आज यह इंकलाब आया है और जनता पार्टी को सरकार बनी है। परंग किसान हिलता हो और लोक सभा न हिलती हो और लोक सभा से उसके लिए आवाज न उठे, तो यह कान खोल कर सुन लें कि किसानों का प्रान्दोलन आपको बही उठा कर फेंक देगा जहां से आप आए हैं। आज जो गुड़ और शक्कर की हालत है, उस को आपको मुनाव पड़ेगा। यह हिन्दुस्तान के किसानों की बात है। कायदे कानून की बात को सम्म लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा देर तक लोक सभा में चला सकते हैं लेकिन दीन, दुखी और दर्दि लोगों की आवाज को ठीक तरह से नहीं रखा जाता। उनकी आवाज को भी यहां पर रखना होगा।

प्रध्यन महोदय, हम किसानों के प्रतिनिधि हैं और हमें उनकी बात यहां रखने का पूरा अधिकार है। इसके लिए बेशक हमें अपनी पार्टी से निकलना पड़े, लेकिन हम अपने इस अधिकार को नहीं छोड़ सकते। आप हमारी बात मुनिये (अवकाश)

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : Hon. Members are very much agitated on this issue and I share their feelings. I am an agriculturist myself and I do share their feelings on this issue. They need information regarding sugarcane and gur prices and khandsari also. A detailed statement will be made by me tomorrow on all these aspects. (अवकाश)

डा० सल्ली मारालचन चोडेप (मंसीरौर) : हम इस प्रश्न पर पूरी बहस चाहते हैं। (अवकाश)

श्री द्विरेत्त बहामुर (योगिपुर) : मैं मंदी, महोदय से विवेदन करना कि वे इस प्रश्न पर पूरा बहस चाहते हैं। (अवकाश)

SHRI PRAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) : Let us have information on levy sugar also. We want information with regard to levy sugar. It is connected with that.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : There was a statement made by the hon. Minister of State for Agriculture on the previous occasion. We had a Half-an-hour discussion on the fixation of sugarcane price. On that occasion Mr. Bhanu Pratap Singh could not answer several questions. Several questions were raised by the other side also. The entire House wanted more information. The entire House demanded a proper price being fixed for sugarcane. I would like to submit to you that we should have a full discussion on this issue tomorrow. Is the Minister agreeable to have a discussion on this tomorrow? What is his reply?

MR. SPEAKER : I do not know.

SHRI K. LAKKAPPA : I draw through you, the attention of the hon. Minister and request him to make a statement in this regard.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : I do not know whether you have the time for this tomorrow or not. I do not know what the business of the House will be tomorrow.

MR. SPEAKER : To-morrow there will not be any time for discussion.

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, this is a most important subject. You will kindly draw the attention of the Minister on this and let him say what he wants to say on this.

MR. SPEAKER : He has promised to make a statement on this.

श्री चन्द्र नेहर लिह (वाराणसी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम से कम आधे दिन के लिए इस पर बर्चा की जानी चाहिए। सरकार द्वारा गंधे के निर्वाचित दाम भी आज चिल मालिक किसानों को नहीं दे रहे हैं। गुड़ का निर्वाच भी रोक दिया गया है। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है।

श्री उपरेत (देवरिया) : जब कोई जहरी बहस आती है तो इंस्टीड में हाउस आफ कामंस और अमरीका में हाउस आफ चिलेटिव रात बारह बजे तक बैठते हैं। यहां पर भी हम रात बारह बजे तक बैठते हैं।

भी भवी राम आगाहो : कल बीस लाख किसान हिन्दुस्तान से यहां एकत्र हो रहे हैं। मैं प्रादेना करता हूं कि जब वह रेली खत्म हो जाए। उसके बाद आप इसके लिए समय रखें ताकि हम भी उसमें भाग ले सकें।

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : I have no objection to a discussion taking place. Time can be given.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : (Uluberia) : There are three ways to satisfy the Members on this issue—one is that the Government should find time for two hours tomorrow for a discussion on the statement to be made by the hon. Minister. I do not think that there is anything coming in the way of such a discussing being permitted tomorrow. After all the business of the House is transacted, we can discuss this problem. Secondly, if the Government is not prepared to do that and the hon. Minister is engaged otherwise, than the Government should be prepared to extend the House for one day only for the discussion of this subject.

The third course that can be adopted is that the Business Advisory Committee should sit this afternoon and streamline the discussion to be taken up tomorrow. We can take out certain things from the Agenda and include this subject for a discussion tomorrow. These are the three courses open to the House and one of them can be adopted.

SHRI PURNA SINHA (Tezpur) : Mr. Speaker, Sir, time capsule has been unearthed and it has already been ripped open and contents have been found out and inventories have been prepared. Certain items were shown to the press. Can the press know much before Parliament can know it? It was Parliament which got it unearthed and it must have the first chance to know the contents. Are you going to ask the Minister to disclose the contents of the time capsule to Parliament before the House adjourns. We want a categorical statement tomorrow.

MR. SPEAKER : The Minister is not here. The Minister for Parliamentary Affairs wants to say something.

अध्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी लार्ग साथ) : माननीय सदस्य इस मुहे पर चर्चा करना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि इस पर चर्चा के लिए आगे समय बढ़ा दिया जाए।

इस पर चर्चा हो यह भावालयक है क्योंकि यह किसानों का मसला है और स्वाभाविक है कि मान नीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम लंब धावर में भी अपना काम जारी रख सकते हैं। आखिर में एक बांटा और भी बैठ कर कुछ समय निकाल सकते हैं और इस पर बह स कर सकते हैं। अगर माननीय सदस्यों को एतराज न हो तो वे मेरे इस मुझाव को स्वीकार कर सकते हैं। यह हमारा मुझाव है।

SHRISAUGATA ROY On a point of order. There was half an hour discussion on sugar industry and when such discussion takes place Ministers are expected to come prepared with policy statements and other information as so that Members do not have raise the matters again. The hon. Minister Bhanu Pratap Singh did not come prepared with a policy statement. So I request the Ministers through you that in future when they come for discussion they should come prepared with facts and figures and policy statements.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I want to move a formal motion that the sitting tomorrow be extended by two hours for this discussion.

12.56 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ACCOUNTS OF ANIMAL WELFARE BOARD, MADRAS FOR 1975-76, REVIEW AND ANNUAL REPORT OF KERALA AGRO-INDUSTRIES CORPORATION LTD. FOR 1975-76; ANNUAL REPORTS (HINDI) OF ORISSA AGRO-INDUSTRIES CORPORATION FOR 1968-69 AND 1969-70 & STATEMENTS.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Animal Welfare Board, Madras, for the year 1975-76 and the Audit Report thereon, under the sub-rule (4) of Rule, 24 of the Animal Welfare Board (Administration) Rules, 1962. [Placed in library. See No. LT-1426/77].

(2) A copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(a) (i) Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Kerala Agro-Industries Corporation Limited, Trivandrum, for the year 1975-76

(ii) Annual Report of the Kerala Agro-Industries Corporation Limited, Trivandrum, for the year 1975-76 alongwith the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in library. [See No. LT-1427/77].

(b) Annual Report (Hindi* version) of the Orissa Agro-Industries Corporation Limited, Cuttack, for the year 1968-69 alongwith the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) Annual Report (Hindi* version) of the Orissa Agro-Industries Corporation Limited, Cuttack for the year 1969-70 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in library. See No. LT-1428/77].

(3) A statement (Hindi and English versions) explaining reason for not laying simultaneously the Hindi version of the Report mentioned at 2(a) (ii) above.

(4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the reports mentioned at (2)(a), (b) and (c) above. [Placed in library. See No. LT-1428/77].

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) : I want to make and observation with regard to the papers laid on the Table of the House ; I have sought your permission to raise this matter with particular reference to items 3, 7 and 8 in today's list of business. Papers, statements, reports etc. are being laid by various Ministers and I have purposely not sought your permission so far to raise certain objections. But now that we are coming to the close of the present session, I thought I shall invite the attention of the House to some important matters. You will be pleased to recall that a number of important statements, reports, reviews etc. covering the activities of the government

and public corporations for which the Government of India are responsible through various Ministries are being laid before the House. This practice though followed strictly and technically in effect and in spirit the purpose is lost if they are laid as late as 4 or 6 years after they were supposed to have been laid. For example, the Minister of Agriculture is laying on the Table of the House today the Hindi version of the annual report of the Orissa Agro-Industries Corporation for the year 1968-69 I know that, fortunately, there is a committee for papers laid on the table of the House which will look into all these cases and I am just now not on that question. My point is that if Ministers bring before the House reports of activities years later, they just go in a routine way ; the matter is referred to the committee and it makes a report. But the purpose of keeping vigilance and the right of interrogating the government are being denied to us. Therefore, my request to you is this. You will see a footnote which says that the English versions of the reports for 1968-69 and 1969-70 were laid on the Table of the House on 28th October, 1976, and the mere translation into Hindi had taken one year and two months. This is something unpardonable : even if reasons are given they are unjustifiable. How can the government take 14 months for mere Hindi translation of a report which was laid already late by six years ?

Now they take 14 months more to lay the Hindi translation. You can see how this very serious procedure laid down over a period of years has been ridiculed and made fun of by the laying of delayed reports. Secondly, the reasons explaining the delay are also being laid on the Table by the Minister today. He lays the report and simultaneously lays the reasons for delay. So, tomorrow I cannot raise the matter. If I knew the reasons for the delay at least a couple of hours in advance, if then there is a serious lapse, I can invite the attention of the House to it with your permission. When both are laid simultaneously, nothing can be done. If you agree, therefore, I suggest that the statement giving reasons for delay in laying either the Hindi version or the original, English version ought to be circulated to all members of Parliament at 7.30 or 8 in the morning along with the list of business, so that we may study those reasons. If the delay is ordinary and technical, we will not waste the time of the House by raising it here. But if it is a serious matter involving accountability of a high order, we will come to you before 10 o'clock, take your permission and raise it in the House.

* The English versions of the reports were

laid on the table on the 28th October, 1976.

23.00 hrs.

MR. SPEAKER : I will look into the matter.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Being the Chairman of the Committee, I want to make a submission.

मेरा कहना यह है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह बहुत गंभीर बात है। हमारी कमेटी ने सामने कई-कई साल ने बाद रिपोर्ट आती हैं और उसका परिणाम यह होता है कि जो कुछ मदन या सदस्य देख सकते हैं कि उसने क्या गड़बड़ है, क्या ठीक है, वह नहीं देख पाते, उसका उद्देश्य खात्म हो जाता है।

कई प्राइवेट या गवर्नमेंट को ऐसी इंस्टीट्यूशन्स हैं जिनमें स्टेट या मेंटर का रूपया लगा है, उनकी 7, 8 साल के बाद रिपोर्ट आती है। कोई हाउस को ऐसी कमेटी नहीं है जो उनकी एक्टिविटीज को बाच करे। कई बार देर में रिपोर्ट लाने का उद्देश्य यह भी होता है कि 7, 8 साल के बाद लाग्नो ताकि जो गड़बड़ी हो, जसको कोई देख नहीं सके।

हमारी कमेटी इतना ही देखती है कि रिपोर्ट ठीक समय पर आई है या नहीं। अगर नहीं आई तो कह देते हैं कि गलती हो गई, नहीं आई। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है।

मेरी प्रायंता है कि इस कमेटी के परव्यु को थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि यह कमेटी, कहां पर गड़बड़ है, कहां ठीक है, कहां ठीक नहीं है, जैसे हाउस की दूसरी कमेटीज देखती हैं, यह कमेटी भी जांच कर सके और मदन के सामने रख सके कि इसमें क्या गड़बड़ है। आपकी मूलना के लिए मैं यह प्रायंता करना चाहता हूँ।

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : There are two types of reports being laid today. One is in item 2(a) "Review

(Hindi & English versions) by Government on the working of the Kerala Agro Industries Corporation for the year 1975-76". There is not much delay in that. But my hon. friend is referring to item 2(b) — "Annual Report (Hindi version) of Orissa Agro Industries Corporation Limited, Cuttack, for the year 1968-69". But he has not read out what follows, viz., "along with the audited accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon".

All that has taken time, and that has been explained.

MR. SPEAKER : The delay of nearly 9 years is too much.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Minister should not be allowed to explain these reasons. It is for the Committee to see why delay has taken place.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : It was only mentioned that it was a report, "along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon."

MR. SPEAKER : Even then 9 years' delay is something unpardonable. But of course, you are not responsible. Somebody else may be responsible. At least in future, these reports should be placed on the Table of the House as early as possible. The Auditor General must have asked for the report earlier.

We will look into the matter and see how we can expedite things. If you can give it in writing, we can see how it can be streamlined.

ANNUAL REPORT OF NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL FOR 1976-77

अम तथा संस्कृतीय कार्य मंत्रालय ने राज्य संस्कृती (बी. सारंग साय) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जावं फलान्दीज की ओर से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के बीच 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति सभा पट्टा पर रखता हूँ।

[Placed in library. See No. LT-1429-77].

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF BHARAT ALUMINUM CO. LTD., FOR 1976-77

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : I beg to lay on the Table a copy each of

the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the Bharat Aluminium Co. Limited New Delhi, for the year 1976-77.

(2) Annual Report of the Bharat Aluminium Company Limited, New Delhi, for the year 1976-77 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in library. See No. LT-1430/77]

AUDIT REPORT ON ACCOUNTS OF CENTRAL BOARD FOR PREVENTION AND CONTROL OF WATER POLLUTION FOR 1976-77

मिसान और आधास तथा प्रूति और पुनर्वासन मंत्रालय में राज्य बंडी (जी राय फिकर) : मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 को उपधारा (6) के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के बारे 1976-77 के लेख सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in library. See No LT-1431/77]

ANNUAL ASSESSMENT REPORT Re. HINDI FOR 1973-74 and 1974-75

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : I beg to lay on the Table a copy of the Annual Assessment Report (Hindi and English versions) on the programme and its implementation for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union for the years 1973-74 and 1974-75.

श्रोतूं पौत्रों औरों मार्क्सांकर (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आइटम 7 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जान-वृक्ष कर हिन्दी में बोल रहा हूँ। अभी श्री मंडल ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संघ-भाषा के नामे हिन्दी के उपयोग में गति लाने के लिए जारी गये कार्यक्रम और उसकी

समीक्षा की रिपोर्ट को सदन के टेबल पर रखा है। आप देखेंगे कि 1973-74 और 1974-75 की रिपोर्टों को प्राप्त सदन के सामने रखा जा रहा है, जबकि 1977 का साल अब होने जा रहा है। उन दर्तों के दीरें हिन्दी के उपयोग में कितना विस्तार हुआ और इस सम्बन्ध में क्या दिक्कतें पेश आईं, जब इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त हमारे सामने आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हम हिन्दी का उपयोग बढ़ाने के सिलसिले में उतने अंधीर नहीं हैं, जितना कि हमें संविधान के प्रावधान और संसद के नियंत्रण के अनुसार होना चाहिए। जब हमें कहते हैं कि संघ-भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का उपयोग, और उसकी प्रतिष्ठा, बढ़नी चाहिए, तो हर एक विनिस्ट्री को पूरे गांधीर्य के साथ उसके उपयोग को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जब इस क्षेत्र की रिपोर्ट ही दो ढाई साल के बाद हमारे सामने रखी जाती है, तो इससे ऐसा सगता है कि दिल्ली में भारत सरकार के कहुत से अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें अंग्रेजी के साथ इतनी मुहम्मत है कि वे हिन्दी के संबंध में संविधान के प्रावधान और इस संसद द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करना चाहते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्रधान मंत्रीजी और सरकार की—हम मानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्सुक है—इस बारे में कुछ कहें।

MR. SPEAKER : Mr. Mavlankar, you can only raise it. This is not an occasion to make speeches.

STATEMENTS Re. ACTION TAKEN BY GOVERNMENT ON VARIOUS ASSURANCES GIVEN BY MINISTERS

अब तथा मंत्रीर्यां कार्य मंत्रालय में राज्य बंडी (जी लार्टन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सोक सभा के विभिन्न सदनों के

दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आकासनों, वचारों तथा की गयी प्रतिक्रियाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शनी बाला निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) समा पट्टन पर रखता है :

(1) विवरण संख्या 10— } पांचवीं लोक सोलहवां सत्र, 1976 } समा

(2) विवरण संख्या 4— } रहना सत्र, 1977 } समा

(3) विवरण संख्या 5— } दूसरा सत्र, 1977 } छठी लोक समा

(4) विवरण संख्या 6— } दूसरा सत्र, 1977 } समा

(5) विवरण संख्या 1— } तीसरा सत्र, 1977 } समा

[Placed in Library. See No. LT-1433/77]

REPORT OF DESHPANDE COMMISSION
RE. DEATH OF JUSTICE D. S. LAMBA,
PREVENTION OF FOOD ADULTERATION
(5TH AMDT.) RULES, 1977 AND REPORT
OF THE COMMITTEE ON DRUG ABUSE
IN INDIA

स्वास्थ्य और विवार कल्याण मंत्रालय
में राज्य मंत्री (श्री अगदम्बी प्रसाद यादव) :
मैं निम्नलिखित पत्र समा पट्टन पर रखता हूँ—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की भारा 3 की उन्नीता (4) के अन्तर्गत पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी० एस० संवा की मृत्यु सम्बन्धी तथ्यों तथा दिस्तियों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित देशपांडे

आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति ।

[Placed in Library. See No. LT-1434/77]

(2) खाद्य अभियंत्रण निवारण अधिनियम, 1954 की भारा 23 की उच्चारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अभियंत्रण निवारण (पांचवीं संवाधान) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 दिसंबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रधिमूलन संख्या साँ० साँ० नि० 732 (३) में प्रकाशित हुए ।

[Placed in Library. See No. LT-1435/77]

(3) भारत में ग्रौपितियों के दुरुस्थियों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी** संस्करण) की एक प्रति ।

[Placed in Library. See No. LT-1436/77]

13.07 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

MINUTES

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to lay on the Table Minutes of the sittings of the Committee on Papers Laid on the Table held on 31st August, 5th October and 20th December, 1977.

13.08 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from

*The English version of the Report was laid on the Table on the 14th November, 1977.

**The English version of the Report was laid on the Table on the 5th December, 1977.

the Secretary - General of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 4) Bill, 1977, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 1977, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Children (Amendment) Bill, 1977, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th December, 1977."

CHILDREN (AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I lay on the Table of the House the Children (Amendment) Bill, 1977, as passed by Rajya Sabha.

13:10 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

SECOND REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I beg to present the Second Report of the Committee on Papers Laid on the Table.

13:12 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

2ND, 18TH, 21ST, 24TH, 31ST, 33RD, 35TH, 41ST, 42ND, 47TH, AND 50TH REPORTS

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki) : I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee :—

(i) Second Report on paragraphs 9 and 10 of the Report of the

Comptroller and Auditor General of India for the year 1974-75. Union Government (Defence Services).

(2) Eighteenth Report on Supplementary Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1973-74 Union Government (Civil) relating to Road Development in Fourth Plan.

(3) Twenty-first Report on paragraph 31 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1974-75. Union Government (Civil) relating to Resettlement of Ex-Servicemen near Seijosa.

(4) Twenty-fourth Report on Paragraphs relating to Railway Expenditure included in the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1974-75. Union Government (Railway).

(5) Thirty-first Report on Action taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Two Hundred and Fourth Report (Fifth Lok Sabha) relating to Expansion of Srinagar Telephone Exchange.

(6) Thirty-third Report on paragraph 33 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1974-75. Union Government (Civil) relating to Haldia Dock Project.

(7) Thirty-sixth Report on Action Taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Hundred and Fifty-eighth Report (Fifth Lok Sabha) relating to Irregular Release of Woollen Garments under a misdeclaration as Rags.

(8) Forty-first Report on Action Taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Hundred and Eighty-first Report (Fifth Lok Sabha) relating to Emergency Agricultural Production Programme.

(9) Forty-second Report on Action Taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Two Hundred and Tenth Report

(Fifth Lok Sabha) on Naval Dockyard Expansion Scheme—Ministry of Defence.

(10) Forty-seventh Report on Action Taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Two Hundred and Ninth Report (Fifth Lok Sabha) relating to Export of Leather.

(11) Fiftieth Report on Action Taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Hundred and Seventy-third Report (Fifth Lok Sabha) relating to Directorate of Advertising and Visual Publicity.

13:13 hrs.

•PUBLIC SECTOR IRON AND STEEL COMPANIES (RESTRUCTURING) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for restructuring of the iron and steel companies in the public sector so as to secure better management and greater efficiency in their working and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for restructuring of the iron and steel companies in the public sector so as to secure better management and greater efficiency in their working and for matters connected therewith or incidental thereto."

13:15 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

TENTH REPORT

श्री चतुर्वेद प्रसाद चट्टर्जी (भारत) : I beg to present the Tenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

FOURTH REPORT

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : I beg to present the Fourth Report of the Committee on Subordinate Legislation.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

FIRST REPORT

SHRI YAGYA DUTT SHARMA (Gurdaspur) : I beg to present the First Report of the Committee on Government Assurances.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki) : Sir, I oppose the introduction of this Bill on two grounds, one technical and the other substantial. Coming to that technical aspect, while going through the Bill I find there are certain provisions which provide for delegation of power, e.g. power to alter the conditions of service of employees, power to form association of companies, power to remove difficulties, power to alter the share structure of the companies by notification. These, according to me, are delegatory powers but I find there is no memorandum attached to the Bill, which gives details of the powers of delegation contemplated or incorporated in the Bill, which is one of the mandatory provisions.

Then, this Bill provides for taking over of certain companies : it is not exactly taking over, but companies which are today under the management of SAIL will become independent companies, directly under the control of the Ministry. But there is no financial memorandum. I do not know. I would like to get some light on this point. Is it the contention of the Minister that when these companies, which were being managed by SAIL so far, will be taken over by the Ministry, there will be no additional expenditure, no additional staff, nothing of that sort ? Apparently, it will involve an additional expenditure, in which case there should be a financial memorandum,

[Shri C. M. Stephen]

or they should say that there is no financial expenditure. Neither of these memoranda is appended to this Bill. Therefore, the Bill as presented to the House is defective on the technical ground I am pointing out, which of course can be rectified with your permission. He can subsequently do it. I am pointing it out so that the Minister may look into it.

Then I come to the substantial ground. I want to draw the attention of the Members on both sides, irrespective of party affiliation, that this Bill represents a major deviation from a vital policy in an extremely vital area of national interest. Steel production is an area of vital interest for us. We know the past history upto 1962. Although we had the steel plants at Durgapur, Bhilai and Rourkela, production remained stagnant around 4 million tonnes. A committee was appointed, it went into the structuring of it, it produced certain proposals and those proposals resulted in the formation of SAIL. The idea was that these companies together and the companies dealing with the inputs, namely, designing, construction, coal supply, they will all come under SAIL so that there can be coordination. The manufacturing concerns need not go to the Ministry or other people, they have nothing to worry about, the supply of the inputs will be the concern of SAIL. That sort of arrangement was brought about. The result was that in 1973-74 production went up by 19 per cent. In 1974-75 it went up further and in 1975-76 still further. As against the 1973 figure, today our production has almost doubled as a result of this streamlining.

There is one element in this Bill which is welcome and another element which is absolutely unwelcome. The welcome element is that the different steel plants which are autonomous units now under separate managements are to be brought under a single management so that sufficient coordination takes place. This is welcome.

the other hand, a very dangerous thing is now being done. The NMDC, MEKON, the refractory, HSIL—all these companies which are today under SAIL, looked after by SAIL, are now being taken apart and put directly under the Ministry. According to me this is a very mischievous move which will be disastrous in the matter of the totality of our production. We will go into the exact reason for this at the consideration stage.

We are today in a position of competing with international concerns.

MR. SPEAKER : Will that not be more relevant at the time of considering the Bill ?

SHRI C. M. STEPHEN : We were importing Rs. 400 crores worth of steel. The position has been reversed. We are importing Rs. 50 crores of fine steel today and exporting steel to the extent of Rs. 400 crores. This is because of the streamlining. But the reverse gear is going to be applied now. If these areas are going to be put directly under the bureaucratic machinery, corruption will be rampant, things will become difficult, co-ordination will collapse, our competition overseas with the Germans and the Japanese in particular will become easily affected, and we will be pushed back. This will be the result.

For example, this is very widely known that in the NMDC there is an area known as Babubegan which was investigated for iron ore—everywhere, when you take over, investigation takes place—for which about Rs. 3 crores, I understand, was spent by NMDC. Now it is reported widely, and deputations are coming, that this particular thing is sought to be handed over to Chowgule. Many stories are afloat. If this story is correct and Chowgules get this, they will be getting the advantage of Rs. 3 crores which was spent for the purpose of prospecting. So, it is a move against the public sector, against a very vital area, where we will be wiped out in the international field. So, I would like to know what the policy of the Government is.

I find dismemberment of SAIL, dismemberment of CSIR, dismemberment of Samachar and dismemberment in the matter of recruitment by the nationalised banks. Everywhere dismemberment is taking place to the point of disintegration. This is a major adverse reversal of a national policy which will affect our self-sufficiency, which will make us subordinate to international cartels, a major reversal of a policy which has proved to be beneficial. I, therefore, oppose the introduction of this Bill.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : Sir, I do not wish to have a lengthy discussion. That will come at the consideration stage. But for the benefit of the hon. Member who has raised certain objections, let me first inform him that there is no need for a financial statement because there would be no expenditure involved from the Consolidated Fund of India.

Secondly, with the steel companies or steel factories construction in over

two years coming to an end, the Hindustan Steel works Construction Ltd. would undertake several other works not connected with steel. In fact, they are already engaged in more work not connected with steel than with steel. in steel Plants like Bokaro and Bhilai. Very soon, they will have to wind up from there. We are looking for foreign partners for them to take work in third countries. Therefore, the purpose of putting that company as an appendage or a part of the steel plants will not be beneficial to the construction company which employs a large number of people and which has to find work both inside India and outside India.

SHRI C. M. STEPHEN : And help the Dastur & Co.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Why encourage the Dastur & Co.?

SHRI BIJU PATNAIK : I am talking of construction works. The Dastur & Co. is not a construction company.

SHRI VAYALAR RAVI : It is a designing company.

SHRI BIJU PATNAIK : The HSCL is a contracting company; it is a construction company.

Then, the MECON are a design and construction company. This company is also taking work in international market, like, in Nigeria and other countries. It is taking a large number of work for steel plants. All over the world, the designing companies, the design consultants, are separated from the producing companies. They have then a great viability. It is so all the world over. They are supposed to be an independent authority, like a judicial authority. They take a designing contract and they do it. If they are a part of the producing company, then it will have an adverse effect. If the steel plants do not come up rapidly, then MECON will have hardly any work in India. Therefore, they have got to look forward to works outside India. I am happy to say that I will be able to give them a lot of work in the third countries. It is for this reason that MECON has been made an independent authority.

Similarly, about refractories, first they were captive refractories. Now, they are expanding in a large way. The largest plant will be at Bhilai itself. But a separate company outside the SAIL is thought of because it is to sell a large part of its products outside steel group itself.

The hon. Member has agreed to the major thing and that is the integration of the steel plants. The holding company idea was started by my predecessor, Mr. Kumaramangalam. I am only taking it up to a final stage of making one company. It is not a part of the Ministry. It will be a separate company. Instead of a holding company, it will be an owning company with full authority to deal with the production of steel.

The NMDC, the major supplier of iron ore to the steel plant, is being separated from there to make it a captive mine of the steel plant. It will come under SAIL. So, the hon. Member need not have any fear that this company is being taken away by some bureaucrat or an administrative Ministry. The NMDC was only dealing with iron ore mine. The Government has decided to give them other non-ferrous areas, like, aluminium, chrome, tin, manganese and whatever other things come in other non-ferrous areas also. They have got also to develop a consultation service because we get demand from various developing countries to send consultancy service from here for mine planning, as is called, in which we have a certain amount of weakness. We have to build that up :

These are the various considerations. It will only increase the efficiency of the entire thing. I would request the hon. Member not to raise his objection to the introduction of this Bill.

SHRI C. M. STEPHEN : The point I was making was this: here was a particular set-up tried in the course of three years and found to be absolutely beneficial in this result.....

MR. SPEAKER : You can raise it during the debate.

SHRI C. M. STEPHEN : Why then did you find it necessary to have a different set-up ? I would also like to be enlightened....(Interruptions).

MR. SPEAKER : Not now. There is a stage for it, later, when you can raise it.

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for restructuring of the iron and steel companies in the public sector so as to secure better management and greater efficiency in their working and for matters connected therin or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BIJU PATNAIK : Sir, I introduce the Bill.

13.25 hrs.

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : प्रध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 223 की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जो मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया है, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि उन्होंने इस हाउस को मिल्लोड किया है—एमजेसी की अप्रूवन लेने के लिए जो तथ्य उन्होंने बताये थे कि प्राइस राइज है, तथा एड आर्डर की प्रावलम है।

MR. SPEAKER : You yourself told me that you would produce additional material which you have got. Again you want to raise it....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I have given every detail to you.

MR. SPEAKER : Merely your giving is not sufficient. I have to look into it.

13.26 hrs.

ELECTION LAWS (AMENDMENT)

BILL**

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951 and the Indian Penal Code.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, and the Indian Penal Code."

The motion was adopted.

SHRI SHANTI BHUSHAN : Sir, I introduce the Bill.

13.26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

13.26 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER : Matters under Rule 377. Mr. Ram Copal Reddy, He is not here....

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : Sir, I want to make a submission.

श्रीमती शृंगारल मोरे (बम्बई उत्तर) : प्रध्यक्ष महोदय, मैंने भी रूल 377 के अधीन मंत्री महोदय को ध्यान देने के लिए एक नोटिस दिया था जिसका जवाब मंत्री महोदय देना चाहते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If the Minister wants to reply, he can inform the Speaker and reply tomorrow.

श्रीमती शृंगारल मोरे : मैंने स्पीकर साहब को इंकार्ड किया था कि आप मंत्री महोदय को रिप्लाई देने के लिए कहे। यह मैंने 14 तारीख को कहा था। जिसके लिए मिनिस्टर साहब ने भी श्री स्पीकर साहब ने भी एसी किया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under rule 377, if the Minister wants to reply, the procedure is, he can inform the Speaker and then reply. Unfortunately, he has not informed the Speaker. If he wants to reply, he can inform the Speaker and reply tomorrow, if he wants.

स्त्रास्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रगति किसी स्तर पर मानवीय सदस्या ने किसी चीज के बारे में कोई जवाब मांगा है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो सदा जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, 377 में इस तरह से नहीं किया जाता है।

*Introduced with the recommendation of the President.

**Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2 dated 22-12-77.

बी राज नारायण : मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी बात को सदन से छिपाना नहीं चाहता हूं । . . . हमें याद नहीं है ।

MR. DEPUTY SPEAKER: The Minister can reply tomorrow. We will send him the extract of what the hon. Member said the other day.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : Sir, I want to make a submission. The time allotted for the Resolution about the recommendations of the Railway Convention Committee is only one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : When we take up that Resolution, you can make that submission.

(i) FAILURE TO INCREASE THE PRICE OF SUGAR CANE

बी रामधारी शास्त्री (पदरीता) : हमारे देश में करीब दस करोड़ लोग गन्ने की खेती पर निर्भर करते हैं । हमारे देश में 253 चीनी मिले हैं । छोटी छोटी खंडसारी की इकाइयां सात हजार में प्रधिक हैं । इन इकाइयों में लागभग बारह लाख लोग छोटे बड़े मिल कर काम करते हैं । केवल पन्द्रह प्रतिशत लोगों के लिए इस सरकार ने सस्ती चीनी की व्यवस्था कर रखी है । हम उम्मीद करते थे कि हमारी सरकार चीनी नियंत्रण मुक्त कर देगी, चीनी की होगी । लेकिन केवल पन्द्रह प्रतिशत लोगों की खातिर सरकार ने एक नकली कंट्रोल कायम कर रखा है और 8·5 प्रतिशत लोग सस्ती चीनी से बंचते हैं । उनको चीनी पाने के लिए खुले बाजार में चीनी खरीदनी पड़ती है । उनको सस्ते दामों पर चीनी नहीं मिलती है । पन्द्रह प्रतिशत लोग दो रुपए पन्द्रह पैसे किलो चीनी पाते हैं और शेष 85 प्रतिशत लोग साड़े बार से लेकर पांच रुपए तक के भाव पर पाते हैं । प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री का भी व्यापार भावा था कि यह कंट्रोल

हट जाएगा लेकिन वह नहीं हटा और पूरानी व्यवस्था चली आ रही है ।

इसके अलावा जो सबसे बड़ा किसान विरोधी काम सरकार ने किया है वह यह है कि चीनी पर लगी हुई एक्साइज ड्यूटी में साड़े सतरह प्रतिशत की छूट देंदी है और यह 85 करोड़ की राशि बन जाती है । 85 करोड़ की छूट 253 मिल मालिकों को दी गई है । लेकिन सात हजार खंडसारी यूनिटें जो हैं जिसमें छोटे जोग लगे हुये हैं उनको यह छूट नहीं दी गई है । जनता पार्टी की पालिसी है कि छोटे छोटे आदमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा । लेकिन उनको एक्साइज ड्यूटी में कोई छूट नहीं दी गई है । उन पर एक्साइज ड्यूटी में निरन्तर बढ़ दी की जाती रही है । महाराष्ट्र की बात मैं आपको बताना चाहता हूं । वहां पर 1974 में 1180 रुपए यह थी । मई में इसको बढ़ा कर 2360 कर दिया गया थानी डम्पना कर दिया । मार्च, 1975 में उसको बढ़ा कर 5900 रुपया कर दिया गया । इस प्रकार मेरी सीधे-भीधे एक्साइज ड्यूटी को पांच गुना कर दिया गया है । इस साल सरकार ने 85 करोड़ की छूट मिल मालिकों को एक्साइज ड्यूटी में दी है । उन्होंने गन्ने के दाम को नहीं बढ़ाया है । साथ ही खंडसारी के जो छोटे छोटे उद्योग-पति हैं उनको कोई छूट नहीं दी गई । उस पर आज भी पांच गुना एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है ।

1948-49 में स्वर्गीय रफी इहमद किदवई ने खाद्य मंत्री के रूप में गन्ने के दाम तय करने के लिए एक कार्मूला निकाला था जो किदवई कार्मूला नाम से बड़ा भश्तुर हुआ था । उस सिद्धान्त के अनुसार 1948-49 में दो रुपए मत गन्ना बिका था और 32 रुपये मत चीनी । एक सिद्धान्त तय हो गया था । लेकिन

[रो रामधारी चांदी]

आज गन्ने के दाम में कमी आई है। चीनी के दाम में किसान का हिस्सा जहां 62 प्रतिशत होता था वह आज छठ कर 43 प्रतिशत रह गया है।

सरकार का कहना है कि चीनी मिल मालिकों को बाटा हो रहा है, चीनी मिलें बाटे में जा रही हैं। रिजर्व बैंक के अध्ययन पर आधारित जो रिपोर्ट है उनको जो गुद लाभ विकिंग कैपिटल पर हुआ है वह 1970-71 में 0.2 प्रतिशत हुआ है, 1971-72 में 7.5 प्रतिशत हुआ है, 1972-73 में 15.7 प्रतिशत हुआ है, 1973-74 में 10.8 प्रतिशत हुआ है और 1974-75 में 9.3 प्रतिशत का गुद लाभ हुआ है। उसके बाद भी यह कहा जाता है कि वे बाटे में बत रही हैं और इस आधार पर उनको एक्साइज ड्यूटी में छूट दे दी गई है।

यह कहा जाता है कि किसान को गन्ने के दाम अधिक देने की इसलिए गुदा-इश नहीं कि मौजूदा स्थिति में अगर दाम बढ़ा दिए गए तो किसान अधिक गन्ना बोना चुक कर देंगे, उत्पादन गन्ने का बढ़ जाएगा। मौजूदा हालत यह है कि पानी, विजली, खाद, मजदूरी के दाम चौ-गुने बढ़ गये हैं पिछले चार वर्ष में। इस आधार पर किसान के गन्ने के दाम कम से कम पन्द्रह रुपए किटल होने चाहिए। यह हमारी मुख्य मांग है। चीनी मिल मालिकों को 1940 से लगातार सबसिदी दी जा रही है। क्या बज़ह है कि किसानों के हितों की रका करने से सरकार करत-राती है और उन के गन्ने के दाम बढ़ाना नहीं चाहती?

बोद्ध ता० को कृषि राज्य मंत्री ने इस पर हुई बहस में स्वीकार किया था कि अगर चीनी को मुक्त कर दिया जाए और सरकार इस दंग से रिलीज करे जिसमें

3 ह० किलो चीनी बिके तो कोई बज़ह नहीं है कि किसानों को गन्ने का दाम 15 ह० न दिया जा सके। यह कृषि कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है। इसलिए जब कृषि राज्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है और गन्ने के दाम में कमी आयी हुई है, किसान को नुस्खान हो रहा है तो मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो यह कि सरकार जिस अनुपात में चीनी मिलों को एक्साइज ड्यूटी में छूट देती है उसी अनुपात में छोटी छोटी खंड-सारी इकाइयों को भी लूट दी जानी चाहिए ताकि वह किसानों को गन्ने का उचित दाम दे सके। यहां मान्यवर, एक सूचना दे दूँ कि गुड के एक्सपोर्ट की बदल ची, एक सूचना या गई कि गुड एक्सपोर्ट होगा विदेशों में, इससे जो गन्ना 8 ह० प्रति किटल मुजफ्फर नगर की खंडसारी बूनियों में बिक रहा था उसका दाम 10 ह० हो गया। हम नहीं जानते कि कल चंडी जी क्या बयान देंगे, उन्होंने खोखणा कर दी कि अब गुड का एक्सपोर्ट नहीं होगा। परिणाम यह हुआ कि फिर से गन्ने का दाम खंडसारी बूनियों में 10 ह० से बढ़ कर 8 ह० प्रति किटल हो गया। इसलिए हमारी मांग है कि सबसे पहले आप खंडसारी पर भी मिलों के अनुपात में एक्साइज ड्यूटी में छूट दें। दूसरी बात यह कि आप गुड का एक्सपोर्ट खोल दें। अगर देर से खोलेंगे तो उसका लाभ आपारियों को होगा। और अगर आप आज कल एक्सपोर्ट खोलेंगे तो उसका लाभ किसानों को होगा। तीसरी बात यह कि चीनी की जो दोहरी मूल्य प्रणाली है इसको समाप्त किया जाये और 3 ह० किलो पर इस तरह से रिलीज की जाय चीनी बाजार में ताकि शहर और गांव के बाजारों में चीनी 3 ह० पर मिले। तब जा कर गन्ने का दाम 15 ह० प्रति किटल किसानों को किया जा सकत है।

मान्यवर, मुझे शमं आयी माननीय कृषि राज्य मंत्री का जवाब मुनकर। वह कहते हैं कि हम कंट्रोल इसलिए नहीं हटायेंगे कि कुछ सोग सस्ती चीनी खाने के आदि हो गये हैं। मैं कहता हूं कि अगर 15 फीसदी लोग सस्ती चीनी खाने के आदि हो गये हैं तो यह मंत्री जी ने समझ लिया है कि 85 फीसदी चुपचाप रहेंगे और 5 रु 0 किलो चीनी खायेंगे? इसलिए खंडमारी पर एक्साइब ड्यूटी खट्ट करनी चाहिये और गन्ने की कीमत बढ़ायी जानी चाहिये।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : मान्यवर, श्रीमती मृणाल गोरे ने कहा है कि कल वह नहीं रहेंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्राप्त उनको आशा दे दें जिसमें मैं उनका उत्तर संक्षेप में दे दूँ।

उत्तराधिकार व्यापार व्यवस्था : ठीक है, यह पहले हो जाने दीजिए।

(ii) MISMANAGEMENT IN THE C.M.I. LTD. AND EASTERN MANGANESE AND MINERALS LTD., DOMCHANCH, BIHAR

श्री रीतखाल प्रसाद बर्नी (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपने क्षेत्र की औद्योगिक समस्या जो अधिक व्यापार से सम्बन्धित है, सदन के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि ईस्टर्न मैग्नीज और मिनरल कम्पनी लिमिटेड और किल्वयन माइक्रोस्ट्रीज लिमिटेड कम्पनी में पिछले कई वर्षों से भिसर्नेजमेंट हो गया है जिसके कारण 4,000 मजदूर भूखों भरने की स्थिति में पहुंच गये हैं। इसीलिए इस संदर्भ में 1,000 से ज्यादा मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर किया हृषा एक भेषोरेंडम मेरे पास आया है जिसको मैंने माननीय विधि मंत्री को पिछले नवम्बर महीने में दे दिया था और कहा कि इस कम्पनी को टेक ओवर कर लिया जाय। इसकी सुचना मैंने श्रम

मंत्री, वाणिज्य मंत्री और खान मंत्री को भी दी थी कि यह कम्पनी बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है और इसके कारण 4,000 मजदूर भूखों भर रहे हैं और 13 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। इन 4,000 मजदूरों के अधिकारियों को भिलाकर यह संख्या 50,000 तक पहुंचती है जो संकटप्रस्त है। इसलिए मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां से 30, 40 करोड़ का अध्यक्ष निर्यात होता है। यह एक सबसे बड़ी कम्पनी है जो सबसे पुरानी और विश्व में विद्युत है। करीब साड़े तीन हजार बर्ग-मील जमीन इसके मालहत है, इसकी दूसरी फॉर्करियां हजारीबाग, कोडरमा, मूमरी, तलेया, गिरीडीह में हैं। इस के कार्यालय दिल्ली और कलकत्ता में भी हैं। इस कम्पनी ने 1960 से प्राविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं किया है उसमें मजदूरों का हिस्सा भी है और कम्पनी का हिस्सा भी है साथ ही साथ 1975 से भीतर मजदूरों को बेतन भी नहीं दिया गया है जो कि 45 लाख कम्पनी के पास बकाया हो गया है। इस तरह से मजदूर भूख-मरी की स्थिति में आ गये हैं।

मजदूरों में प्राविडेंट फंड अधिनियम के अन्तर्गत दर्कास्त भी दी कि उनके अधिकारिय निधि के पैसे मिलें, लेकिन 68-एच के अन्तर्गत उनको पैसा नहीं मिला है। इसी कारण वहां पर 13 मजदूरों की मृत्यु भी हो गई है जिसका पूरा विवरण मेरे पास है।

कम्पनी की दुर्दशा को जानने के लिए केन्द्रीय सरकार के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक टीम नवम्बर, 1976 में वहां पहुंची थी। उसने इसके दोषों की जांच-पड़ताल करके यहां पर रिपोर्ट भी दी थी कि इस कम्पनी को अधिनियम की आरा 209, 237 और 408 के अन्तर्गत अधि-

[श्री रोतलाल प्रसाद दर्भी]

ब्रह्मण करना चाहिये । लेकिन भीती तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

यह एक प्रतिक कम्पनी है, इसके माझे 7 लाख शेयर होल्डर हैं, लेकिन आज यह कम्पनी उन सभी शेयर होल्डर्स की पूँजी खत्म कर चुकी है । साथ ही साथ कम्पनी के डायरेक्टर्स ने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से 6 कम्पनियों का नियन्त्रण किया है और सारे भारतवर्ष में उस पूँजी से 23 कम्पनियां दूसरे प्रदेशों में खोली हैं सारे डायरेक्टर्स ने आम आदर्श कम्पनियां बना ली हैं । इस कम्पनी को अब इसके अफसर चला रहे हैं । सारे अफसर लखपति हैं, कोई भी 10, 50 लाख से कम नहीं है । इस प्रकार से आज भी कम्पनी की करोड़ों रुपए की पूँजी पड़ी है, इसके 200 से अधिक मकानात हैं और 500 एकड़ से ज्यादा जमीन भी प्राइवेट हैं और बहुत सी मज्जीनरी है । करोड़ों रुपए का माइक्रो स्ट्रोम और फैंबरीकेट भाइका पड़ा दूधा है ।

यदि सरकार इसे अविष्यहण कर के इन मजदूरों को राहत नहीं देती है तो ऐसी हालत में बहुत लोग भूखों मरने लगें । छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में अभ्रक के ग्रामाचा और कुछ नहीं है । अभ्रक भी हीरे जवाहारात की तरह बहुत ही बहुमूल्य बनिज है ।

मैंने भंडी भ्रोदय को 27 नवम्बर, 1977 को एक बैमोरेंडम भी लिखकर दिया था, लेकिन भीती तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है । इस दशा में मैंने सदन का ध्यान इससिए दिलाया है कि अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो 4,000 मजदूर यहां आकर सत्याप्रह करेंगे और एक विकट स्थिति उत्पन्न होगी ।

(iii) REPORTED NEWS ABOUT WRONGFUL CONFINEMENT OF MR. JUSTICE S. K. VERMA BY THE MANAGEMENT OF SWADESHI POLYTEX LTD., GHAZIABAD

श्री शरद यादव (जबलपुर) : उपायक महोदय, मैं यह बहुत संचिन मामला आपके सामने उठा रहा हूँ । मैंने चाहा तो यह या कि यह कांचित अटेंशन या किसी और रूप में दिया जाता, लेकिन हर महत्वपूर्ण सवाल को यहां 377 में डाल दिया जाता है ।

स्वदेशी पोलिटेक्स एक मिल है जो आधुनिक धारा तंयार करती है । एक स्वदेशी काटन मिल है आपको मालूम है कि 8 तारीख को इस सदन में उस मामले पर बहस हो चुकी है । वहां 13 भजदूरों की जाने जली गई । यह सब जो मामला गडबड चल रहा है, या सडाई-सडाई चल रही है, इसके पीछे राजा राम और सीताराम नाम के दो पूँजीपति भाई हैं । यह जो सत्ता में सांद है, ये लड़कर इस तरह से बहां पर होली खेल रहे हैं और लोगों की जान जा रही है ।

स्वदेशी काटन मिल में 8 हजार भजदूर हैं । आधुनिक धारा बनाने वाली स्वदेशी पोलिटेक्स मिल, जो गाजियाबाद में है इस पर सीताराम जयपुरिया का कब्जा है । ये सीताराम जयपुरिया साहब पूँजीपति तो ही ही लेकिन राजनीति में भी चुस गए हैं । जब कार्यस की सरकार भी, तब भी बहुत ताकतवर ये और धर्दूजनता सरकार है तब भी ताकतवर हैं ।

एक बड़ी भंडी घटना यहां घटी, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश इलाहाबाद के हाईकोर्ट के भूतपूर्व लीफ जस्टिस श्री एस० ब० वर्मा के बहां शेयर्स के मामले में काफी घपला है । कानपुर की स्वदेशी मिल ठीक नहीं चल रही है । उसके 14 लाख शेयर्स स्वदेशी पोलिटेक्स गाजियाबाद में हैं । उसके शेयर बेचना चाहते हैं और जो सीताराम जयपुरिया हैं उनके शेयर उसमें 2200 हैं, लेकिन वह किसी तरह से भी उस पर कम्जा बनाए बैठे हुए हैं ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सारी गडबड के कारण कहा कि सीताराम जयपुरिया उस बैठक की

प्रध्यक्षता नहीं करेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी एस० के वर्षा, को प्रध्यक्षता करने के लिए कहा गया। जब वह 6 तारीख को वहां पहुंचे तो सीताराम जयपुरिया ने कानपुर से बुलाये गए गुडो को सहायता से उन्हें एक बाधरूम में बन्द कर दिया, और डाई घंटे तक वहां रखा। जो शेयरहोल्डर्ज शेयर्ज बेचना चाहते हैं, उन्होंने याने में रपट की। लेकिन एस० भी और कलेक्टर आदि ने कोई कार्यवाही नहीं की। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को डाई घंटे तक बन्द रखा गया, लेकिन सिर्फ सारी वर्दी में सिर्फ दो सिपाही वहां पहुंचे। श्री वर्षा किसी तरह से पीछे के दरवाजे से निकल कर भागे और उन्होंने भी रपट लियाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यह बहुत संगीन घटना है कि जो आदमी हिन्दुस्तान के सब से बड़े प्रांत का मुख्य न्यायाधीश रहा है, उसे डाई घंटे तक बन्द रखा गया, लेकिन सीताराम जयपुरिया इतना ताकतवर हो गया है कि उस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। लगता है कि वह आई० डी० बी० आई०, एल० आई० सी० और वित्त मंत्रालय से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है।

स्वदेशी काटन मिल में आठ हजार मजदूर कफी समय से ग्राही और भुखमरी से पीड़ित हैं। दो वर्ष से उन्हें समय पर तन्त्रज्ञान नहीं मिल रही है। आई० डी० बी० आई० का अधिकारी वर्ष सीताराम जयपुरिया के साथ मिला हुआ है और चौदह लाख रुपये के शेयर्ज नहीं बिकने देता है। मैं वित्त मंत्रालय और इंडस्ट्रीज मंत्रालय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि एशिया की सब से बड़ी धारा बनाने वाली कानपुर की यह काटन मिल आज खतरे में है, वहां के आठ हजार मजदूरों के भविष्य का प्रश्न है, लेकिन सीताराम जयपुरिया और आई० डी० बी० आई० के बेयरमेन उस कारकाने को बर्बाद

करने पर तुले हुए हैं; क्यों नहीं इस बारे में उचित एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं शेयर्ज को बेचने की अनुमति दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 1977 में लैंड रेवेन्यू के अन्तर्गत एक रिसीवर भी नियुक्त किया तथा कम्पनी के एक करोड़ रुपये की कीमत के स्वदेशी पोलिटेक्स के बेयर भी एटैच कर लिये, ताकि उन्हें बेच कर सरकार का छण तथा मजदूरों का बेतन चुकाया जा सके। परन्तु आई० डी० बी० आई० का सहयोग न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार उन लेयरों को अभी तक नहीं बेच सकी है।

इस लिए मैं कहता चाहता हूँ कि इस बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाये, सरकार इस भास्तै में इन्टरव्हीन करे और जो लोग सीताराम जयपुरिया के साथ मिले हुए हैं, उन्हें सब्ज सब्जा दे, ताकि आठ हजार मजदूरों की जान बचे। सत्ता के सांडों से हमें कोई मतलब नहीं है। उस कारकाने का बचाव होना चाहिए और आई० डी० बी० आई० के जो अफसर सीताराम जयपुरिया से मिले हुए हैं और कांग्रेस सरकार के समय से गुलठरे उड़ा रहे हैं, उन के खिलाफ कार्यवाही की जाये। क्या जनता सरकार के आने के बाद भी वह व्यक्ति इतना ताकतवर है कि एल० आई० सी०, वित्त मंत्रालय और इंडस्ट्रीज मंत्रालय उसके विशद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में विस्तृत बयान दे कि चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किये जाने के बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

(iv) FIRE ACCIDENT IN SAMACHAR OFFICE, BOMBAY

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Sir, recently four persons died because of the fire accident in Samachar Office in Bombay. You know that there are so many accidents in railways; there are so many stabbings in

[Shri P. Rajgopal Naidu]

Ambassadors' Offices and there is so much of sabotage in the country. Many people suspect that this is also a sabotage.

Government has not given the details with regard to the recent fire accidents. Government has also not said anything about the help given to the families of victims, whether compensation was given or not. It is creating a scare in the country. Unless Government takes stern measures to put down all this violence it will create confusion in the country. Therefore, I request the Government to investigate into the matter and let the House know about the details.

(v) FAILURE TO GIVE CITIZENSHIP RIGHTS TO REFUGEES WHO CAME TO INDIA AFTER 1971 INDO-PAK WAR

ओं भागु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपराज्यम महांदय, मैं भाज उस समस्या को सेवा चाहता हूं जिस का समाधान भाज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था यह समस्या सेत्रीय नहीं है, किन्तु एक राष्ट्रीय समस्या है। 1971 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के समय सिन्धु और गुजरात की सीधा पर रहने वाले जो लोग ये उन्होंने हमारी सेना को रास्ता बताया। मैं उन सब गांवों का देख कर आया हूं, उस समय जब हमारी सेना पाकिस्तान पर आक्रमण करने जा रही थी तो उन्हें रास्ते का पता नहीं था कि कौन से रास्ते से जा कर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान के अन्दर रहने वाले उन व्यक्तियों ने उसे रास्ते बताये जिस के कारण हमारी भारत की सेना पाकिस्तान को परास्त करने में सकून हां गई। परिणाम यह हुआ कि हमारा जो समझौता द्वाया उस समझौते में जब हम उस क्षेत्र को खाली कर के यहां आए तो क्यों कि उन्होंने भारत की सेना को रास्ता बताया था इसलिए भगर वे पाकिस्तान में रह जाते तो दो बातें उन के साथ होती—या तो उनका जीवन पशु-तुल्य होता या वे मात्र के बाट उतार दिए जाते, इसलिए वे हिन्दुस्तान में जले आए। उन की संख्या सार्वत्र आधा लाख है। भाज उनकी दशा अर्थात् दवानीय है। मुझे आश्वर्य होता है कि बंगला देश के बच्चियों के रहने

के लिए देवरी कैम्प में और अन्य स्थानों में पक्के मकान थे, लेकिन उन के लिए एक तम्बू नहीं, एक टेन्ट नहीं और हमारे भवालय ने गत बर्ष उनको आवास के लिए 2 सौ रुपये दिए। क्या दो सौ रुपये में कोई मकान बन सकता है? 200 रुपये में तो कोई बास का लघर भी नहीं बन पाता है। जैसे तंसे कर के उन्होंने जो ज्ञोपही बनायी वह आग लगने के कारण जल कर ज्ञाक हो गई। अब आज उन के रहने के लिए कोई मकान नहीं है। जाने के लिए उन्हें तीस रुपये मिलते हैं और बालको को 15 रुपये मिलते हैं। तीस रुपये में आज को महंगाई के जमाने में क्या कोई जीवन का निर्वाह कर सकता है। उन बच्चों को पूरा राजन फिले, वह भी नहीं होता। केवल 30 रुपये उनको मिलते हैं और आचर्य की बात यह है कि आज उन में से कोई भारतीयों के कैम्प में अन्यायक के पद पर लग गया तो गत 6 बर्ष में दो हुई सदस्ती उस से रिकवर हो रही है। वह कहां से देते? उन के पास जाने के लिए पैसा नहीं और उनसे रिकवरी के लिए आईंडर चले गए। हम ने कई पत्र लिखे भवालय को कि कम से कम रिकवरी तो बन्द कर दी जाय। मुझे आपसे यह कहना है कि आखिर इनका क्या अपराध है, क्या दोष है? इन का अवरास तो यही था कि जो हमारी भारत की सेना वह आक्रमण करने के लिए गई उसे उन्होंने रास्ता बताया और यही नहीं, भारत सरकार ना जिस में कोई पैसा नहीं लगता, एक नागरिकता का अधिकार भी उन को वह नहीं दे सकती। पुरानी सरकार तो कह रही थी कि इन को बापस भेजेंगे। हमारी उन के साथ बात चीत चल रही है। कैसे ये बापस जाएंगे। जाएंगे तो भौत के बाट उतारे जाएंगे। भगर उन्हें नागरिकता हा अधिकार होता तो उन में कई ऐडबोकेट्स हैं, कई पोस्ट ऐ यूट हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती थी या वे कोई बन्दा कर सकते थे। भाज वे पहुंच तुल्य जीवन तो नहीं बिताते। यह समस्या बहुत बड़ी है। मैं ने इसलिए

इस के ऊपर कालिंग प्रटेंशन दिया था। भाज उन के भरने जीने का प्रश्न है। उन के लिए दबावियाँ नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, शोकने को कागड़त नहीं, रहने को मकान नहीं, कुछ भी उन के पास नहीं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर क्या भारत सरकार केवल 200 दिये साल में उनके मकान के लिए टेकर बैठत बैठ जायेगी? मैं निवेदन करूँगा कि सरकार उन के आवास की, उन के एजुकेशन की व्यवस्था करे और भीमातिशीघ्र रिकवरी बन्द कर। मैं जानता हूँ केवल एक मंत्री महोदय का यह काम नहीं हो सकता। सारा मंत्रिभंडल बैठकर इस के ऊपर जल्दी निष्पत्य करे और निष्पत्य कर के उन्हें नागरिकता का अधिकार दे दे ताकि वे पक्षुवत जीवन न बिता कर भारत के अन्य नागरिकों की तरह अपने पुरुषार्थ से पंजी कप्रा सके और दबनीय दमा में न रहें।

(iv) SALE OF SEVERAL THOUSAND EAST PAKISTAN REFUGEE WOMEN FROM MANA CAMP

SHRI SAMAR GUHA (Contd) : Sir, I want to draw the attention of the House through you to a very shocking and at the same time shameful affair that has been reported to the Chief Minister of West Bengal by a delegation of MLAs who were sent to Mana camp, Deoli camp and other different camps where the former East Pakistan refugees have been rotting for periods ranging from 7 to 15 years. Recently a group of MLAs was sent there to see the condition of the refugees in those camps. On the 17th, they and also 17 members of those refugee camps have made a representation to the Chief Minister of West Bengal wherein they have said that about 10,000 girls and women have been taken away from the Mana camp and other camps also and sold outside.

SHRI SHYAM NANDAN MISHRA (Begusarai) : What are the authorities doing?

SHRI SAMAR GUHA : There are serious complaints against the authorities. The girls and women have been subjected to shameful behaviour. There

are reports against the police also that some of the girls were taken away and atrocities committed on them. You will remember, I raised this matter of the rotting conditions in which the refugees live in different camps for 7 to 15 years. 1,30,000 former East Pakistan refugees have been kept by the Government deliberately in Mana and other camps, from where it is very difficult for them to come here and get any information whatsoever. They cannot come to the cities and make complaints. All kinds of reports against the employees and some other agencies are also coming again and again. The Minister for Rehabilitation is not here. I want to make a humble suggestion through you to the Minister that he may make a statement on this matter. The report has come out in Ananda Bazar Patrika of 18th December and it has been submitted by responsible persons who visited the camps. I would humbly request the minister to enquire into the matter about the behaviour meted out by the government employees and also many other agencies working there to the refugees who have been kept in Mana camp, Deoli camp and other camps in Dandakaranya. An enquiry should be made and a report presented here. The conditions in which the refugees are living are almost at a sub-human level. A team of Members of Parliament should visit these refugee camps and make a report to the Government about their condition and also the policy in regard to their rehabilitation. These refugees who met the Chief Minister of West Bengal made an appeal that they want to go to Andamans. The other day when I raised the matter, the minister said, they will not be sent to Andamans. Almost every session I have been bringing this matter to the attention of the House. The Government promised that they will be sent to Andamans, but the Minister said the other day that they will not be sent to Andamans. The areas have been cleared there and these refugees want to go there. I would again humbly submit, let the minister make an enquiry about this report that has come out. Also, let him send a team of Members of Parliament to these refugee camps to see the conditions there and make a report and also submit a report about the policy and programme for their rehabilitation.

STATEMENT RE : APPOINTMENT BY INDIAN RED CROSS SOCIETY OF OFFICIALS ON A COMMITTEE TO DISTRIBUTE RELIEF MATERIALS

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (भी राजनारायण) : श्रीमन्, 24 जून,

[श्री राज नारायण]

1977 को रेड-क्रास के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न श्रीमती मुमाल गोरे ने यहां पर उठाये थे। इन का यह कहना सही है कि हम ने आश्वासन दिया था कि इस की जांच कराई जायेगी। अपने उस आश्वासन के मुताबिक हम ने जांच आरम्भ की और हम ने घर मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखा कि सी० बी० आई० के द्वारा इस की जांच कराई जाए। सी० बी० आई० के अधिकारी गये लेकिन मन्त्र में सी० बी० आई० के अधिकारियों ने मुझ को यह सूचित किया कि क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, इसलिए इस की इक्वायरी सी० बी० आई० के द्वारा नहीं की जा सकती। फिर हम ने घर मंत्री को कहा कि आधिकर इस की जांच की कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सी० बी० आई० और मन्त्र लोगों ने कहा कि इंटेलीजेन्स बोरो के जरिये जांच कराई जा सकती है। उस में भी योड़ा विलम्ब हुआ। तो हम ने एक और रास्ता निकाला कि कम से कम हमारा स्वास्थ्य विभाग, जितना रुपया उस ने रेड क्रास को दिया है, उस रुपये की तो इक्वायरी करा ही सकता है। उस इक्वायरी को करते समय जो चीजें भिल जाएंगी, तो इस सम्बन्ध में और ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी। तो सदन को जो मैंने आश्वासन दिया था, इन स्प्रिट हम ने उस के मुताबिक तत्कालीन कदम उठाए थे, यह मैं सदन को आशवस्त करना चाहता हूँ।

श्री श्याम नम्बन मिश्न (बेगूपराय) : अब इस में आप क्या कर रहे हैं।

श्री राज नारायण : उसी पर मैं आ रहा हूँ। क्या इन के प्रश्न थे। एक तो इन का प्रश्न यह था कि जो इक्वायरी की बात की गई थी, उसमें फरदर कार्यवाही क्या हुई। फरदर कार्यवाही यह हुई कि जो रेडक्रास के चैयरमैन थे, वे जो अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सम्मेलन हो रहा था, मूलकों का, उसमें चले गये थे। इसलिए इस में योड़ा सा विलम्ब

हुआ उन के बहां रहने से। जब वे बहां से लौट कर आए, तो उन की तरफ से यह आफर आया कि वे स्वतः जांच कराने के लिए तैयार हैं और जांच होने के बाद यह पाया गया कि रेड क्रोस की तीन कारों हैं, डी०ए० ८६५८, डी० ए०९ बी० ६१४१ और डी० ए०९ सी० ८२९५। इन का कहना था कि इन पर से रेडक्रास का चिन्ह हटा दिया गया। मंत्रालय गया था रेड क्रोस का कह कर ताकि कस्टम ड्यूटी खत्म हो जाए मगर बाद में रेड क्रोस का चिन्ह हटा दिया गया और वे पर्सनल स्टाफ कार की तरह से इस्तेमाल की जाने लगीं। एक तो यह चारंथा।

तूसरा कहना यह है कि कुछ रेलवेज ने रेड क्रोस लालों को इवर उबर आने जाने की सहायितें दी हैं और उस में उन्होंने उन का काफी दुष्प्रयोग किया है। तो हम ने रेलवे मंत्री जी से रिक्वेट की है कि वे इस की जांच कर लें कि इसमें कुछ दुष्प्रयोग हुआ है या नहीं। उस की जानकारी जब रेल मंत्रालय से मिलेगी, तो माननीय सदस्या और सदन को दे दी जाएगी।

अबली बात यह थी कि स्टेट बैंक के ४ चैंक ५२,००० रुपये के विद्वान कर लिये गये प्रीर जो रुपया विद्वान किया गया प्रीर इन का कहना था कि वह ठीक ढंग से नहीं हुआ है। इस के लोकनेट्स भी गायब हैं।

चौथा प्रश्न जो आज का था, वह यह था कि आंध्र प्रदेश के लिए जो रिलायिक कमेटी गई है, उन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन के ऊपर पहले से आरोप ये जबकि बंगला देश के समय रेड क्रोस के जरिये माल भेजा गया था और जिस की बाजार में बहुत शीहरत हुई थी। वह गलत ढंग से बेचा गया था प्रीर उस को बेच कर धन कमाया गया था। उनके बारे में इनका कहना था कि ऐसे लोग भी वहां पर गये थे क्या? इसके बारे में हमारा कहना यह है कि २६ तारीख को हमारे स्टेट मिनिस्टर

और एडीशनल सेकेटरी वहां जा रहे हैं जो जा कर के जांच करेंगे कि सचमुच में उनके जरिये से माल का वितरण हो रहा है या नहीं ।

श्री बलंत साठे (प्रकोला): मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो जांच करायी है, क्या आपको मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जो रेडकास की है, उसने, खास कर बमला देश में जो रेडकास का मामला हुआ, उस प्रकारण के बारे में उस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने जांच करा कर आपको एक खत लिखा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच करायी है और उन्हें संतोष है कि कोई दुष्योग भारतीय रेडकास द्वारा नहीं हुआ है । क्या आपने वह खत देखा है ?

श्री राज नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारे स्टेट मिनिस्टर जा रहे हैं, एडीशनल सेकेटरी जा रहे हैं । वे जा कर यह जांच करेंगे कि आंध्र में, तामिलनाडु में, केरल में, रेडकास का जो माल माया है उसका सम्मुचित रूप से वितरण हुआ है या नहीं ।

हमने एक अहतियती कार्यवाही कर ली है कि आंध्र प्रदेश में जो रेडकास सोसायटी है वह स्वतः उस माल को वितरित करे जो माल यहां से जाए । यह उसकी जिम्मेदारी नहोगी ।

एक प्रश्न आया कि क्या हम स्टेट मवन्मेट के जरिये से मदद कर रहे हैं या नहीं ? जितनी भी मदद आंध्र ने मायी, केरल ने मायी, तामिलनाडु ने मायी, वह सारी की मारी मदद भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल स्टोर आरगेनाइजेशन द्वारा दी गयी । इस आरगेनाइजेशन द्वारा आंध्र प्रदेश को 35 लाख, 9 हजार, 375 रुपये के मूल्य की रोगनाली, कोटनाली और बेकलीन आदि दवाइयां भेजी गयीं । हसी आरगेनाइजेशन द्वारा धन्व राज्यों की श्री

दवाइयां भेजी गयीं जो कि टूफान से पीड़ित थे । इनका विवरण इस प्रकार है । तामिलनाडु 5 लाख, 61 हजार, 625 रुपये की दवाएं भुगतान आघार पर, लक्षद्वीप को 94,525 रुपये की दवाएं भुगतान आघार पर भेजी गयीं । केरल को हैजा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये की दवाएं मुफ्त भेजी गयीं । जितनी भी मदद राज्य सरकारों ने हम से मायी, वह सब हमने भेजी है । अब इनके सवालों में जो जौधी सवाल है ।

श्री बलंत साठे : लेकिन जो करण लोगों को दी गयी ?

श्रीमती मृताल गोरे (बम्बई उत्तर) : मेरा जो करण लोगों के लिए चाहै है उसके बारे में आप बतायें ।

श्रीमती मृताल गोरे : उसके बारे में कहा है कि जांच की जा रही है ।

श्री राज नारायण : आंध्र प्रदेश रेडकास सोसायटी आजकल वही इस सारे माल को वितरित कर रही है ।

श्रीमती मृताल गोरे : क्या आप स्वतंत्र रूप से इस सब की जांच करायेंगे, इसका जवाब मुझे चाहिए ? वह जवाब दिया जाए ।

श्री राज नारायण : वहां जो मेनेजिंग बाड़ी है इंडियन रेडकास सोसायटी की, उसने एक जांच बिठायी है । श्री सुविष्णव दत जो कि पहले विदेश सचिव थे भारत भूतपूर्व केन्द्रीय विजिलेंस कमिशनर भी रह चुके हैं, उन्होंने अधीन यह जांच हो रही है । माननीय सदस्या को इस जांच से संतोष नहीं है । उनका तर्क है कि जिस मेनेजिंग बाड़ी के विश्व आरोप है उसी मेनेजिंग कमेटी द्वारा जांच क्यों बिठायी गयी ? मैं सम्मानित सदस्या को इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ । परंग श्री दत की जांच

[भी राज नारायण]

के बाद कोई ऐसी स्थिति रहती है कि और जांच कराने की आवश्यकता है तो और जांच करा ली जाएगी और छोड़ा नहीं जाएगा। उनके इस व्याइंट में लाजिक है, तरं है कि जिस के बिल्ड शिकायत हो वही जांच करों बिठाए। इस बात को मैं प्रधान मंत्री जी तथा और सब लोगों को बता दूँगा। सम्मानित सदस्यों के प्रधार जो भाव हैं और सम्मानित सदस्यों के जो भाव हैं...

भी बसन्त साठे : दत्त साहब को यहां की प्रोसीडिंग भेज दें।

भी राज नारायण : भेज दी जाएंगी। प्रधान मंत्री, पूरी सरकार को इसकी जानकारी करा दी जाएगी ताकि कोई लेकूना न रहे।

हमें किसी पद का लालच नहीं है। अगर अपने कर्तव्य के पालन में हमें कड़ेमोटली यह मालूम हो जाएगा कि बाधा पड़ रही है तो पद को किसी भी अग हम छोड़ सकते हैं...

भी बसन्त साठे : किस को धम्की दे रहे हैं?

भी राज नारायण : उनको आम्बासन देता हूँ।

भी बसन्त साठे : हटने से उनको क्या सन्तोष हो जाएगा?

भी राज नारायण : उनको आम्बासन देना चाहता हूँ ताकि उनके मन में शंका न रहे कि हमारे और मैनेजिंग बाही के बेयर्बैन के बीच में कोई सांठगाठ हो गई है और सांठगाठ के जरिये ऐसी चीज हुई है। इसको हृषा करके वह अपने मन से निकाल दें। हम दुसरी बालाए बाले नहीं हैं, हम सीधे बालने वाले हैं, स्टेटफार्मर्ह हैं, औ सोचेंगे वही करेंगे जो कहेंगे वही करेंगे।

14:15 hrs.

RESOLUTION RE. FIRST REPORT OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : Sir, I beg to move :

"That this House approves the recommendations made in paras 5, 6, 7, 11, 14, 17 and 18 contained in the First Report of the Committee appointed to review the rate of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance which was presented to Parliament on the 17th November, 1977.

That this House further directs that the action taken by Government on the recommendations made in this Report, should be reported to the Committee".

Sir, by a resolution passed by Parliament on the 15th January, 1976 in the Fifth Lok Sabha and on 20-1-76 in the Rajya Sabha, the recommendations contained in paras 4, 5, 15, 16, 17 and 23 of the Eleventh Report of the Railway Convention Committee, constituted in 1973, in the matter of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues as well as ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance, were approved by Parliament with the further direction that the action taken by the Government on the other recommendations made in that Report, as well as in the Eighth and Ninth Reports, should be reported to the said Committee. The action taken on these reports has been duly advised to that Committee.

The recommendations made in the Eleventh Report of the Railway Convention Committee, as approved by Parliament, determined the rate of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues and other ancillary matters in respect of the financial year 1976-77.

With the dissolution of the Fifth Lok Sabha, the Railway Convention Committee constituted in 1973 became *unctus officio*. On the constitution of the Sixth Lok Sabha, a resolution was passed by this House on 2nd August, 1977 and by the Rajya Sabha on 4th August, 1977 constituting a new Railway Convention Committee, consisting of 12 members from the Lok Sabha and 6 members from the Rajya Sabha. As the recommendations of this Committee in the matter of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues and other

ancillary matters duly approved by Parliament in respect of the current financial year (1977-78) were not available at that time, the budget estimates were framed on the basis of the arrangements approved by Parliament in respect of the financial year 1976-77.

In their First Report, the Railway Convention Committee, 1977, have recommended that the financial arrangements between the Railway undertaking and General Revenues in the matter of dividend payable and other ancillary matters, as approved by the Fifth Lok Sabha in respect of the financial year 1976-77, may be continued in respect of the current financial year (1977-78) and the next financial year (1978-79) also.

As observed by the Committee, during the year 1976-77 the financial performance of the railways registered a marked improvement over the previous two years. The Committee have also noted with gratification that the budget estimates presented by me in June, 1977 for the year 1977-78 envisaged a net surplus of Rs. 32.50 crores as against the net surplus of Rs. 26.45 crores projected in the interim budget presented by me in March, 1977. I am happy to say that during the period April-October 1977, the Railways' earnings have shown a further improvement, in that our gross earnings are Rs. 89.5 crores more than the earnings for the corresponding period last year and the net working results are also better than the budget proportion for the current year by about Rs. 50 crores.

As the Convention Committee have pointed out in their Report under consideration, the Railways' indebtedness to the General Revenues under the Development Fund and the Revenue Reserve Fund continue to be substantial not withstanding the marked improvement in the Railways' financial performance. I agree with the observation of the Convention Committee, it would need several years of sustained effort on the part of the Railways to wipe out these liabilities. It shall, however, be the constant endeavour of the Railway undertaking to augment the earnings and to keep the working expenses under strict check in order that the loans taken from the General Exchequer may be repaid as quickly as possible.

With these few words, I commend the resolution for the consideration of this House. Before I sit down, I would like to express my grateful thanks to the Chairman and other Members of the Convention Committee for the arduous labour undertaken by them, for their sympathetic consideration of the Railways' problems

and for the expedition with which they have finalised their recommendations in this regard for the years 1977-78 and 1978-79.

MR. DEPUTY SPEAKER : Resolution moved :

"That this House approves the recommendations made in paras 5, 6, 7, 11, 14, 17 and 18 contained in the First Report of the Committee appointed to review the rate of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance which was presented to Parliament on the 17th November, 1977.

That this House further directs that the action taken by Government on the other recommendations made in this Report, should be reported to the Committee."

Shri Mohd. Shafi Qureshi.

श्री बोहूम्बद शाही कुरेशी (अनन्तनाथ) : डिल्टी स्वीकर साहब, मुझे इस बात की जांची है कि रेलवे कंवेंशन कमेटी ने प्रपनी जो पहली रिपोर्ट पेश की है इसमें उन्होंने तक-रीबन उन्हीं सिफारिशात को दोहराया है जो इससे पहले की रेलवे कंवेंशन कमेटी किया करती थी। मैं बजीरे रेलवे का काफी एहतराम भी करता हूँ लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह अखबार में एक परमानेट कौलम होता है मौसम का हाल बताने का इसी तरह से पिछले एक, दो महीने से रेलवे एक्सीडेंट्स कौलम ने भी मूरत अक्षियार करती है। अखबार पढ़ने पढ़ते जब मुबह आदमी मौसम का हाल मालूम करता है तो उसे यह भी खबर मिलती है कि रेलवे एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं। और पढ़ने वाला नाउम्मीद नहीं होता क्योंकि किसी न किसी सफे पर उसको इस किस्म की खबर जहर मिलती है।

जो रेलवे कंवेंशन कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास है इसमें दो तीन बातें काफी अहम हैं। कंवेंशन कमेटी ने रेलवे की कमाई की बढ़ी साराहना की है। जैसा कि मंत्री जी को मालूम है और अब उन्हें तजुर्बा भी हो गया

[बी मोहम्मद ज़ाकी कुरेही]

होगा कि रेलवे में सुधार लाने के लिये काफी हिम्मत, काफी बक्त, और काफी मेहनत की ज़रूरत होती है। और इसकी बिगाड़ने में उतना बक्त नहीं लगता जितना कि बनाने में लगता है। अगर 1976-77 साल में जहां पर कि उन्होंने 8 करोड़ पहले दिखाया था कि इजाफा होगा वहां 87.33 करोड़ का सरल्पस मिला है। तो यह इस बात का नतीजा है कि इससे सालों पहले रेलवे की कार कंदंगी को मुद्दारने के लिये इन्हाँहाँ कोशिश की गई थी। मुझे यकीन है कि रेल मंत्री साहब इसमें सियासत या पार्टी का जो हमारा एक दूसरे के मुख्यालिफ़ करने का नज़रिया होता है, वह नहीं लायेगे। लेकिन एक चीज़ में अज़ं करूँगा कि जो सुधार रेलवे में लाया गया है उसको वह बरकरार रखें। मुझे उन की मुश्किलात का पूरा अहसास है, क्योंकि जब वह इस तरफ बैठा करते थे, तब उन्होंने बहुत लम्बे-बौद्धे वायदे रेल कर्मचारियों से किये थे। उस बक्त शायद उन्हें यह स्थान नहीं था कि कभी उन के सिर पर भी जिम्मेदारी आ पढ़ेंगी और अगर आप इजाजत दें तो मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उस बक्त उन्होंने बड़ी गैर-जिम्मेदारी की बातें की थीं। क्योंकि अगर वे जिम्मेदारी की बातें होती, तो आज वही मांगें उन से हो रही है और वे उन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन की माली हालत अभी भी इन्हीं सुधरी ही ही नहीं है कि वे रेल कर्मचारियों की तमाम मांगों को मन्त्र कर सकें।

इस में कोई शक नहीं, उस बक्त हमारे मामने कुछ मुश्किलात थीं, उन की कुछ मांगें माली गईं, कुछ नहीं माली गईं, लेकिन अब जो हालत अच्छी बनी है और जैसा 1977-78 के मुतालिक उन का स्थान है कि 32 करोड़ रुपये का सरल्पस वे रेलवे में कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ़ रेलवे की कार्यकर्त्ता को बजा-तोर-पर वह उस दर्जे पर कायम रखेंगे कि जिस दर्जे पर

उन्होंने पिछली हूँकूमत से लिया है, बहिक उन की अपनी काबिलियत को देखते हुए हम चाहेंगे कि वे इस में काफी इजाफा भी करेंगे।

एक बात में वह अज़ं करना चाहता हूँ—जो बहुत डिम्बिंग है और जिस से मुझे दुख होता है—जहां रेलवे की आमदनी बढ़ी है, वहां रेलवे का खर्चा (एक्सप्रेसिव्चर) भी बढ़ता गया है। बन्वेन्जन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो ग्रांडडे दिये हैं—उस का सोसं रेलवे बजट वा जो एक्सप्रेसिव्चर में ग्रोरे-एडम है—उस में आप देखें—बिंग-एक्स-पेन्सेज जहां 1974-75 में 1148 करोड़ रुपये था, आज यह सूचन है कि बिंग-एक्सपेन्सेज बढ़ने गये हैं। इस तरफ आप को ध्यान देना चाहिये—जहां रेलवे की आमदनी बढ़े, वहां बिंग-एक्स-पेन्सेज बढ़ने गये हैं। इस तरफ आप को ध्यान देना चाहिये—जहां रेलवे की आमदनी बढ़े, वहां बिंग-एक्स-पेन्सेज बढ़नी चाहिये। इस के लिये उन्होंने कुछ कोशिश की है या नहीं की है—मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं यह चाहूँगा कि आप इस तरफ पूरी तरज्जु हो।

बन्वेन्जन कमेटी ने जो सब्जेक्टस इस बार एकजागिनेशन के लिये चुने हैं—उस में उन्होंने चार चीजों की तरफ़ ध्यान तोर से ध्यान दिया है। एक तो यह कि वे पसोनल-पालिसी एजमिनिस्ट्रेशन की देखेंगे, रेलवे का हिंदुस्तान की इकानामी में जो हिस्सा है, वह बिंग हृद तक आदा बनते हैं और आगे क्या करता है। रेलवे में जो कराणन, रिक्वेट्सोरी और डमरी बुरी चीजें हैं, उन को कैसे दूर करता है। पैसेजर्स बिंग और रिंज्वॉकेशन के लिये भी वे गौर करेंगे। इस सिलसिले में एक बात हाउम को मालूम होनी चाहिये कि पैसेजर्स बिंग और रिंज्वॉकेशन के लिये एक कमेटी पिछली सरकार ने बनाई थी और उस के नेतृत्व में भी कृष्णकांत थे, जो अनाज भी रेलवे कन्वेन्शन कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने काफी अच्छी सिफारिशात गवर्नेंट को दी थी और

काफी सिकारिशात को गवर्नर्मेंट ने मान लिया था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मंत्री जी दोबारा उन पर विचार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो बातें पहले मानी गई थीं, उन को बदल दिया जाय। मेरी उन से अवृद्धास्त है कि जो भी रिपोर्ट बनती है, उस में काफी बदल लगता है। उसको बदलने से पहले वे जरा उन पर और कर लें कि उन के बदलने से रेनबै को नुकसान होगा या फायदा होगा।

रेलवे के एक्सरेन्सेज को कम करने के लिये उन्होंने रेलवे बोर्ड की तत्कालीन का डिक्ट किया था। उन्होंने बजट स्पीच में इस का डिक्ट किया था कि रेलवे बोर्ड को हम ने बदल दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब वह जकड़े गये हैं। इस मामले में जैसे लकड़ों की हराकेरी पहले हुआ करती थी, वही आज भी है, कोई बचत प्राप्त नहीं की है, सिर्फ यह कह दिया है कि एडोशनल मेम्बर जो पहले रेलवे बोर्ड में हुआ करते थे, उन का नाम अब बदल कर एडवाइसर कर दिया गया है, सिर्फ लेबल बदल दिया है, अन्दर सब कुछ वही है जो पहले था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा कदम उठाया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्बं कमीशन की रिपोर्ट को माना है, लेकिन आप देखें कि इस में स्पष्टे के हिसाब से रेलवे को कितनी बचत हुई है। अगर हम इस कार्यवाही से हिन्दुस्तान की रेलवे को रुपयों में बचत हुई है, खर्च कम हुआ है, तब मैं समझूँगा कि यह अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन अगर लेबल बदल दिया है और खर्चों वैसे का बंसा है तो मैं समझता हूँ कि यह प्राप्तकी अपनी खुशफ़हमी है और हाउस को भी उसी में रखना चाहते हैं। जहां तक खर्चों का तालुक है—बहां पर देखा जाय कि खर्चों की कोन-कोन सी मद्दें हैं जिन में कोई बचत हुई है—इस के लिये आप एक कमेटी मुकर्रर करें।

आप ने एक्सीटेंडस के लिये एक कमेटी मुकर्रर की है जिस का चेयरमैन आप ने एक साबका जन्म की बनाया। मुझे मालूम नहीं कानूनी नुक्ते-नियाह से वह इस में क्या देखेग, क्योंकि मरने के लिये आईन की इजाजत नहीं लेनी होती है, वह आईन के खिलाफ़ बात नहीं करता है। एक पैसेन्जर को जब आप रेलवे में बैठाते हैं तो उस की जान और माल का तहफ़कु़ब और हिफाजत करना आप का फर्ज हो जाता है — और जब तक वह अपनी उस मंजिल पर नहीं पहुँचता चाहे वह माल या पैसेन्जर हो, तब तक प्राप की जिम्मेदारी रहती है लेकिन अभी हम ने देखा कि बदलिस्ती से पिछले एक दो महीनों में-में इस के बारे में ज्यादा नहीं कहांगा—जो फिरा भुलक में फैनी हुई है, उस फिरा में पूरी इतिलाय अब्दवारों में नहीं आती है क्योंकि आज बदलिस्ती से अब्दवारों ने खुद अपने ऊर सेसर लगा दिया है और वे तमाम खबरे अब्दवारों में नहीं लापते हैं, जो भुलक में हांती है और रेलवे में जो बाक़पात पेश भाते हैं वे भी उन में पूरी तरह से नहीं आते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि रेलवे में एक्सीटेंडस के मामले में आप को खास तौर पर अहतपात बरतनी चाहिए आपने यह तस्लीम किया है कि रेलवे में जो एक्सीटेंडस अभी हाल में हैं, उनमें सेबोटेज या और उन में ऐसे लोगों का हाथ जो जो भुलक में गड़बड़ पैदा करना चाहते थे।

इसके साथ साथ रेलवे के कर्मचारियों ने यहां पर मुजाहरे भी किये और अपनी कुछ मार्गे आप के सामने रखीं। अभी कल या परसे लोगों रनिंग स्टाफ़ एसेसिवेशन ने 24 घंटे की हड़ताल न सिर्फ दिल्ली में की बल्कि हिन्दुस्तान के तमाम डिविजनल हेड्स्कार्टर्स जो हैं, पर वह हड़ताल हुई।

PROF. MADHU DANDAVATE : We have accepted their demand's and they are satisfied and have withdrawn their strike.

भी भौतिक जल्दी कुरेही : ठीक है, मैं बुश हूँ कि आप ने उन की मांगें मान लीं लेकिन मैं एक बात की तरफ आप का व्याप दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि कहीं ऐसा न हो कि रेलवे कर्मचारी अपनी जायज मांगें आप के सामने रखें और उन मांगों को रखने के लिए वे कोई कदम उठाने के लिए मजबूर हो जायें, तो उस बक्त वे सिद्धोंटियर्स जो मुल्क में गड़बड़ करना चाहते हैं उस का फायदा उठा कर कहीं रेलवे कर्मचारियों को बदलाम न करें क्योंकि उन की यही एकट है, यही कौशिल है। मुझे इस बात की ज़रूरी है कि रेलवे रिंग स्टाफ एक्सेसियेन्ट के मुतालबात को आप ने मान लिया है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि कुछ सिफारिश उन की सवित कंडिशन्स के बारे में मानी गई थीं और उसमें उन को कुछ बरायात, कुछ कम्सेन्स दिये नए थे। उन को आप ने बापस ले लिया है। मेहरानी कर के जो कम्सेन्स उन को दिये गये थे, वे सही पाए जाने के बाद उन को दिये गये थे और आप तो बहुत दयालु हैं और आप के हाथ चुने हैं, वे आप उन को दीजिए और इन छोटे छोटे कर्मचारियों को परेशान न करिए क्योंकि आगर आप इन के मतालबे टालते रहेंगे तो उन के दिल में बैचेती और बेहृनी-नानी रहेंगी। मैं जाहंगा कि ऐसी बात न हो। आज जो ये बातें मुल्क में हो रही हैं, मुक्तिलिक किस्म के लेबर फन्टस पर गड़बड़ हो रही है, कहीं ऐसा न हो कि वे लोग जो सेबोटेज में इस बक्त दिलचस्पी ले रहे हैं और मुल्क में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं, इस का फायदा उठा कर रेलवे में ज्यादा एक्सेसेंट्स न करें क्योंकि मैं समझता हूँ कि रेलवे के सफर में सब से बड़ी जरूरत इत्मीनान को जरूरत होती है। आप मेहरबानी कर के पिछले एक महीने के आंकड़े, अदादो-शुमार देख लें, तो आप को अहसास हो जाएंगा कि रेलवे में यात्रियों की ताकदाद पहले से कुछ कम हो रही है।

इस के साथ ही साथ मैं यह भी घर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे पास रिपोर्ट आई है कि रेलवे में कर्जान फिर गुरु हो गया है। मैं इस के लिए आप पर इजाम नहीं लगाता लेकिन कुछ हमारे साथी जो मुक्तिलिक जगहों से आते हैं वे बताते हैं कि पहले बाला सिलिला किर मुह हो गया है। नई दिल्ली और दूसरे स्टेशनों पर वे ट्रेवलिंग एजेंट जिन को हमेशा के लिए हटा दिया गया था, लाइनों में लग कर 50 और 100 टिकट ले लेते हैं और बाद में यात्रियों को 50, 100 और 200 परसेन्ट पर दोबारा टिकट बेच देते हैं। हम जाहंगे कि पिछली सरकार ने जो अच्छा काम किया है, उस को आप जारी रखें और जो बुरा काम किया है, उस को बस्त्य करके अच्छा काम करें। जहां तक रेलवे में कर्जान का ताल्लुक है, वह फिर बड़ना गुरु हो गया है, इनडिस्प्लिन गुरु हो गया है और आज नाड़ी में जो शाकी सफर करते हैं, वे आप की तारीफ नहीं करते, आपको बदलूँगा नहीं देते लेकिन यह ज़रूर कहते हैं कि पहले जैसा मामला नहीं है। मैं इस बारे में आपने ऊपर क़ट्टिंग नहीं लेना चाहता लेकिन यह ज़रूर कहता हूँ कि इस सम्बन्ध में आप को कुछ करना चाहिए।

दूसरी बात, हिप्टी स्वीकर साहब, काफी परेशानी की है। सरकार मरकजी लाने से रेलवे को कर्जा देती है। पहले का यह कर्जा 228 करोड़ रुपये का था जो कि 477 करोड़ रुपय तक पहुँच चुका है। मेरे बाल में रेलवे को जो कर्जा हो रही है, उसमें तो यह कर्जा अपनी पवास बच्चों तक भी जारी रहेगा। आप जो जनरल रेवन्यूज से उसे दिखाइदें दे रहे हैं वह कभी उसे पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप आमदानी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, खर्च कम करने की कोशिश कीजिए ताकि यह जो बोझा है इसको कम किया जा सके।

इस रिपोर्ट बैं स्टाफ क्वार्टर्स के बारे में कहा गया है। जहां तक कमेटी की सिफारिशों

کا تالٹک ہے، میں سامنہ رکھتا ہوں کہ کچھ بچھی ہے । رہلے کامبھاریوں کو یہ مرتلہ نہیں ہے کہ آپ ہنکے لیے رہپا کیس فکھ میں ڈالتے ہیں، ڈبلپرمنٹ فنڈ میں ڈالتے ہیں یا کمپنیل فنڈ میں ڈالتے ہیں । ہنکا تو یہ جنہیں وہ ہے کہ ہنکے سیر پر چلتے ہوں جیسے وہ اپنے پر اپنے بچھوں کو اپنیتیاں سے رکھ سکے । اسکے لیے میں چاہوں، ہم نے بھی کوئی کیا ہے اور آپکو بھی کامپنیا کرنی چاہیے کہ رہلے کے پاس بہت فاٹلر جنمیں پڑی ہوئی ہے । بھی تک 40-45 فیسیوں کوئی کام کا مکان میلے ہے । آپ رسم فاٹلر پڑی ہوئی جنمیں پر رہلے کامبھاریوں کو کامپانیٹیک سوسائٹیک بناانے کو ہدایات دے کر ہنکا بھنک کو ہستے مال کر دے دیجیے جیسے کہ ہنکا پر مالی ستوری بھلیک بنا سکے । آپکے لیے کچھ بچھوں سے میل سکتے ہیں، انہوں نے 100 سے بیش سکتے ہیں । سٹاف کامپانیس بناانے کے لیے آپکو رہپا بچک دے سکتے ہیں । اس تارہ سے آپکے اپنیاہیک کو ہاؤسینگ کی پرائیم کاٹی ہدایتک کے ڈالنے کے لیے رہلے کے ڈالنے کے لیے آپکو رہپا بچک دے سکتے ہیں । اس تارہ سے آپکے اپنیاہیک کو ہاؤسینگ کی پرائیم کاٹی ہدایتک کے ڈالنے کے لیے رہلے کے ڈالنے کے لیے آپکو رہپا بچک دے سکتے ہیں ।

میں جیسا کہ سامنہ نہیں ہو گا । سیکھ اکھی بھی بات میں آپ سے اور جنمیا کی جو رہلے میں ڈیسپلینیٹ اسپر پانکچوئیلٹ پر کارکن پڑا ہے یا ہنکا اسپر جیسا کہ ہنکا کامپانیا کے بارے میں بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ فیر آپ نے لگا ہے । ہنکا جیسا کہ سکھی سے اسپر جیسا کہ جنمیا کی جنمیا سے ہنکا دباؤ تکہ ہنکا کو ہی چڑھا ہو گا । کامپانیک ہنکا سامنہ اسکی کو دیکھتے ہوئے ہو گا । اسکے لیے آپ کامبھاریوں کو ہدایات دے کر ہستے مال کر سکتے ہیں । آپکو اس تارک بھی جیسا کہ ہنکا دباؤ کے لیے ہستے مال کر سکتے ہیں ।

شروع مقصود شیخ قریشی

(انہیں ناک) : تیقی سیدھر ماحب -

صرف ہنی بلت کی خوشی ہے کہ دیلوے کلوبیشن کمیتی نے لیلی ہو یعنی دیلوٹ پیغام کی ہے، اس میں انہیں نے تقدیماً انہی سفارشات کو دوھیا ہے جو اس سے بھٹکی دیلوے کلوبیشن کمیتی کیا کرتی تھی ۔ میں دیلوے کلوبیشن کامپانی اجتہاد ہی کوئتا ہیں لیکن اسے دیلوے دیکھ کے سانہ کہنا یوئیا ہے کہ جھیطخ اخبار میں ایک ہومانیڈت کالم ہوتا ہے میں کام کا حال بتائی کا اس طرح یہ بھی دیلوٹ دیلوٹیوں میہدوں سے دیلوے لیکسوسڈیلٹس کالم نے ہی صورت اجتہاد دے لو ہے ۔ اخبار یوئیے یوئیے جس ادھی سی موسم کا حال معلوم کرتا ہے تو اسے ہے ہی خبر ملتی ہے کہ دیلوے لیکسوسڈیلٹس کلکھ ہوئے ہیں اور یوئیے واڑ نامہد نہیں کرتا کہوئیکہ کسی نے کسی ملکہ یہ اس کو اس قسم کی خبر فروڑ ملتی ہے ۔

جہ دیلوے کلوبیشن کمیتی کی دیلوٹ ہمیوں پاٹس ہے اس میں دو تین ہائیکلیوں کافی اہم ہیں ۔ کلوبیشن کمیتی نے دیلوے کی کمائی کی ہی سراہنا کی ہے ۔ جیسا کہ ملکتی جی کو معلوم ہے اور اب انہیں تجھری بھی ہو کر ہو گا کہ دیلوے میں سداھا لے لے کر کلیوں ہے کافی دلت اور

[شیخ محمد شلی قویشی]

کالی مصلحت کی فروخت ہوتی ہے -
لور اس کو بکار لے میں اتنا وقت
نہیں لکھتا جتنا کہ بدلے میں لکھتا ہے -

اگر 1976-1977 سال میں جہاں پر
کہ انہوں نے آئے کروڑ بھلے دکھایا تھا
کہ ملکہ ہوا ۸۷.۳۳ کروڑ کا سریلر
میں ہے - تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے
کہ اس سے سالوں پہلے دیلوے کی
کاروباری کو سنبھارنے کے لئے انتہائی
کوشش کی گئی تھی - مجبہ یقین
ہے کہ ہبھل ملکی صاحب اس میں
سھاستا یا پاہنس گا جو ہمارا لیک
دوسرے کی مطالبہ کرنے کا نظریہ
ہوتا ہے وہ نہیں لٹھاتے - لیکن لیک
چوڑ میں عرض کروکتا کہ جو سندھا
دیلوے میں لیا گیا ہے اس کو وہ
بیولار دیکھیں - مجبہ ان کی مفہومات
کا پیرو لحساں ہے کہونکہ جب وہ
اس طرف بیکھا کرتے تھے تب انہوں
نے بھئے لئے چوڑے وھے ہبھل
کو مچاہیوں سے لگتے تھے - اس وقت
عاید انتہیں یہ خیال نہیں تھا کہ
کہوں ان کے سر پر فسعداری آپسیکی -
لور اگر آپ اخواہ دیں تو میں یہ
بھی کھلا چلھتا ہوں کہ اس وقت
انہوں نے ایسی ہمہ زمدادیوں کی باتیں
کی تھیں، کہونکہ اگر وہ زمدادیوں کی
باتیں ہوتیں تو وہی آج مانگیں
ان سے ہو رہی ہیں اور وہ ان کو
پیرو انتہیں کو ہا دے رہی ہیں - کہونکہ
ان کی صالیحیت ابھی بھی اقلی

سدهی نہیں ہے - کہونکہ دبی
کومنیٹیوں کی تمام مانگیں کو ملکہ
کو سکھیں -

اس میں کوئی شک نہیں اس وقت،
ہمارے سامنے کچھ مسئلہات تھے، ان
کی کچھ مانگیں مانی گئیں اور کچھ
نہیں مانی گئیں - لیکن اب جو
حالت اچھی بدلی ہے اور جو سا ۷۷-۷۸
کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ۳۲ کروڑ
دوسرا کا ۰ دبیس وہ دبیلے میں کو
دیکھنے میں امید کرنا ہوں کہ نہ
صرف دیلوے کی کاریہ کردگی کو بھا
طلو پر پر پر اس درجہ پر قائم
کہیں کے جس درجہ پر انہوں نے
پیچھی حکومت سے لیا ہے - بلکہ
ان کی ایسی قابلیت کو دیکھتے ہوئے
ہم چاہیے کہ وہ اس میں کافی
لشکر بھی کریں گے -

لیکن بات میں یہ عرض کونا
چاہتا ہوں جو بہت قسیر بیک ہے
اور جس سے مسجد دکو ہوتا ہے -
جہاں دیلوے کی آمدنی بڑی ہے وہاں
دیلوے کا خوچہ بھی بروختا کیا ہے -
کلوبیشن کمیٹی نے ایسی دبیوں میں
جو آنکھے دیئے ہیں اس کا سوس
دیلوے بجت کا جو ایکسپریم لیٹری
سینیورنگ ہے اس میں آپ دیکھیں -
ووکلک ایسکولیسیز ۷۳-۷۵ میں جہاں
۱۱۲۸ کروڑ دوپتہ تھا آج یہ صورت
ہے کہ ووکلک ایسکولیسیز بوجہ کو

۱۱۰ کووڑ دوئیں تک پہلیج کیا ہے -
 جہاں ایک طرف دیلوے کی آمدنی بوئی ہے وہاں سانہ سانہ ووکلگ ایکسپریس بوجتے کئے ہیں - اس طوف آپ کو دھیان دیتا چاہئے، جہاں دیلوے کی آمدنی بوئی وہاں ووکلگ ایکسپریس کم کوئے کی کوشش ہونی چاہئے - اس کے لئے انہوں نے کچھ کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے - لیکن میں یہ چاہوں کا کہ آپ اس طرف پوری توجہ دیں -

انہوں نے کافی اچھی سفارقات کوونسلت کو دی تھیں - اور کافی سناشات کو کوونسلت نے ملن لیا تھا - لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ملتیں جی دوبارا ان پر وچار کرنا چاہتے ہیں - اور چاہتے ہیں کہ جو باتیں پہلے مانی گئیں تھیں ان کو بدل دیا جائے - میری ان سے مردمائیت ہے کہ جو ہی دیورت بنتی ہے اس میں کافی وقت لگتا ہے - اس کو بدلنے سے بہلہ وہ ذرا ان پر فور کو لیں کہ ان کے بدلنے سے دیلوے کو نقصان ہوا یا فائیدہ ہوا -

کلوبیشن کیتی نے جو سچیکنیس اس بار ایکرامیلیشن کے لئے چلے ہیں اس میں انہوں نے چار چیزوں کی طرف خاص طور سے دھیان دیا ہے - ایک تو یہ کہ وہ پرسونل پالیسی ایڈمنسٹریشن کی دیکھیلگئے، دیلوے کا ہندوستان کی اکانسی میں جو حصہ ہے وہ کس حد تک ادا کرنے ہیں اور آئے کیا کرنا ہے - دیلوے میں جو کریشی، شوت خودی اور دوسروی ہوں چیزوں ہیں لہ کو کیسے دو کرنا ہے - پیسٹھو، بکلگ اور دیزرویشی کے لئے ہوئی وہ غور کریلگئے - اس سلسلہ میں ایک بات ہاؤس کو معلوم ہونی چاہئی کہ پہلے جوں بکلگ اور دیزرویشی کے لئے ہوئی اور اس کے لئے ایک کمیتی پہلی سچار نے بذائی تھی اور اس کے چیزوں میں شری کوشن کا نام تھا - جو آج بھی دیلوے نولیشن کمیتی کے میمبر ہیں -

دیلوے کے ایکسپریس کو کم کوئے کے لئے انہوں نے دیلوے ولڈ کی تکمیل کا ذکر کیا تھا - انہوں نے بھت سچیگ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ دیلوے ولڈ کو ہم نے بدل دیا ہے - مجھے اس بلت کی خوشی ہے کہ اب وہ جکٹے کئے ہیں - اس معاملے میں جیسے لفڑوں کی ہیرا یہیں بہلہ ہوا کرتی تھی وہی آج بھی ہے - کوئی بھت آپ نے وہاں پوئیں کی ہے - صرف یہ کہہ دیا ہے کہ اقیسلن میمبر جو بہلے دیلوے ولڈ میں ہوا کرنا تھا ان کا نام اب بدل کو ایڈوانسز کر دیا گیا ہے - صرف ایوں بدل دیا ہے اندر سب کچھ وہی ہے - جو بہلے تھا - میں یہ کہلا چلتا ہوں ۔ آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے - کہ ایڈمنسٹریٹو دیویمز کی دیورٹ کو

[شو مصعد شدی قریبی]

مانا ہے - لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں دوپٹے کے حساب سے دیلوے کو کتنی بچت ہوئی ہے اور اس کا دروازی سے ہندوستان کی دیلوے کو دوپیوں میں بچت ہوئی ہے - خرچے کم ہوا ہے - تب میں سمجھوں کہ یہ اچھا قدم اٹھایا گیا ہے - لیکن الگ لہل بدل دیا ہے اور خرچے دیسے کا دیسا ہے تو میں سمجھتا ہیں کہ یہ آپ کی اپنی خوبی ہے - اور ہاؤس کو بھی اسی میں یہ رکھا چاہتے ہیں - جہاں تک خرچے کا تعلق ہے وہاں پر دیکھا جائیں کہ خرچ کی کون کون سی مدین ہیں جو میں کوئی بچت ہوئی ہے - اس کے لئے آپ لوک کیتھی متعدد کریں -

آپ نے ایکسپریلائس کے لئے ایک کمیتی مقرر کی ہے جس کا چیزوں آپ نے ایک سابق جج کو بھالیا ہے - سمجھ معلوم نہیں قاتلوں نکتہ تکہ سے وہ اس میں کہا دیکھ دیکھتے - کیونکہ مرنے کے لئے آئوں کی اجازت نہیں لہلی ہوتی ہے - وہ آئوں کے خلاف بات نہیں کرتا ہے - ایک پیسٹھر کو جب آپ دیلوے میں بھٹکاتے ہوں

تو اس کی جان اور مال کا تھلکھل لیوں حداہت کرنا آپ کا فریق ہو جاتا ہے - اور جب تک وہ اپنی امن میں تک نہیں پہنچتا چاہے وہ مال ہو با پیسٹھر ہو - تب تک آپ کی نسعداری دھتی ہے لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ بدلتستی سے پہنچتے ایک دو مہملوں میں - میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہونتا - جو فنا ملک میں پہنچی ہوئی ہے اس فنا میں ہوں اطلاع اخباروں میں نہیں آئی ہے کیونکہ آج بدلتستی سے اخباروں نے خود اپنے اپنے میلس لٹا دیا ہے اور وہ تمام خبروں میں نہیں چھاپتے ہیں جو ملک میں ہوئی ہوں لیوں دیلوے میں جو رانیات پہنچ آئے ہیں وہ بھی ان میں ہوں یہ طرح سے نہیں آئے ہیں - میں یہ موضع کرنا چاہتا ہوں کہ دیلوے میں ایکسپریلائس کے معاملے میں آپ کو خاص طور پر احتیاط برتنا چاہتے ہیں - آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دیلوے میں جو ایکسپریلائیٹ ابھی حال میں ہوئے ہیں ان میں سیوٹمیج تھا اور ان میں اپنے لوگوں کا ہائی تھا جو ملک میں گروپو پرہدا کونا چاہتے ہیں -

اُس کے ساتھ ساتھ دیلوے کے کوسمچاریوں نے بہل ہو مظاہرے ہی کئے اور اپنی کچھ مانگیں اُپ کے سامنے دکھنے - ابھی کل یا پرسوں لوگوں دنلگ سٹاف ایسوسیشن نے ۲۲ کھلتے کی ہوتا نہ موف دلی میں کی بلکہ ہلدوستان کے تمام قویوں میں ہفتہ کوارٹر چوہن دہار پر وہ ہوتا ہے -

PROF. MADHU DANDAVATE: We have accepted their demands and they are satisfied and have withdrawn their strike.

شیخ مصطفیٰ شفیٰ قریشی :

تھیک ہے میں خوہ ہوں کہ اُپ نے ان کی مانگیں مان لیں لیکن میں ایک بات کی طرف اُپ کے دھمکی دلتا چلعتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیلوے کوسمچاری لہنی چاہیز مانگیں اُپ کے سامنے دکھنے اور ان مانگیں کو دکھلے کے لئے وہ کوئی قدم اٹھانے کے لئے مجبور ہو جائیں ۔ تو اس وقت وہ سہوٹھرے ہو ملک میں کوپوں کونا چاہتے ہیں اس کا فائدہ اتنا کہ کوئی کوپوں کو ہذنم نہ کریں کیونکہ اس کی بھی لہر ہے، بھی کوپھر ہے۔ مجبو اس بات کی خبی ہے کہ دیلوے دنلگ سٹاف

ایسوسیشن کے مطالبات کو اُپ نے مان لیا ہے اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مشارکت ان کی سروس کلکتیشن ہے بارے میں مانی گئیں تھیں اور اس میں ان کو کچھ مزاوات، کچھ کمسیشن ڈنے کئے تھے۔ ان کو اُپ نے واپس لے لیا ہے۔ مہدیانی کو کہ جو کمسیشن ان کو دئے گئے تھے وہ صحیح ہائے جانے کے بعد ان کو دئے گئے تھے اور اُپ تو بہت دبالتا ہیں اور اُپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ اُپ ان کو دعویٰ کے اُن چھوٹے چھوٹے کوسمچاریوں کو پریمان نہ کریں۔ کیونکہ اگر اُپ ان کے مطالیم تالیق دھیلکے تو ان کے دل میں بھیچیں لور پاٹھیلائی دھوکی۔ میں چاہوںکے لہسی بات نہ تو اُج جو یہ باتیں ملک میں ہو وہی ہیں، مختلف قسم کے لہبہ فرنٹ پر کوپوں ہو رہو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو سہوٹھج میں اس وقت دلچسپی لے رہے ہیں اور ملک میں کوپوں پیدا کونا چاہتے اس کا فائدہ اتنا کہ دیلوے میں زیادہ سہوٹھج نہ کریں۔ کیونکہ میں

[غلوں محمد شفیٰ قبیشی]

سمجھتا ہوں کہ دیلوے کے سفر میں سب سے بڑی ضرورت اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مہربانی کو کچھ لیک مہدیت کے آنکھے، عدد و شاد دیکھ لیں تو آپ کو احساس ہو جاتا کہ دیلوے میں یاتریوں کی تعداد پہلے سے کچھ کم ہو گئی ہے۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہی صرف کرنا چاہونا کے مہرے پاس دیوالیس آئی ہیں کہ دیلوے میں کوئی یہ شروع ہو گیا ہے۔ میں دیلوے میں آئی تھے آپ یہ اظام نہیں لگانے لہکن کچھ ہمارے ساتھی ہو مختلف چیزوں سے آئے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ پہلے والا سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے۔ نئی دلی لارڈ دوسرے ستمالیں یہ وہ تریولیک ایجنسیس جنکو ہدیت کے لئے ہتا دیا گیا تھا، انہیں میں لگ کر ۱۰۰۰-۵۰ تک لے لیتے ہیں لیو پہر بعد میں یاتریوں کو ۱۰۰۰-۵۰ اور ۱۰۰ ہر سو ہفت پر دوبارہ تکت بیج دیتے ہیں۔ ہم چلناکر کے پیچھے سوکار نے جو اچھا کام کیا ہے اس کو آپ چاری دکھنے۔ اور جو برا کام ہے اس کو ختم کر کے اچھا کام کریں۔

جہاں تک دیلوے میں کوپشن کا تعلق ہے وہ یہ ہو گیا شروع ہو گیا ہے اور آج انسپکشن شروع ہو گیا ہے اور آج گزی میں جو یاتری سلو کوتے ہیں وہ آپ کی تعریف نہیں کرتے۔ آپ کو بد دعا نہیں دیتے۔ لہکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہاں جو سما معااملہ نہیں ہے۔ میں اس بارے میں اپنے اپر کوئی کہتے نہیں لہلا چلاتا لہکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس سیلہدہ میں آپ کو کچھ کرنا چاہئے۔

دوسری بات ۲۷۷ تک سہیکرو صاحب، کالس پریسٹی کی ہے۔ سوکار میکانی خزانے سے دیلوے کو ترکہ دیتی ہے۔ پہلے کا یہ ترکہ ۲۲۸ کروڑ روپیہ کا تھا۔ جو کہ ۳۷۷ روپے تک پہلیج چکا ہے۔ صورتے خیال میں دیلوے کو جو کمائی ہو رہی ہے اس میں تو یہ ترکہ الگی پیچاس برسیں تک جاری رہے۔ آپ جلوں دیکھنے سے اسے قیوبنڈنگ دے رہے ہیں۔ وہ کہیں اسے پورا نہیں کر پانیگئے۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ امدادی ہو ہانے کی کوشش کیجیئے۔ خرچ کم کر کی کوشش کوچھ گئی تاکہ یہ جو بوجھا ہے اس کو کم کیا جائے۔

اُس دیوڑت میں ستاف کو اور ترزا کے
بادے میں کہا گیا ہے ۔ جہاں تک
کمپنی کی سفارشات کا تعلق ہے میں
سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی ہیں۔
دیلوے کو مچا دیوں کو یہ مطلب نہیں
ہے کہ آپ ان کے لئے دیوبیدہ کس فنڈ
میں ڈالتے ہیں ۔ تیوبیمیٹ فنڈ
میں ڈالتے ہیں یا کوہی میتل فنڈ میں
ڈالتے ہیں ۔ ان کا تو غرض یہ ہے کہ
ان کے سو یو چھت ہو جس میں
وہ اپنے اور اپنے بھوپال کو احتیاط سے
دکھ سکیں ۔ اُس کے لئے میں چھوٹا
ہم نے بھوپال کو شفعت کی تھی ۔ اور
آپ کو بھوپال کو شفعت کی تھی کہ
دیلوے کے پاس بہت فالتو زمین
بڑی ہوتی ہے ۔ اپنی تک ۳۰ - ۳۵
لکھ میڈی لوگوں کو ہی مکن ملے ہیں ۔
آپ اس فالتو بڑی زمین پر دیلوے
کو مچا دیوں کو کو آپریٹھو سوسائٹی
بلانے کی اجازت دے کر اس زمین
کو استعمال کرنے دیجئے جس سے
وہ اسہر ملتی ستودیز بلڈنگ بلانے
سکیں ۔ آپ کے لئے قومیہ بھلکوں سے
مل سکتے ہیں ۔ ایل - ائی - سی -
سے مل سکتے ہیں ۔ ستاف کو اور ترزا
بلانے کے لئے آپ کو دیوبیدہ بھلک دے
سکتے ہیں ۔ اس طرح سے آپ کے

ایسپلائیز کی ہاوسنگ کی پروپریٹی کافی
حد تک حل ہو سکتی ہے ۔ دیلوے
تربیک کے دونوں طرف اور دوسرو
جگہ کافی زمین بیوی ہوتی ہے ۔ خود
میں نے دھلی میں انذین دیلوے کی
زمین کو دیکھا ہے کہ اسے ہے
بڑے پونچی پتھروں کو پانچ یانچ ۔ وہ
دیوبیدہ میں کوئی بھی دے دکھا ہے ۔
حالانکہ اس زمین کو بیکھا جائے تو
۱۰ - ۱۰ کروڑ دیوبیدہ اُ جائے گا ۔ وہ
دیوبیدہ آپ کو مچا دیوں کی بھروسے کے
لئے استعمال کو سکتے ہیں ۔

میں زیادہ سے نہیں کہونا ۔
حرف ایک ہی بلت میں آپ سے
اور کہونتا کہ جو دیلوے میں
تسہل اور پلکچھولتی ہو فرق پڑا
ہے اس کی اور دھیان دیں ۔
کریشن کے بادے میں بھوپال میں آپ
سے کہا چاہتا ہوں کہ وہ بھوپال
لٹا ہے ۔ اسے جتنی سختی سے اور
جتنی جلدی سے اسے دھا سکیں اُنہاں
عی اچھا ہو گا ۔ کہونکہ اس سے عام
پاتروں کو دامت ہوتی ہے ۔ پیشانی
ہوتی ہے ۔ آپ کو اس طرف بھوپال
دھیان دے کو اسکے بادے میں کوئی
انتظام کرنا چاہئے ۔]

SHRI M. KALYANASUNDRAM (Tiruchirappalli): Before I begin my speech, may I know one thing? As promised by the hon. Railway Minister the other day, his statement on the restructuring of the Railways Board can also be taken up for discussion together with this resolution so that we may discuss both together. Is that the position, Sir?

PROF. MADHU DANDAVATE: In the other House, members who participated referred to the restructuring also.

SHRI M. KALYANASUNDRAM: I should also join the Railway Minister in thanking the Railway Convention Committee for their maiden report. One word about the Convention Committee itself before I proceed further. Before 1971 the function of the Railway Convention Committee was limited to settling the finances to be appropriated to the general revenues. During the past 6-7 years, the scope and functioning of the Railway Convention Committee have enlarged. They are functioning more or less as a watch dog on the functioning of the railway administration, its finances, its method of working, etc. I think this should be kept up and the Railway Convention Committee may be made a Standing Committee and not as an annual committee. If there is a change, there will be no continuity. I think for two years one committee should be allowed to function. This should be considered by the Speaker and also by the Railway Minister.

With regard to the recommendation made by the Convention Committee, this House has to accept them as they are because we are nearing the next budget. Still my suggestion will be that sufficient allocations should be made for the on-going schemes which are delayed because they are also contributing for the losses in revenue. Sir, large amounts of money gets locked up in construction. Construction works get prolonged for a long time without earning any revenue during that period. This is a thing which must be avoided. Secondly, the railways could not improve their earnings due to non-fulfilment of promises of traffic made by other industries; plan targets are not fulfilled and no traffic is forthcoming. While the Railways have made arrangements for that traffic, that traffic which has been promised is not forthcoming which is another reason why the railways are being put to financial difficulties.

The hon. Member who spoke earlier referred to the fact that the working expenses have been on the increase, and

that the revenue is not commensurate with expenditure incurred. I do agree that there is scope for improving the revenues, but this is not the correct way of looking at it, that is to say, to go by what is the amount spent, what is the return etc. We have to see what is the service which is being rendered and whether there is any improvement in that. This is a public utility service and on the efficient working of the railway system depends the entire economy of the country, not to speak about the defence of the country. Those who are decrying the increase of working expenses, I think, do not realise the results or the services rendered by the railways.

I do not hold any brief for the Railway Administration. I will come to this point a little later. How are we to judge the performance of the railways? It is not to be judged by the increase of working expenses or by the revenues. They are sharing some social burdens. The hon. Minister told us about the indebtedness of the railways to the general revenues. No doubt the indebtedness is of the order of Rs. 477 crores in the current year. For a superficial observer, it would appear to be a huge amount. But those who know how much the railways are incurring as a loss due to carrying this social burden would appreciate the obligation that the general revenue owes towards the railways.

The suburban service being run in the metropolitan cities is a very important service for industrial workers and office-going employees. Their rates are quite cheap and this has to be so. I will oppose any idea of increasing these rates. This is an essential service for the wage-earners. The railways are incurring a loss of Rs. 200 crores a year for running the suburban service alone. Then comes foodgrains. Then comes the needs of the defence services,—all concessionary rates. Therefore, one has to take into account all these factors. But this does not mean that there is no scope for improvement of earnings or for streamlining the working expenditure. There is scope for improving the working expenses. Now, there is a lot of wasteful expenditure; in spite of the increase in working expenses, complaints are coming that the workers do not get proper tools with which to work. Supplying of spare parts should be immediately attended to. The complaint is that the quality of spare parts, tools and other consumer goods supplied to the work shops and the loco sheds and other areas are deteriorating in addition, the working expenses have gone up.

Another anomaly is that while working expenses are increasing, our workshops are not put to full use. There is a surplus capacity in our workshop. Skilled workers are available in the railway workshop; plants and machinery that are available in the railway workshop are also good. It has got to be put to greater use so that you can bring down the cost of expenditure on repairs and maintenance. The effective way of bringing down the expenditure on repairs and maintenance is by making the workshop to work to its full capacity by making available to it the spare parts and other qualitative consumer stores without difficulty as and when they are required.

This takes me on to the question of purchase, supplies, storage and distribution of stores in the railways. There is a lot of scope to streamline all these things and to improve them thereby preventing the leakage of revenue and wasteful expenditure on spares. If the Railway Administration has cared for the cooperation of the workers, the expenditure on repairs and maintenance could be brought down and their surplus capacity more fully used.

Then, Sir, the hon. Member, Shri Qureshi who was pleading for the railwaymen just now forgot that it was under his regime that he put a ban on the construction of new quarters. I would request the Railway Minister to lift this ban on construction of new quarters and provide for the staff adequate quarters. Another point is that all vacancies in the higher grades are kept pending although he has been promising in this House several times to fill up the posts. In the bungalow and in the workshop, the officers' posts are not filled up as and when they arise as a measure of economy. Hours of work are not properly enforced. The Railway Minister told us very recently that ten hours duty has been enforced in respect of running staff. It is not correct. He is misleading. In 1973 when Mr. Qureshi was the Minister of State for Railways, he entered into an agreement with the loco running staff that the hours of work for the running staff would be ten hours. But, that has not been enforced at all since then. What the Railway Minister claims is different. Passenger services are already having ten hours work because passenger and express trains have to run fast; you can have ten hours duty there for the loco running staff who are working in the passenger services. This refers only to the goods services. For running the goods trains, no where in India, you have enforced the ten hours work leaving aside the thirteen or fourteen hours of work. Look at the protest by

the loco running staff and the administration. The goods train services will give 50% of the railway earning. The loco running staff have to bear the burden and they are resisting; therefore, I say that their grievances should be sympathetically considered.

There is a lot of scope for improving the revenues. The main point here is that the workers must not be made the target for any project of economy. Three lakhs of workers are still being treated as casual labourers. This was one of the demands of the trade unions in 1974 strike. Nothing has been done although it is nearly one year now. It may mean some financial commitment. But can the railways run without those labourers? It is impossible: all that labour force is necessary. They are kept as casual labourers for paying low wages. This is cheating the workers and exploitation of labour. This should be rectified as early as possible, at least by the next budget.

One word about the finances of the railways. Looking from a distance the finance of the railways may look depressing. But you must judge their performance during thirty years after Independence in the background of what they were at that time. We inherited overaged wagons, overaged coaches and locos over-capitalised permanent way. The Britishers took away more than Rs. 770 crores by way of compensation. Today we can be proud of the achievements that have taken place and for this improvement it is the nation, it is the railway men who have contributed. It has not been done by one person or by the Railway Board alone. Of course I acknowledge the services of our engineers; some of them are very good. Recently the railway bridge over Amaravati a river between Karur and Tiruchirappalli was washed away completely and it was reconstructed within 30 days and train services were restored.

PROF. MADHU DANDAVATE: 15 days ahead of time.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: So, we should acknowledge their services also. There should be fair deal to the workers who have contributed for the growth of the railways.

A lot of improvements have to be made in the structure of the Railway Administration. During his budget speech the hon. Minister promised that he was

[Shri M. Kalyan-sundaram]

going to implement the recommendations of the Administrative Reforms Commission. Now he has laid a statement; I do not know what that statement contains. It appears to me that there is only change in the nomenclature and not any material change in the structure.

Instead of additional members, there will be advisers. This point is that the work in the Railway Bhawan must be reduced. The area of operations should be zonal division and not Rail Bhawan. Railway Board must confine itself to policy and laying down guidelines. The general managers must be the key men who should be answerable for efficient running and they should be made answerable for losses. In the present arrangement you are not able to fix responsibility on anybody. I am not against any individual official of the Railway board; within their own limitations they are doing their best. I do not want to demoralise them. But the structure is such that they cannot do better. The Railway Board members come there at the age of 55 with only three years more to retire. So, they have to look for some favour somewhere to prolong their service somehow or other. There is no dynamism and no effort to make new approaches. The re-structuring should be in this direction, not change of nomenclature. The re-structuring should enable young people to come. It is not only a question of fulfilling the expectations of our people. The developing countries are now looking to us for help in the matter of construction of railways. So, the railways have a great future.

I wish the Railway Minister all success and I hope he will take my criticism in the proper light and do the needful.

SHRI V. M. SUDHEERAN (Alleppey): Sir, I do not want to speak for a long time. The minister has referred to some important aspects of efficiency of the railways. Of course, I welcome the measures taken by the minister to improve the efficiency and working of the railways. But I am very sorry to say that the aims and objectives have not yet come to our expectations. There must be a thorough decentralisation of the administration. The zonal railways should be given more powers. Looking to the Rail Bhavan in Delhi for every minor problem is not the solution. Therefore, immediate and adequate steps must be taken by the minister to give powers to the zonal railways to discharge the basic tasks regarding the day to day administration in the railways.

Utilisation of money is an important point. Getting revenue is another important point. For getting revenue, the

railways must introduce new lines wherever they are remunerative. In this budget speech, the minister has given us a ray of hope about introduction of new lines. As far as Kerala is concerned, Alleppey is my constituency and the introduction of a new line from Ernakulam to Alleppey is very important. It affects the coastal area of Kerala and it is very remunerative. The report shows that 18% returns are expected. I do not want to speak in detail about it. The matter is pending before the Planning Commission; I don't know why they are delaying the matter. The Government and people of Kerala are very much interested in this railway line. Even the youth of Kerala has offered unskilled manpower needed for this work.

PROF. MADHU DANDAVATE: The old man of Kerala has told it to us.

SHRI V. M. SUDHEERAN: That itself shows the anxiety and interest of the people in regard to this line. I am convinced that the Minister is also very much interested in it. I thank him for it. I request him to use his good offices with the Planning Commission to get it sanctioned as early as possible.

Regarding electrification of railways, electricity is cheaper in Kerala, and the Government there has offered it at cheaper rates. It is the duty of the Government to exploit the cheaper power. The density of traffic in Kerala is very high. Those who have to travel daily to their offices find it difficult. There must be a dialogue with the Government of Kerala regarding power and other matters. Steps must be taken to introduce electrification of the railways there, soon.

Regarding double lines, the position between Shoranur and Cochin is very difficult. New lines and new coaches have not been introduced. Doubling of railways is also important.

There is a proposal in the Railway Ministry for new lines between Trichur-Kuttipuram-Guruvayoor; and another line between Mysore-Tellicherry. I request the Minister to use his good offices to get these new lines sanctioned, to obtain clarifications from the Planning Commission and to fulfil the expectations of the people of Kerala.

The next point is about facilities at railway stations. Although during the last 10 years, some efforts have been made by the concerned governments, they are not adequate.

Now about catering. During my recent journey from Cochin to Delhi, I found that the catering service in the Railways is not good, especially in the southern region. The food supplied from the kitchen car is good, but the one supplied from the basic kitchen is not at all good. It is very dirty. This is another important matter to be taken into consideration.

15.00 hrs.

SHRI K. A. RAJAN (Trichur) : Sir, it is very much expected that with the restructuring of the Railway Board, which the hon. Minister mentioned in his statement, and with all his dynamism he will be able to implement some of the schemes of major reforms which we have in view.

If I remember correct, in the new restructured body there is going to be a person specifically in charge of industrial relations, to look after the problems of labour. Now there are so many problems in the railways, and they could not be solved because there is no proper man to handle the problems in the proper way. It is a big organisation and so it is natural that some problems or other crop up. Unless the Railway Board looks into those problems from the point of view of the overall interest of the railway employees, I do not know whether any efficiency in the proper running of their railways is possible. Therefore, I would inform the hon. Minister that, in spite of all his good intentions, he should have a special eye on the industrial relations problems, especially because this is a major public sector organisation which employs lakhs of workers.

When we speak on the railways, there is a natural tendency for everyone to make more demands on the railways. All of us represent some constituency or other and we want more railway lines in our areas. But it is not feasible on account of financial difficulties. All the same, I would mention the construction of the Alleppey-Ernakulam railway line. The Minister himself is convinced of its necessity. It is remunerative because it will increase the traffic of commercial products from the neighbouring areas.

The other demand is for electrification. During his visit to Trivandrum he mentioned that electrification requires heavy initial investment. We understand all that. Still the hon. Minister, with his imagination, if he takes some interest, he can do something in the matter. Now thousands of employees are working in offices in Ernakulam and because of the congestion, they cannot be absorbed in the city. It has become a problem to get accommodation in Ernakulam. If there

is electrification of railway line, people can stay 20 or 30 miles away, come to the city for employment and then return in the evening. So far as the heavy initial expenditure is concerned, the Kerala Government would be willing to give some help. Similarly, voluntary service by the youth organisations and other people would be available. Considering all this, I would say that the electrification of this line should be expedited.

Coming to catering in railways, it is true that we cannot expect luxurious food. But the complaint is mostly not about the food as such, but the way in which it is being served, neatness, the worn-out utensils that are being used etc. This should be looked into.

Finally, I want to refer to the pitiable condition of the people who work in the catering service of the railways. They are all commissioned vendors. They get some sort of commission on the tea and snacks which they sell. Their condition of service is very bad. They are not regular employees. They can be sacked at any time. They are not given any of the amenities available to other employees, even though they number about 1,000 in the main lines alone. I am not demanding that they should be paid very heavy salaries, but they should be given at least the minimum salary which is given to an unskilled worker and there should be some security of job.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : Sir, I am thankful to the members of the House, who extended their unanimous support to the Resolution on the recommendations of the Railway Convention Committee. It was rightly pointed out that till 1971 the scope of the Convention Committee was rather restricted. After that, the Convention Committee of their own, merely by convention, changed the old convention and they started enlarging the scope of the Convention Committee. I am happy that the new Convention Committee is not seized merely with the matter of making a recommendation about the rate of dividend, but it is trying to examine in depth a number of problems which will ultimately be able to help us to streamline the entire administration, various problems related to labour and also the problems of the users of the railways.

We began our debate with Shri Qureshi who, with his past experience, complimented himself for the fine financial performance of the previous regime. I would not find fault with him. I have myself admitted that, as far as finance was concerned, certain infrastructure was built up. But I think he

[Prof. Madhu Dandavate]

should give us the credit for this, that if we were to mismanage affairs, it would have been easy for us to demolish the infrastructure, but we tried to improve upon it. I am very happy to say that by the end of October our gross earnings are Rs. 82.3 crores more than the corresponding period of last year. Not only that. We are even far ahead of the Budget proposals for this period, about Rs. 52 crores ahead.

That way, the financial performance is quite good. Then, the question might be asked cynically: if the financial performance is improving, why is it that the Railway Convention Committee has decided to continue the reliefs that the earlier committee had granted in 1979? There, I must point that, though with the co-operation of the railway employees we have been able to improve the finances of the railways, there is a certain backlog of the burden of indebtedness which continues. You will be surprised to know that at the end of 1977 the indebtedness was of the order of Rs. 461.9 crores. At the end of 1978 it is expected to be Rs. 370.81 crores. This indebtedness, as was rightly pointed out, is due to a number of burdens that we are carrying.

Generally, what we do is that as far as capital expenditure is concerned about construction of railway lines and allied matters, we draw from the general revenue and repay six per cent dividend to general revenue. Some time in the past it was merely a transfer of entry from one account to another, but I have shown in my Budget presented in June that we will be meeting the dividend obligation from the internal resources of the railways. That particular progress we have maintained. I must admit that last year also the same thing was done. We have continued the process.

As Mr. Kalyanasundaram rightly pointed out, the railways in our country are not run purely on commercial lines. We are a social utility service, and at the same time there is a commercial aspect. There are many parts in the world, in Western Europe and Asia, where the social burdens are not lifted by the railways but by the concerned Government's general revenues. If our railways are actually lifting social burdens of the order of Rs. 214 crores. I am not sorry for that, because the railways in India, in the present social context, have to be run not merely as a commercial proposition. We have to carry foodgrains. We are offering to industrial labour and the middle class suburban traffic at a much lower cost. Then, in times of calamities like cyclones and floods, we are required to move food and other commodities free of charge. Only recently when I was in Andhra last

week I announced that not only would all the relief materials be moved free of charge; but because a large number of animals have been killed as a result of tidal waves in Andhra, if the Punjab and Haryana Governments are prepared to send cows and other animals to provide the necessary milk facilities in Andhra, we will examine in depth the free movement of these animals also to Andhra, so that this urgent problem can also be tackled. These are the various problems that are there.

While initiating the debate, Shri Qureshi pointed out that sometimes we find that the working expenses are going up. Here I must agree with what Mr. Kalyanasundaram has said, that when the gross earnings improve, when the passenger and goods traffic improves and we try to rationalise and modernise our equipment, when we try to have new types of cadres, very often it does happen that our expenses go up. But this time we have been able to have Rs. 30 crores of working expenditure less and that is the reason why our gross earnings are able to go upto Rs. 52 crores as far as the Budget proposals are concerned. I can assure the House that while curtailing the working expenditure, we will not try to retrench the workers and that our entire stress will be to see that it will have an effect on the economy in certain directions where wasteful expenditure can be avoided.

SHRI VAYALAR RAVI: Does it include the purchase also?

PROF. MADHU DANDAVATE: Not that.

I also wanted to point out that sometimes there is a temptation to reduce the maintenance and repair expenditure and thereby show that the working expenditure has gone down. I can assure the House that since the needs and claims of safety are the prior claims in our social life today, we will not curtail any expenditure on repairs and maintenance at all. That particular side will be properly balanced.

Again, while initiating the discussion, Mr. Qureshi referred to the accidents. He said, "Everyday, we are hearing about accidents and hardly any day passes that we are not able to hear about accidents." Here, I would like to point out to the hon. Member—he knows it very well because he himself has been a Railway Minister—that in the railway parlance what we call an accident is altogether different what a common man describes an accident. They are rather surprised, when they find that the number of accidents have gone upto 515. But I want to point out that we must

not be complacent and, at the same time, we must not take an alarmistic view. In the railway parlance, even when there is a small short circuit in a coach and there is a small fire not doing any damage to the passengers, even that is described as an accident. Collision, derailment, slight slipping of a pair of rails, a slight fire in the coach not causing any damage, all of them constitute an accident. That is the reason why it appears as if 515 accidents appear to be a very large number.

I would like to tell the House that since in the railway parlance an accident means something different from what an ordinary man understands, if you look at the list of accidents right from 1964 to October, 1977, you will find that in 1964-65, there were 1,293 accidents; in 1965-66, there were 1,200 accidents; in 1966-67, there were 1,201 accidents; even during the previous regime, in 1974-75, there were 925 accidents; in 1975-76, there were 964 accidents; in 1976-77, there were 788 accidents; during October last year, there were 474 accidents and now there are 515 accidents. You will find not that the number has really gone up very much. But sometimes when certain damage is done to the reputation of the railways, when some prominent accidents take place, when there is a loss of life, then a certain alarm is created. I do not know whether the debate on railway accidents will come up, but I can assure the House that as far as the safety is concerned, we are going to give priority to the safety problems.

We have deployed 25,000 men, 14,000 from gangmen and 11,000 from the RPF. So, these 25,000 men are patrolling the entire railway track of about 61,000 km. on which about 11,000 Indian railway trains are moving every day. The direct result of that is that in the last entire week, our patrolling men who are very vigilant were able to detect five cases of removal of fish-plates before the trains passed on those routes. As a result of that, the accidents have been avoided. But that potential mischief is there. Also, at some places with the help of dog-squads, we have been able to arrest certain persons. I do not want to allege that any particular agency or an organisation is responsible. But I can assure the House that the Government will do everything in its power to find out which agency is playing with the lives of the people and we will deal with them very firmly.

SHRI HITENDRA DESAI (Godhra) : Has it not been done so far ?

We are prepared to cooperate with you on that.

PROF. MADHU DANDAVATE : We are trying to find out.

In addition to that, there are, throughout the country, on the trunk routes, 1,300 stations which require actually circuiting of the tracks in the case of 420, we have already completed circuiting, by the end of March, 1978, on 50 more trunk route stations, circuiting of the tracks will be completed; and on the rest, it will be completed in one and a half years. Thus on all the 1,300 trunk route stations we will be completing circuiting of the tracks.

We are also trying to see that inspection is improved. We have an ultrasonic device with the help of which we can go on checking the rails and also oscilloscope by which we can check whether there are cracks in the rails, and that work is also going on.

We are taking a number of safety measures by which we will be able to prevent accidents, by which the number of accidents can be considerably reduced and better safety will be ensured.

Some one pointed out that some allegations were being made that the railway employees were responsible for the accidents. I want to refute that theory altogether. It is stated that the railway workers are discontented and, therefore, they are indulging in sabotage activities. That allegation has been made in some newspapers. I will take this opportunity to indicate to the House that in the last seven months of the Janata Government, how many demands of the workers which were pending for the last several years have been conceded. I would like to give that list. I have got them in my fingertips.

One is, all those who had been thrown out during the 1974 strike have been unconditionally reinstated, their punishments have been annulled.

Those who were under MISA and DIR during the Emergency have been brought back with a hundred per cent neutralisation of their salaries.

It was the constant grouse of the railway employees that their children had gone before the Railway Service Commission and passed the examinations and their names had also appeared on the panel but they never got the jobs, but with somebody's recommendation, 1,500 ad hoc people had been given jobs. We have sent all those cases to the Railway Service Commission and only if they get regularised, they will get their jobs.

[Prof. Mihnu Dandavat:]

Young employees and officers were saying that, in the past, due to favouritism, a number of people, even after attaining the age of superannuation, were getting extensions—one extension, two extensions, promotion during extension, and so on. We have now declared that, henceforward, throughout the Indian Railways, whoever completes 58 years, his service ends then and there. Even the Chairman of the Railway Board has not been made an exception to this, and the day he completed 58 years, he had to go. That is what we have done.

The Indian Railways were founded in 1853, and we are now in 1977. In 124 years of Indian Railways, the Class IV employees never got the selection grade. For the first time, after 124 years we have given to 50,000 Class IV employees selection grade in this country.

The question of dearness allowance was raised by all the trade unionists in this House. We settled that issue, and I am very happy to say that all the railway employees, no matter to what category they belong, right from 1st September, have been granted dearness allowance on the basis of revised dearness allowance; they have been paid just on the same basis as other Government employees.

The question of CDS was tackled very effectively. We have cancelled the CDS now, and the payment is being made. There are some complaints. We are looking into those.

Firemen, Grade B, were able to get promotion to the extent of 25 per cent. We have improved it to 50 per cent.

Licensed porters who put on trade uniform were required to pay a licence fee of Rs. 10. They constitute the poorest class on the Indian Railways. Their licence fee has been reduced from Rs. 10 to Rs. 5.

There were apprentices in this country; they were given training, but they were not getting jobs. I have made an agreement with the Apprentices Union that, by the end of March, 1978, 50 per cent of all these vacancies which will be created will be filled by these apprentices and they will be given jobs. These are the problems which we have tackled or have been tackling.

There is one more reference. The former Minister of State referred to the famous agreement about 10-hour duty. The

trade unionists in this House know it very well that safety demanded that ten-hour duty for loco-runningmen should be accepted. The previous Government made the agreement. After the agreement was made by the previous Railway Minister, the matter was referred to the then Finance Ministry. The then Finance Minister took the attitude that the Miahbhoi award talks of ten-hour duty, and our Minister has entered into an agreement of 10-hour duty with the loco running staff, and it is not necessary to go beyond that. He took the pretext of the 1974 strike and said that once they have gone on strike in 1974, the written agreement does not stand and that agreement was broken. I am happy to state that only this week, I have announced in the Parliament that we have revived that agreement; 15,000 more jobs, 10,000 plus 2,500 more jobs have been created. As a result of that, on one side the Miahbhoi award and on the other side, the ten-hour duty will be respected. That is what we have done.

The only issue that remains to be settled is the question of bonus and we have announced that we are settling this question in a phased manner. The militants on the other side who talk of bonus have forgotten that during the emergency, even those workers who were getting bonus were deprived of that; that bonus was abolished by mutilating and destroying the old Bonus Act. The first act of the new Government, as far as the Industrial labour is concerned, was to restore the *status quo ante*. Whoever was getting the bonus according to the old Bonus Act has started getting the same. The next phase will be about the Government departments like the P&T, Defence and Railways. Already, the Bhothalangam Committee is studying in depth the problem of income, wages and prices. We have already declared, the Prime Minister has already declared and I wish to make it clear that some misunderstanding that was being created about the Prime Minister that he told the railway workers that there would be no bonus, is not correct. He never told like that; it was a wrong news that appeared. The Prime Minister and myself have made it clear in this House that what the Prime Minister told the railwaymen or their representatives was that those who were covered by the previous Bonus Act, were getting the bonus now and as far as others including the railwaymen are concerned, only when the Bhothalangam report comes, we would settle that.

There is one more point. We have got the corporate enterprises group. In addition to the Railway Board at the official level, at the popular level, we have got this corporate enterprise group.

The representatives of the Railway Board, the Railway Minister, the representatives of the two recognised Federations and the representatives of the Officers' Federation sit together and discuss a number of policy matters. They act in an advisory capacity and we are seeing to it that this important *modus operandi* for participation and advisory capacity should be extended down to the zonal level. I am happy to announce today in this House that this forum which was taken to the zonal level, we have decided to take it to the divisional level so that more and more consultations at the lowest level are possible.

These are the things that we have done in this period of 6-7 months. Those who allege that we are anti-working class people should realise that what you could not do in 20-25 years, we have done in the course of this small period. That is the pro-working class people attitude of the new Ministry. We will continue to follow the policy of no-confrontation with the trade unions and cooperation with the trade unions. This is how we are going on and because of their cooperation we are able to augment our gross earnings. That attitude will continue to be there.

SHRI VAYALAR RAVI : Regarding apprentices, some diploma and engineering degree holders have represented to you from the Madras zone and I have also made representations to you, but nothing seems to have been done so far. Will you kindly look into that?

PROF. MADHU DANDAVATE : I will examine that.

As far as the structure of the Railway Board is concerned, I had agreed last time that along with the Report of the Railway Convention Committee, even the restructuring problem should be taken up and it was perfectly within the rights of the Members to refer to the restructuring of the Railway Board. Probably, if you just look at the paper, it may appear that the restructuring of the Railway Board is just a superficial restructuring, but I would request you to go into the details. I am very happy to say that the Administrative Reforms Commission recommendations were lying in the shelf for a number of years. It was not under our Government that the Administrative Reforms Commission was set up; it was under the aegis of the Congress Government that the Administrative Reforms Commission was set up. I appreciate and admire the fine work done by them. All that Madhu Dandavate has done is that the recommendations of the Administrative Reforms Commission which were kept pending in the shelf for years together are being imple-

mented. We have promptly acted with our dynamism and we have seen to it that these are implemented. What I have announced is not new in the sense that during my budget speech in June, I had explained what would be the parameters of the restructuring. I have already indicated to you that broadly we are going to accept the recommendations of the Administrative Reforms Commission. That does not mean that this is the last word on restructuring. Restructuring may go on but it is not merely the change in the nomenclature. To those members of this House like Mr Qureshi or Mr Kalyanasundaram or others who said that the restructuring is only that the number of members of the Board has been reduced, additional membership has been abolished and three advisers have been appointed and that it is only a change in name or surname, I want to tell that that is not the only change that has been brought about. The major change in the restructuring has been that I have decided that some of my powers as Minister, both administrative as well as financial, will go to the Railway Board and then considerable powers of the Railway Board have been transferred to the General Managers of the Zonal Railways and number of powers have been transferred from the zonal level to the Divisional level and we are going to spell out all those details and what will be the net result. Even when I was in the Opposition, I never demanded the abolition of the Railway Board. My friends will realise that I have always said that it must be re-organized and restructured. I never took up the irresponsible stand that the very instrument of administration should be destroyed because I know that the structure of the Railway Board is such that it is not merely the IAS officers who come and sit on the Railway Board. Not that way. Those who are technicians those who have worked for years in the railways, Mechanical Engineers, Civil Engineers, Electrical Engineers, men concerned with transport and signalling--it is these men who by gradual promotion become General Managers. And whenever any new vacancy arises, the seniormost General Manager of the operational line becomes actually a member of the Railway Board and the seniormost Member of the Railway Board becomes its Chairman. So, Sir, basically, the Railway Board is a functional organisation. It is not merely that academicians are brought into this but those who are concerned with the hard realities of the railways, its techniques and technologies, its operations and all the operations on the Railways and those who are concerned with the functional capacity come to the Railway board and we have only tried to restructure it. By this devolution of power and more and more delegation of power from the top to the bottom, I can assure

[Prof. Madhu Dandavate] you that in the coming months and years, a number of problems will be tackled at the lower level whether they are in Trivandrum or whether they are in Cochin or whether they are in Lucknow or whether they arise in Bombay and they henceforward they need not come to the Railway Board. A considerable number of problems need not come to the Railway Board and a considerable number of problems will be solved at the zonal level and also at the divisional level. This itself will give a greater impetus to the efficiency of the railways and that is how the problems are going to be solved.

There are many issues which were raised by hon. Members and I do not want to go into the details. But I would like to refer to one important aspect and that is the question of housing. In this entire scheme of finances, we can assure you that we are not going to curtail the housing activities at all. Here I want to give one reference. There was a controversy going on as to whether we should be able to pay ex-gratia payment to the railwaymen or we should have additional grant to give them some amenities. We discussed this proposition at the governmental level and when we found that when some ex-gratia payment is to be made to the workers, rather than making it in the form of an ex-gratia cash payment, it is better that we spent it on their amenities. Suppose Rs. 16 or 13 or Rs. 14 crores are to be spent, we would have been able to give a packet of Rs. 100 to each worker. We decided to spend Rs. 15 crores and in lieu of the fine contribution the railway employees have made towards the financial performance of the railways, how we decided on the distribution of the Rs. 15 crores is that we had the corporate Enterprises Group meeting at the various zonal levels and there even unrecognised unions were consulted and in consultation with the trade unions we decided as to on which part of the amenity we should spend this amount. The decision is that it should be spent for repairing the quarters, for giving better facilities, for constructing community halls in the residential areas where the workers are staying, for giving Central Schools to the railway workers. On all these matters we are spending the money and that is how we have been able to make one further contribution towards housing facilities, repairs of the houses of workers, etc. I can assure the House, as has been rightly suggested by the last speaker, that we should not curtail the housing facilities for railway workers. Formerly house construction work was banned. We have not banned it at all. On the contrary, we are going to expend it. Today we are very happy that amongst all the public sector undertakings the railways have been able to provide housing to 40 per cent of its workers still we are not

satisfied and we will continue to improve it.

Then, Sir, food is such a commodity that one is never satisfied with it. Even in our homes, if we are satisfied with the morning meal, we always tell our wives that the evening meal was not so good as the morning meal. She would say, 'I will compensate it in other ways.' Anyway that is the present position. Even in our homes we are not satisfied with the food arrangements. I am myself not fully satisfied, but you will find that on various routes we are gradually trying to improve the situation.

For example, in all these super-fast trains which we have introduced, the food is very good. At some places where there are best kitchens with modern equipments we will try to improve them and where there are patty cars we will try to improve them. These are some of the measures by which we will make improvement in the type of food that is provided. I will take cognizance of all the constructive suggestions which we have been made and I will try to improve all these things.

I will conclude with a very sensitive issue and that is, construction of new lines. Sir, you will be surprised to know that if we have to complete even the pending construction works in our hand we would require nearly about Rs. 331 crores whereas we have been given anything between Rs. 29 to Rs. 27 crores. We are asking the Planning Commission to change the whole norms. Unless we are able to get more allocation from the Planning Commission, it is not possible to start new line construction.

A suggestion was made that we could utilise the surplus. We have been able to show a surplus of Rs. 32.5 crores today. We are already having a gross income which is Rs. 83.2 crores more than the previous year. If the same trend continues, the surplus is bound to be more, but what happens is this. Whenever we generate any surplus, that is utilised in wiping out a part of the past indebtedness. So, we cannot utilise this, as some members suggested. So, some different norms should be evolved and these still will have to be discussed at the appropriate level. We will try to discuss this and we will find out whether some other machinery will have to be evolved.

Regarding the Ernakulam Alleppey line, I have told friends in Kerala that as far as the Ministry is concerned, we are fully satisfied. This is an important line to be undertaken. The Kerala Government has assured us that they will give some sleepers free. They said that

whatever government land is there, that will be given free of charge. So, that will slightly bring down the construction expenditure. So, we will have it examined.

I now come to the problem of electrification.

The problem of electrification is an important one from the point of view of railway statistics. There is the rolling stock of train whose weight is 1,000 tonnes. If we move it to one kilometre we call it 1,000 gross kilometre. For moving this 1,000 gross kilometre, what is the fuel consumption? In the case of steam operation it is Rs. 10; in the case of diesel operation it is Rs. 5. In the case of electric, it is only Rs. 4. Comparatively it is very much less. In the long run it is very advantageous. But now comes the paradoxical question: Why are we not able to do this electrification on a large scale? The answer is this: If we have to electrify one k.m. of railways, the initial capital investment required is between Rs. 10 to Rs. 13 lakhs. I had a meeting of the scientists. They all belong to my own fraternity and I can talk and discuss matters at their own level. I asked them to put some research work by which we can bring down the initial capital investment in the case of electrification from 10 to 13 lakhs to 7 to 8 lakhs. per k.m. If we are able to do that—I am confident we will be able to do that—we will certainly be able to move ahead.

Then a question was asked: What about Kerala where there is surplus of electrical energy? As you know, there are certain general norms. These are as follows: Number one priority will be electrification of high density routes on the trunk routes. Number two priority will be such routes which are contiguous to that. Number three priority will be even for non-trunk routes provided there is traffic density available there, on those routes. These are the priorities which have been fixed, and I am sure, Kerala will be able to have its due share out of them.

These are general parameters which we have fixed up. I do not want to take much of your time.

I am thankful to all the hon. Members of the House who have participated in the debate. Without any bitterness, they have tried to make concrete suggestions and you can rest assured that I am capable of responding to the suggestions that have been expressed by the hon. Members and I will implement their constructive suggestions that have been made.

बो राम सेवक हवारी (रोपडा) : माननीय मंत्री जी ने पिछड़े हुए इलाकों की प्रावधिकता देने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

प्रो० मधु बंडलते : उसका जवाब मैं मंगलवार दे चुका हूँ। हमारे मंत्रालय की निवित राय है कि पिछड़े हुए इलाकों में नई रेलवे लाइन शुरू करने के मामले में प्रावधिकता दी जाए। लेकिन प्राविन्दि कमिशन ने आज तक जो नाम्बं निर्वाचित किए हैं उन के अनुसार हर बक्स यहीं केवा जाता है कि रिटेन अवर दस परसेंट से अधिक हो तो वहां प्रावधिकता दी जाए। हमने नोट तंयार करके बता है विस में कहा है कि खोदी सी तबदीली इस नाम में और कस्टोटी में की जाए और पिछड़े हुए इलाकों में नई रेलवे लाइन होने के बाद यातायात के बढ़िय काफी आवश्यकी बहु हो सकती है और इस तरह की रिपोर्ट अवर हम प्राप्त के सामने पेश करें तो वहां के लिए प्रावधिकता दी जाए। इस प्रकार की सिफारिश हमने प्राविन्दि कमिशन को की है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House approves the recommendations made in paras 5, 6, 7, 11, 14, 17 and 18 contained in the First Report of the Committee appointed to review the rate of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance which was presented to Parliament on the 17th November, 1977.

That this House further directs that the action taken by Government on the other recommendations made in this Report, should be reported to the Committee".

The motion was adopted.

15.36 hrs

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER FOR WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after a marathon wait, this very simple business has really come up. I am conscious of the fact that the House has to dispose of a lot of business before it adjourns tomorrow. Therefore, I am going to be very brief.

This Bill which has been before the House is a very simple one and I hope the hon. Members will support this.

I beg to move* :

"That the Bill further to amend the Requisitioning and acquisition of Immovable Property Act, 1952, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Under the Defence and Internal Security of India Act, 1971, the Ministry of Defence requisitioned lands at various places for the purposes connected with the defence of the country. With the revocation of the promulgation of the Emergency, the validity of the Defence and Internal Security of India Act, 1971 would have ceased after six months, i.e., on the 26th of September, 1977, and all the immovable properties requisitioned or purported to be requisitioned under the said Act and the rules made thereunder, would have, therefore, to be released on or before the 26th of September, 1977. Since the Ministry of Defence considered it necessary to retain these properties under requisition beyond that date for purposes of the defence of the country, and the Parliament was not in session, the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Ordinance, 1977 was promulgated on the 23rd September, 1977 until such time as it could be replaced by suitable legislation in the following session of Parliament. The Ordinance amended the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, to provide that the afore-mentioned properties shall be deemed to have been requisitioned under that Act. Accordingly, the present Bill seeks to replace the afore-said Ordinance.

With these words, I commend the Bill for the consideration of the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved:

"That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Bill

15.38 hrs.

[**SHRI M. SATYANARAYAN RAO**
in the Chair.]

MR. CHAIRMAN : Mr. Banatwalla, are you moving your amendments?

SHRI G. M. BANATWALLA : My point is that this is not the stage for moving the amendments.

MR. CHAIRMAN : All right. Mr. Jagannathrao.

SHRI JAGANNATH RAO (Berhampur) : Mr. Chairman, Sir, I agree with the hon. Minister that this is a simple Bill.

This Bill seeks to replace the Ordinance which was promulgated on the 23rd or 26th of Sepber, 1977 because the Defence of India Act, 1971 expires six months after the revocation of emergency. Some properties were acquired during the emergency which was proclaimed because of war with Pakistan. The purpose for which these properties were acquired during the emergency should continue so that the Government may continue to have the properties in their possession. Then, what was the purpose for which those properties were acquired or requisitioned. I do not know why during the war time these properties were requisitioned and whether the purpose for which they were requisitioned was served or not. I do not know this.

If the purpose during the war time ceases to exist, it is not correct nor is it legal for the government to continue possession of the requisitioned properties. That is what the High Courts and the Supreme Court have held. What is happening? I have previous experience of this. Properties were requisitioned during the Second World War. They were not released even in 1960. The reason given by the Government was that the Government was not in possession of properties to give accommodation and therefore they had to continue in possession of requisitioned properties. That is not valid as per decision of the courts. During wartime you have to meet aggression and you requisition certain properties. There is no war now. We are living in peaceful times. It cannot be said that the purpose for which the properties were requisitioned continues.

SHRI SIKANDAR BAKHAT : I am not saying it; Defence Ministry says it.

*Moved with the recommendation of the president.

SHRI JAGANNATHA RAO : The purpose now would not be the same because we are not at war with any other country. I have also experience of the government; Government has always been saying : we have no accommodation and therefore we should continue it. How can a poor citizen stand up against government which is so powerful. He cannot go to a court. How many can afford to go to the Court and get a legal remedy ? Therefore, I request the government not to stand on technicalities.

Secondly, I should like to know the list of properties that were acquired. What were the properties that were requisitioned during war time in 1971 under the Defence of India Act. Are all the properties required by the government? Your argument is : Government has no accommodation; it has no resources to build their own rooms or whatever it is; that argument is not valid to continue to be in possession.

My next point is about compensation or rent. You pay to the owner a nominal sum. Here again a poor citizen has to fight a government. Even ordinary tenants, once they get possession of the house, do not leave the house and a poor landlord has to go to the court to evict him. Here there is no question of vacating. The rent that you were paying in 1971 would not be adequate now. Therefore, you should reconsider and see that the compensation you pay during the continuance of the requisitioned building or property is adequate.

I request the hon. Minister to enlighten the House on the points I have raised. The Government should not insist that the Defence Ministry wants the properties to be in their position. They will continue to want because you do not want to build your own buildings, because you do not have resources. That is not a valid ground and hence I should request the government to release the properties.

SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA (Uluberia) : I support this Bill because it serves a national interest for defence purposes. For national reconstruction you will be requiring this power to acquisition or requisition properties. The only thing that you should be careful about is that the person who is losing his property should get adequate payment and he should be properly rehabilitated.

If he is a poor man and if his means of livelihood or avocation is affected, he should be properly rehabilitated.

With these words, I support the Bill.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani) : Sir, this amending Bill, which seeks to amend the requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, provides that all those properties which were requisitioned under the Defence of India Act should be deemed to have been requisitioned and deemed to be in requisition under this Act of 1952 because the Defence of India Act lapsed six months after the revocation of the proclamations of emergency. As already pointed out, the minister should enlighten the House with respect to certain important information, namely, the number of properties that had been requisitioned under the Defence of India Act. We must also have a glimpse at the nature of these properties that were requisitioned, whether they were residential premises and if so, whether they were occupied by the owners themselves. These are the various information that we must have before we are in a position to makeup our mind about continuing the requisition of the premises.

However, it is well known that the Defence of India Act was a purely temporary measure. It was passed in order to meet the exigencies of war. We had the proclamation of emergency in 1971. Thereafter, there was another proclamation in 1975 and both of them have been referred to under the Defence of India Act. Solemn assurances were given to this House that the measures sought to be taken under the Defence of India Act would be purely temporary in nature. It was said on the floor of the House that there was no intention whatsoever on the part of the government to interfere with the life, properties and avocations of the ordinary citizens. I may quote the then Prime Minister from this debate when the Defence of India Bill was under consideration —Lok Sabha Debates (Third Session) Vol. IX 3rd session, 1971, col. 38 :

"This Bill only seeks to provide the necessary legal sanction as a consequence of the proclamation of emergency made by the President. We have tried to interfere as little as possible with the normal avocations of our citizens."

Further, at the end of the debate, another assurance was given to the House because the House was agitated about several points and the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri K.C. Pant, said—I quote from the same volume, col. 74 :

"While support came from almost all sections of the House, certain points were raised in the course of the discussion. One of these was that this measure should not extend beyond the period of Emergency. In a democratic country, the sentiment

[Shri G. M. Banatwalla]

is natural, and I respect it. I can say that our intention is that this should not extend beyond the requirements of the Emergency."

Now, Sir, the solemn assurances given on the floor of this House do carry some meaning and significance. It is rather disappointing to see that the measures that have been taken under the Act are now sought to be vested with some sort of permanence. This is specially more shocking when it comes from the Janata Party Government. The Janata Party had totally opposed emergency and had promised that the aberrations of the emergency will be done away with; and it is rather shocking that this government of the Janata Party has now come forward with this bill to invest the measures taken under the Defence of India Act with regard to requisition, with a sort of permanence. Is it their attitude, to condemn Emergency and the measures taken under it on the one hand, and at the same time to continue to reap the benefits and advantages of the Emergency which have accrued to the Government at the expense of the poor citizens? I hope, therefore, that this particular attitude would be abandoned; and that aberrations, whether they are of pre-Emergency, Emergency or post-Emergency variety, are done away with.

This Bill seeks to create a post-Emergency wrong, injustice or aberration, by giving permanence to the measures taken under the Defence of India Act during the period of the two emergencies. Here also, we must know the number of properties requisitioned and acquired under the first proclamation of Emergency and again, the number acquired after the second proclamation of Emergency. I hope the House will be enlightened on this.

We must look at this issue on the basis of certain road principles. Requisitioning is temporary by its nature; and acquisition is permanent by its nature. If the needs of the Government are to continue, it is wrong to continue to have the property under a type of temporary requisition, because such a requisition is a wrong and an injustice to the common citizen, and it puts him to hardships. If the needs are to continue, the requisition should be turned into an acquisition. It is also a point that must be seen on the basis of broader principles.

However, Government should try to cater for its needs by causing the least possible expenses to the citizen. If more and more accommodation is wanted for Defence purposes, there can be no grudge.

ing it, but at the same time there is need for proper and adequate measures to be taken with respect to them.

I may say that when the properties are required under the Defence of India Act, the measures are very sweeping in nature. There are certain built-in safety measures in the Requisitioning and Acquisition of Immovable property Act of 1952—which are not available to properties requisitioned under the Defence of India Act. For example, under the 1952 Act, such properties which are residential in character and are occupied by the owner himself, cannot be requisitioned. And in the case of other residential premises, alternate accommodation has to be provided to the tenant. These safety measures, protecting the interest and the rights of the citizens, are not to be found under the Defence of India Act. Therefore, any measure to continue the requisitioning of the premises under the Defence of India Act, by an amendment of 1952 Act should be a very unwelcome measure. I hope these points will be duly considered by the Government.

There is one more pertinent issue that I have to raise. Under the Defence of India Act, a property is requisitioned for a variety of purposes, other than also the defence of the country. Section 23(1) says that the property can be requisitioned for purposes of public order, defence of India, civil defence, public safety, internal security, efficient conduct of military operations, for maintaining supplies and services essential for the life of the community and so on. We, therefore, find that under this broad category of public order, maintenance of internal security and maintenance of civil supplies also a property can be requisitioned under the Defence of India Act. But this is not so in the case of our normal legislation which goes under the title of Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act of 1952. According to section 3(1) of the Act of 1952, a property can be requisitioned only for a public purpose, being a purpose of the Union. The statement of objects of our amending Bill that is before the House says that these properties should continue to be under requisition for purposes of defence of the country. I would draw your attention to the statement, where the specific words are "for purposes connected with the defence of the country these premises are to be requisitioned."

However, we find that the properties have been requisitioned under the Defence of India Act for a variety of purposes, for a wider list of purposes, and therefore it would be unfair to include them within the meaning of "premises requisitioned".

under the 1952 Act. It is a serious aberration. I would have understood if only such properties which were basically required for purposes of defence had been sought to be kept under requisition. But here there are other properties under the Defence of India Act, which have been requisitioned for other purposes, like maintenance of civil supplies, public order and maintenance of internal security, a very obnoxious term these days. They have been requisitioned for these purposes. Am I to understand from the Government that they have now adopted all those obnoxious terms as very good in character, and they continue to reap the benefits of the same?

Sir, I have placed these points before you and before the House, not in any spirit of confrontation with the Government on this particular issue. That there must be a proper strengthening of the defence of the country is a point on which no body can have two opinions. But, then, this amending Bill has raised several issues, and it is in the spirit of understanding of all these issues that I have placed my views before the Government and this House. I hope these will receive serious consideration at the hands of the Government.

1400 hrs.

SHRI VALAYAR RAVI (Chirayinkil): I fully support the sentiments expressed by Shri Banatwalla who raised certain relevant points.

First of all, I would like to know from the hon. Minister whether he has brought forward this Bill on the recommendations of the Defence Ministry, because they have to recommend that it is necessary for defence purposes that the properties requisitioned in 1971 should continue in their possession. If they have so recommended, it is necessary for him to have a thorough discussion with the Defence Minister and then also use his own discretion because the Defence Minister might simply have forwarded the recommendation of his officers. When the properties were requisitioned under the Defence of India Rules the people might not have been able to raise any protest, but today the situation is normal and we are living in a peaceful atmosphere. Is it necessary still to think in terms of enemies around us?

In this connection, the hon. Minister might have received a representation that one of the friendly countries has confiscated properties in the name of enemy property. This has happened in Bangladesh. I am only saying that we cannot

take the same attitude. So, it is necessary that there should be a reconsideration of the approach.

No doubt he would have discussed it with the Defence Minister, that is inevitable, but nobody, whether it is the Government or an individual, wants to give up a property once it has got hold of it. Everybody wants to hold on to it. That is the natural tendency, and that may prevail even in the Defence Ministry. So, it is a very serious matter.

As Mr. Banatwallah and Mr. Jagannath Rao have pointed out, assurances have been given on the floor of the House that this was only a temporary measure and that when the time came, the properties would be returned to their owners, but by bringing this amendment, we are making it a permanent measure.

There is reference here to properties requisitioned before 21st March, 1977. That date refers to the revocation of the emergency. But is it a fact that many other properties had been requisitioned before that date for other purposes also? He must know what happened in Delhi, for instance. I know his views and he knows my views on the subject. I do not support what happened in Delhi in those days. I am only raising a doubt, he can correct me. By this law are you not going to perpetuate whatever had been requisitioned in those days, depriving the right of property of poor people who had a few square metres of land in the name of beautifying the city or maintaining law and order? For example, in the Jama Masjid area not only were people thrown out, properties were also requisitioned. So, if in Delhi and some other parts of the country properties had been requisitioned for such purposes, why do you want to legalise it? Why can't you look each case on merit? Why can't you look each case with a purpose? The purpose should be looked into: the merit should be looked into. It should be looked into whether it is for a national purpose, whether it is useful for the society or the community or whether it is a superfluous thing, some kind of a thing, to please some affluent sections of the society. If it is so, I would urge upon the hon. Minister not to agree to that. He should not be a party to that. All the time, the decisions are taken by the bureaucrats at the official level. That is why I would request the hon. Minister to have his personal discretion in the matter. By making this enactment, there is some kind of an infringement on the right of the citizen which they have already surrendered. A temporary thing is being made into a permanent measure. With these words, I would request the hon. Minister to reconsider this matter.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Mr. Chairman, Sir, this Bill is a routine Bill which has been forwarded to the Ministry of Works and Housing by the Ministry of Defence and they are going through the process of passing it.

As has already been pointed out, the Bill is a continuation of the process that was started from 1962 when the first Emergency due to external aggression was there and the Defence Ministry took over certain houses and certain properties for use of defence purposes. Now, when the Emergency lingers longer than usual, its powers also degenerate. That had also happened to Emergency due to external aggression. Firstly, this Act was used to acquire property which was absolutely necessary for defence purposes. Then, what happened was that some Colonel wanted a house in some posh area and as he could not get it normally, he used this law to acquire that house and to stay in that house. Then, some General wanted another house in another posh area and he also used this Act to acquire that property.

Now, we are guaranteeing by this Bill the right of property to high military officers to occupy any civilian property, may it be for residential purpose, may it be for luxurious purpose, and to continue to have it. As you will see, in all big cities there is not sufficient accommodation available for the army. For example, in Calcutta in my own city, I know that there are many houses which have been acquired by the army in order to house their officers because there is insufficient accommodation for defence people in Calcutta. In Bombay also, a large number of houses have been acquired. In all places wherever there are big military establishments, a large number of houses have been acquired. The defence is a good pay master. They pay on the first of the month. I am not for the property owners who may be thinking that they are getting less money. But what should happen is that the defence people also, when they are operating in the civilian field, should be prepared to take recourse to the normal law of the land in getting the property. They should compete in the rents, like any other organisation because no such exigencies exist at the moment. The Government should draw up a plan for five or ten years, that they will not take any private property any more and that there will be a flat for every military personnel staying in any city or an area which is congested. This a thing which I want to convey to the hon. Minister.

The problem of defence accommodation is a big problem. For the army, it is a very big problem because there is the question of family postings and non-family postings and there is insufficient accommodation

for the army personnel. So, I want to bring it to the notice of the hon. Minister that it has some bearing on the problem of insufficient accommodation in big cities where a large number of houses have been taken over by the army people. It is very difficult to change the rents. You get your rents all right but it is very difficult to change the rents and there is a lot of bureaucratic red tape there. The competitive rents are not there. A plan should be drawn to have houses in the main cities for defence personnel so that for residential purposes the properties of ordinary citizens are not requisitioned.

Secondly, with regard to the defence requisitioning of properties on which refugees have settled, the hon. Minister has to do something about it since he looks after supply and Rehabilitation also. In Calcutta, there are many lands which during the last war were to be requisitioned by the Defence. After the World War, when the use for them was over, the refugees came and settled there; and they had been living there for a long time. In the last three or four years, what has been happening is that the rent of land has been going up, and these owners sometimes have lodged cases in High Courts to ask the Defence to de-requisition the property. Or, in some other cases, the Defence people think as to why they should keep these lands which are occupied by the refugees and which are not occupied by Defence People. I know of two cases where the Defence people forcibly tried to evict the refugees in Alipore and Dhakuria, the Defence forcibly tried to evict them from the land which was requisitioned by the Defence, the old barracks, in which refugees were living in sub-human conditions; they said that they would bring bulldozer and everything and get these refugees out of that place.

My appeal to the Works and Housing Ministry is that all Defence properties which have been requisitioned by the Defence Ministry and which the Defence Ministry wants to give up and in which there is refugees settlement now, should be acquired by the Central Government directly so that the refugees get permanent ownership or some right on the land on which they have been living for the last 30 year and to which their economic well-being and living is connected. This is a very big problem in Calcutta because, I know, in Defence areas, some 50,000 people are living; they are living in those barracks which belong to Defence and which were acquired by Defence. While passing this Bill, I would say, effort should also be made to see that the refugees are given permanent rights, so that the Defence cannot all of a sudden decide 'We want to give up this land; we want to de-requisition the land; let the refugees go to

Hell, let them be thrown on the streets'. The Central Government should take over these lands so that this does not happen.

As I have already mentioned, a long-term programme for having houses for Defence personnel in big cities like Calcutta, Bombay, Hyderabad, etc., should be taken up, so that the Defence people, for their residential purposes or for having their NCC units, do not take recourse to this law which is an Emergency law for acquiring the properties of ordinary citizens. That is all.

SHRI SIKANDAR BAKHT : I thank the hon. Members for having shown interest in this Bill, and I would like to dispel some of the misunderstandings with regard to this Bill. Primarily, there were no residential buildings which were acquired during this period, there were only some lands which had been acquired. I would like the hon. Members to know that this Bill seeks to amend the 1952 Act. The 1952 Act contemplates that requisitioning of properties is done for a maximum period of ten years. As far as the compensation part is concerned, I am happy to let the hon. Members know that this compensation will be reviewed after every five years. Due consideration is paid to the primary difficulties which arise on account of requisitioning of land.

I wish to assure the hon. Members that Government would not have considered retaining these lands if it had not been considered imperative by the Defence Ministry. These lands are required to be retained for purposes of Defence alone. It is really a very delicate matter for me to dilate on, but I do really hope that all of us are concerned, so far as our Defence necessities and requirements go, and that you would not like to subject these to a very minute surgery asking why, what sort of Defence requirements are they, and all that. I assure the House that it was considered to be absolutely necessary to retain these properties for the defence of the country. After all, there are extraordinary circumstances during aggression, but there are certain circumstances which do continue throughout, and the Defence Ministry consider that, in accordance with the permanent measures which the Defence Ministry has to undertake, this retention of lands is absolutely necessary.

My hon. friend, Mr. Banatwalla, said something about the aberrations of Emergency. I want to avoid referring much to what happened during Emergency. But, certainly, I am sure, the requirements of the Defence Ministry cannot

be categorised or placed in the same category as Emergency things or the aberrations committed during the Emergency. It is entirely of a different type. All the aberrations of Emergency which my hon. friend referred to, related to things happening inside the country, whereas this particular thing is required for some other purposes.

Some hon. Member wanted to know the list of the properties. I have already stated that this list does not include any residential houses, so the question of displacement of the occupants and their consequent rehabilitation does not arise. I would like to tell the House that the lands acquired are at Umed Bhawan, Kota (September, 1976), Ganganagar (May, 1977), Suratgarh (May, 1977), Udaipur (May, 1977), Amritsar, Barmer, Jassia, Mitorikhurd Barmer, Banar and Jodhpur. This is the list of places where the lands have been acquired. No residential place is there.

My friend, Shri Roy mentioned something about the refugees because of the land which has been acquired for defence purposes in Calcutta. Unfortunately, it does not concern this Bill. He is welcome to give me the full particular, and I would certainly look into the matter.

The House will appreciate that the Government does not at all intend to create any difficult situation for our citizens. We are doing this under absolute requirements and it is necessary for the defence of India. Therefore, I am sure, this will not call for much of a dissection and I hope, the Hon. Members will pass this Bill unanimously.

MR. CHAIRMAN : Mr. Vinayak Prasad Yadav.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa) : I beg to move.

That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, be referred to a Select Committee consisting of 7 members, namely :—

1. Shri S.S. Das 2. Shri Ramapati Singh 3. Shri Sikandar Bakht 4. Dr. B. N. Singh 5. Shri Chandradas Prasad Verma 6. Shri R.I.P. Verma; and 7. Shri Vinayak Prasad Yadav, with instructions to report by the last day of the first week of the next session. (4)

MR. CHAIRMAN : Now, I shall put the amendment moved by Shri Vinayak Prasad Yadav to the vote of the House.

The amendment was put and negatived

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up clause by clause consideration. Clause 2.

SHRI G.M. BANATWALLA : In view of the assurance given by the hon. Minister, I do not want to move my amendment.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 2 was added to the Bill

MR. CHAIKMAN : There are no amendments to Clause 3. So, the question is :

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SIKANDAR BAKHT : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed"

Dr. Ramji Singh

डा० रमजी शिंह (बांगलुरु) : सभापति जी, सचमुच यह बहुत छोटा बिल है, 25 बाराये इसमें पहले भी, भव एक बार इन्होंने इस में जोड़ी है। मैं समझता हूँ कि यहीं भटोदय इस संबोधन विवेयक को लाने से पहले मूल विवेयक पर भी कुछ नवार ढाल दें। और उस की कुछ आवश्यक धाराओं का भी संबोधन कर दें, तो यादा अच्छा होता। 1968 में जब इस बिल को लाया गया

और इस को पास किया गया, तब से भव तक यह हमारे सामने अस्थायी रूप से था, लेकिन इस विवेयक के द्वारा इसको स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया है। बल्लुतः हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि जो काम एमजॉन्सी के लिये किया जाये, उसको विलक्षुण सामान्य रूप में न रखा जाय। जैसे एक बात मैं आप के द्वारा माननीय बंदी जी से कहना चाहूँगा —क्या कारण है कि प्रतिरक्षा के लिये कोई जमीन वा कोई भकान 15 बड़ों से अस्थायी रूप से कब्जे में लिये हुए हैं। यदि प्रतिरक्षा विभाग को उस भकान या जमीन की स्थायी रूप से बहरत है—प्रतिरक्षा के लिये लिंगी भी चीज़ की बहरत भारतवर्ष के लिये प्रबन्ध बहरत है—तो उस को स्थायी रूप से एकवायर क्यों नहीं कर लिया जाता। इत तरह से उस को बहर में लटकावें रखने को क्या बहरत है, उस को स्थायी रूप से के लोकिय, तब इस में हम सोमों के कुछ कहने को आवश्यकता नहीं रहेगी।

दूसरी बात—बहुत सारी जमीनों को, जो इस कानून के अन्दर सरकार के कब्जे में है, कहीं-कहीं उन को दूसरों को दे दिया जाता है। जैसे बनारस की जमीन है, बनारस में जो जमीन सरकार के कब्जे में थी, उस को हृतिनों को दिया गया, उन को उस पर सेंटिल किया गया, लेकिन उन से 20 लूना अर्थात रेट दिया गया, यह कौन सी सेंटिल है? मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का काम न हो। इसी लिये, सभापति भटोदय, मैंने एक छोटाहा संबोधन बहुत सोच-विवार के बाद इस बाकि भव एसी जमीन भाष्य के पास काहिल है तो उस में हृतिनों द्वारा भन्नुस्खित जातियों को सेंटिल कर दिया जाय। राज्य सभा की बहस में भी भंडी भटोदय ने देखा होता—यहाँ भी यह बात स्पष्ट रूप से साई गई थी कि ऐसी जमीनें जो सरकार के अधिग्रहण में हैं, वे हृतिनों को कील-नुना ज्यादा रेट पर दी जाई है।

मेरी इस सम्बन्ध में भंडी जी के दो विनाशी हैं—यदि प्रतिरक्षा विभाग को किसी

भूमि की आवश्यकता है तो प्रतिरक्षा विभाग के लिये भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति प्रड़ंगा नहीं ढाल सकता है, उस जमीन पर मकान का अधिष्ठात्र स्थायी रूप से कर लिया जाय, लेकिन उस को इस तरह से घबर में न रखा जाय। यह बात आधिक दृष्टि से भी ज्यादा अच्छी होती। दूसरी बात—यदि आप के पास कोई जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, उस पर आप को कोई काम नहीं है तो आप उस को हरिजनों और अनुसूचित जातियों को दीस-गुना किराया निकर नहीं, बल्कि सामान्य रूप से दे कर उन को सैटिल कर दें।

मैं केवल हन्दी दो बातों की ओर माननीय मंत्री जी का व्यान आवश्यित करना चाहता था। इस बिल का समर्थन मैं इस लिये करता हूँ कि अपेक्षी बार वे किर हस को बिन्दा नहीं करेंगे और जो एमजॉसी की ओरें हैं उस को एमजॉसी तक ही रखेंगे।

चौं विकासर बहार : सभापति जी, मैं बहुत गुम्भाजार हूँ—सम्यानीय सदस्य ने इस बिल का समर्थन किया है। लेकिन उनकी इतिहास के लिये मैं सिफ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे मिनिस्टर आक स्टेट फार बिफैन्ट इस बहत यहां मौजूद हैं। अगर वह भीजूद न होते तो वो कुछ माननीय सदस्य ने फरमाया है, वे बातें उन तक पहुँचाने की कोशिश करता।

जहां तक हरिजनों की बात है—यह कम से कम इस बिल के परव्यु के बाहर की बात है। इम्बूवेबिल प्राप्टीक सिफ़ पब्लिक परस्पर के लिये स्ती जाती है। दूसरे उस मकान के लिए वह जरूरत प्रधर बाकी नहीं रही, तो वह प्रोपर्टी रिलीज हो जाती है। जेड्यूल फास्ट्स और जेड्यूल ट्राइल्स के लिए इस बिल के मात्रहृत जमीन को रोकना भुमिका नहीं है। यही मुझे अर्ज करना चाहा।

MR. CHAIRMAN : Now, the question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.38 hrs

BETWA RIVER BOARD (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH).

Sir, I beg to "move".

"That the Bill to amend the Betwa River Board Act, 1976, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

वह जो विषेषक प्रस्तुत है वह एक मामूली सा विषेषक है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र से गुजरती है और उस क्षेत्र से गुजरती है जो ड्राइ प्रोन इलाका कहलाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने मिल कर यह निष्क्रिय किया कि राजधानी में एक बांध बना कर इसके पानी का उपयोग तिचाई के लिए किया जायेगा। उस समय केवल तिचाई के लिए यह योजना बनी थी। बाद में दोनों राज्य सरकारों ने मिल कर यह निष्क्रिय किया कि जो बांध बनेगा, जो पानी इकट्ठा होगा, उसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जायेगा और वैसे पानी के बटवारे के लिए सहमति हो गई थी, उसी प्रकार से बिजली के बटवारे के लिए भी दोनों राज्य सरकारों में सहमति हो गई है। अब क्योंकि बिजली बनने की बात है, इसलिए कुछ संशोधन पुराने एकट में लाये जा रहे हैं जिनमें बिजली का यह काम भी करव हो सके।

बोर्ड के बठन में केन्द्रीय सरकार के बिजली मंत्री या उनके कोई नामीनी और राज्य सरकारों के बिजली मंत्रियों को बोर्ड

[री भानु प्रताप सिंह]

में शामिल किये जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

दूसरा संशोधन, जोकि महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, यह है कि फाइनेन्शियल एडवाइजर अगर राज्य में न उपलब्ध हो, तो केन्द्रीय सरकार उन दोनों राज्यों के परामर्श से केन्द्र से किसी को भेज सकती है।

इसके अतिरिक्त एक शास्त्रिक संशोधन यह है कि जहां-जहां केवल ईम की बात आई है, वहां विजली का उत्पादन करने की बात भी कही गई है।

बस इस बिल में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। बाद में जो प्रश्न उठेंगे, उनका मैं उत्तर दे दूँ।

बी टेल प्रताप सिंह (हमीरपुर) : सभापति महोदय, अभी-अभी जो बिल हमारे सम्बन्ध रखा गया है, मैं उसका स्वायत्त करता हूँ।

जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो राजमाट नाम से बांध बनाया गया है, उसका उपयोग न केवल सिवाई के लिए किया जाये बल्कि उससे विजली भी बनाई जा सकती है और ऐमा करना अच्छा रहेगा। इस ओर सरकार का ध्यान गया है, इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ।

अब मैं इस बिल की कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा। मूँहे कुछ इस बात का दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने मेरे संशोधन को देखा होगा लेकिन उस पर उन्होंने अपनी राय छाप्ट नहीं की। यह सही है कि पावर हाउस के लगाने की व्यवस्था हो, इसलिए इस बिल में संशोधन नाया गया है और दुसरा संशोधन जो माननीय मंत्री जी ने महत्वपूर्ण बताया

है, वह यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में जो अधिकारी हों, उन्हीं में से इस बोर्ड में कार्र करने का चयन करना है लेकिन सम्भव है कि कोई फाइनेन्शियल एडवाइजर अच्छा न मिले जोकि मध्य प्रदेश सरकार के प्रत्यंगत हो या यू० पी० सरकार के प्रत्यंगत हो तो उसके लिए संशोधन दिया है। ये संशोधन ठीक है कि यहां केन्द्र से फाइनेन्शियल एडवाइजर निया जा सकता है, जो कि योग्य हो उसे ले लिया जाये। लेकिन मैं कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। विगत कांग्रेस सरकार में इस संशोधन विधेयक को न रखने के सम्बन्ध में जो भूले हुई हैं मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा।

बीमन, यह बोर्ड गठित किया जाएगा जिसका नाम बेतवा रिवर बोर्ड होगा। वही उस प्रोजेक्ट का संचालन करेगा। इस बोर्ड के सम्बन्ध में पिछली कांग्रेस सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की हुई है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि आते हैं उनके समावेश की इस संशोधन के द्वारा इस बोर्ड में व्यवस्था हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष वहां के, प्रथमांतर केन्द्र के पिचाई मंत्री होंगे। इस बांध के सम्बन्ध में उस समय मिचाई को ही बात थी। केवल सिवाई के लिए इस बांध का निर्माण किया जा रहा था। इसलिए इस बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए सिवाई मंत्री जी को अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था की गयी। लेकिन अब कूकि वहां पावर हाउस भी बनाया जा रहा है तो इस बात को देख कर इस बिल में कोई संशोधन नहीं किया गया। मैंने इसी दृष्टि से अपना संशोधन रखा है कि विजली मंत्री उसके सदस्य होंगे।

बिल बोर्ड का हम गठन करने जा रहे हैं और जिस बांध के लिए हम बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें यह बातें ध्यान में रखनी होंगी। वह दस किलोमीटर

लम्बा बांध बनेगा । 214 स्वायार किलोमीटर जमीन उसमें ढूबेगी । उत्तर प्रदेश के 26 गांव और मध्य प्रदेश के 22 गांव उसमें ढूबेंगे । इतना बड़ा एरिया उसमें ढूबें पर करीब करीब 16 हजार की पापुलेशन वहां विस्थापित होगी । इतनी बड़ी जनसंख्या वहां से हटायी जायेगी जिससे भयानक समस्याएं पैदा होंगी । मैं नहीं कहता कि सिचाई भवी औ केन्द्र में होंगे वे वहीं के होंगे । आज हमारे सिचाई भवी पर्यावर के हैं, ऊर्जा भवी दक्षिण भारत के हैं । वे दोनों सक्षम हैं । लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भवियों का भी समावेश करने की कोशिश की जाये । क्योंकि वे उस क्षेत्र से आते हैं, वहां के जन प्रतिनिधि हैं और वहां की जनता की माकांक्षाओं का वे अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । इसलिए मैंने अपना संशोधन रखा है ।

साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इस बोर्ड में उन संसद् सदस्यों का भी समावेश किया जाये जो बुन्देल खण्ड क्षेत्र के रहने वाले हैं । वे भी इस बोर्ड के सदस्य होने चाहिए । क्योंकि वहां के जन प्रतिनिधि होने से वे वहां की जन भावनाओं को अच्छी तरह से समझने हैं और वे इस बोर्ड के कुशल संचालन में काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं । यह मुझाव मैंने इसलिए रखा है कि वहां के विस्थायितों की जगह बदलती होगी क्योंकि बहुत जारे गांव ढूब जुहे हैं । मुझे पता है कि वहां जो विस्थापित हुए हैं उनको अभी तक जमीन नहीं मिली है, उनको मुआवजा नहीं मिला है । इसलिए ऐसी समस्याओं के सम्बन्ध में वहां के जन प्रतिनिधि काफी सक्षम हो सकते हैं । इसी क्षयाल से मैंने अपना संशोधन रखा है । दूसरे किलोमीटर लम्बा यह बांध बनेगा, सब्दों आदमी वहां मजदूरी करेंगे । वहां ठेकेदार काम करेंगे, इंजीनियर्स काम करेंगे । आप जानते हैं कि मजदूर लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं । उन्हें दो-दो महीने तक मजदूरी नहीं मिलती है ।

मैं यहां दिल्ली में देखता हूं कि बहुत सारे बाहर से मजदूर काम करने के लिए आये हुए हैं और डी०डी०४० का काम कर रहे हैं । उन्हें दो-दो महीने का पेमेंट नहीं मिला है । उन लोगों के लिए कई जगहों पर मिलना पड़ा है ताकि उन्हें मजदूरी मिले । विहार तक से लोग मजदूरी करने के लिये यहां आये हुए हैं । लोग यहां दिल्ली में इस आशा से आते हैं कि यहां मजदूरी मिल जाएगी करने के लिए । डी०डी०४० के तहत जो ठेकेदारों द्वारा मजदूर रखे जाते हैं उनको वे समय पर मजदूरी नहीं देते हैं और जन-प्रतिनिधियों के बीच में पड़ने पर ऐसा भी हुआ है कि उनको देनी पड़ गई है । अगर जन प्रतिनिधि सहयोग देते हैं तो मैं समझता हूं कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने में वे ज्यादा सक्षम हो सकते हैं ।

अब विजली का उत्पादन भी वहां होगा । सिचाई करने के लिए बांध बनेगा और नहरें खोदी जायेंगी । अब नहरें कहां-कहां बन सकती हैं इसको इंजीनियर लोग तो देखेंगे ही लेकिन वहां के जन-प्रतिनिधि भी इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कहां पर ये बनें और उससे ज्यादा लाभ हो सकता है । बुन्देलखण्ड बहुत पिछड़ा हथा थेवा है । वहां बहुत ही कम सिचाई के साधन उपलब्ध हैं । उम्र थेवा को इस मामले में प्राथमिकता देने की जरूरत है । अब कहां नहर ने जानी चाहिये और कहां से जा सकती है इसके बारे में भी वहां के प्रतिनिधि उम्र बोर्ड में कारगर मुझाव दे सकते हैं और वे भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं और ज्यादा अच्छा काम वे करता सकेंगे ।

वहां पर विजली का उत्पादन भी होगा । अभी माताटीला डैम से विजली उत्पन्न होती है । आपको सुन कर ताज्ज्वल होगा कि बुन्देलखण्ड की, वहां यह विजली उत्पन्न होती है, बड़ी भारी उपेक्षा की गई है, जिस इसके को विजली के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, जहां विजली वैदा होती है

[भी तेज प्रताप सिंह]

उसको बहुत थोड़ी दी गई है, अनुपात में बहुत कम दी गई है। बड़े-बड़े व्यापारियों को बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को दी गई है। मुगल-सराय तक बहां से बिजली ले जाई गई है। ये यह नहीं कहता है कि किसी दूसरी जगह बिजली नहीं जानी चाहिए। लेकिन इतना ये अवस्था कहना चाहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वह फेयर होना चाहिए। फिर बहां के प्रतिनिधि बोर्ड में होंगे तो वे इस बात का प्रावधान करने की कोशिश करेंगे कि बुन्देलखण्ड के उत्थान के लिए बिजली और पानी समान रूप से बहां भी उपलब्ध किया जाये, जहां अनुपात में न्यायोचित रूप में दिया जाये। इंजीनियर आदि लोग इसमें सकारात्मक नहीं होंगे और इसमें कभी रह सकती है और इस प्रकार की कमी को हम आज भी महसूस कर रहे हैं।

एक संज्ञोधन मैंने बिल्कुल इभोर्ड सा दिया है। विवेयक में प्राविधिन किया गया है कि जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं उत्तर प्रदेश और यथा प्रदेश के, कोई भी सरकारी अधिकारी हैं, वे जब बहां बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, मुझाब दे सकते हैं और यह एक बहुत अच्छा प्राविधिन है। उनको बोर्ड करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से बहां के विधायियों को एज०एल० एज० को भी बोर्ड में आने और मुझाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। वे बोर्ड के सदस्य नहीं होंगे लेकिन मुझाब और संज्ञोधन वे दे सकते हैं। जिस प्रकार से आपने अधिकारियों के लिए अवस्था की है उसी तरह से बुन्देलखण्ड के जो विधायक हैं, असेम्बली के मेम्बर हैं और जो बहां की समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, कहां किस तरह से क्या काम करता चाहिए, इसको ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं और समझते हैं कि किस ढंग से काम किया जाये ताकि ज्यादा तरकी हो सके, उनको भी बोर्ड में जाने का, बहुत में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। यह भी न नजरअंदाज हो गई

बी पिछ्ले 1976 के एक में। मैं समझता हूं कि यह बड़ा ही इभोर्ड सा संज्ञोधन है और इसको आन लिया जायेगा। इसके बोर्ड की मेम्बरशिप भी नहीं बढ़ती है। जिस तरह से अधिकारी मुझाब दे सकते हैं उसी तरह से विधायक भी दे सकते हैं अपको कर देनी चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन न हो।

एक आध और कांसिक्युएंटस एमेंट्मेंट मैंने दी है। आपने ईफीलीयन्ड दी है। आधे राजधानी ईम की दी है लेकिन राजधानी पावर हाउस का उसमें समावेश नहीं हुआ है। वह भी होना चाहिए था। इसके बारे में मैंने लंगोधन दिया है।

इसी तरह से गेड्पूल में राजधानी रिवर-वायर का उल्लेख किया गया है लेकिन राजधानी पावर हाउस जो बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसको मैंने जोड़ दिया है।

मैं आशा करता हूं कि आप इनकी ओर ध्यान देंगे और जो कंसिक्यूएंटल एमेंट्मेंट है जिसका होना अनिवार्य और आवश्यक है, उनको आप समझेंगे और उन्हें स्वीकार करने की हुआ करेंगे।

बी लक्ष्मी नारायण नायक (बजुराहा) : समाप्ति महोदय, कुषि और सिर्वाई लक्ष्मी जी ने जो विवेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्वत करता हूं। अभी राजधानी से केवल सिर्वाई का ही काम होना था। अब उससे बिजली भी तैयार होगी। इसलिये जरूरी है कि, जो भारी बोर्ड बनावा जाय वह उसमें विद्युत मंडी का स्थान नहीं था, उनको उसमें शामिल किया जाय जो कि इस बिल में किया गया है, और केन्द्रीय अधिकारी भी उसमें शामिल कर लिया जाय, यह भी उसमें संज्ञोधन है। मुझ इतनी बात है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिछ्ले दिनों से मैं बराबर देखता था रहा हूं कि जब कोई बांध बनता है, कोई नई योजना बनती है तो उसमें पक्षपात होता है, और वह इसलिये

होता रहता है कि जो नीचे की बात जानका बहुरी है कि आखिर सही बात क्या है, उसको नहीं जाना जाता। अब जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को कहा है कि हम कोई बात जनता से छुपा रखना नहीं चाहते हैं। जो जनता की विवरण हैं, उसकी सही भावना है या जिस बात में जनता को ज्यादा से ज्यादा मुविधा मिले उसकी ज्यादा से ज्यादा चिन्ता करेंगे, इस बात की घोषणा की है। तो इसी बात को लेकर मैं मर्दी जी से कहूँगा कि आपने आं बोहं बनाया, विसमें मर्दी को लिया, ठीक है। लेकिन अभी तक कागजी को देख कर ही सारी कांघवाही होती थी, बैठक के समय जो कांगड़ तामने हुए, उनमें कोई कारण या मुझाक हुया उससे ही सारा काम हो जाता है। लेकिन ये सा कि अभी माननीय देव प्रताप लिहू ने कहा इसमें जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए को देखें कि आखिर सरकार जो काम कर रही है उसका जनता पर क्या असर हो रहा है। कहीं कोई बात छूटी तो नहीं है, जनता के हितों के विपरीत हो रही जा रही है। ऐसे लिहाई थी, विजली को घोषणा है, अभी बात है इसका कोई विपरीत नहीं करता। लेकिन काम किस दर्जे से जले इसकी देखभाल वहाँ के जन-प्रतिनिधि अच्छी तरह से कर सकते हैं। नालाटीली थीं यहाँ जिसमें भारत प्रदेश की काजी बैठक इवी, लेकिन लिहाई भारत प्रदेश को नहीं मिली, विजली में भी जोगढ़ थीं। कै है बारे भारत प्रदेश की विधायक सभा में संसदीकरण पड़ा तब जो कि भर्तुकल से मुविधा मिली। और अभी भी क्या है कि बौ तरह का इतजाम करना पड़ता है। विजली भी घर में सभी दूर्वा है लेकिन लालटें भी रखनी पड़ती है क्योंकि 7 बजे रोशनी लिलेगी विजली की और अच्छेरा जल्दी हो जाता है। यह आम शिकायत है। जब हम विजली का किराया देते हैं तो हमको समय पर रोशनी मिलनी चाहिए। बराबर अधिकारियों से कहते हैं

लेकिन कोई ज्यान नहीं देता। बहर ठीकमगढ़ में मिल जाती है समय पर क्योंकि वहाँ विजलीश रहता है। लेकिन गांव में 7 बजे मिली तो मिली नहीं मिली तो कोई पूछने बाला नहीं है। किसानों ने मिलाई है लिये विजली के पम्प लगाये हुए हैं लेकिन कब विजली मिलेगी और कितनी देर तक मिलेगी कुछ पता नहीं। जब चाहें विजली बन्द हो जाती है। अधिकारियों से कहते हैं, कोई मुनवाई नहीं, कोई ज्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये जो योजनायें बढ़ती हैं उनका वास्तविक आभ जनता को मिलना चाहिये। अबर कोई शिकायत है तो उसको बल्दी दूर करना चाहिये।

मैंने सुनाया दिया है कि विस देव में इसका पाली लिहाई के लिये जला है उस देव का संसद सदस्य बहर इस बोहं में रखा जाय। और मैं मानता हूँ कि जब हम बोहं इस संसोधन का हृदय से समर्पण कर रहे हैं तो लिहाई मर्दी जी हमारे संसोधन पर प्रधारण भीर करे। कोई ज्यादा नहीं है, केवल मुना, जंजुराही, हमीरपुर और साती इन चार जगहों के ही संसद सदस्य इसमें रहे जायें। ताकि बोहं की बैठक में कोई उल्लंघन कैसला न हो जाये, और जनता के प्रतिनिधि वहाँ सही लेलाह दे सकें और जनता की भावना को व्यक्त कर सकें।

वहाँ संकेत नहर का सम्बन्ध है, ठीकमगढ़ जिले के लिए सर्व ही चुनी है और राजवाहन बोहं की नहर वहाँ बाली है। लेकिन मुझे बताया जया है कि ठीकमगढ़ जिले में वह नहर नहीं बाली। इसका क्या कारण है? कुछ अधिकारियों के लाय इस बारे में जब मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि बाली ज्यादा होता है। आखिर ठीकमगढ़ जिले के लिए कोई तूसरा बांध तो नहीं बनाया जायेगा। कहा जाता है कि ठीकमगढ़ जिले में सिलाई हो रही है। भारतवर्ष में ठीकमगढ़ ऐसा जिला है, जहाँ प्राप्त हजार कुपं हैं और वहाँ

[बोही लकड़ी नारायण नायक]

रहट से सिचाई होती है। लेकिन उसमें कितनी मेहनत और पैसा लगता है। तीन आदमी लगते हैं और बैल लगते हैं। उस सिचाई को मान लिया जाता है, तो जो नहर से लिचाई होती है, क्या उसे सिचाई नहीं मानना चाहिए? प्रधिकारी यह दलील देते हैं कि टोकमगड़ डिले में रहट से ज्यादा सिचाई होती है।

मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह बोहं की बैठक में इस प्रश्न को उठायें। अगर टोकमगड़ डिले में नहर नहीं जायेगी, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। प्रगर टोकमगड़ डिले को राजवाट का पानी न दिया गया, तो वह ठोक बात नहीं होगी, और हम लोग बराबर इसका विरोध करेंगे। जिस से जनता को यह बात मानूम हुई है, उस से वह बहुत कोष में है।

मैं आगा करता हूँ कि मैंने यह जो सुनोष्टम रखा है कि जनता को सही भावना को बोहं में पहुँचाने के लिए सम्मद लोकों के संसद-सदस्यों को भी उसने शामिल किया जाना चाहिए, मंत्री महोदय उसे स्वीकार यह रखें।

इन लब्दों के साथ मैं इस विषेषक का समर्यन करता हूँ।

मैं जानू अताप त्विः : समारपि महोदय, मैं प्राननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषेषक के सम्बन्ध में अपने मूल्यवान् सुझाव दिये हैं। परन्तु मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में कुछ गलतकहरमिया और भ्रम हैं। मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा।

यह कहा गया है कि बोहं में जन-प्रतिनिधि होने चाहिए। मैं समझना हूँ कि यदि इस बात को सफाई हो जाये कि बोहं का कार्य खेल क्या होगा, तो फिर जन-प्रतिनिधि इत्यादि की बात जायद नहीं आयेगी। यह बोहं के बल इत्यादि काम करेगा कि बांध और विजलीघर

की स्थापना कर देगा। योही दूर चलने के बाद पानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों का हो जायेगा। जो विजली बनेगी, वह भी बोहं दोनों सरकारों में बांट देगा। फिर किस के खेत की सिचाई होगी, जिस गांव में विजली लगाई जायेगी, किस डिले में पानी और विजली जायेगी, इसका निर्णय इस बोहं के अधिकार में बिलकुल नहीं होगा। बोहं तो केवल इस बांध और विजलीघर की स्थापना करेगा और उसकी चलाये रखने की जिम्मेदारी उसकी होगी। उसके बाद जो विजली और पानी होगा वह राज्य सरकारों के मुपुद कर दिया जायेगा और उस के वितरण की व्यवस्था करना गज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बोहं में भी रहें जन-प्रतिनिधि तो उसमें किये गये कैफाने राज्य सरकार पर लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार पूर्णतया इस बात में स्वतंत्र होगी कि जो उसके हिस्से का विजली और पानी है उसको अपने-अपने लेव में किस तरह से वितरित करे। अब जो यह सुनाव आया है कि उसने एम०एल० एप० और एम०पीड० को भी जामिल कर लिया जाय तो उससे बोहं बहुत बड़ा हो जायगा और वहें बोहं से यह देखा गया है कि काम ठीक से नहीं जलता है। इसके प्रसारा जैसा भैने निवेदन किया बोहं का काम बांध और पानी का केवल इंतजाम कर देना है वह एक तरह से टेक्निकल और एक्सोक्यूटिव बोहं यह है। कोई पालिसी इत्यादि बोहं तय करने वाला नहीं है। परन्तु पालिसी इत्यादि का उसने निर्णय नहीं होना है तो उसमें जन-प्रतिनिधियों को कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती।

यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को तो बोहं में नियमित होने का अधिकार है और विधायकों को नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ देना चाहना हूँ, इसने उसकी व्यवस्था है:

"The Board may permit any officer of the Central Government, or the Government of Madhya Pradesh or Uttar

Pradesh, to attend any of its meetings and take part in the proceedings, but such officer shall not be entitled to vote."

तो कोई जरूरी नहीं है और उसको कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से उसके बाद का जो दूसरा क्लाउ तैयार है उसके अंतर्गत यदि बोर्ड आवश्यकता समझेगा तो विधायकों को, संसद सदस्यों को उसमें बुला सकता है। उसमें यह है:

"The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be decided by regulation, any person whose assistance and advice it may desire in complying with any of the provisions of the Act."

तो कोई भेदभाव की बात नहीं है। जिस प्रकार से सरकारी अधिकारी बुलाए जा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर उसी प्रकार से बदि बोर्ड जरूरत समझेगा तो उन को भी बुला सकता है।

श्री तेज प्रसाद सिंह: यह इजाजत देने या बुलाने का प्रयत्न नहीं है। आप जरा और से देखें इसमें है बोर्ड में परमिट, मैंने आपको लिखा कि मुझको आज्ञा दे दें दाने की तो आप ने दे दी, ऐसिन मैंने लिखा तब आपने परविलन दिया और दूसरा क्लाउ जो है जो सारे लोगों के लिए है उसमें है कि दिवोर्ड इंसेल्म में एकोशिएट, यानी आप ही जिस को बाहे बुला लें। इन दोनों में बड़ा फर्क है।

श्री जायु प्रसाद सिंह: बोर्ड को अधिकार है कि प्रफसर को या विधायक की या अन्य व्यक्ति को वह चाहे तो बुला सकता है।

श्री अनिका प्रसाद पाण्डेय (बांदा): स्वेसिफिक मैक्सन आफिससे के लिए है कि बुला सकता है।

श्री जायु प्रसाद सिंह: आफिसर जब मुझाया जाता है तो आपने एक्सपर्टार्ड ज के लिए बुलाया जाता है। उस को कुछ विशेष ज्ञान है इसलिए उस को बुलाया

जाता है। यदि समझा गया कि किसी विधायक में या संसद सदस्य में इस किस्म की विशेष योग्यता है और उस से परामर्श लेना आवश्यक है तो उसे जरूर बुलाया जायगा। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ यह एंजीक्यूटिव बाड़ी है। उस को एक काम कर देना है। किर पानी कैसे बटेगा, विजली कैसे बटेगी यह उस के अधिकार की बात नहीं है। वह तो पानी विजली बना कर दे देगा।

श्री तेज प्रसाद सिंह: वह एंजीक्यूटिव कमेटी अलग है।

श्री जायु प्रसाद सिंह: अब यह भी एक मुझाव रखा गया कि केन्द्रीय सरकार के जो उपमंत्री हों विचार्ड और पावर के और जो उस क्षेत्र के निवासी हों उन को भी उस का सदस्य बनाया जाय। इस को भी मानने में मुझे बहुत बड़ी कठिनाई है क्योंकि रिंडाउन स्पॉर्स से यह गलत है। एक व्यक्ति जब मिनिस्टर हो जाता है तो वह किसी एक विशेष लेत का नहीं रह जाता और किसी एक विशेष लेत के हित को देखना उस का काम नहीं है। इसे एक बार मान लेने के बाद आगे चल कर बहुत काम्प्लीजन पैदा हो सकता है। इसलिए इस को भी मानना संभव नहीं है।

इसमें एक प्रयत्न यह उठाया गया कि पावर हाउस की डेफिनीशन होनी चाहिए परन्तु जो भ्रमन्डमेन्ट देख है उसमें ही एक प्रकार से डेफिनीशन दी जा चुकी है। राजघाट पावर हाउस की डेफिनीशन देने की इसलिए प्रावश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही लिख दिया गया है: hereinafter referred to as the Rajghat Power House.

उस संशोधन में ही इसकी डेफिनीशन ही दी गई है इसलिए कोई भ्रम होने की सम्भावना नहीं है। राजघाट है

[श्री भानु प्रताप सिंह]

से सदा हुआ जो राजघाट पावर हाउस
है उसके लिए लिव्र दिया गया है :

hereinafter referred to as the Rajghat Power Houses.

इसके बाद अलग से कोई परिभाषा देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । जब विधेयक में ही परिभाषा आ गई है तो अभी होने की सम्भावना नहीं है ।

मैं समझता हूँ मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं इसलिए अब मैं निवेदन करूँगा कि माननीय सदस्य अपने संज्ञोधन वापिस ले लें जिससे यह काम तेजी से हो सके । जितना ही इसमें विलम्ब होगा सिचाई विजली मोहूर्या करने में उतनी ही देरी होगी ।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to amend the Betwa River Board Act, 1976, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

CLAUSE 2 (Amendment of section 4)

SHRI LAKMI NARAIN NAYAK : I beg to move:

Page 1,—

after line 16, insert—

"(d) the Members of Parliament of the areas proposed to be irrigated by the Rajghat Dam." (1)

SHRI TEJ PRATAP SINGH : I beg to move :

Page 1,—

for lines 8 to 12, substitute—

"(a) where the same Union Minister is not in charge of both Irrigation and power, the Union Minister in charge of power and such Ministers or Deputy Ministers in the Union Ministry or Department in charge of Power or Irrigation who are residents of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ;" (3)

Page 1,—

after line 16, insert—

"(d) all the members of Parliament residing in the districts of Bundelkhand region of Uttar Pradesh Madhya Pradesh." (4)

Page 1,—

after line 16, insert—

"(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) The Board may permit any officer of the Central Government or the Government of Uttar Pradesh or Madhya Pradesh or any State Legislator residing in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh or Madhya Pradesh, to attend any of its meetings and take part in the proceedings but such officer or Legislator shall not be entitled to vote."

(5)

Page 1,—

for lines 14 and 15, substitute—

"(c) the Ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in Charge of Finance, Irrigation and Power and also Ministers and Deputy Ministers of the aforesaid two States residing in Bundelkhand region (Jhansi, Jalaun, Hamirpur, Banda, Lalitpur, Tikamgarh, Chhattarpur, Dhatia and Panna Districts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh)." (8)

MR. CHAIRMAN : I put amendment No. 1 to the House.

Amendment no. 1 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I put amendment Nos. 3, 4 and 5 to the House.

Amendments nos. 3, 4 and 5 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I put amendment No. 8 to the House.

Amendment no. 8 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 (Amendment on Section 10)

SHRI TEJ PRATAP SINGH : I beg to move:

Page 2.—

After line 10, insert—

"(c) in clause (r), after the words "Rajghat Dam" the words " and the Rajghat Power House" shall be inserted. (6)

MR. CHAIRMAN : I put amendment 6 to the House.

Amendment No. 6 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clauses 5 to 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 5 to 7 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : There is Amendment No. 7—Clause 8 (New) — in the name of Shri Tej Pratap Singh. Is he moving?

No. There is also Amendment No. 2—Clause 1A (New) in his name.

He is not moving.

The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (बजुराहा) : माननीय सभापति जी, आमी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि बोर्ड का काम बेकल इतना ही है कि जो बांध बनेगा, उस की हूप रेखा बना दे कि कितनी लागत में बतेगा । जहां तक मैं समझता हूं—बोर्ड यह भी तो तय करेगा कि बांध कितना बनेगा, कितनी लागत होगी और कहां तक उस की नहरें जायेगी, किन-कित जिलों में नहरें जायेगी, भेन-नहर कहां जायेगी—ये सब बातें बोर्ड तय करेगा, तभी उस का सही एस्टीमेट बन सकता है । मैं चाहता हूं कि बोर्ड जब इत बातों को तय करे, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे टीकमगढ़ जिले को छोड़ दिया जाय, जैसाकि आज कल कुछ सुनने में आ रहा है । मैं इस अवसर पर यद्यो महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि इतने बड़े जिले को छोड़ा नहीं जायगा । आप संसद सदस्यों को इस में रखें या न रखें, हालांकि मैं चाहता हूं कि उन को रखा जाय, आप इस बात को नहीं चाहते हैं—मैं नहीं समझता कि इस में ऐसी क्या दिक्कत है कि संसद सदस्य उस में जा सकें और अपनी राय बहां दे सकें—मैं सिफ़र इतना ही चाहता हूं कि उस में कोई पक्षपात न हो, हमारा टीकमगढ़ जिला छोड़ न दिया जाय ।

मैं चाहता हूं कि आप सब बातों पर गौर करते हुए इस बात का आश्वासन बहर दें कि जो सर्वे हो चुका है, उस को छोड़ा नहीं जायगा ।

श्री अमिताल प्रसाद पांडे (वांदा) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं कि बोर्ड कोई पालिसी तय नहीं करेगा कि पानी का बटवारा या जो पावर पैंडा होगी, उस का बटवारा कैसे होगा । अभी तक जब कि बहां पर कोई डैम नहीं बना था, पावर स्टेसन नहीं बना था, केवल नदियों के बारे में, डैम बनाने के बारे में दो राज्यों के बीच में झगड़ा

[बो अधिकार प्रसाद बोर्ड]

पैदा हो गया था। इसलिये भगवर यह भी जी भी तय नहीं होगी तो फिर उन के बीच में अगड़ा शुरू हो जायगा। इह लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस में संसद सदस्यों, एम० एल एन० तथा उस क्षेत्र से प्राप्त वाले सभी मंत्री गणों को भी उस में शामिल किया जाय और इस तरह के अगड़ों का बही बोर्ड में निवारा करवाने की कृपा करें। दुन्देलखण्ड एरिया ऐसा है जो मध्य प्रदेश और यू० पी० दोनों के बांधर को मिलाता है। वहां पर इतनी नदियाँ हैं, छोटे-छोटे नाले हैं जिन से काफी सिवाई हो सकती है, लेकिन आपस के अगड़े के कारण न वहां पर नहरें बन पाई और न हैम बन पाया—इस लिये मेरा ऐसा विस्वास है कि वहां के जन प्रतिनिधियों को रख कर ही इस मसले को हल करना चाहिये ताकि कोई क्षेत्र उपेक्षित न रह जाय।

दूसरी बात—जैसा भी तक माता-टीना हैम के पावर हाउस के बारे में होता रहा है—वहां पावर तैयार होती रही नैकिन उस क्षेत्र की उपेक्षा कर के दूसरे क्षेत्र को दी जाती रही। मैं यह नहीं कहता हूँ कि दूसरों को न दी जाय, लेकिन जिस क्षेत्र में पैदा हुई है, उस की उपेक्षा न की जाय और यह तभी सम्भव है कि जब कि वहां पर जन-प्रतिनिधि हों। भी तक वहां व्यूरो-क्रेनी के अनुसार कार्य होता रहा जिस का परिणाम यह निकला है कि वह भावना पैदा हुई कि हमारा क्षेत्र हर तरीके से उपेक्षित है। बेनवा रिवर बोर्ड जब पिछले वर्ष आया, उस समय भी यह प्रावाज उठी थी कि वहां के जन-प्रतिनिधियों को उस में रखा जाय।

इस का जो शब्दूल है, उस को भी बेनव करना चाहिये—अगव आप इस को बेनज नहीं करेंगे तो एक लीगल नेकूना रह जायगा। इस लिये इस और भी आप का व्याप आकर्षित करना चाहता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय नायक जी से मेरी पूरी सहानुभूति है और टीकमगढ़ के इलाके से मेरी जानकारी है परन्तु जायद में उन्हें स्पष्ट नहीं कर पाया कि पानी कहां बटेगा, यह इस बोर्ड के अधिकार के अन्दर नहीं है। गर्तों ने अनुसार पानी रोक कर और कुछ दूरी पर ले जा कर आधा-आधा बट जाएगा और उस पानी को राज्य सरकारे कहां ले जाएंगी, यह इस बोर्ड के फैसले की बात नहीं है।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो नहरें बनेंगी वे भी राज्य सरकारे अपने पैसे ये बनाएंगी और उस में बोर्ड का पैसा नहीं लगेगा। बोर्ड तो बांध बना कर और पावर हाउस बना कर कुछ दूर तक जहां पर राज्य सरकारों की सरहद नहीं है, पानी और दिनजी पहुँचा देंगी। इसलिए इस में अगड़ा होने की संभावना नहीं है। दोनों को पानी और विजली बराबर बटेंगी। इस और जो व्याप दिलाया कि विधायक और भेज्वर प्राक पालियामेंट रखें जाएंगे, तो अगड़े कम होंगे, यह तो संचयने का विषय है वैसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई इस का सवाल नहीं उठेगा क्योंकि दोनों का अपना जो भाग है वह निश्चित है और अपने-अपने क्षेत्रों में पानी देने की जिम्मेदारी उन की होगी, नहरें बनाने की जिम्मेदारी उन की है। बोर्ड तो केवल विजली और पानी महाया कर देगा। मैं समझता हूँ कि इस से काफ़ी सफाई हो गई होगी। अब बिल को पास किया जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.07 hrs.

**MOTION RE : TWO SERIOUS
TRAIN ACCIDENTS ON THE
NORTHERN RAILWAY—**
Contd.

MR. CHAIRMAN : Now, we take up the motion moved by Shrimati Parvathi Krishnan on the 23rd November, 1977, regarding the two serious train accidents on the Northern Railway. Mr. Briji Bhushan Tiwari was speaking. He is not here now. Mr. Stephen. He is also not here. Mr. Saugata Roy.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore) : The discussion on the railway accidents which was taking place on November 23, 1977, in this House was interrupted by a peculiar incident, an incident which we can call a tragedy of the first order or an incident which we can call an irony of fate. Just when the House was debating the railway accidents' news came that the Ahmedabad-Delhi Mail had been derailed near Rewari and that there was a Member of Parliament among the 10 who were killed. This only underlines the seriousness of the situation, and this also underlines that, in spite of all the noble sentiments expressed by the Minister not enough has been done to prevent railway accidents. I am not one with those who demand the Railway Minister's resignation for every railway accident though I do think that the example of Shri Lal Bahadur Shastri resigning after that railway accident was a noble one. I do not think shifting of one Railway Minister will solve the problem. The problems are basic into which one has to go in depth, one has to go in detail.

It is good, after the accidents, after the discussion took place in the House, only three days back, the Minister has appointed a Committee to go into these railway accidents and to recommend measures for ensuring safety in the railways. But the point I want to make really and seriously here is that railway accidents are not isolated incidents which happen just once in a while. We know of the three big railway accidents which took place at Sarai Gopal Naini and Rewari. But, as the figures will show, a number of accidents have taken place. The number of accidents from April to October this year was higher than the number of accidents in April to October last year or during the same period in 1973 or 1974. This shows that somewhere something wrong is happening. It is not only psychological that people think because of the two recent serious accidents that there is something wrong, but the whole system in the railways is showing signs of cracking, if I may say so, seriously.

I will not go into the railway strike or in matters relating thereto. My sympathies even about strike lie with the workers. I shall also not go into the regours that were imposed during the emergency. My sympathies also lie with the workers who were victimised during the emergency. But, I would definitely say that there has been an overall slackening of discipline in the entire railways after this Government has taken over. Some people say that it is a 'spill-over effect'; the people who were dismissed have been taken back and some people are not satisfied and, therefore, they are not working. Some people say that some officers were not happy because these people have been taken in, and therefore, they are not working properly. Now-a-days, everywhere, in the railways, you find that the trains are not running in time; almost all the major trains are late. The other day, I came by "Rajdhani Express"; it was supposed to reach here at 10.30, but we reached at 1.00 O'clock.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : At least, you reached safely.

SHRI SAUGATA ROY : Yes, and there might have been an accident at Kanpur, it was found that the engine had some defect. The driver apparently thought that it had been repaired and he left the station. After going for some distance, the engine went wrong. Another engine was sent for and only then the train started.

So, you will find, Sir, that there has been a general slackening on the part of the railwaymen all along and it is the duty of all of us that this slackening is not there, because railways are the national property. Anything that happens is not the concern of Prof. Madhu Dandavate alone or of Shri Sheo Narain alone, it is the concern of all of us.

Sir, the reasons for this slackening are many, but to me, the most important of them, seems to be the discontentment among the railway staff. The railway staff, for some reasons or the other, have worked with exemplary dedication for the last few years. They had high expectations from this Government. These expectations have, however, not been fulfilled. They expected that as their own leaders, who had been agitating for their demands, were in this Government, some of their demands will now be fulfilled. Firstly, I would like to mention about their demand of bonus which has been agitating them for so long. The railwaymen this year demanded that they should be given one rupee at least, so that they know that there would be bonus for them and that bonus would be granted to them as a right. But, it was not done. I know, there were many impediments, but that is not the only thing. Then, there

[Shri Saugata Roy]

the question of demands of the loco mining staff. There is a very old demand; for a long time they have been demanding eight-hour working. Though various steps have been taken for example the implementation of the Milkboy award etc., somehow or the other their running hours still exceed eight.

This is not to talk of only the loco staff, like the gangmen. They have the same problem when their normal working hours are not maintained. Let us talk of the signalmen, the person who sits at the signal post. He sits in some isolated place right in the middle of the jungle and he may have to sit for even nine hours if his reliever does not come in time. The Controller who may be sitting in the air-conditioned room, has only six hours duty to put in whereas the signal man has to do anything from 8-9 hours duty. So, a genuine effort is necessary by all to see that where the genuine grievances exist, they are redressed. A government cannot live on giving hope only. It has to state clearly that these are our imitations, these are our objectives, we can give you this much and beyond this we cannot go, but this government is not doing that.....(interruptions) You see is that there has been considerable improvement. It is not so. On the other hand, there is much deterioration. I am not saying anything derogatory against your Minister. But please do not provoke me into that all that. So, what I am saying is that we should seriously consider to satisfy these grievances of the railway staff, what steps should be taken, whether we should go into their demands in detail and so what can be done and what cannot be done, without letting them live on false hopes.

The next question is with regard to the rolling stock, we have in our railways. Every day some demand or the other is made for a new railway line. It is quite a justified demand in a country where though you have already nearly 61,000 miles of railways, but still more mileage is necessary. But you cannot go into projects for more mileage before improving your rolling stock. Now what is happening is that these lines are getting old and your rolling stock is getting old. When the fish plates are found removed, you say that it may be due to sabotage. Very well, but it is also possible that these things get old and get rusted and things get opened like that. It is also possible. So a fresh look is necessary into the conditions of the rolling stock as it exists.

Then the question is what safety measures we should recommend to the people because you will remember that in the recent Naini accident, it was because of the man at the signals which ultimately led to the accident. Now,

can we allow so many human lives hang on the wisdom or the unwisdom of a single signal man? Is there any system to obviate this? I cannot say that you can man all the unmanned level crossings in a single day. I do not say that you can introduce route relay interlocking system in a day. But the Railway Minister should declare that this is our programme for manning the unmanned level crossings and for introducing route relay interlocking so that we may know that within a certain period of time railway travel will become safe.

Then again I would say that I mentioned three points: (1) the grievances of the railway staff, (2) the condition of the rolling stock and (3) the condition of the signalling equipment and the modernisation necessary for unmanned level crossings.

The last point I want to make is with regard to the Railway Board. The Railway Minister recently announced the restructuring of the Railway Board. But, if I may tell you, the Railway Board is and continues to be, in spite of the restructuring, the most bureaucratic structure in the whole of India....

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): That is right.

SHRI SAUGATA ROY: The Railway Board is responsible for redressing the grievances of the employees. The Railway Board is responsible for the mounting discontent among the employees and also for creating dissension among the employees. They think that theirs is an empire. Those who sit in the Railway Board think, that 'the Ministers come and go but we stay here for ever and so it is our business to see how the Railways run.'

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: They say, 'Ministers are casual and they are permanent.'

SHRI SAUGATA ROY: Yes, they say that Ministers are casual labour. As you know, the problem of casual labour is a very great problem in the Railways. Some new thinking should be done with regard to the Railway Board. The important question is this: Does the Railway Ministry need an apparatus like the Railway Board to run its affairs? This should be gone into in detail because we find that there is a lot of bureaucratisation at various levels. The chain of command gets broken at many places. There is no leadership in the zonal railways and at the divisional levels. The General Managers and other

officers of the Railway Board and other people do not inspire confidence down below. If there is any British institution we have today, the Railways are the most-British institutions which we have. They follow archaic British traditions; you have the Railway Institute; they follow Christmas Hall and other things. So, a fresh look is necessary in this matter in regard to the structure of the Railway Board and of the whole administration.

I am happy that after November 23, there has not been any more serious accident on the Railways. I do not know whether it is due to any fortuitous circumstances or because accidents or not reported or because of the greater pains taken by the Railway Ministry to avoid accidents. Let us not view the problem of accidents from any party point of view. It is not a party issue. When somebody dies, it may be your sister or my sister. Let us not condemn some Minister or the other. We should find out proper solutions for such issues. I would be happy if the Railway Minister will sit down with the opposition and discuss all these matters. With regard to constitutional amendments they discuss with us because they cannot be passed without our support. Regarding railway matters you should discuss with us. We do hope that with the new effort that is being made, there will be more safety all round. All efforts should be made to guard all the railway track and level crossings, so that people cannot walk across as they like. We find such things happening in Bombay and Calcutta and several other places. If we do that we will avoid a number of accidents.

Finally, I think, the House should take a serious note of the accidents which have taken place and should recommend Strong measures for preventing further accidents.

डा० रामचंद्र सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, दुर्घटनाये प्रगर भाकिस्मक हों तो कुछ नहीं, लेकिन यह जो दो दुर्घटनाये हैं जिनके बारे में खास करके श्रीमती पार्वती हृष्णन ने बहस उठायी है, यह दोनों दुर्घटनाये मानवीय भूल की प्रतिफल हैं। और इससे जवादा भीर कोई दुखदाई नात नहीं हो सकती है कि हमारी भूल से बहुत से लोगों की जान चली जाय। मेरे इसके सम्बन्ध में 3, 4 श्रेष्ठ वार्षिक प्राप्तके ब्रह्मा रथाना चाहता है। उन्हीं जान यह कि दुर्घटना कीसे हुई जल्दी

जांच हो रही है, लेकिन इतनी बात तो है कि दुर्घटना के 1 चंटे के बाद रिलीफ ट्रेन बहुत गई। बूसरे यह कि 8० बी० ए० सी० के जवान जो बिस्कुल नजदीकी के बह दो चंटे के बाद वहां पहुंचे। उही बगह और बूसरे लोग नावरिक सारे वहां के करवाले के लोग भद्र बरका काय बद्द करके वहां दूर्घट गए, लेकिन 8० ए० सी० के जवान और रिलीफ ट्रेन ज्यादा देर से पहुंची। इससे मालूम पड़ता है कि प्रशासन में एक जबड़न है और इस प्रकार को दुर्घटनायों से कुछ संवेदना नहीं मिलती है। सच बात तो इतनी है कि सेना की सहायता बहुत देर से ली गई। कहा जाता है कि 7 बजे उनकी सर्विसेज ली गई प्रगर सेना की सहायता पहले ली जाती तो शायद कुछ अमूल्य जीवन बच जाते। जब हम मानते हैं कि ये दोनों दुर्घटनाये मानवीय भूद्र का प्रतिफल हैं, तो दो बातें हमारे सासने आती हैं: एक तो प्रशासनिक पकड़ की कसी है, और दूसरे कुछ भसामाजिक तथा असंतुष्ट तरह इन कामों में प्रवृत्त हैं। इसलिए प्राज इन दोनों प्रश्नों पर हम लोगों को किबार करना है।

रेल दुर्घटना, या किसी अन्य दुर्घटना, का राजनीतिकरण करना एक पाप है। इसलिए इस विषय पर राष्ट्रीय परिषेष्य जै और इनका जावना के ऊपर उठ कर विवार करना चाहिए। कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि वर्तमान प्रशासन ने मजदूरों के साथ न्याय नहीं किया है। मैं रेलवे मंत्री के इस बक्तव्य की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा कि विषये आठ महीने में रेलवे मजदूरों के साथ जो न्याय किया गया है, वह पिछले तीस बचों में नहीं हुआ है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि रेलवे मजदूर लुब्ज और असंतुष्ट है, इसलिए वे कुछ ऐसे काम करते हैं, तो ऐसा सतता है कि कुछ लोग खुद मर्हित करते हैं और उतका दोष रेलवे मजदूरों पर लोगना चाहते हैं।

[दा० रामजीसिंह]

कुछ लोगों का कहना है कि इमर्जेंसी के बाद सब बातों में गडवडी और गिरावट हुई है। लेकिन हमें निर्भीक होकर मानना चाहिए कि रेलवे की क्षमता इमर्जेंसी काल से अधिक बढ़ी है। यही कारण है कि तोड़-फोड़ करने वालों का सबसे ज्यादा जोर रेलवे पर रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं विनम्रतापूर्वक दो नीन मुझाव देना चाहूंगा। एक मुझाव तो राष्ट्रपिण्ड वापु ने दिया था। पना नहीं कि ट्रेकिनिकली यह भ्रम्भव है या नहीं, किन्तु इस की जांच कराइ जानी चाहिए। यह देखा गया है कि दुर्घटनाओं में इंजिन ने साथ बाले चार पांच डिब्बे ही ज्यादा क्षतिग्रस्त और ब्लॉक होते हैं। क्यों न ऐसा किया जाये कि इंजिन के साथ तीन चार डिब्बे मालगाड़ी या पासल के रखे जायें, ताकि जन-जीवन की क्षति कम हो, और अगर माल आदि की क्षति हो भी जायें, तो कोई हज़र नहीं है।

हमारा दंड विज्ञान का विषेयक आ रहा है। उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस प्रकार की तोड़-फोड़ करने वालों के लिए कम से कम सज्जा मत्यु-दंड हो और उनकी समरी द्रायल की जाये। तोड़-फोड़ करने वाले लोगों को, चाहे वे राजनीति में हों और चाहे किसी संस्कृतिक मंस्था में हों, राष्ट्र वे जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है।

इसके अलावा प्रश्नामन की पकड़ को चुस्त और दुरुस्त करना चाहिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन यह तथ्य है कि 1973 के बाद इन दुर्घटनाओं में बढ़ि ह रही है। 1973-74 में 782, 1974-75 में 925 और 1975-76 में 964 दुर्घटनायें हुईं। अगर विज्ञान के बढ़ने के साथ दुर्घटनायें भी बढ़ती हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने विज्ञान को प्रथम नहीं दिया है। इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एनक्वायरी कमेटी

की रिपोर्ट को व्यान में रखना चाहिए। मैंने अभी सुझाव दिये हैं कि मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं में कैसे कमी की जा सकती है। अभी री-स्ट्रक्चरिंग घाफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की बात रेल भंडी ने बतायी है और सबमध्य में अपने काम का विकेन्द्रीकरण किया है। जहां विकेन्द्रीकरण होगा वहां कार्य की क्षमता बढ़ेगी ऐसा पूरा विवाद है।

रेलवे सेवा आयोग में भी रेलवे विभाग में जानकार और अनुभवी लोगों को रखना चाहिए। जनरल मैनेजर के स्तर के लोगों को भी कुछ लोगों को भर्ती करने का एक विधि के मुताबिक अधिकार देना चाहिए। उनका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। रेल भंडी वह अनुभवी है लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें लोगों को तो प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन क्लास प्ली और क्लास फोर के कर्मचारी, जो असल में काम करते हैं उनके प्रशिक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था होनी चाहिए? भारतवर्ष के अंदर बड़े-बड़े इंजीनियर केवल ट्रेन पर कामजी काम करते रहते हैं। असल काम तो जो क्लास प्ली और क्लास फोर के एम्प्लायी करते हैं, जो गम्भीर है या और जो छोटे-छोटे कर्मचारी लोगों के हैं वे करते हैं। तो उनके प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया आवश्यकता है। आज इस प्रशिक्षण का भी अभाव है जिसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं।

अगर इस प्रकार की दुर्घटना किसी लेव में हो जाय तो सामूहिक दण्ड क्या उस लेव में देना चाहिए या नहीं, इस पर मैं अभी अपनी बात नहीं रखूंगा। लेकिन अगर किसी खास दल या संगठन के लोग इस प्रकार का खिलवाड़ राष्ट्र के जन-जीवन के साथ करते हैं तो ऐसी संस्थायां पर अविलम्ब प्रतिवन्ध लगाना चाहिए।

अभी जां स्थिति है रेलवे की दुर्घटनाओं के संबंध में उसमें सिवनलिंग की प्रक्रिया के

संबंध में भी रेल मंत्री ने बताया। उस में भी सुधार होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से ताकि सिगनलिंग की कमी के कारण दुर्घटना न हो सके। भभी नीनी में क्या हुआ? सिगनल केव हो गया। विज्ञान के युग में सिगनलिंग फेल कर जाय इससे लगता है कि कहीं कोई गड्डडी है। सब खबरें बन्द हो सकते हैं लेकिन जहां वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न है वहां पर कोई भी कटौती या कोई भी कृपणता नहीं हो सकती। नयी लाइनें बन्द हो सकती हैं लेकिन इस में कमी नहीं की जानी चाहिए। क्यों कि आज रेलगाड़ी से चलने में हर आदमी एक बार भगवान को इमरण कर के चलता है। यह स्थिति सब के साथ है, हमारे साथ भी है और आप के साथ भी है। यह बहुत प्रचली बात है कि रेल मंत्री जी ने बहुत सारे लोगों को रेलवे ट्रेक की हिफाजत करने के लिए कहा है लेकिन यह केवल रेलवे मजदूरों का ही दायित्व नहीं है। हम तो समझते हैं कि स्वयं सेवी संस्थाएं और राजनीतिक दल क्या केवल कुर्सी और गही के लिए ही होते हैं? हम सोगों का भी कर्तव्य है कि रेल मंत्रालय जो रेल लाइनों की हिफाजत के लिए एक महा-प्रबन्ध कर रहा है उस में अपना योगदान दें। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब सोगों को भी उसमें योगदान देना चाहिए।

हम दुर्घटनाओं की रिपोर्टों में यह देखते हैं कि 51 प्रतिशत दुर्घटनाएं डिरेलमेंट से होती है जिस का कारण डिफेक्टिव इंजन होता है। इंजन में अगर डिफेक्ट है तो उस का सुधार होना चाहिए। 38 प्रतिशत फेन्योर आफ मैट्रीरियल की बजह से दुर्घटनाएं होती हैं। उसमें भी सुधार होना चाहिए और 11 प्रतिशत दुर्घटनाएं मिसलेनियम कारणों में होती हैं। इन सारी चीजों को देखना चाहिए कि किस तरह से हम लोकोमोटिव को रोडवर्डों बनाएं, किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल करें, किस तरह से बेटिनेंस को ठीक करें, किस तरह से कोप्राइंडिनेशन करें ताकि दुर्घटनाएं न हों।

जहां तक कैरिज और वैगन का सबाल है यह आप जानते हैं कि 25 प्रतिशत डिरेलमेंट जो गलत वैगन होते हैं जिन की ठीक से मरम्मत नहीं होती है उसके कारण होते हैं। उन में भी सुधार करने की आवश्यकता है। आज क्या होता है कि जब कोई रेल दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री एक जांच कमीशन बैठा देते हैं। उस की रिपोर्ट आती है तब तक मामला ठण्डा पड़ जाता है। जब कार्यवाही करने का समय आता है तो कुछ होता नहीं है। हम को लगता है कि जितनी भी रिपोर्ट आई है अगर उन्हीं का कार्यालय ठीक तरह से होता तो दुर्घटनाएं रुक जातीं। यह विज्ञान का युग है। दुनिया के दूसरे देशों में जहां रेल गाड़ियों की स्पीड यहां से दुगुनी होती है वहां दुर्घटनाएं कम होती हैं तो क्या कारण है कि यहां इतनी दुर्घटनाएं हों? इसीलिए एक रिसर्च एंड ड्रॉनिंग सेंटर भी रेल मंत्रालय में स्थापित होना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं जितनी कम से कम की जा सके की जाय और यह रिसर्च डिपार्टमेंट इस चौंज को देखें। जब तक यह काम नहीं होगा दुर्घटनाएं बढ़ती रहेंगी।

रेल मंत्रालय का जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसके साथ हमको, सारी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में क्या किया गया है, वह भी बताया जाना चाहिए। दुर्घटनाओं पर जब बहस शुरू हुई तो कुछ लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इन दुर्घटनाओं को राजनीतिक-कारण करने की कोशिश की लेकिन मैं समझता हूँ कि यह कोई राजनीतिक कार्य नहीं है। शुरू में कुछ लोगों ने हमारे परिव्राग और हृदय में सज्जे रेल मंत्री के इस्तोफे को भी मांग की, उनको ग्रायद पता होगा कि अगर श्री लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री के रूप में इस्तीफा देने वालों में भारतवर्ष में प्रथम थे तो श्री मधु दण्डवने प्रधान मंत्री को अपना इस्तीफा देने वालों में दूसरे हैं — यह अलग बात है कि प्रधान मंत्री जो ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया।

[द० रामबी मिह]

इसलिए जिस प्रकार की भावना से व काम कर रहे हैं, मैं विपक्ष के मानवीय नेताओं से और सभी से कहूँगा कि रेल की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय काम समझ कर इसके निवारण के लिए हर स्तर पर सहयोग दें। ट्रेड यूनियन के कानों में बेतन, पेशन प्रमोशन, यह सारे काम थीक हैं लेकिन अगर कोई जीवन के साथ खिलाड़ करता है तो उस ट्रेड यूनियन को भी बैन कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में पूरी छान-बीन की जानी चाहिए।

एक चौज में और कहना चाहता हूँ। रेल विभाग में इंटेलिजेंस भी कायम होनी चाहिए। रेलवे का 40-50 हजार मील का ट्रैक है, आप हर जगह पर सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है और दुर्भाग्य से रोज घटनायें हो रही हैं। इसलिए इंटेलिजेंस का होना भी जरूरी है जो कि इसका पता लगा सके। अगर वह पहले से है तो उसको और लक्षण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दुर्घटनायें होती हैं उसमें जब तक लोग गैंगमेन से नहीं मिलते तब तक घटनायें नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से अपने समाजवादी हृदय के रेल मंडो से कहना चाहूँगा कि आप रेलवे के कर्मचारियों के बेतनों में जहाँ भी बूढ़ि करना चाहें करें लेकिन पहले आपके गैंगमेन के बेतन में बूढ़ि करनी चाहिए और उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आप उन गरीब मजदूरों का बेतन बढ़ा देंगे तो राजमुच में समूची रेलवे लाइन की सुरक्षा का इंश्योरेंस कर लेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि सचमुच में श्रीमती पार्वती कृष्णन ने जो प्रस्ताव रखा है उसके द्वारा इस सदन का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट किया है और इस राष्ट्रीय विपत्ति को हटाने में प्रस्तावक महोदय का भी स्थान होगा। धन्यवाद।

SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA (Uluberia) : Sir, it is a matter of concern that repeated accidents are taking place on the railways.

Somewhere it is sabotage, somewhere it is failure of automatic signalling, somewhere it is over-work and so on.

MR. CHAIRMAN : I want to take the sense of the House. There is a long list of names from both sides. Is it the pleasure of the House that this discussion should continue beyond today?

HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : All right. It will be continued tomorrow or whenever it may be.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : How much time has been allotted?

MR. CHAIRMAN : When we started this discussion today, 3 hours 15 minutes were left. Today we will be utilising 1 hour. So, 2 hours and 15 minutes will still be left. It will be taken whenever we can get time. We do not know when. It will spill over.

PROF. MADHU DANDAVATE : Only this morning some friends coming from the rural areas had demanded that there must be some discussion on the issues of gur and sugar. They were very emphatic about it; and the Speaker has already said that we will permit it. It will have to be decided as to when the allocation of time will be made. Therefore, let us know specifically when it will come up tomorrow. Office must be knowing about it.

MR. CHAIRMAN : The Speaker will consider the position and give a decision.

PROF. P. G. MAVALANKAR : Quite a good chunk of time is still left. If we don't use it, and if it is left out tomorrow, it will go on to the Budget session. Then the whole purpose of having spent time during this session will be lost. I suggest that the feeling of the House be conveyed to the Speaker. Let us tell him that we are in favour of having the discussion tomorrow by extending the time, if possible beyond 6 p.m. for discussing both Railway and sugar.

MR. CHAIRMAN : It will be conveyed to the Speaker.

SHRI SHYAMA PRASANNA BHATTACHARYYA : Accidents may occur for various reasons. Sabotage also, if it is there, may be there for various reasons. The other day, Mr. Dinen Bhattacharya was saying that at the particular railway junction where the

accident took place, the pointsmen were working for about 20 hours. You can understand that it is beyond the physical limits of pointsmen to put in so much of duty. It may be true to some extent. You must be very careful in seeing to it that workers are not compelled to work beyond their physical capacity. It is most important.

Someone was saying that because the Railway workers were expecting bonus and that it was not being given, they might be causing this. But from my own experience I can say that when the Railway strike was going on, and there was severe repression, the fighting Railway workers saved the railway track and railway property. As such, no black spot can be given to them; and their struggle should not be misunderstood. So, that question does not arise.

A committee has now been appointed. You have to see very seriously as to where are the points where workers are over-worked, or where there is a defect in the automatic signalling system. These things are to be studied—not only by experts. We must know from the people in the surrounding areas, as to how it happens. Now, 25,000 people have been appointed. It is good.

PROF. MADHU DANDAVATE : They are deployed. They are already in employment; and they have been deployed.

SHRI SHYAMPRASTANA BHATTACHARYYA : The conscience of the people of our country must be roused, so that before any work of sabotage is successfully carried out, the people in the surrounding areas may catch them red-handed. These people can give you a better report than the officials, about the real culprits. That is the most important thing.

Then, we must develop the patriotic spirit among the people to save the national property in the same way as we save and protect our body. The railways is such an important thing in the whole structure of our country and it can be saved best by the people themselves, and they will do it if their patriotic urge is developed from all angles. I hope the Railway Minister will do something in this direction.

The relationship between the officers and the class 4 employees must be thoroughly changed. While I do not want to accuse the officers, at the same time I want to say that the officers use the class 4 staff as their slaves. They are

compelled to do even their domestic work like slaves. This attitude should be changed. Of course, you cannot do it rapidly. In fact, I have told some of the labour union leaders that when they want to fight for their rights why they are allowing these things to continue and why they are not trying to stop these things. This attitude has to be changed, and that requires consistent effort on the part of the Minister and the railways.

The toiling people must be given the proper respect and the maximum of consideration. The railway authorities should understand that it is the gangmen, the physical workers, who are building the lines, who are laying the points, who are correcting the things, and they are the main strength of the railways to build, maintain and save. They must be roused, they must be respected and their co-operation must be taken. That is the best guarantee to save our country wide railway lines.

I think the Janata Government is still far away from the Janata. You must understand that you have many things to do. How far will you go? When you really fulfil the aspirations of the toiling people, then you can be sure that the railway lines will be safe in their hands.

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति जी, रेल दुर्घटनाओं की तरफ सदन का ध्यान श्रीमती पांवंती कृष्णन् ने आकृष्ट किया है। इस बहस में हिस्सा लेते हुए मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। यह ठीक है कि कई दुर्घटनाएं हुई हैं और उस में अनेकों लोग मरे हैं। यह बहुत ही दुःखद है लेकिन जब हम इस की तह में जाते हैं तो देखते हैं कि साधारण मजदूर जो चतुर्थ श्रेणी से लेकर तीसरी श्रेणी के मजदूर हैं, उन की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जिस अनुपात में अफसरों की संख्या में बढ़ोतारी हुई है। जो सुपरवीजन का काम करते हैं, जनरल मैनेजर से लेकर नीचे के जो सुपरवाइजरी अफसर हैं, उन की संख्या में बहुत बढ़ि हुई है जैसे पहले एक सी० ओ० पी० एस० था और एक डिप्टी सी० ओ० सी० एस० अब एक तो वह है ही लेकिन उन के नीचे 5-

[श्री युवराज]

एहीशनल सी० ओ० पी० एस० 2 डिस्ट्री सी० ओ० पी० एस० है और इसी तरह से आप देखेंगे कि दूसरे अफसरों की संख्या में जरूरत में ज्यादा बढ़ि हुई है लेकिन जो आपरेटिंग स्टाफ है, ड्राइवर है, गेंगमैन है, कंविनेंस है, गार्ड्स हैं उन की संख्या में बढ़ि नहीं हुई है।

अब मंत्री जी ने कहा कि पिछले सात-आठ महीनों में काफी आमदानी हुई। अगर आमदानी नहीं होती है और ये जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं वे भी नहीं होतीं तो हम कह सकते थे कि हमारी रेल की यात्रा में सुरक्षा है और जो आशंकाएं आज लोगों के दिलों में व्याप्त हो गयी हैं, जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है जो कि सारे समाज के लिए चिंता की बात है, वह नहीं होती। मैं यह कहूँगा कि जिस तरह की अफसरताही पहले हावी थी, इसी तरह का अफसरताही आज भी चल रही है, उसमें कमी नहीं हुई है। इस्पेक्टर करने का काम जो जनरल मैनेजर का है, डी० एम० का है, दूसरे अफसरों का है, वे अपने दफ्तरों में बैठ कर इस्पेक्टर करते हैं। वह मजबूर दिवारा जो रात को ट्रैक पर पहरा देता है, जो कंविन में काम करता है, वह आज भी उतने ही चंटे काम करता है जिन्हें कि पहले करता था। जब यादी चलती है तो ड्राइवर के पास या स्टेजन मास्टर के पास इस तरह के कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिसमें वे इन दुर्घटनाओं को रोक सके।

दुनिया के अन्दर, योविधत रशिया में सब से कम रेल दुर्घटनाएं होती हैं। उनके पास ऐसे साधन भी बूँद हैं कि अगर कहीं रेल की पटरी छिपक गयी है, कहीं ट्रैक अलग हो गया है तो संत हो जाता है। इसलिए वहाँ कम से कम दुर्घटनाएं होती हैं। हमारा देश इतना बड़ा देश है, रेलवे से हम इतनी आमदानी भी करते हैं, हमारे पास इन्हें अच्छे रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्हें अच्छे अफसर हैं लेकिन यह सर्वताक बात है कि इतनी

रेल दुर्घटनाएं हमारे देश में हो गयीं। इन बड़ी हुई दुर्घटनाओं को हम किस तरह रोकेंगे यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। निश्चिन रूप से हमारी अव्यवस्था दोषपूर्ण है। जब तक इस अव्यवस्था में मुश्वार नहीं होगा तब तक ये दुर्घटनाएं रुकी नहीं और हमारी एकीजियेंसो बढ़ेगी नहीं।

एक दूसरी बात की तरफ मैं आपका व्यापार आकृष्ट करना चाहूँगा जो दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक हमारे श्री बी० पी० शर्मा जी है जो यहाँ दिल्ली में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सर्वार्थ अण्डरटेकिंग में नौकरी करते हैं। वहाँ वे मुपरिस्टेन्डेंट टेक्नीकल हैं। एक उन्होंने इजाद की है जिसमें हानि वाली दुर्घटनाओं का पूर्व आमाव हो जाएगा। उन्होंने 5-8-77 को रेल मंत्री जी से मिल कर अपनी इस इजाद का उनके सामने डिमांस्ट्रेशन किया। उसमें बाद रेलवे के निदेशक रिसर्च स्टेंडर्ड आरगेनाइजेशन द्वारा जो कि लक्षनक में है, उन्हें दो बार बुलाया गया। उन्होंने वहाँ भी अपनी इजाद को दिखायाया। प्रब उनसे यह मांग की जा रही है कि आप अपना डायरेक्टर भेजिए। लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर तब दूँगा जब मैं भी वहाँ भी बूँद रहूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी तरफ से डिमांस्ट्रेशन होगा। जो हम डायरेक्टर देंगे उसकी बर्ची हो, मिनट ही और हमें एक कापी दे दो। उनका यह भी कहना है कि डिमांस्ट्रेशन के लिए हमें न इंजन चाहिए न और कुछ चाहिए, हमें सिफेर एक आइल ट्रैक दे दो उसके बाद वह अपनी मशीन का डिमांस्ट्रेशन करें। दिखायेंगे और यह बतायेंगे कि किस तरह से दुर्घटनाओं को रोकने में मफलता प्राप्त की जा सकती है। आज प्रगतिमन को मुस्ती आरता परवाही की बजाह से जिस अविन ने उँच बरस निरंतर तप्पस्था करें; इस चोब को इजाद किया है उसको डिमांस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैंने उसको परसनली देखा है, जो यंत्र उन्होंने बनाया है मैंने अविनियत उसे देखा है।

वह कोई टाय नहीं है, बच्चे का खिलौना नहीं है। मैं सभी मानवीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि एक दिन मुकर्रेर हो और आप उन सबको नियंत्रित करके उस यंत्र को देखें। सदस्यगण आपनी मांसों से देख सकते हैं कि इस यंत्र की महायता से दुर्घटनाएँ रोकने में किस प्रकार सहायता मिलेगी। यह नहीं ईचाद एक सफल ईचाद है या नहीं है। हम लोग आज जिस तरकीब को इस्तेमाल करते हैं वह पूर्व जमीनी का सिस्टम है और उमे हम फेल सेफ सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। उसी सिस्टम को हमने यहाँ एडाप्ट किया है। जब एक के बाद दूसरी रेल दुर्घटना होती है, तो हम हाथ मलते रह जाते हैं, केवल संवेदना व्यक्त करने आपने कर्तव्य की इतिही समझ लेते हैं। आप सोचें कि जिसे परिवार के लोग मारे गए हैं, कोई गरीब आदमी जो परिवार की रोटी कमाता या और परिवार का पालन पोषण करता या, कोई मम्पस्प्र आदमी जो उत्तराधिकारी परिवार का या जब वह मारा जाता है तो एकास या पच्चीस हजार स्पष्टे का मुआवजा देने में क्या कोई कम्पेसेशन उनका हो जाता है? यह एक स्टील बक्से हम कर रहे हैं। पुरानी नीति पर ही हम आज भी चल रहे हैं। प्रगति कोई यह कहता है कि काम बहुत भर्खरा हो गया है तो इसको मैं नहीं मानता हूँ। यह ठीक बात है कि रेल मंडी जी बड़े ईमानदार हैं, उनकी इंटेंडेंटी में किसी को कोई शक नहीं है, कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता है लेकिन रेलवे का प्रगासन चन्द्र अफसरों के हाथ में है।—जिधर वे चाहते हैं उधर गाड़ी भोड़ देते हैं, साधारण गैंगमैन ट्रूक पर पहरा देने हैं, ग्राम पंचायतों से अपील की जाती है कि वे पहरा देने का प्रबन्ध करें और उस बालैटीयर मदद करने में लिए तैयार हैं लेकिन क्या होता है? एन एफ रेलवे की गाड़ी तेजपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बहुत से लोग मारे उनको भ्रष्टाचारीय काति हुई। कटिहार से लेकर असम की नाइन ओ हिन्दुस्तान में सब से बड़ी आमदानी का

जरिया है उसको आज तक बरीनी कटिहार तक भी आड़ेज करने की स्वीकृति नहीं दी गई है। जो पुस्तिका बांटी गई है इस में ऐसी दसों लाइनों की चर्चा की गई है जिन को आपने नहीं बनाने की व्यवस्था की है, भीटर गेज से ब्राड में कनवर्गंग की भी आपने स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन बरीनी से कटिहार तक जो भीटर गेज की लाइन है और जिस पर से पच्चीसों माल गाड़ियाँ जाती हैं जिस लाइन में हजारों जबान आते जाते हैं, युद्ध के काम के लिए हैं उसको ब्राड गेज बनाने के लिए आपने पास पैसा नहीं है। साउथ में नई लाइन बन सकती है, बंगाल में बन सकती है, जहाँ के लोग हल्ला कर सकते हैं वहाँ बन सकती है लेकिन हम लोग अराजकता नहीं फैला सकते हैं लाइन को पटरी पर सो नहीं सकते हैं, पटरी को उड़ाड नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कनवर्गंग नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस और भी आप व्याप दें।

हमारे यहाँ बिहार में एक बाबू साहब हैं, बाबू बच्चा सिंह। वह अप्रेजों के जमाने में सिंहापुर से लेकर हिन्दुस्तान तक तमाम चारों पर ठेके लेकर स्टीमर और फैरी सर्विस चलाते थे। आज रेलों फैरी सर्विस नहीं चला सकती है और कहती हैं कि बाटा होता है लेकिन बच्चा सिंह फैरी सर्विस चला रहे हैं। रेलों कहती है कि बाटा लगता है लेकिन उनको बूढ़ा लाभ हो रहा है। बीहापुर से लेकर बरारी तक मनहारी से लेकर सकरी तक पुरानी रेलवे लाइन एवं फैरी सर्विस काफी दिनों से बन्द पड़ी है। मनहारी घाट से जो रेलवे की फैरी सर्विस चलती थी जब फरक्का वैरेज नहीं बना या तब मनहारी घाट ही एक ऐसा मार्ग था जिससे ग्रसाम का कनकता के लोगों से सम्पर्क होता था। आप नो पुराने कानिकारी रहे हैं। आज वह घाट बन्द है। उनकी स्टीमर फैरी चालू है। बाबू बच्चा सिंह की फैरी दो-तीन बार चलती है।

सभापति महोदय : आप समय और
लेंये ?

18.00 hrs.

श्री पुष्टराज : जी हां ।

The House stands adjourned till 11.00
a.m. tomorrow

सभापति महोदय : तो आप अगले दिन
बोलियेगा ।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven
of the Clock on Friday, December 23, 1977/
Pausa, 2, 1899 (Saka)]